लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Fourth Lok Sabha

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9—शुक्रवार, 24 नवम्बर, 1967/3 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 9, Friday, November 24, 1967/Agrahayana 3, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
241.	हिन्दुस्तान फिल्म कम्पनी द्वारा तैयार की गई खराब रा फिल्में — Defective Raw Films Manufactured by Hindustan Film Company	1181-1182
242.	बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड — Bennett Coleman & Co. Ltd.	1183-1187
244.	हंगरी से टायरों के आयात के संबंध में केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा जाँच — C.B.I. Investigation into import of tyres from Hungary	1187-1188
245.	हिन्दुस्तान मोटर्स कम्पनी के शेयर — Shares of Hindustan Motors	1189-1193
248.	चाय का निर्यात — Export of Tea	1193-1196
	अल्प सूचना प्रश्न Short Notice Question	
	अ० सू० प्र० 4 दक्षिण रेलवे के मद्रास स्थित मुख्यालय में इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर — Electronic computors in Headquarters of Southern Railway, Madras,	1196-1200

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या S.Q. Nos.		
243.	काली सूची में दर्ज समवायों की आस्तियों तथा दायित्वों के बारे में जाँच — Enquiry into Assets and Liabilities of Black listed companies	1200

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by by him.

ता० प्रश्न संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
246.	निवेली लिग्नाइट बिजली घर से बिजली की सप्लाई	Power Supply from Neyveli Lignite Power Station	1200
249.	सिडनी में एशिया और सुदूर पूर्व के देशों के लिये आर्थिक आयोग का सम्मेलन	ECAFE Conference in Sydney	1201
250.	बैरल और ड्रम उद्योग	Barrel and Drum Industry	1201-1201
252.	दक्षिण कोरिया द्वारा भारतीय इंजन डिब्बे आदि की खरीद	Purchase of Indian Rolling Stock by South Korea	1202-1203
253.	सरकारी उपक्रमों में अप्रयुक्त क्षमता	Unutilized Capacity in Public Undertakings	1203
254.	स्कूटरों के निर्माण सम्बन्धी योजनायें	Scheme re. Scooter Manufacture	1204
255.	दुर्गापुर धातु- मिश्रित इस्पात संयंत्र	Durgapur Alloy Steel Plant	1204
256.	निर्यात में कमी	Fall in Exports	1205
257.	औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projects	1206
258.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिये कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials for B.H.E.L.	1206
259.	निवेली लिग्नाइट कार-पोरेशन का घाटा	Loss to Neyveli Lignite Corporation	1207
260.	राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात	Exports by S.T.C.	1207-1208
261.	हिन्दुस्तान मोटर्स कम्पनी द्वारा लोहे की चादरों का आयात	Import of Sheets by Hindustan Motors	1208
262.	औद्योगिक कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Material to Industrial Units	1208-1209
263.	लकड़ी के स्लीपर	Wooden Sleepers	1209
264.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास कच्चे लोहे का स्टाक	Stock of Pig Iron with M.M.T.C.	1209-1210
265.	कोयले के मूल्यों सम्बन्धी संकट के कारण रेलों को हानि	Loss to Railways due to Crisis in Coal Prices	1210

ता० प्रश्न संख्या S.Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
266.	आम चुनावों के दौरान विशेष विकास निधि का दुरुपयोग — Misuse of Special Development Fund during General Elections	1211
267.	भारत - पश्चिम जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र में मन्दी — Recession in Indo-West-German Industrial Sector	1211
268.	प्रशुल्क आयोग — Tariff Commission	1211
269.	संयुक्त राज्य अमरीका में आयात व्यापार पर प्रतिबन्ध — Trade Barriers against Imports into the USA	1212
270.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों के लिये परियोजना भत्ता — Project Allowance for N.C.D.C. Workers	1212-1213
अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.		
1625.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का पुनर्गठन — Reorganisation of Public Sector steel plants	1213
1626.	ओखला औद्योगिक बस्ती के कारखानों की इमारतों का बीमा — Insurance of Okhla Industrial Estate Factory Premises	1213
1627.	ओखला औद्योगिक बस्ती में स्थित कारखानों से किराये की वसूली — Rent recovery from factories at Okhla Industrial Estate	1213-1214
1628.	दानापुर - राजगीर रेलगाड़ी का लूटा जाना — Looting of Danapur-Rajgir Train	1214
1629.	यात्री कारों का निर्माण — Manufacture of Passenger Cars	1214
1631.	यवतमाल - ऐल्लिचपुर छोटी लाइन — Yaotmal Ellichpur N. G. line	1214
1632.	हावड़ा से दिल्ली के लिये सुपर ऐक्सप्रेस रेल गाड़ी — Super Express train from Howrah to Delhi	1215
1633.	मुकन्द आयरन एंड स्टील लिमिटेड बम्बई के अंश — Shares of Mukand Iron and Steel Ltd., Bombay	1215
1634.	विग, विगलेट तथा फाल का निर्माण — Manufacture of Wigs, Wiglets and Falls	1216
1635.	कोयला खानों की रायल्टी की बकाया राशि — Arrears of Royalty of Collieries	1216-1217

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1636.	त्रिवेन्द्रम में बुनकर सेवा केन्द्र	Weavers' Service Centre at Trivandrum	1217
1637.	नारियल-जटा बोर्ड का सचिव	Secretary, Coir Board	1217
1638.	गुजरात में बिड़ला और टाटा के उद्योग	Industries owned by Birlas and Tatas in Gujarat	1218
1639.	गुजरात में नये उद्योग	New Industries in Gujarat	1218
1640.	गुजरात में औद्योगिक बस्तियाँ	Industrial Estates in Gujarat	1218-1219
1641.	गुजरात में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Gujarat	1219-1220
1642.	गुजरात में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Gujarat	1220
1643.	सागर जिले में कैल्साइट के निक्षेप	Calcite Deposits in Saugor District	1221
1644.	आसाम में चाय बागान	Tea Gardens in Assam	1221
1645.	निर्यात के बदले में मेवों का आयात	Import of dry fruits against exports	1221-1222
1646.	प्रिसीजन इंस्ट्रुमेंट्स फैक्टरी पुडूसेरी	Precision instrument Factory Pudussery	1222
1647.	हैवी प्लेट एंड वैसल प्रोजेक्ट	Heavy Plates and Vessel Project	1222-1223
1648.	अनुसूचित जातियों के यातायात प्रशिक्षणार्थी	Scheduled Castes Traffic Trainees	1223
1649.	खाद्य तेल का आयात	Import of Edible Oil	1223
1650.	ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Tractors	1223
1651.	बंगाल बन्द के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railway on account of Bengal Bandh	1224
1652.	कोरबा में एल्यूमीनियम संयंत्र	Aluminium plant at Korba	1224
1653.	आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संस्था	Import and Export Trade Control Organisation	1224-1225
1654.	इंजीनियरी उद्योगों में मंदी	Recession in Engineering Industries	1225
1655.	अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्धारित मूल्यों पर वितरण	Distribution of Essential Commodities at fixed prices	1226
1656.	मैसर्स रेमन इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता	M/s Raymon Engineering Works, Calcutta	1226
1657.	टाइल उद्योग	Tile Industry	1226

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1658.	धनबाद स्थित हिन्दुस्तान जस्ता फैक्टरी में हड़ताल	Strike in Hindustan Zinc Factory, Dhanbad	1227
1659.	केलों का निर्यात	Export of Bananas	1227
1660.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Gajendergadkar Commission's Recommendation by Hindustan Cables Ltd.	1228
1661.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर	H. M. T., Bangalore	1228
1662.	विदेशी पूंजी विनियोजन	Foreign Investment	1228
1663.	सस्ते कपड़े का मूल्य	Prices of Cheaper Varieties of Cloth	1229
1664.	निर्यात बढ़ाने के लिये संगणक	Computers to Boost Export	1229
1665.	आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों में उत्पादित कपास	Kapas Produced in Krishna and Guntur Districts	1229-1230
1666.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अंश	Shares of British India Corporation	1230
1667.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास	Industrial Development in West Bengal	1230-1231
1668.	मोटरकार किस्म जाँच समिति का प्रतिवेदन	Motor Car Quality Inquiry Committee Report	1231
1669.	रेलवे तथा इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किये गये कोयले के मूल्य	Price of coal supplied to Railways and Steel Plants	1231-1232
1670.	नये उद्योगों की लागत तथा मूल्य ढांचा	Cost and price structure of new Industries	1232
1671.	रेलवे के स्कूलों के शिक्षक	Teachers in Railway Schools	1232
1672.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची के अध्यक्ष	Chairman, Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1233
1673.	पूर्व तथा दक्षिण- पूर्व रेलवे के मुख्य कार्यालयों में संगणकों के प्रयोग के विरुद्ध प्रदर्शन	Demonstration against Introduction of Computors in Eastern and S. E. Railway Headquarter Offices	1233
1674.	मिट्टी के बर्तनों की कला के विकास का केन्द्र	Development Centre for Pottery Crafts	1233-1234

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
1675.	निर्यात सार्थ-संघ	Export Consortia	1234-1235
1676.	भारत यूगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य की बैठक	India-Yugoslavia UAR Meeting	1235
1677.	थाना जिले में नमक उत्पादन में कमी	Loss in Salt Production in Thana District	1235
1678.	ह र के निकट हैवी इलेक्ट्रीकल्स संयंत्र	Heavy Electrical Plant near Hardwar	1235-1236
1679.	भारतीय प्रतिनिधि मंडल की जापान की यात्रा	Visit of Indian Delegation to Japan	1236
1680.	सरकारी उपक्रमों का विस्तार	Expansion of Public Undertakings	1237
1681.	लाइसेंस नीति के संबंध में डा० हजारी का प्रतिवेदन	Dr. Hazari's Report on Licencing Policy	1237
1682.	दिल्ली, एक शुष्क पत्तन के रूप में	Delhi as Dry Port	1237
1683.	अप्रयुक्त माल डिब्बे	Wagons Lying Idle	1238
1684.	ग्रामोफोन रिकार्डों का निर्यात	Export of Gramophone Records	1238
1685.	कटनी में कच्चे लोहे का उत्पादन	Manufacture of Pig Iron at Katni	1239
1686.	बिनौले का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	F.O.B. Value of cotton seed Extraction	1239
1687.	बस्तर में कागज तथा लुग्दी संत्र	Paper and Pulp plant in Bastar	1239
1688.	नरखेड़ - अमरावती रेलवे लाईन	Narkher-Amravati Railway Line	1239-1240
1689.	हवादार माल डिब्बे	Ventilated Wagons	1240
1690.	गाड़ियों का न चलाया जाना	Cancellation of Trains	1240-1241
1691.	गरहरा वाहनान्तर (ट्रांशिपमेंट) यार्ड के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Workers of Garhara Transhipment Yard	1241
1692.	जयपुर के लिये बुक किये गये चीनी के माल डिब्बों का लापता होना	Sugar Wagons booked for Jaipur Missing	1242

अता० प्रश्न संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
1693.	भारत - संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार	Indo-UAR Trade	1242-1243
1694.	मण्डपम स्टेशन से धनुषकोडी तक रेलवे लाइन	Railway line from Mandapam Station to Dhanushkodi	1243
1695.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कालमेसरी (केरल) कारखाने का विस्तार	Expansion of Hindustan Machine Tools, Kalamassery (Kerala)	1243-1244
1696.	पश्चिम बंगाल में हड़ताल के कारण उद्योगों को हुई हानि	Loss to Industries due to Hartal in West Bengal	1244
1697.	यूरिया की उत्पादन लागत	Cost of Production of Urea	1244
1698.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा पुर्जों तथा उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Spare Parts and Components by B.H.E. L.	1244
1699.	निर्यात प्रधान कताई मिलें	Export Oriented Spinning Mills	1245
1700.	केरल में लोह अयस्क के भण्डार	Iron Ore Deposits in Kerala	1245
1701.	सौराष्ट्र मेल का पटरी से उतरना	Derailment of Saurashtra Mail	1245-1246
1702.	रेलगाड़ियों पर पत्थर फेंकने की घटनायें	Stone throwing incidents on trains	1246
1703.	इस्पात कारखानों की क्षमता	Capacity of steel plants	1246
1704.	मोटरकारों के लिये अपेक्षित विभिन्न किस्म की धातुओं तथा उत्पादों का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों द्वारा निर्माण	Manufacture of various types of Metals and products required for motor cars by H.S.L. Plants	1247
1705.	कल्याण रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया जाना	Remodelling of Kalyan Railway Station	1247
1706.	किरकी और शिवाजी नगर (मध्य रेलवे) के बीच दुर्घटना	Accident between Kirkee and Sivajinagar (Central Rly.)	1248
1707.	लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिये निगम	Corporation for export of goods produced by small scale Industries	1248

अता० प्र० सं० S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1708.	अंगोरा ऊन का आयात	Import of Angora Wool	1248
1709.	रेलवे पार्सल कार्यालय, वाराणसी	Railway Parcel Office, Varanasi	1249
1710.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने को घाटा	Loss to Durgapur Steel Plant	1249
1711.	भिलाई इस्पात कारखाना	Bhilai Steel Plant	1249
1712.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में मंदी	H.M.T. Suffering from Recession	1249-1250
1713.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये उपकरणों का आयात	Equipment imported for Public Sector Industries	1250-1251
1714.	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिये नकद सहायता	Cash assistance for export commodities	1251
1715.	भारतीय रेलवे को वित्तीय सहायता के बारे में पश्चिम जर्मनी के साथ बातचीत	Discussions with West Germany for financial assistance to Indian Railway	1251
1716.	राज्य व्यापार निगम के पास ऊन के स्टाक का जमा हो जाना	Accumulation of wool stocks with S.T.C.	1251-1252
1717.	हरियाना, दिल्ली और पंजाब के लिये माल डिब्बे	Wagons for Haryana, Delhi and Punjab	1252
1718.	रेलवे समय सारिणी	Railway Time Table	1252
1719.	खानों के लिये रायल्टी की दरें	Royalty rates for Mines	1252-1253
1720.	पटसन उद्योग को हानि	Loss to jute Industry	1253
1721.	उदयपुर जिंक संयंत्र	Udaipur Zinc Plant	1253-1254
1722.	छोटी कार	Small Car	1254
1723.	स्वर्ण सायनाइड का आयात	Import of Gold Cyanide	1254-1255
1724.	दीपू रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे)	Railway Station, Diphu (N.E. Rly)	1255
1725.	नाहन ढलाई घर (फाउंड्री) द्वारा केन क्रशरों की सप्लाई	Supply of Cane Crushers by Nahan Foundry	1255
1726.	उद्योग निदेशक, दिल्ली द्वारा जारी किये गये अनिवार्यता प्रमाणपत्र	Essentiality certificates issued by Director of Industries, Delhi	1256

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1727.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में अनियमितताएं	Irregulatities in Hindustan Machine Tools	1256
1728.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में निर्मित औजारों का गुण-प्रकार	Quality of Hindustan Machine Tools	1256-1257
1729.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा खरीदे गये पानी के मीटर	Water Meters purchased by Heavy Engineering Corporation	1257
1730.	उड़ीसा में कुटीर उद्योग	Cottage Industry in Orissa	1257-1258
1731.	माल यातायात के संबंध में रेलवे का कार्य	Performance of Railways in Handling Goods Traffic	1258
1732.	कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Coal	1258
1733.	कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे	Circular Railway in Calcutta	1259
1734.	बड़ी रेलवे लाइन को जोगीघोपा से तिनसुकिया तक बढ़ाना	Extension of B.G. Railway line from Jogighopa to Tinsukia	1259
1735.	गुंटाकल–बंगलौर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Guntakal-Bangalore M. G. Line into B. G. Line	1259
1736.	काण्डला तथा करैकल पत्तन	Kandla and Karaikal Ports	1259-1260
1737.	मैसूर में उद्योगों का बन्द होना	Closure of Industries in Mysore	1260
1738.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में मशीनी औज़ारों का स्टाक	Stock of Machine tools with H.M.T.	1260-1261
1739.	बोकारो इस्पात संयंत्र का निदेशक-मंडल	Board of Directors of Bokaro Steel Plant	1261
1740.	सिंगापुर की मंडी से रूई का आयात	Import of Cotton from Singapur Market	1261
1741.	काली मिर्च का निर्यात	Export of black pepper	1261
1742.	शिशु आहार का मूल्य	Prices of Baby Food	1262
1743.	नारियल जटा बोर्ड	Coir Board	1262
1744.	अरब देशों को निर्यात	Export to Arab Countries	1262-1263
1745.	इंजीनियरिंग उद्योग में मंदी	Recession in Engineering Industry	1263-1264

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1746.	पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार	Trade with East European Countries	1264
1747.	उद्योगों के लिये विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration for Industries	1264
1748.	बिड़ला फर्मों को जारी किये गये लाइसेंस	Licences issued to Birla Concerns	1264-1265
1749.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन	Reorganisation of Hindustan Steel Ltd.	1265
1750.	दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के कुली	Porters at Delhi and New Delhi Railway Stations	1265
1751.	गाड़ियों में बिजली तथा पंखों की दोषपूर्ण व्यवस्था	Defective lighting and Fan Equipments in Trains	1265-1266
1752.	दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification on Delhi Howrah Line	1266-1267
1753.	एक्सप्रेस/मेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना	Late Running of Express Mail/Trains	1267-1268
1754.	माल डिब्बा निर्माण उद्योग	Wagon Building Industry	1268
1755.	सरकार द्वारा सूती कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of cotton Textile Mills	1268-1269
1756.	पश्चिम बंगाल में उद्योगों का बन्द होना	Closure of Industries in West Bengal	1269
1757.	पश्चिम बंगाल में रेल-गाड़ियों पर हमला	Attack on Train in West Bengal	1270
1758.	बिड़ला के औद्योगिक कारखानों द्वारा कदाचार	Malpractices by Birla Industrial Units	1270
1759.	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production	1270-1271
1760.	दुर्गापुर तथा रूरकेला इस्पात संयंत्रों का विस्तार	Expansion of Durgapur and Rourkela steel Plants	1271-1272
1761.	इराक, लेबनान तथा लीबिया को व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation to Iraq, Lebanon and Libya	1272
1762.	इस्पात का निर्यात	Steel Export	1272-1273

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1763.	उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951	Industries (Development and Regulation) Act, 1951	1273
1764.	तकनीकी विकास महानिदेशालय	Directorate General of Technical Development	1273-1274
1765.	विदेशों के साथ व्यापार	Trade with Foreign Countries	1274
1766.	पैरिस में महाराष्ट्र सरकार का वाणिज्यिक केन्द्र	Maharashtra Government Commercial Centre in Paris	1275
1767.	धातुमिश्रित और विशेष इस्पात परियोजनाओं के लिये परियोजना संबंधी प्रतिवेदन	Project Report for Alloy and Special Steel Projects	1275
1768.	केरल में लौह-अयस्क के निक्षेप	Iron Ore Deposits in Kerala	1275-1276
1769.	काँडला पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore through Kandala Port	1276
1770.	बॉक्साइट का निर्यात	Export of Bauxite	1276
1771.	भारत में ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacturing of Tractors in India	1277
1772.	रेलवे में चार्जमैन और फोरमैन	Chargemen and Foremen on Railways	1277
1773.	रूसी ट्रैक्टरों के लिये टायरों तथा ट्यूबों का आयात	Import of Tyres and Tubes for Russian Tractors	1277-1278
1774.	ट्रावनकोर टिटेनियम उत्पाद	Travancore Titanium Products	1278
1775.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कालमेसरी कारखाने में तालाबन्दी	Lock out in Kalemessari Unit of H.M.T.	1279
1776.	उपनगरीय यात्राओं के लिये रेलवे किराया निर्धारित किया जाना	Fixation of Railway Fares for Suburban Journeys	1279
1777.	पारादीप बन्दरगाह में पटसन मिल	Jute Mill at Paradeep Port	1279-1280
1778.	नये वेस्पा स्कूटर के साथ फालतू पहिया न दिया जाना	Non-supply of spare Wheel with New Vespa Scooters	1280
1779	चोर बाजार में बेची गई मोटर गाड़ियाँ	Vehicles sold in Black market	1280

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1780. संयंत्रों की पूरी क्षमता का प्रयोग	Utilisation of Plants to their full Capacity	1281
1781. मैसूर में अयस्क तथा खनिजों के लिये सर्वेक्षण	Survey for Ore and Minerals in Mysore	1281-1282
1782. राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रोयोजित उद्योगों में रोजगार	Jobs in Centrally sponsored industries in states	1282
1783 इंडिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स, सेरामपुर	India belting and cotton mills, Serampur	1282-1283
1784 बिहार में रेलवे लाइन के निकट बम	Bomb near Railway line in Bihar	1283
1785. लोगों द्वारा रेल गाड़ियों को रोका जाना	Stopping of trains by public	1283
1786. उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर माल से भरी गाड़ियाँ खडी रहना	loaded wagons lying on station on N. Railway	1283
1787. खेमकरन स्टेशन का पुनर्निर्माण	Reconstruction of Khem Karan Station	1283-1284
1788 अर्थ-व्ययस्था में मंदी	Recession in Economy	1284
1789 नारियल - जटा की वस्तुओं का निर्यात	Export of Coir Products	1284-1285
1790. रेलवे की आय	Railway Earnings	1285
1791. प्रीसीजन इंस्टेंमेंट्स फैक्टरी, पालघाट	Precision Instruments Factory, Palghat	1286
1792. दिल्ली से अमृतसर को जाने वाली गाड़ियों का देर से चलना	Late running of trains from Delhi to Amritsar	1286
1793. लघु उद्योग	Small scale industries	1286
1794. भेड़ बकरी की चर्बी के आयात के लिये लाइसेंस	Import licences for Mutton Tallow	1286-1287
1795. संसद् सदस्यों को फिएट कारों का आवंटन	Allotment of Fiat cars to M.Ps.	1287
1796. मेसर्स अमी चंद प्यारे लाल एंड कंपनी	Messrs. Aminchand Pyarelal & Co.	1287-1288

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1797.	गेहूँ के उत्पादों के लिये भारतीय मानक संस्था के विशिष्ट विवरण	I.S.S. for Wheat Products	1288
1798.	दक्षिणी कोरिया को रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Supply of Railway Wagons to South Korea	1288
1799.	रेल दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाना	Compensation to victims of Railway accidents	1289
1800.	केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters by Kerala State Industrial Development Corporation	1289-1290
1801.	हावड़ा के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Howrah	1290
1802.	राजस्थान में गन्धक के निक्षेप	Sulphur deposits in Rajasthan	1290
1803.	आन्ध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में विमान द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण	Aerial Mineral Survey in Andhra Pradesh, Bihar and Rajasthan	1290-1291
1804.	आन्ध्र प्रदेश में ताँबे और शीशे के निक्षेप	Copper and Lead deposits in Andhra Pradesh	1291
1805.	औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था संबंधी थैकर समिति का प्रतिवेदन	Report of Thacker Committee on Industrial Licensing	1291
1806.	संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के लिये निगम	Corporation for sick Textile Mills	1292
1807.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों का कार्य-संचालन	Working of N.C.D.C. Mines	1292
1808.	राज्य व्यापार निगम के पदाधिकारियों द्वारा विदेश यात्राएँ	Tours Abroad by the Officers of S.T.C.	1292
1809.	आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा मैसर्स इंटर-नेशनल ब्यूरो आफ मैशीज़ को किया गया भुगतान	Payment made by C.C.I. & E. to Messrs International Bureau of Machines	1293

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1810.	मेंढकों की टाँगों का निर्यात	Export of Legs of Frogs	1293
1811.	मैसर्स इंटरनेशनल ब्यूरो आफ मशींज़ लिमिटेड से आयात तथा निर्यात के महा-नियंत्रक द्वारा मशीनों की खरीद	Purchase of Machines by C.C.I. & E. from M/s I.B.M. Ltd.	1294
1813.	कोयना में आल्योमीनियम परियोजना	Aluminium Project at Koyana	1294-1295
1814.	जोगीघोपा से गोहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार	Extension of B. G. Line from Jogighopa to Gauhati	1295
1816.	चलचित्रों का निर्यात	Export of Films	1295-1296
1817.	रॉक फॉस्फेट का आयात	Import of Rock Phosphate	1296
1818.	लाइट रेलवे	Light Railways	1297
1819.	कच्ची ऊन का आयात	Import of Raw Wools	1297-1298
1820.	बम्बई की कुछ फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी विनि-यमों के मामले में की गई अनिय-मितताएं	Irregularities in Foreign Exchange Viola-tions by some Bombay Firms	1298
1821.	कपास के मूल्य	Prices of Cotton	1298
1822.	राजकीय व्यापार निगम द्वारा चावल का निर्यात	Export of rice by S.T.C.	1298-1299
1823.	कटक से पारादीप पत्तन तक रेलवे लाइन	Railway line from Cuttack to Paradip Port	1299
1824.	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में दलकोल्हा और तेलता स्टे-शनों के बीच रेल दुर्घटना	Accident between Dalkolha and Telta Stations (N.E.F. Rly)	1299-1300
1825.	काकिनाडा पत्तन में कच्चे लोहे की चोरी	Theft of Pig Iron at Kakinada Port	1300
1826.	इन्टेग्रल कोच फैक्टरी को इस्पात की चादरों की सप्लाई	Supply of steel sheets to Integral Coach Factory	1300-1301
1827.	विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का कारखाना	Zinc Smelter Plant at Visakhapatnam	1301-1302

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1828.	काण्डला में निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Free Trade Zone at Kandla	1302
1829.	ट्रांजिस्टर के सैलों का वितरण	Distribution of Transistor Cells	1303
1830.	औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में पार्लियामेंटरी असिस्टेंट (संसद् कार्य सहायक)	Parliament Assistants in the I.D. & C.A. Ministry	1303
1831.	आसाम में मंगलदायी और खरुपतिया से तंगला तक रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना	Extension of Railway line from Tangla to Mangoldai and Kharupatia in Assam	1303
1832.	आसाम में बड़ी लाइन का विस्तार	Extension of B.G. Line in Assam	1304
1833.	पंजाब में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना	Tractor Factory in Punjab	1304
1834.	मैसर्स रेमन इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता	M/s Rayman Engineering Works, Calcutta	1304
1835.	रबड़ का आयात	Import of Rubber	1304-1305
1836.	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car	1305
1837	पानीपत और गोहाना के बीच रेल लाइन	Rail Link between Panipat and Gohana	1305
1838.	हरियाना में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Haryana	1305-1306
1839.	हरियाना में ट्रैक्टर परियोजना	Tractor Project in Haryana	1306
1840.	रोहतक में इस्पात का कारखाना	Steel Plant at Rohtak	1306
1841.	रेलगाड़ियों की टक्कर और पटरी से उतरने की दुर्घटना	Railway Collisions and Derailments	1306-1307
1842.	इराक के साथ व्यापार	Trade with Iraq	1307
1843.	सरकारी सीमेंट कारखाना, सुवाखेड़ा	Government Cement Factory, Suwakhera	1307
1844.	नये उद्योग	New Industries	1307-1308
1845.	यूरोप और अमरीका में चाय समिश्रण कारखाने	Tea Blending Factories in Europe and USA	1308

अता० प्रश्न संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1846.	बिजली से चलने वाले लघु उद्योग	Power driven small scale industries	1308-1309
1847.	इस्पात कारखानों को दिये गये कोयले का मूल्य	Price of coal supplied to steel Plants	1309-1310
1848.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तकनीकी दोष	Technical Defects in Durgapur Steel Plant	1310
1849.	पटसन की वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Goods	1311
1850.	एक्सपो–67 कनाडा में भारतीय मंडप	Indian Pavilion at Expo-67 Canada	1311-1312
1851.	टेलीविजन सेटों का आयात	Import of Television Sets	1312
1852.	राज्य व्यापार निगम द्वारा नियुक्त वितरण एजेंट	Distributing Agents Appointed by S.T.C.	1312
1853.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये ब्रिटेन से सहायता	British Assistance for Durgapur Steel Plant	1312-1313
1854.	उदयपुर में फास्फेट के निक्षेप	Phosphate Deposits in Udaipur	1313
1855.	1966-67 में रेलवे दुर्घटनाएँ	Railway Accidents in 1966-67	1313
1856.	चमड़ा कमाने की सामग्री	Leather Tanning Material	1313-1314
1857.	पश्चिम बंगाल से उद्योगों का पलायन	Flight of Industries from West Bengal	1314
1859.	उत्तर रेलवे का लोको वर्क-शाप, अमृतसर	N. Rly. Loco Workshop, Amritsar	1315
1860.	बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन पर रेलगाड़ियों में स्थानों का आरक्षण	Reservations at Bombay Central Station	1315
1861.	दक्षिण रेलवे की आय में कमी	Decrease in Revenues of Southern Railway	1316
1862.	व्यापार मण्डल (बोर्ड आफ ट्रेड)	Board of Trade	1316
1863.	हेवी इंजीनियरी कमलैक्स राँची का कार्य संचालन	Working of H.E.C. Ranchi	1316-1317
1864.	श्रीलंका से चाय का आयात	Import of Tea from Ceylon	1317
1865.	बोकारो इस्पात परियोजना का निर्माण	Construction of Bokaro Steel Project	1317-1318

अता० प्रश्न संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1866.	मशीनरी का आयात	Import of Machinery	1318
1867.	चलती रेलगाड़ियों में चोरी तथा डकैती की घटनाएँ	Incidents of Thefts and Dacoity in Running Trains	1318
1868.	मध्य प्रदेश में लोहे की नई खानें	New Steel Mines in Madhya Pradesh	1318-1319
1869.	पश्चिम निमाड़ जिले में रेलवे लाइनें	Railway Lines in the Western Nimar District	1319
1870.	भारत के मार्ग से नेपाल द्वारा आयात	Imports by Nepal through India	1319
1871.	नेपाली नौभार का परिवहन	Transportation of Nepalese Cargo	1320
1872.	नादियाद के निकट गुजरात एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	Derailment of Gujarat Express near Nadiad	1320
1873.	भारत के निर्यात के बारे में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का दल	U. N. Experts Team on India's Export	1320-1321
1874.	आसनसोल यात्री गाड़ी	Assansol Passenger Train	1321
1875.	चाय, काफी और रबड़ का उत्पादन	Production of Tea, Coffee and Rubber	1321
1876.	वित्तीय और/अथवा तकनीकी सहयोग	Financial and/or Technical Collaboration	1321-1322
1878.	रेलवे विभाग में हिन्दी पर्यवेक्षक	Hindi Supervisors on Railways	1322
1879.	रेलवे स्कूलों में अध्यापक	Teachers in Railway Schools	1322-1323
1880.	दिल्ली में उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Northern Railway Employees in Delhi	1323
1881.	बलोत्रा रेलवे स्टेशन के लिये नई इमारत	New Building for Railway Station, Balotra	1323
1882.	गुजरात में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज लाइनें	Broad Gauge, Metre Gauge and Narrow Gauge Lines in Gujarat	1323-1324
1883.	मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Madhya Pradesh	1324
1886.	थाइलैंड से घटिया किस्म के मेस्टा का आयात	Import of Lower Grade Mesta from Thailand	1324
1887.	कपड़ा उद्योग के लिये समिति	Committee for Textile Industry	1324-1325

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1888.	छत वाले माल डिब्बों की कमी	Shortage of Covered Wagons	1325-1326
1889.	रेलवे दुर्घटनाएँ	Railway Accidents	1326
1890.	उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उद्योग	Industries in U. P. in Public Sector	1326
1891.	वाराणसी में टैक्टर बनाने का कारखाना	Tractor Factory in Varanasi	1327
1892.	घाघरा नदी पर रेलवे का पुल	Railway Bridge over the River Ghaghra	1327
1893.	वातानुकूलित डिब्बे	Air conditioned Bogies	1328
1894.	दिल्ली और लखनऊ के बीच एक यात्री गाड़ी का चलाना	Running of a Passenger Train between Delhi and Lucknow	1328
1895.	बम्बई के एक चलचित्र अभिनेता को स्टेनलैस स्टील के आयात का लाइसेंस	Import Licence for statinless steel granted to a Bombay Film Star	1328-1329
1897.	लपेटवों (रोलिंग) चादर बनाने का धातु	Rolling sheet Metal	1329-1330
1898.	स्टैंडर्ड हैरल्ड कारों के लिये दरवाजों के हैंडलों का आयात	Import of Car Door handles for standard Herald Car	1330
1899.	निर्यात संवर्धन परिषदें	Export promotion councils	1330
1900.	नीवेली में बिजली का उत्पादन	Power produced at Neyveli	1330
1901.	फिलिपीन के साथ व्यापार	Trade with Philippines	1331
1902.	विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौते	Foreign collaboration Agreements	1331
1903.	इस्पात के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये समिति	Committee to Assess steel production	1331-1332
1904.	मध्य रेलवे में चलती गाड़ी से गिरने की घटना	Falling incident from Running Train on Central Railway	1332
1905.	तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco	1332-1333
1906.	मध्य रेलवे में ललितपुर होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर स्टेशनों की आय तथा वहाँ पर उपलब्ध सुविधायें	Earnings of and amenities provided at Lalitpur, Hoshangabad and Narasinghpur stations on Central Railway	1333-1334

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1907. लघु उद्योगों का विस्तार	Expansion of small scale industries	1334-1335
1908. दंडकारण्य में कागज तथा लुग्दी परियोजना	Paper and Pulp project in Dandakaranaya	1335
1909. चश्मे (आप्टीकल) संबंधी उपकरण परियोजना, लखनऊ	Optical Instruments Project, Lucknow	1335
1910. बिड़ला संगठनों में सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी	Retired Government Officers working in Birla Organisations	1335-1336
1911. मिहिनपुरवा स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Mihinpurwa Station	1336
1912. राज्यों द्वारा सूती कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Cotton Textile Mills by States	1336-1337
1913. नारियल जटा के धागे के निर्यात पर उपकर	Cess on the export of Coir Yarn	1337
1914. कच्चे रबड़ का मूल्य	Price of Raw Rubber	1337
1915. अल्जियर्स में सम्मेलन	Conference at Algiers	1337-1338
1916. रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production at Rourkela Steel Plant	1338
1917. रेलवे समय सारिणी	Railway Time Tables	1338
1918. अग्निगुंडला में ताम्बा परियोजना	Copper Project Agnigundala	1339
1919. आसाम में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Assam	1339
1920. अमरीका से रेल की पटरियों का आयात	Import of Rails from USA	1339
1921. बल्लारपुर कोयला खान	Ballarpur Colliery	1340
1922. इस्पात कारखानों में 'घेराव'	Gheraos in Steel Plants	1340
1923. कल्याण स्टेशन के यार्ड में शंटिंग	Shunting at Kalyan Station Yards	1340-1341
1924. दीवाँ-दहानू रेलवे लाइन	Diva Dahanu Railway Line	1341
1925. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of National Coal Development Corporation	1341
1926. पुर्तगाल के साथ व्यापार	Trade with Portugal	1342
1927. रूपनरायनपुर केबल्स फैक्टरी	Rupnarainpur Cables Factory	1342

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1928. बिड़ला बन्धुओं के बैंक	Banks owned by Birla	1342-1343
1929. जापान को कोयले का निर्यात	Export of coal to Japan	1343
1930. उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना	Delicensing of Industries	1343
1931. रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा टिन प्लेटों की सप्लाई	Supply of Tinplates by Rourkela Steel Plant	1343-1344
1932. सरकारी क्षेत्रों में इस्पात कारखाने	Steel Plants in Public sector	1344
1933. इस्पात कारखानों के कार्य का समय-समय पर पुनर्विलोकन	Periodical Review of the working of Steel Plants	1344
1934. इस्पात कारखानों की क्षमता	Capacity of steel plants	1345
1935. वैक्यूम ब्रेक	Vacuum Brakes	1345
1936. सहकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Cooperative Sector	1345
1937. भारी वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के मूल्यों तथा वितरण पर नियंत्रण	Control of price and distribution of Heavy Commercial vehicles	1346
1938. पिंजोर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ का कारखाना	H.M.T. Factory, Pinjore	1346
1939. सीमेंट की मूल्य वृद्धि	Price Increase of cement	1346
1940. इस्पात के बिलेटों के निर्यात के लिये राज-सहायता	Subsidy for Export of Steel Billets	1347
1941. बुनकर सहकारी समिति	Weavers' Cooperative Society	1347
1942. रबड़ का आयात	Import of Rubber	1347
1943. उपभोक्ता वस्तु निगम	Consumer Commodity Corporation	1348
1944. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ तथा सरकारी कर्मचारी	R.S.S. and Government Employees	1348
1945. पतराटू में पानी की सप्लाई	Supply of Water at Patratu	1348
1946. सैनिकों द्वारा बिना टिकट यात्रा	Trawel without Tickets by Army Men	1349
1947. आसाम में रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents in Assam	1349
1948. रेशम के धागे का निर्यात	Export of Silk Yarn	1349-1350
1949. उड़ीसा सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के लिए की गई सिफारिश	Industrial licences Recommended by Orissa Government	1350

अतां० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1950.	उड़ीसा में खनन पट्टे	Mining leases in Orissa	1350
1951.	मनीपुर से पशुओं का निर्यात	Export of Cattle from Manipur	1351
1952.	रत्नगढ़ और अहमदाबाद के बीच सीधे जाने वाली रेलगाड़ी	Through Railway Coach between Ratnagarh and Ahmedabad	1351
1953.	हावड़ा स्टेशन पर उपद्रवी भीड़ द्वारा हमला	Mob Attack at Howrah Station	1351-1352
1954.	सरकारी क्षेत्र की ट्रैक्टर परियोजना संबंधी प्रतिवेदन	Report for Public Sector Tractor Project	1352-1353
1955.	चैकोस्लोवाकिया की एक फर्म के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors in Collaboration with a Czech. Firm	1353-1354
1956.	क्रॉलर ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये लाइसेंस	Licence for manufacture of Crawler Tractor	1354-1355
1957.	हैवी इलेक्ट्रिक्ल लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Ltd. Bhopal	1355-1356
1958.	आपरेशन हार्ड रोक अभियान	Operation Hard Rock	1356
1959.	रेलवे में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes Railway Employees	1357
1960.	महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना	Aluminimum Factory in Maharashtra	1357
1962.	दक्षिण-मध्य रेलवे में सोमपुर स्टेशन पर रेलवे क्वार्टर	Railway Quarters at Sompur Station (S. C. Rly).	1358
1963.	औद्योगिक बस्तियों की क्षमता	Capacity of Industrial Estates	1358
1964.	राजकीय व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री	Sale of Cars by S.T.C.	1358-1359
1965.	देहू रोड स्टेशन पर पैदल चलनेवालों के लिए ऊपरी पुल	Pedestrian Overbridge on Dehu Road Station	1359
1966.	रूई का आयात	Import of Cotton	1359
1967.	उद्योगों के लिए तरीके	Processes for Industries	1359-1360
1968.	आसाम में उद्योगों के लिए आयात लाइसेंस	Import Licences for Industries in Assam	1360
1969.	ऊन का निर्यात	Export of Wool	1360-1361
1970.	रेल के माल डिब्बों के निर्यात के लिए क्रयादेश	Export Orders for Railway Wagons	1361

अतां० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1971.	किसान बोगी	Kisan Bogies	1361-1362
1972.	बरसुआन लोहे की खानों में लौह अयस्क की लागत	Cost of Iron ore in Barasuan Iron mines	1362
1973.	रूरकेला इस्पात कारखाने में मन्द गति (स्लो डाउन्स) के कार्य	Slow Downs at Rourkela steel Plant	1362
1974.	रायपुर से भोपाल तक रेल-गाड़ी की व्यवस्था	Train Service from Raipur to Bhopal	1363
1975.	भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, मैसूर	Bhadravatti Iron and Steel Works, Mysore	1363
1976.	खोई हुई सम्पत्ति के दावे और रेलवे की सम्पत्ति की चोरी	Lost Property Claims and Theft of Railway Property	1363-1364
1977.	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड	All India Handicrafts Board	1364-1365
1978.	उड़ीसा में फैरो-क्रोम परियोजना	Ferro Chrome Project in Orissa	1365
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling attention to Matter of Urgent Public Importance	1366
कलकत्ता और केरल में चीन समर्थक नारे लगाये जाने के समाचार		Reported pro-Chinese slogans in Calcutta and in Kerala	1366-1367
श्री हुक्म चन्द कछवाय		Shri Hukam Chand Kachwai	
श्री विद्याचरण शुक्ल		Shri V. C. Shukla	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	1368-1369
सभा का कार्य		Business of the House	1369-1370
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव		Motion of No-confidence in the Council of Ministers	1370-1383
श्री च० चु० देसाई		Shri C. C. Desai	
श्री बलराज मधोक		Shri Bal Raj Madhok	
श्री तु० राम		Shri T. Ram	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री		Shri Prakashvir Shastri	
श्री दी० चं० शर्मा		Shri D. C. Sharma	
श्री गणेश घोष		Shri Ganesh Ghosh	
श्री समर गुह		Shri Samar Guha	
श्री ही० ना० मुकर्जी		Shri H. N. Mukerjee	

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi	
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	1384
	चौदहवाँ प्रतिवेदन	Fourteenth Report	
	विधेयकों द्वारा दल परिवर्तन करने के बारे में संकल्प	Resolution Re: Crossing of the Floor by Legislators	1384-1395
	श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	
	श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
	श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	
	श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel	
	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	
	श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	
	श्री शशिभूषण वाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai	
	श्री राजाराम	Shri Rajaram	
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
	श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	
	श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
	नागालैंड में युद्धविराम के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re : Cease Fire in Nagaland	1395-1396
	श्री चेंगलाराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	
	श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 24 नवम्बर, 1967/3 अग्रहायण, 1889 (शक)
Friday, November 24, 1967/ Agrahayana 3, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान फिल्म कम्पनी द्वारा तैयार की गई खराब रा फिल्में

*241. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फिल्म कम्पनी, उटकमण्ड द्वारा निर्मित बहुत सी ब्लैक-एण्ड-ह्वाइट पाजिटिव रा फिल्में खराब पाई गई हैं और सेंट्रल रा फिल्म एडवाइजरी कमेटी ने उनकी सप्लाई रद्द कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो खराब फिल्में कितनी हैं तथा उनका मूल्य क्या है और इसके कारण कम्पनी को कितनी हानि हुई है;

(ग) खराब फिल्में बनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में खराब फिल्में न बनें इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): (क) जी नहीं। उपभोक्ताओं को केवल नगण्य प्रतिशत खराब फिल्मों का पता चला था केन्द्रीय कच्ची फिल्म सलाहकारी समिति को नहीं।

(ख) कुल संभरण में से 8 प्रतिशत अप्रैल से अक्तूबर, 1967 में किया गया था जिसका मूल्य 25,000 रु० था।

(ग) इस प्रकार के जटिल तथा बढ़िया किस्म के उद्योग में ख्याति प्राप्त तथा प्रतिष्ठित कम्पनियों के उत्पादन में इस प्रकार की छोटी-मोटी खराबियाँ हो जाना कोई असाधारण बात नहीं है। यहाँ तक कि आयात की गई सिनेमा की फिल्मों में भी कुछ खराबियाँ पाई गई थीं जिन्हें संभरण कर्त्ताओं द्वारा ठीक कराना पड़ा था।

(घ) किस्म नियंत्रण का सुनिश्चय करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किए जा रहे हैं और जब भी कोई शिकायतें मिलती हैं उनकी पूरी जाँच-पड़ताल की जाती है।

श्री बाबूराव पटेल: मैं हानि की प्रतिशतता जानना चाहता हूँ। यह नहीं बताई गई है।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): यह प्रतिशतता 0.8 है। यदि माननीय सदस्य संख्या जानना चाहते हैं तो यह इस प्रकार है। अप्रैल-अक्तूबर 1967 के दौरान 35 एम० एम० और 16 एम० एम० के 24,622 रोल बाजार में आये थे, इनमें केवल 250 खराब निकले हैं।

श्री बाबूराव पटेल: चूंकि विदेशी फिल्मों में खराबियां पाई गई हैं, इस कारण हमारी फिल्में भी खराब नहीं होनी चाहिये। यह एक सरकारी उपक्रम है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री संसद की एक समिति नियुक्त करेंगे जो इस विषय की जाँच करे और इस घाटे वाले उपक्रम को लाभ वाला उपक्रम बनाया जा सके?

श्री नाथपाई: हम इसका समर्थन करते हैं। श्री पटेल उस समिति के अध्यक्ष होने चाहियें।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: यह उद्योग बड़ा पेचीदा उद्योग है। ये खराबियाँ केवल हमारे उद्योग में ही नहीं हैं, अपितु अन्य देशों के उद्योगों में भी हैं। हमें जिस समय पता चलता है, हम तुरन्त इस ओर ध्यान देते हैं। मेरे विचार में समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रंगा: इस विषय को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को क्यों नहीं सौंप दिया जाता?

श्री दामानी: क्या इन फिल्मों को बनाने में किन्हीं विशिष्ट पुर्जों का प्रयोग होता है, और यदि हाँ, तो इन पुर्जों को देश में ही तैयार करने के लिये क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: हम उत्पादन को बढ़ा रहे हैं और जहाँ तक संभव हुआ आयात में कमी कर दी गई है। श्री रंगा के सुझाव के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति इस पर यथासंभव विचार करेगी।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्: क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ निर्माताओं के आवेदनपत्र अभी भी सरकार के पास पड़े हुए हैं और क्या उनको कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: इसके लिये मुझे पूरी सूचना मिलनी चाहिये।

श्री बूटा सिंह: पिछली बार जब हम इस उपक्रम को देखने गए थे, तो हमें बताया गया था कि विदेशी सहयोगी उचित सामग्री लाने में सहायता नहीं कर रहे हैं। क्या यह कठिनाई समाप्त हो चुकी है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: जी हाँ, किसी समय कुछ कठिनाई थी, क्योंकि फ्रांस में ही सहयोग में कुछ परिवर्तन हो गया था। अब उसने एक अमरीकी फर्म के साथ समझौता किया है। हाल ही में मैं जब पेरिस गया था तो इसपर विचार किया गया था और अब स्थिति में सुधार हो गया है।

बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

*242. श्री राममूर्ति :
श्री नायनार :
श्री प० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री ज्योतिर्मय वसु :
श्री चक्रपाणि :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मैसर्स बैनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड को एक संस्था टाइम्स आफ इण्डिया, बम्बई के कर्मचारियों का, कम्पनी के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन सरकार को मिला है :

(ख) अभ्यावेदन में उल्लिखित मुख्य बातें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जाँच करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) हाँ, श्रीमान

(ख) प्रतिवेदन में दिए गए मुख्य इंगित निम्नलिखित हैं :—

(1) यह आरोपित किया गया है कि कम्पनी के अध्यक्ष ने मजदूरों को कम्पनी की कुल कमाई का 6.06 प्रतिशत, 1965 के बोनस के तौर पर मंजूर करने को राजी कर लिया, तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि वेतन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को अंतरिम सहायता प्रदान की जायेगी, परन्तु बाद में वह अपने अंतरिम सहायता देने के वचन से फिर गया। यह आरोपित किया गया है कि 1966 का बोनस 4 प्रतिशत के रेट से दिया गया है।

(2) कम्पनी का अध्यक्ष श्री तथा श्रीमती एस० पी० जैन से नकद दो लाख रुपए अपने निर्वाचन खर्च के लिये प्राप्त करने के लिये, आरोपित किया गया है।

(3) न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को बीमा व्यापार देने के बजाय, अध्यक्ष ने यूनीवर्सल कापर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ ही व्यापार चालू रखने का निर्णय किया। इसके फलस्वरूप टाइम्स आफ इण्डिया कोआपरेटिव स्टोर्स 30,000 रुपए से ऊपर के कमीशन से वंचित हो गया है।

(ग) उपरोक्त संख्या (1) का आरोप राज्य सरकार से संबंध रखता है, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने स्वयं प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ भेज दी हैं। ऊपर की संख्या (2) का आरोप की जाँच की जा चुकी है। उपरोक्त संख्या (3) के आरोप के विषय में, मामले की जाँच से पता चलता है कि दी औरयंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने टाइम्स आफ इण्डिया बिल्डिंग, नई दिल्ली के बीमा के लिये दो बार कमीशन, अर्थात् 12-1-1965 से 12-1-1966 तथा 12-1-1966 से 12-1-1967 तक टाइम्स आफ इण्डिया एम्प्लाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड को दे दिया। जहाँ तक चालू अवधि का संबंध है, अर्थात् 12-1-1967 से 12-1-1968 तक उक्त सोसाइटी को कोई कमीशन नहीं दिया गया है। यद्यपि लाइसेंस, जिसके अनुसार दी टाइम्स आफ इण्डिया एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, बीमा एजेंट का कार्य करने के लिये प्राधिकृत है, 12 जनवरी 1968 तक विधि मान्य है। कम्पनी के अध्यक्ष ने

दृष्टिकोण अपनाया है कि एक सोसाइटी एजेन्ट नियुक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि वह अपने उप-नियम के अनुसार एजेन्ट का कार्य करने का अधिकार नहीं रखती।

श्री राममूर्ति : भारत सरकार के समवाय विधि प्रशासन द्वारा क्या जाँच की गई थी कि 6 प्रतिशत बोनस दिए जाने की माँग मान ली गई थी, परन्तु वास्तव में कोई भुगतान नहीं किया गया? बीमा कार्य के लिये सहकारी समितियों को एजेंट नियुक्त करने के बारे में समवाय विधि में चाहे कोई उपबंध न हो, परन्तु क्या वह बीमा कम्पनी के एजेंट के लिये सहकारी समिति को काम करने से रोकने का कोई उपबंध है, जिससे उसे कमीशन मिल सकता हो?

श्री रघुनाथ रेड्डी: जैसा कि मैंने कहा है इस विषय में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई है और वह इस विषय में विचार कर रही है। समवाय निधि का ऐसे विषयों से कोई सम्बन्ध नहीं है। सहकारी समिति को तो सहकार समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया होगा और रिकार्ड से पता चलता है कि इसे बीमा कम्पनी का एजेन्ट नियुक्त किया गया था और 1965–66 तथा 1966–67 के लिये इसे कमीशन का भुगतान किया गया था। निदेशकों के बोर्ड की बाद में जब बैठक हुई तो उसने बीमा प्रीमियम को विभिन्न वर्गों में बाँट दिया गया। 20 प्रतिशत यूनिवर्सल को दिया गया और शेष 80 प्रतिशत तीन कम्पनियों के लिये था, जिनमें यूनिवर्सल फायर कम्पनी भी थी। परन्तु बाद की एक तारीख को यह विषय जब अध्यक्ष के समक्ष गया तो उन्होंने अपने आदेशों में परिवर्तन कर दिया और आदेश दिया कि सहकारी समिति को कमीशन न दिया जाये। उन्होंने इस धारणा पर आदेश दिए होंगे कि समिति के उपनियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के काम के लिये कमीशन नहीं दिया जा सकता।

श्री नायनार: क्या यह सच है कि कम्पनी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति से उस कम्पनी की हालत और खराब हो गई है और यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है? अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वयं बताया है कि कम्पनी के अध्यक्ष को श्री और श्रीमती जैन से 2 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि मामले के इस पहलू के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री रघुनाथ रेड्डी: प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ न्यायाधिकरण के आदेशानुसार डा० कूपर इस कम्पनी के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और उनके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद उनके स्थान पर वर्तमान अध्यक्ष श्री कुन्ते की नियुक्ति की गई थी। इस मामले की जाँच पड़ताल करना समवाय विधि बोर्ड का काम नहीं है। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न भी उनके पहले प्रश्न का ही भाग है। मैं माननीय सदस्य से सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि समवाय विधि के विभिन्न खण्डों के अधीन बहुत से मामलों पर उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है और वे न्यायालय के विचाराधीन हैं। इसलिये सरकार के लिये यह उचित नहीं है एक अध्यक्ष के चरित्र अथवा उसकी गतिविधियों की जाँच-पड़ताल करे क्योंकि अभी बहुत से मामले उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं।

श्री पं० गोपालन : कम्पनी के वर्तमान हालात के कारण और विशेषतया नये अध्यक्ष की नियुक्ति के कारण "टाइम्स ऑफ इण्डिया" के भूतपूर्व सम्पादक श्री मैनपुरिया तथा कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारी श्री हरिहरण ने कम्पनी को छोड़ दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को कम्पनी के अध्यक्ष के अतिरिक्त, कम्पनी के लिये नियुक्त किये गये निदेशकों से भी इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है?

श्री रघुनाथ रेड्डी: जहाँ तक उन परिस्थितियों का सम्बन्ध है, जिनके अन्तर्गत माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित व्यक्तियों ने कम्पनी को छोड़ा अथवा उनकी नियुक्ति की गई, उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिये सरकार को पूर्व सूचना चाहिये। जहाँ तक इस प्रश्न के दूसरे पहलू का सम्बन्ध है, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में समवाय विधि के खण्ड 388 (3) के अन्तर्गत बहुत से मामले उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं और सरकार के लिये इस मामले के बारे में कुछ भी कहना उपयुक्त नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: बीमे के कमीशन के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि अधिकार में लिये जाने से पहले यह कारोबार कौन कर रहा था तथा इस कारोबार को अब कौन कर रहा है तथा इस समय यह कमीशन किसको मिल रहा है। और क्या यह व्यक्ति अध्यक्ष का सम्बन्धी है? कर्मचारियों को कितना बोनस देने का बचन दिया गया था और उन्हें वस्तुतः कितना बोनस दिया गया?

श्री रघुनाथ रेड्डी: वास्तविक कमीशन लगभग 30,000 रुपये जो कि सहकारी समिति को मिल रहा था, वर्ष 1965–66 और 1966–67 में "दि यूनिवर्सल फाइर एण्ड जनरल इनशोरेंस कम्पनी" इस कारोबार को कर रही थी तथा सहकारी समिति को आढ़त प्राप्त हो रही थी। इस समय जब कि यह प्रश्न पूछा गया है, मेरे लिये यह बताना कठिन है कि वह व्यक्ति अध्यक्ष का सम्बन्धी है अथवा नहीं। यदि माननीय सदस्य इस बात को जानना ही चाहते हैं, तो हम इसकी पूछताछ करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु: इस कारोबार को इस समय कौन कर रहा है और क्या वह व्यक्ति अध्यक्ष का सम्बन्धी है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया गया? मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर देना आप के लिये बहुत असुविधा जनक है. क्योंकि इससे सभा में उत्तेजना फैल जायेगी।

श्री रघुनाथ रेड्डी: जहाँ तक बीमा प्रीमीयम की अदायगी का प्रश्न है इसका आदेश निदेशकों की सलाह से अध्यक्ष द्वारा दिया गया था। मैं पहले बता चुका हूँ कि निदेशकों के बोर्ड ने एक संकल्प पारित करके सहकारी समिति को आढ़त प्राप्त करने का अधिकार दिया था तथा इसके विरुद्ध अध्यक्ष ने यह अधिकार स्वयं प्राप्त कर लिया और इस आशय का आदेश जारी कर दिया तथा इसे कानूनी बनाने के लिये दूसरे निदेशकों की सहमति प्राप्त कर ली।

श्री ज्योतिर्मय बसु: बीमा व्यापार की आढ़त इस समय किस को मिल रही है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: महोदय, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस समय बीमा आढ़त का लाभ किसे मिल रहा है और क्या वह व्यक्ति अध्यक्ष का सम्बन्धी है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): इस बात का पता लगाने के लिये कि बीमा आढ़त का लाभ किसे मिल रहा है, हमें पूर्वसूचना चाहिये, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। हम इस बात का पता लगायेंगे कि अध्यक्ष से उस का क्या रिश्ता है।

श्री चक्रपाणि: मैं यह जानना चाहता हूँ कि अध्यक्ष के अतिरिक्त सरकार द्वारा किस-किस व्यक्ति को कम्पनी का निदेशक चुना गया? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशकों ने कम्पनी के कारोबार का कोई मूल्यांकन किया है तथा क्या सरकार किन्हीं निष्कर्षों पर पहुँची है और यदि हाँ, तो सरकार ने क्या-क्या निष्कर्ष निकाले हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकारी निदेशक हैं—डा० हजारे और प्रो० एस० के० भट्टाचार्य। वे बहुत ही ऊँचे दर्जे के और स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है।

श्री अ० वि० पाटिल : क्या मंत्री महोदय ने इस मामले के बारे में कम्पनी के अध्यक्ष से, जो कि इस सभा के एक सदस्य हैं, विचार विमर्श किया है ?

अध्यक्ष महोदय : और वह माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यद्यपि यह सुझाव बहुत अच्छा है, तथापि मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले पर विभिन्न मुकदमे चल रहे हैं, इसलिये अध्यक्ष से इस मामले पर विचार-विमर्श करना उचित नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते उन मुकदमों का क्या नतीजा होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : जो प्रश्न पूछे गये हैं तथा जो उत्तर दिये गये हैं, उनसे कोई अर्थ सिद्ध नहीं हुआ है। जहाँ तक प्रबन्ध अथवा सहकारी समिति अथवा उच्च न्यायालय की कार्यवाही का सम्बन्ध है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले से सरकार का क्या सम्बन्ध है और सरकार "टाइम्स ऑफ इण्डिया" के कर्मचारियों की शिकायतें कैसे दूर करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस मामले से सकार का सम्बन्ध यह है कि हमसे कुछ जानकारी पूछी गई थी और हमने वह जानकारी दे दी है।

श्री स० कुण्डू : हम सब जानते हैं कि इस कम्पनी का बहुत से समाचारपत्रों पर नियंत्रण है। इस सभा में तथा अन्यतर ये घोषणायें की गई हैं कि छोटे समाचारपत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। क्या यह सच है कि अहमदाबाद से यह कम्पनी "टाइम्स ऑफ इण्डिया" समाचारपत्र का तीसरा संस्करण निकालने वाली है तथा अखबारी कागज के लिये अतिरिक्त कोटे का आवेदन किये बिना बम्बई संस्करण से अखबारी कागज प्राप्त कर के यह संस्करण आरम्भ किया जायेगा ? अहमदाबाद में "वैस्टर्न टाइम्स ऑफ इण्डिया" नामक एक समाचारपत्र हाल में आरम्भ किया गया है तथा यह कम्पनी श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा आरम्भ किये गये इस समाचारपत्र को समाप्त करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यद्यपि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता, तथापि मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि इस मामले पर सरकार का ध्यान दिलाया गया है तथा कम्पनी विधि प्रशासन इस मामले की पेचीदगियों का अध्ययन कर रहा है।

श्री दत्तात्रय कुंटे : महोदय मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मैं इस कम्पनी का अध्यक्ष हूँ तथा मुझे समवाय विधि न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, माननीय मंत्री ने बताया है कि उन्हें एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कम्पनी के अध्यक्ष ने अपने चुनाव के लिये जैन बन्धुओं से 2 लाख रुपये प्राप्त किये थे। मैंने अपना चुनाव लड़ा है तथा उसका ब्यौरा भी दिया है जिस से यह ज्ञात होगा कि मैंने अपने चुनाव पर कितना धन खर्च किया है। दूसरे जहाँ तक जैन बन्धुओं से रुपये लेने का प्रश्न है, मैंने उनसे कोई धन नहीं लिया है, क्योंकि मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि आढ़त सहकारी समिति को नहीं मिलती तथा आढ़त किसी ऐसे व्यक्ति को मिल रही है जो मेरा सम्बन्धी अथवा परिचित है, मैं कहना चाहता हूँ कि यह कारोबार सीधे बीमा कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इसलिये इस मामले से कोई आढ़ती सम्बन्धित नहीं है। मुझे इस बात का भी पता नहीं है कि कम्पनी के प्रबन्धक अथवा निदेशक कौन हैं। उप-

विधियों के सम्बन्ध में मुझे एक बात कही गई थी कि उप-विधियों के अन्तर्गत उस सहकारी समिति को यह कारोबार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैंने सहकारी समिति को कहा था कि वह इस बात की जाँच करे। उन्होंने मुझे यह लिखकर सूचित किया है कि उनकी ऐसी उप-विधियाँ नहीं हैं। मैंने उनको सूचित किया था कि वे उस उपविधि को पास करवा लें, तथा तब तक कानून के लिहाज से मैं उन्हें यह कारोबार नहीं दे सकता। फिर जहाँ तक श्री नामपूरिया का सम्बन्ध है, वह स्वेच्छा से काम छोड़ कर गये हैं। चूंकि उन्हें मलेशिया में एक अधिक अच्छा रोजगार प्राप्त हो गया था, इसलिये वह मेरे पास आये थे और अनुरोध किया था कि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र जाने की अनुमति दी जाये। जहाँ तक उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामलों का सम्बन्ध है, इस कम्पनी के अध्यक्ष के विरुद्ध अथवा कम्पनी के अध्यक्ष की हैसियत से श्री कुंटे के विरुद्ध कोई मामला नहीं है।

हंगरी से टायरों के आयात के सम्बन्ध में केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा जाँच

244. **श्री न० कु० सांघी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने हंगरी से टायरों के आयात के लिये मेसर्स रामकृष्ण कुलवन्त राय को एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में जाँच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) जाँच से यह प्रकट हुआ कि हंगरी टायरों के आयात तथा उनके वितरण के लिये एजेंटों के चुनाव के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम ने उचित ध्यान और सावधानी से काम नहीं लिया।

श्री न० कु० सांघी: खराब टायरों के मामले का अब पूरा पता लग गया है। क्या वाणिज्य मंत्री को इस बात का पता है कि टायरों और ट्यूबों की बड़े पैमाने पर चोर बाजारी हो रही है ? क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टायरों और ट्यूबों की देश में कमी है उनके वितरण के लिये उचित कानून क्या नहीं बनाया है ?

श्री दिनेश सिंह: यह कहना बहुत कठिन है कि टायरों और ट्यूबों के वितरण के सम्बन्ध में कानून क्यों नहीं बनाया गया। वितरण के सम्बन्ध में काफी कानून बने हुए हैं। अतः मैं समझता हूँ कि इसके लिये नया कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूँ कि लोक लेखासमिति ने इस सारे प्रश्न पर विचार कर लिया है और उसकी रिपोर्ट आ गई है। सरकार की ओर से उत्तर दिये जा चुके हैं तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के सम्बन्ध में कुछ जाँच-पड़ताल की जा रही है। आपने भी इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति देकर कृपा की है। अतः तब सारे आँकड़े प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

श्री न० कु० सांघी: जब जांच पड़ताल की जा रही है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार विदेशी निर्माताओं से भी यह पूछे गयी कि क्या टायरों और ट्यूबों के सम्बन्ध में उनके साथ कोई गुप्त करार तो नहीं हुआ है जैसा कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी के सम्बन्ध में किया गया है। क्या विदेशी संभरणकर्ताओं से यह पूछा जायेगा कि भारतीय आयातकर्ताओं और विदेशी संभरण कर्ताओं के बीच करार में कोई चीज गलत थी।

श्री दिनेश सिंह: मुझे इस बात में बहुत संदेह लगता है कि कोई विदेशी सम्भरण कर्ता यह स्वीकार करेगा कि उसके साथ यह यह गुप्त करार हुआ है चाहे उसने ऐसा किया ही हो। जाँच पड़ताल की जा रही है और हम निस्संदेह इस बारे में भी उनसे बातचीत जारी रखेंगे।

Shri Madhu Limaye: May I know whether Messers Ram Kishan Kulwant Rai Firm is a concern of Messrs. Amin Chand Pyare Lal against whom many charges have been levelled and proved. One of the charges was a charge of tax evasion. Last time when a question was raised in this regard the Finance Minister had given an assurance to this House that he will bring forth a Bill under which the property of tax evaders and other such defaulters will be confiscated . Hence if it is a concern of Messers Amin Chand Pyare Lal Group then may I know the reasons on account of which the Bill is not being brought forth at an early date ? May I know whether there is any truth on this charge that Messrs Amin Chand Pyare Lal influenences the Government by pleasing the Minister and kins of Ministers and helping them. I want the Minister to ponder over the matter and then answer it, I never speak without any basis.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : I know well that the Hon. Member does not speak without any basis but according to us his bases are not the bases. After all we have to see the basis. If there is any complaint against any Minister then I am prepared to go into that but we have not received any complaint. As regards the Bill I had made a mention myself, nobody had given me any suggestion. But one has to face many legal difficulties to bring forth the Bill. The Bill should fulfil the legal obligations. Hence it takes time and it will take time.

Shri Madhu Limaye : The first part of my question should be answered by the Minister of Commerce. I had asked whether Messrs Ram Krishan Kulwant Rai's firm is a concern of Messrs Amin Chand Pyare Lal Group and what concrete action is going to be taken by Government in that connection. It has been said that an investigation is being made. May I know when Government propose to take any action against these companies?

Shri Dinesh Singh : The question of taking concrete action against them will arise when the investigation is completed. I fail to understand what the Hon. Minister wants. Does he want that action be taken before the investigation is completed? The extent to which this firm is related to Messrs Amin Chand Piyare Lal that Company Law Department can only tell. But we hear like that.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के बारे में मैंने अनुमति दे दी है और हम इस सभा में चर्चा करने जा रहे हैं । इसलिए अन्य प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री स० कुण्डू : परन्तु चर्चा के लिये काफी समय दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसमें कुछ नहीं कर सकते । प्रत्येक चर्चा के लिए तीन दिन का समय नहीं दिया जा सकता । मैं हर समय सभा में चर्चा की अनुमति देता हूँ ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the quantity of goods, Messrs Ram Krishan Kulwant Rai takes from Hungary every year and the amount of goods supplied legally and amount of goods supplied illegally i. e. in black market by them. May I khow the needs of tyres in the country and the steps taken by Government to fulfil the same ?

Shri Dinesh Singh : It is not possible for me to tell at this time the amount of goods being imported by this firm from Hungary, because this is questions concerning tyres only. This is a question of 1959-60 when this firm had imported tyres from Hungry. As far as I remember it has been mentioned in the report of P. A. C. that that company was allowed to import 40,000 tyres while they imported 39,850 tyres.

Shri Hukam Chand Kachwai : The second part of my question has not been answered. I wanted to know the extent to which goods are sold by them legally and the extent to which they are sold illegally ?

Mr. Speaker : Next question.

हिन्दुस्तान मोटर्स कम्पनी के शेयर

*245. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** **श्री राम सिंह अयरवाल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स कम्पनी के जाली शेयरों के परिचालन के बारे में जाँच पूरी हो गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस किस्म की शिकायतों की जाँच करने में आम तौर पर काफी समय लग जाता है।

श्री काशीनाथ पान्डेय : यह बात कहाँ तक सच है कि इस कम्पनी द्वारा यह शिकायत किये जाने पर कि नकली शेयर चल रहे हैं, मंत्रालय ने इस जाँच की पहल स्वतः की थी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कम्पनी द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने पर जाँच स्वतः शुरू हो गई। पहली एफ० आई० आर० (पहली जानकारी रिपोर्ट) 137 दिनांक 25–2–66 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 465, 468 तथा 471 के अन्तर्गत दिल्ली में दर्ज की गई उसके बाद 24–11–65 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 465 तथा 471 के अन्तर्गत एफ० आई० आर० 1318/1319 कानपुर में दर्ज की गई, और कलकत्ता में दिनांक 21–8–65 को हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफ० आई० आर० 371 दर्ज की गई लेकिन बाद में दिल्ली को स्थानान्तरित की गई एफ० आई० आर० 312 दिनांक 24–6–66 पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। ये एफ० आई० आर० अपने-अपने पुलिस स्टेशनों में दर्ज किये गये हैं, दूसरी शिकायत 29–7–67 को केन्द्रीय गुप्तचर विभाग में दर्ज की गई है और केन्द्रीय गुप्तचर विभाग उन अन्य पुलिस स्टेशनों के सहयोग से, जो इन एफ० आई० आर० के बारे में जांच कर रहे हैं, जाँच कर रहा है। जाँच चल रही है। मैं माननीय सदस्यों से केवल एक अनुरोध करूँगा कि चूंकि जाँच चल रही है और इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है इसलिये वे इस मामले में अग्रेतर जानकारी प्राप्त करने के लिये दबाव न डालें ताकि मामले की जाँच ठीक तौर पर हो सके।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या यह सच है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग भी इस मामले की जाँच कर रहा है और यदि हाँ, तो मंत्रालय द्वारा की जा रही जाँच तथा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जाँच में कहाँ तक ताल-मेल चल रहा है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कि 29–7–67 को केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के पास शिकायत दर्ज की गई थी और तब से लेकर केन्द्रीय गुप्तचर विभाग उन अन्य पुलिस स्टेशनों के सहयोग से, जहाँ एफ० आई० आर० पहले दर्ज की गई थी, मामलों की जाँच कर रहा है, एक लाख रुपये के नकली शेयर बरामद हो चुके हैं और यह कैसे हुआ, और किन-किन व्यक्तियों का इसमें हाथ है आदि बातों के बारे में जाँच चल रही है। इसलिये इस बारे में इस समय और कुछ बताना जाँच के लिये ठीक नहीं है।

Shri Ram Singh Ayarwal : May I know why this investigation has not been completed so far when the F.I.R. was filed in 1965 and what are the factors responsible for this inordinate delay in the matter and what steps have been taken to put an end to the monoply of the Hindustan Motors in the matter of distribution of shares. Whether the company had received an offer from some French factory in regard to the manufacture of small car, and that offer was ignored ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जब एफ० आई० आर० पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है, तो उस मामले की जाँच करने के लिये सम्बन्धित पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकार प्राप्त करेगा, जैसा कि मैंने बताया है, इस मामले से तीन पुलिस स्टेशनों का सम्बन्ध है और ये जाँचें राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं। केवल 29–7–67 को, जब यह शिकायत (एफ० आई० आर०) केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के समक्ष दर्ज की गई, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर कार्यवाही की और केन्द्रीय गुप्तचर विभाग इस मामले की जाँच के सिलसिले में अन्य पुलिस अधिकारियों से सहयोग कर रहा है और छान-बीन चल रही है जैसा कि इस बारे में मैं पहले बता चुका हूँ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्या इस जाल-साजी का पता लगते ही कम्पनी ने अंश-धारियों तथा जनता को इस बारे में तुरन्त अवगत कराके स्वतः आवश्यक कार्यवाही कर दी थी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस कम्पनी ने एक शिकायत के रूप में यह पहली जानकारी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में स्वतः दर्ज की थी। मैं ऐसा समझता हूँ कि अंशधारियों को यह बात शायद मालूम हो गई थी, यदि इस बारे में माननीय सदस्या जानकारी चाहती हैं, तो मुझे पूछना पड़ेगा और मालूम करना पड़ेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें हिन्दुस्तान मोटर्स के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, और यदि हाँ, तो कितने ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ, अर्थात् इसके लिये आप मुझे बाध्य न करें।

Shri Bibhuti Mishra : As the company itself filed the First Information Report, I want to know whether the company is cooperating with the Government with a view to bringing the culprits to books ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : पुलिस मामले की जाँच किस तरह कर रही है, इसका इल्म हमें नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह कम्पनी सरकार के साथ सहयोग कर रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : केन्द्रीय गुप्तचर विभाग इस मामले की जाँच कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये आप को पता नहीं है, चं० चूं० देसाई।

श्री चं० चूं० देसाई : पहली रिपोर्ट खुद कम्पनी ने दर्ज कराई, वह केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से सहयोग कर रही है और उसने अंश-धारियों तथा स्टॉक एक्सचेंज को भी एक नोट परिचालित किया है। इससे ज्यादा कोई होशियार कम्पनी और कर भी क्या सकती थी, और सरकार की राय से उसे जो करना चाहिये था वह उसने नहीं किया, और इसलिये वह दोषी है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह तो अपनी-अपनी राय की बात है। यह तय करना पुलिस का काम है।

श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा : क्या किसी कम्पनी के शेयरों की जाल-साजी का यह पहला मामला है अथवा अन्य कम्पनियों के शेयरों की जाल-साजी के मामले भी सामने आये हैं ?

अध्यक्ष महोदय: कम्पनियों की समूची सूची देना उनके लिये कैसे संभव होगा ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : एक और कम्पनी के बारे में हम जाँच कर रहे हैं ।

श्री स० कुण्डू : मैं मंत्री जी से केवल एक चीज पूछता हूँ । यह एक ऐसा मामला है जिसे कम्पनी ने दर्ज कराया है और पुलिस 1965 से इस मामले की जाँच कर रही है। दो वर्ष बीत चुके हैं । अभी जाँच पूरी होनी बाकी है उसके बाद मुकदमा दायर होगा और फिर यह मामला, यथा स्थिति, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष आयेगा । तब तक कांग्रेस सरकार भी चली जायेगी । देर से अन्धेर हो जाता है और कभी-कभी देर करके की जाती है और न्याय नहीं हो पाता । इसलिये मैं एक विशेष आश्वासन चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय पुलिस अधिकारियों को एक महीने में जाँच खत्म करने तथा मुकदमा दायर करने का निदेश देंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : 29–7–1967 को इस मामले को केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को सौंपने की केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही से स्वतः यह संकेत मिला है कि सरकार इस मामले की जाँच यथा शीघ्र पूरी करवाने के लिये चिन्तित है।

श्री शशी रंजन : क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को केवल जालसाजी का यही विशेष मामला सौंपा गया है अथवा इस कम्पनी की स्थापना के पश्चात् जो-जो बातें हुई हैं, वे सभी सौंपी गई हैं— जैसे कोई न कोई युक्ति निकालकर कम्पनी के शेयर गिरा देना और फिर उनमें वृद्धि कर देना और तब उन्हें बाजार में ले आना आदि । इसलिये मंत्री महोदय यह बतायें कि इस जाँच की विषय-वस्तु क्या है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जब कोई पहली जानकारी रिपोर्ट एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है, तो कोई पुलिस अधिकारी केवल उसी शिकायत के बारे में तहकीकात कर सकता है और न कि किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में ।

श्री शशी रंजन : यह उचित नहीं है । कम्पनी की स्थापना से ही जाँच की जानी चाहिये ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है इसलिये मंत्री महोदय को उनके बारे में निश्चत रूप से बताना चाहिए। यह भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि इसके लिये कम्पनी जिम्मेदार है अथवा जनता के कुछ लोग जिम्मेदार हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस प्रकार के षडयंत्र देश में बड़े पैमाने पर फैले होते हैं अतः कुछ व्यक्ति को इसके लिये जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है । इस अवस्था में लोगों के नाम आदि भी बताना उचित नहीं है क्योंकि इससे वास्तविक दोषियों के छूट जाने की सम्भावना है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : जाच के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

श्री क० नारायण राव : दोषी व्यक्तियों का पता लगाना एक अलग बात है और बोगस शेयरों का पता लगाना एक पृथक बात है । मैं जानना चाहता हूँ कि बोगस शेयरों का पता लगाने तथा उनको बन्द करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : समवाय विधि प्रशासन मामले के इस पहलू की जाँच कर रहा है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : इस बात को देखते हुए कि बड़े पैमाने पर बोगस शेयर जारी किये जा रहे अंशधारियों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है इससे पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है और कम्पनी को कहा गया है कि शेयरों के हस्तांतरण से पूर्व दो अन्य निर्देशकों को शेयरों की वास्तविकता की पुष्टि करनी चाहिए।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का यत्न किया है कि समवाय विधि में किस त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार मामले के इस पहलू पर विचार कर रही है। हमें इस बात का भी पता है कि कम्पनी लॉ जटिल है फिर भी इन मामलों के बारे में इसमें कुछ त्रुटि दिखाई देती है और इस पहलू की जाँच की जा रही है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : स्वतंत्रता के पश्चात् देश में धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है। जैसा कि रिजर्व बैंक के नोटों के मामले में धोखा हुआ है उस प्रकार ही मामला शेयरों का है जो कुछ भी कम्पनी की ओर से सरकार को सहायता अथवा केन्द्रीय जाँच ब्यूरों को सहायता अथवा दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिये किया जाना था वह किया गया है और इस समय जो भी विलम्ब हो रहा है वह पुलिस की ओर सेही हो रहा है। विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह अपनी-अपनी राय है।

श्री हिम्मत सिंहका : क्या कम्पनी ने प्रमुख समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिया है जिसमें लोगों को नकली शेयरों के बारे में सावधान रहने की चेतावनी दी गई हो ? क्या कम्पनी ने शेयर होल्डरों को भी कुछ शेयरों के नकली होने के बारे में लिखा है ? क्या कम्पनी ने लोगों को नकली शेयरों के बारे में चेतावनी देने के लिये सट्टा बाजारों को भी नोटिस दिया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्रश्न के भाग प्रथम का उत्तर 'हाँ' में हैं। दूसरे भाग के बारे में हमें जानकारी नहीं है।

Shri Kameshwar Singh : The Hon. Minister has stated that the enquiry is being held in regard to the bogus shares. It is a separate thing that delays being caused. I would like to know whether this aspect of the matter these bogus shares were brought to the market by the company itself is also being enquired into? Whether any enquiry is also being held against the management of the company?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा मैं उसको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मामले की जाँच हो रही है। जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा उसके लिये किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व हमें बहुत से साक्ष्य प्राप्त करने होंगे और साक्ष्य के बिना हम इस मामले के बारे में कुछ नहीं कह सकते।

Shri M. A. Khan : Whether it is a fact that the company has declared to give some money for capturing the culprits. If it is so, the amount thereof ?

Shri Bhogendra Jha : Keeping in view that the people are aware of the fact that the manager of the company is a leading conspiratro I would like to know whether the enquiry is being held against all the shares-holders or only against those share-holders whose names have been supplied by the company?

Secondly, keeping in view that the Company has established its monopoly and the country is convinced that under the pressure government is not starting new industries, I would like to know whether government are considering to take over this company as it has been exposed ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): My colleague has already answered the first part of the question. Police is investigating into all these matters and the police and the company law coordinating with each other. So far as the second part of the question is concerned the time is not ripe to take over the company.

श्री शिवनारायण: यदि समवायविधि इतनी दोषयुक्त है तो सरकार उसमें संशोधन क्यों नहीं करती ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अपराध तो भारतीय दन्ड विधि के अन्तर्गत आते हैं न कि समवाय विधि के अन्तर्गत, हो सकता है समवाय विधि में दोष हों । हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

चाय का निर्यात

*248. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** **श्री प्र० के० देव :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री न० कु० साँधी :**
श्री वेदव्रत बरूआ : **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में चाय के संयुक्त निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में श्री लंका के प्रतिनिधियों के साथ कोई वार्ता हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) नई दिल्ली में 11 और 13 सितम्बर, 1967 के बीच श्रीलंका और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच निर्यात किये जाने वाले चाय के यूनिटों के शनैः शनैः गिरते मूल्यों को रोकने तथा मूल्यों को बढ़ाने के प्रश्न पर विशेषकर और श्रीलंका और भारत में चाय उद्योग की समस्याओं पर वार्ता हुई थी। इन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये संयुक्त रूप से उपाय ढूंढ़ने के लिये निकट भविष्य में बातचीत का एक अन्य दौर कोलम्बो में होगा ।

श्रीमती ज्योत्स्तना चन्दा : हम लोगों को अथवा सरकार को इन उपायों का कब पता लगेगा ताकि कोई कार्यवाही की जा सके ।

श्री दिनेश सिंह: जैसे ही इन पर वार्ता हो जायगी और उनको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि चाय के निर्यात में कमी इस कारण हुई है क्योंकि निर्यात की जाने वाली चाय की किस्म अच्छी नहीं थी ?

श्री दिनेश सिंह : निर्यात में कमी के कई कारण हैं । इसका कोई विशेष कारण नहीं है ।

श्री म० ला० सोधों : संयुक्त उपायों की बात करना बहुत अच्छा है परन्तु अन्य वस्तुओं की तरह भारतीय चाय का भी अलग रूप बनाये रखना आवश्यक है । चाय के अलग रूप को बनाये रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । क्या लन्दन तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में चाय के मिश्रण कारखाने स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है जिससे भारतीय चाय का पृथक रूप भी बना रहे और विदेशी मुद्रा की बचत भी हो ?

श्री दिनेश सिंह : चाहे चाय हो अथवा कोई अन्य वस्तु, हम पृथक रूप बनाये रखने के लिये उत्सुक हैं। हमारे पास दार्जिलिंग चाय, नीलगिरि चाय तथा आसाम चाय की किस्में हैं। चाय की इन उच्च किस्मों में कोई स्पर्धा नहीं है। मध्यम श्रेणी की चाय को ही हानि हो रही है। विश्व में इसकी स्थिति को बहाल करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : मिश्रण कारखाने स्थापित करने के बारे में आप क्या कहते हैं ? यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने कारखाने स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि इस समय मिश्रण अन्य लोगों द्वारा किया जाता है और हमारे अपने कारखाने नहीं हैं। पेरिस, लन्दन और अन्य स्थानों में हम मिश्रण का काम नहीं करते।

श्री दिनेश सिंह : मैं इस बारे में बातचीत करता रहा हूँ। यदि माननीय सदस्य इसे करने के लिये कुछ व्यक्ति ढूंढ़ने में मेरे साथ सहयोग करें, तो मैं उनका अत्यन्त आभारी होऊँगा।

श्री वेदव्रत बरूआ : क्या मैं मंत्री महोदय से चाय के उत्पादन की स्थिति के बारे में पूछ सकता हूँ। श्रीलंका ने अपने बागान का क्षेत्र अत्यधिक बढ़ा लिया और विश्व के निर्यात व्यापार में भारत को प्रथम स्थान से हटा दिया है। इसलिये क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने श्री लंका सरकार से अपने चाय बागान क्षेत्र को सीमित करने के बारे में बातचीत की है जिसमें विश्व में चाय का उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक न हो जाये ?

श्री दिनेश सिंह : हमने भी अपने बागान का क्षेत्र बढ़ाया है।

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि वे श्रीलंका के परामर्श से एक सामान्य नीति बनाये जाने की आशा करते हैं। शायद उन्हें मालूम है कि श्रीलंका ने पहले ही अपने रुपये के अवमूल्यन की घोषणा करदी है। इस प्रकार प्रतियोगी बाजार में हमें जो लाभ था, वह समाप्त हो गया है। प्रतिस्पर्धा केवल श्रीलंका से ही नहीं है, जिसकी विक्रय प्रणाली हमारे से अच्छी है। वे बाजार में अपने माल की माँग पैदा कराने में सक्रिय हैं न कि दूसरों को हानि पहुंचाने में, दोनों में अन्दर है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्व अफ्रीका के देशों से भी चाय आ रही है। श्रीलंका के रुपए के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए सरकार श्रीलंका के परामर्श से क्या कदम उठा रही है कि भारत और श्री लंका के बीच इस सम्बन्ध में जो अन्तर है वह बना रहे, यदि भारत की स्थिति में सुधार नहीं होता, तो कम से कम उसकी वर्तमान चाय मंडी बनी रहेगी।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि कुछ समय पहले हमने भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था। इस स्थिति में हमें प्रतीक्षा करनी है और श्रीलंका के अवमूल्यन के प्रभाव को देखना होगा, क्या उसके निर्यात शुल्क में समंजन होगा और इसका विदेशी मंडी पर क्या प्रभाव होगा। उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीलंका ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है। क्या सरकार यह अनुमान लगाने की स्थिति में है कि इस अवमूल्यन से भारतीय चाय के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री दिनेश सिंह : मैं पूर्व प्रश्न के सम्बन्ध में इसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री बलराज मधोक : क्या बंगाल में कुछ चाय कम्पनियों ने सारे साल चाय की पत्तियाँ चुनने का प्रयास किया है, जो पहले केवल आठ महीने होता था, जिससे उन बागानों में चाय का उत्पादन 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गया है ? क्या अन्य स्थानों में भी ऐसा किया जायेगा जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाये और हम अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता कर सकें ?

श्री दिनेश सिंह : जी हाँ। हमें प्रसन्नता है कि हम ऐसे स्थानों का विकास कर सके हैं जहाँ सारे वर्ष पत्तियाँ चुनना संभव है ताकि श्रमिकों से अधिक लाभदेय ढंग से काम लेना संभव होगा, जिससे हमारे विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन उत्पादन बढ़ाने से स्वतः लाभ नहीं होता क्योंकि विदेशों में बेचने की क्षमता की भी सीमा है। पिछले चन्द वर्षों में हमारा उत्पादन निरन्तर बढ़ता रहा है लेकिन हमारा निर्यात उस गति से नहीं बढ़ता रहा है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : हाल में श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने सुझाव दिया था कि चाय के निर्यात के सम्बन्ध में भारत और श्रीलंका के बीच गला काट प्रतियोगिता से बचने का दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालें। इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने यही कहा है। एक बैठक हुई थी और दूसरी बैठक शीघ्र होने की आशा है।

श्री हेम बरुआ : श्रीलंका के रुपये के अवमूल्यन के बारे में श्री नाथपाई के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि हमने भी अपने रुपये की अवमूल्यन किया है। इसके बावजूद भी चाय के सम्बन्ध में श्रीलंका की तुलना में अभी तक हमारी स्थिति सुधरी नहीं है। क्या श्रीलंका के साथ एक समान निर्यात नीति बनाते समय सरकार समस्या के इस पहलू पर भी विचार करेगी? आसाम में कुछ बागानों को अलाभकर घोषित करके बन्द कर दिया गया है। इन चाय बागानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये सुधार करने के हेतु तथा साथ ही इस मामले में श्रीलंका से आगे निकलने के हेतु निर्यात बढ़ाने के लिये, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : पहले मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि निर्यात के बारे में निर्णय करने में अवमूल्यन ही अन्तिम बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि निर्यात शुल्क तथा उपकर तथा अन्य बातें भी इस अन्तर को कम करती हैं। इसलिये, हमें क्या करना है, अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह इसके सम्पूर्ण प्रभाव का अध्ययन करने का प्रश्न है। संभवतः आज कोई प्रभाव नहीं पड़े लेकिन हमें सम्पूर्ण प्रभाव देखना है। जहाँ तक हमारे प्रयासों का सम्बन्ध है, हमें यह देखना है कि उचित यूनिट मूल्य बना रहे, अर्थात् यदि यूनिट मूल्य कम हुआ तो हम सबको हानि होगी। जैसा कि श्री नाथ पाई ने पहले बताया, न केवल भारत और श्रीलंका को ही नहीं अपितु पूर्व अफ्रीका को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिये हमें यह देखना है कि यूनिट मूल्य कम नहीं होता है।

जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, आधुनिकीकरण और नवीकरण किये जाने वाले चाय बागानों की सहायता करने के बारे में हमने संगठन तथा नये पौधे लगाने के सम्बन्ध में इन चाय बागानों को हम पर्याप्त सहायता देते रहे हैं।

श्री हेम बरुआ: मेरा पहला स्पष्ट प्रश्न था कि चाय के निर्यात में रुपए के अवमूल्यन से पहले ही श्रीलंका हमसे आगे है और अब चूंकि श्रीलंका ने अपने रुपए का अवमूल्यन कर दिया है हमें आशंका है कि श्रीलंका और आगे निकल जायेगा। इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : अवमूल्यन अन्तिम बात नहीं है; निर्णायक बात तो निर्यात शुल्क का समंजन है। मुझे खेद है कि इसका सम्बन्ध अर्थशास्त्र से है, राजनीति से नहीं। असल बात यह है कि अवमूल्यन किये जाने पर भी आप इतना निर्यात शुल्क रखें जिससे यूनिट मूल्य उतना ही बना रहे और इसलिये अवमूल्यन का कोई प्रभाव पड़े अथवा नहीं।

श्री हेम बरुआ : श्रीलंका के रुपये के अवमूल्यन से पहले भी निर्यात शुल्क था ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : अभी मंत्री महोदय ने मध्यम और निचले दर्जे की चाय के बारे में कठिनाइयों का उल्लेख किया और बताया कि बढ़िया किस्म की चाय की बिक्री अच्छी रही है। इस चाय के सम्बन्ध में श्रीलंका हमारा प्रतिस्पर्धी रहा है और उसके द्वारा निर्यात संवर्धन की कार्यवाही किये जाने से पहले भी वह हमसे आगे रहा है। क्या इस बातचीत के दौरान न केवल बढ़िया किस्म की चाय के बारे में अग्रेतर विचार विमर्श होगा अपितु चाय की अन्य किस्मों के बारे में भी विचार-विमर्श होगा ताकि दोनों सरकारों द्वारा एक संयुक्त निर्यात संवर्धन अभियान आरम्भ किया जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हा; हमारी संयुक्त संवर्धन कार्यवाही होनी चाहिए। पहले ही हमारी कुछ संयुक्त संवधन गतिविधियाँ हैं और देखना यह है कि हम उनमें कैसे सुधार करसकते हैं। यह ठीक है कि हम इस ओर ध्यान दें कि अन्य देश क्या करते हैं और उस हद तक हम अपने प्रयासों को तेज करें, मैं यह बताना चाहता हूं कि केवल हमारा ही नहीं अपितु श्रीलंका की चाय का यूनिट मूल्य भी कम हुआ है। वास्तव में यदि हम 1965 और 1966 के आँकड़े देखें तो पता चलेगा कि जब हमारा निर्यात 10 प्रतिशत कम हुआ है, श्रीलंका का निर्यात 10.6 प्रतिशत घटा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know from the Hon. Minister the reasons for decline in export of Indian tea while our production is going up and what steps have been taken to counteract them? What has been the impact of devaluation by England and Ceylon on tea exports ?

Shri Dinesh Singh : The two main reasons are our high cost of production and the increasing domestic consumption and as a result thereof we do not earn much profit. There may be other factors also but as regards this we are doing our best. As I have already stated we are trying new systems of plantation as well. An Hon. friend just now mentioned about picking of tea all the year round. We are making progress in that direction.

As regards the impact of devaluation by England on tea, I have already stated that it has not been announced. Unless their export duty is readjusted. we cannot tell the impact.

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Question

दक्षिण रेलवे के मद्रास स्थित मुख्यालय में इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर

अ०सू०प्र० 4. श्री नम्बियार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मद्रास स्थित मुख्यालय में एक इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाया जा रहा है;

(ख) क्या इसके कारण दक्षिण रेलवे में कर्मचारियों में बड़ा असंतोष फैला हुआ है, जिन्होंने काम बन्द कर देने की धमकी दी है; और

(ग) इस रेलवे में काम के बन्द हो जाने के गंभीर खतरे तथा कम्प्यूटर का लगना रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) विरोध में कुछ सभाएँ की जाने की रिपोर्ट मिली है। 10 नवम्बर को सबरे उपस्कर की सुपुर्दगी में रुकावट डालने की कोशिश की गयी थी। पुलिस ने लगभग 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया लेकिन कुछ घन्टों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। काम बन्द नहीं हुआ है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

श्री नम्बियार : क्या यह सच है कि उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्वी तथा बहुत से अन्य रेलवों में संगणक (कम्प्यूटर) लगाये जाने से हज़ारों कर्मचारी फालतू हो जायेंगे ? क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार की यह नीति है कि इन संगणकों कों लगाये जाने के फलस्वरूप कोई छटनी न हो और क्या संगणक न लगाने के बारे में रेलवे विभाग पुनर्विचार करेंगा, जो विदेशों से किराये पर लिये गये हैं और जो हमारे देश में नहीं बनाये गये ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैंने सभा में यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि केवल संगणक लगाये जाने के कारण किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जायेगी । हम ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि उनके पदोन्नति के अवसर भी यथा पूर्व बने रहेंगे । इस प्रकार जितने कर्मचारी इस समय काम कर रहे है वे काम करते रहेंगे और कोई छटनी नहीं होगी । इसके अतिरिक्त संगणक लगाने से यदि किसी क्लर्क विशेष का तबादला करना पड़ा तो वह भी उसकी सहमति के बिना नहीं किया जायेगा ।

श्री नम्बियार : क्या मैं यह पूछ सकता हूँकि क्या रेलवे मंत्री ने संगहणकों को लगाये जाने से पहले इस सम्बन्ध में श्रमिकों के साथ बातचीत की थी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हाँ; 5 अप्रैल 1967 को इस विषय में एक ज्ञापन तैयार किया गया था और दोनों संगठनों के श्रमिकों को दिया गया था ।

श्री नम्बियार : उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ? इसका पूर्ण उत्तर दिया जाये ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : जो संगणक लगाये जा चुके हैं क्या मंत्री महोदय ने उनकी कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में विचार किया है ? क्या यह सच है कि उनकी कार्य प्रणाली बहुत खराब है और गलत आंकड़े दिये जाते हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : सभी रेलवों में हमारे पास यूनिट रिकार्ड उपकरण हैं और उनमें वास्तव में मशीन द्वारा संगणन आँकड़ों का संकलन, और आंकड़ों के समेकन आदि का कार्य आरम्भ हो गया है । हमें पता चला है कि इस कारण पहले 25 लाख रुपये कम लिये जाने का पता चला था और अब यह धनराशि 94 लाख रुपये हो गयी है । यह एक विशेष दृष्टान्त है । वेतन पंजी बनाने के कार्य में अब आकड़े अधिक सही बताये जाते हैं और इस सम्बन्ध में शिकायतों की संख्या न्यूनतम हो गई है । कई प्रकार की अग्रिम राशियों की कटौती करनी होगी और कई प्रकार के भत्तों को जोड़ना होगा । अब ये सब काम मशीने करेंगी जहाँ बिल्कुल सही, नवीनतम और तत्काल आंकड़े और सूचना उपलब्ध होती है जिसके कारण वेतन पंजी का कार्य बहुत ही संतोषजनक और शीघ्रता से किया जा सकता है ।

श्री कृष्ण मूर्ति : इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर उन देशों में लगाये जा रहे हैं जिन्होंने बहुत प्रगति कर ली है और जहाँ श्रमिक अधिक संख्या में उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये वहाँ तो यह कार्यवाही उचित है । भारत में क्योंकि पहले इतनी बेरोज़गारी है, इसलिये रेलवे, जीवन बीमा निगम तथा अन्य संस्थाओं में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने की और करोड़ों रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता है और फिर इस के साथ-साथ शिक्षित लोगों के रोज़गार के अवसर समाप्त हो जायेंगे ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह मामला हम लोगों के लिये रोजगार के अवसरों का ही नहीं हैं। बात यह है कि कई प्रकार के काम हैं और इस काम में इतनी वृद्धि हो गई है कि सामान्य तरीकों से इतना काम करना और नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इसलिये कुछ न कुछ आधुनिकीकरण किया जाना अनिवार्य हो गया है। जहाँ तक रोज़गार के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने यह पहले ही बता दिया है कि इस कारण से कोई छटनी नहीं होगी।

श्री कृष्ण मूर्ति : महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। इस बात की कोई शिकायत नहीं मिली कि काम करनेके वर्तमान तरीके संतोषजनक नहीं है। इसलिये इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

Shri Ram Charan : Is it a fact that the officer who has recommended installation of computers, his son is employed in the firm from where the computers have been hired ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी है। पिछले कई वर्षों से रेलवों में यूनिट रिकार्ड उपकरण लगे हुए हैं। वर्तमान इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर की व्यवस्था उसी दिशा में एक कदम है। यूनिट रिकार्ड उपकरण छेद किये गये कार्डों के आधार पर कार्य करता है। संगणक (कम्प्यूटर) का लाभ यह है कि इसमें सूचना हमेशा उपलब्ध हो सकती है जिसका किसी हवाला देने, संकलन, समेकन या किसी और सम्बन्ध में उपयोग किया जा सकता है। यूनिट रिकार्ड उपकरणों के काम में जब भी आवश्यकता होती है, छेद किये गये कार्डों द्वारा दी गई सूचना का उपयोग किया जाता है। अतः मशीन द्वारा पहले ही काम होता है। यह तो उससे आगे की कार्यवाही है। जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस मामले में किसी व्यक्ति की रुचि है, इस मामले पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। प्रश्न यह है कि आधुनिकीकरण कसे किया जा सकता है, इसी सम्बन्ध में यह आगे की कार्यवाही है।

श्री अमृत नाहाटा : रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम या रेलवे में जब भी कभी कोई संगणक लगाया जाता है, हमें यही बताया जाता कि छटनी नहीं होगी। परन्तु क्या ये स्वचालित मशीनें लगाये जाने से भविष्य में इस देश के लोगों के रोज़गार के अवसर समाप्त नहीं हो जायेंगे जहाँ लाखों शिक्षित लोग बेरोज़गार पड़े हैं और नौकरियों की तलाश कर रहे हैं ? क्या यह कहना घाव पर नमक छिड़कना नहीं है कि हमारे शिक्षिति एवं बुद्धिमान लोग वह काम नहीं कर सकते जो ये मशीन कर सकती हैं ? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जितना खर्च लोगों द्वारा काम करनेपर होता है उससे अधिक खर्च इनके किराये पर होगा ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहाँ तक भविष्य की बात है यह तो अपनी-अपनी राय है कि इससे भविष्य में रोज़गार के अवसर कम होंगे या बढ़ेंगे। एक विचार यह भी हो सकता है कि यदि आधुनिक तरीकों से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है तो उस अवस्था में अन्य क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी। जहाँ तक छटनी का सम्बन्ध है मैंने इस सम्बन्ध में पहलेही आश्वासन दे दिया है।

श्री अमृत नाहाटा : भविष्य में रोज़गार के अवसर ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस सम्बन्ध में अभी कोई सूचना नहीं दे सकता।

Shri Ramavtar Shastri : Is it not a fact that employees working in Railways, Insurance Companies and organised labour are against the installation of these electronic computers ?

Is it also not a fact that an agitation is going on and some arrests have been affected in South Eastern Railway? I want to know as to why government are making it a prestige issue? Does government not consider it proper to yield to public opinion? I want to know that what is the hitch in this matter ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस विषय पर संगठित श्रमिकों के साथ बातचीत हुई थी और उन्होंने हमें अपने विचार बताये हैं। हमने उस सम्बंध में निर्णय लिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : सभी रेलवे कर्मचारी विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि आप आधे घण्टे की चर्चा कर लें। प्रश्नों के समय इस प्रकार इतने अनुपूरक प्रश्न पूछने से कार्यवाही नहीं चल सकती।

Shri Hukam Chand Kachwai : The work which is done by Ministers, it would be better if it is done by computers.

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा विचार है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि इण्डियन लेबर कांफ्रेंस में जब स्वचालित मशीनों के बारे में चर्चा हुई थी तो सभी पक्ष इस बात पर सहमत थे कि स्वचालित मशीनें या इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने से पहले उस बारे में चर्चा की जायेगी और सम्बन्धित पक्षों की सहमति से उन्हें लगाया जायेगा। जहाँ तक रेलवे का सम्बन्ध है सरकार ने आल इण्डिया रेलवेमैन फेडरेशन और अन्य संघों को एक ज्ञापन भेजा है परन्तु न तो आल इण्डिया रेलवेमैन फेडरेशन और न ही दक्षिण पूर्व रेलवेमैन के संघ ने और न ही किसी और संघ ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। इस सम्बन्ध में अब भी आन्दोलन चल रहा है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या मंत्री महोदय एक सम्मेलन बुलाकर इस विषय में नये सिरे से विचार करेंगे और देखेंगे कि ऐसी वस्तुएँ न लगाई जायें ?

श्री चे० मु० पुनाचा : माननीय सदस्य शायद त्रिपक्षीय सम्मेलन की कार्यवाही की बात कर रहे हैं जिसमें मशीनें लगाने या बिजली द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण लगाने के सम्बन्ध में मान्यताप्राप्त संघों से परामर्श करने की बात कही गई है। उपरोक्त बात का ध्यान रखते हुए संगठित श्रमिकों को इस सम्बन्ध में चार महीने के अन्दर उत्तर देना चाहिये था। यह ज्ञापन 5 अप्रैल को सम्बन्धित संघों को भेजा गया। एक श्रमिक संघ ने सहमति व्यक्त की है और दूसरे ने चार महीने में भी अब तक उसका कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत समय बाद वे लोग ग्वालियर में मिले थे और कुछ निर्णय लिया था परन्तु उस समय तक रेलवे ने भी अपना निर्णय लेना था। हमने दोनों फैडरेशनों को पुनः लिखा था।

श्री अम्बाजागन : देश में बेरोज़गारी की समस्या बढ़ रही है और सरकार उसका समाधान करने में असमर्थ है और क्योंकि सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाये जाने के प्रश्न पर सारे देश में आन्दोलन चल रहा है इसलिये क्या मंत्री महोदय अभी कम्प्यूटर न लगाने के विषय में विचार करेंगे ? दक्षिण रेलवे में कम्प्यूटर लगाये जाने पर वहाँ के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और मद्रास राज्य के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को लिखा है कि कम्प्यूटर न लगाये जायें। उसके बावजूद यदि मंत्री महोदय को कर्मचारियों के आन्दोलन की परवाह नहीं तो क्या उनके पास बेरोज़गारी की इस विकट समस्या के समाधान के लिये कोई और तरीका है ?

श्री च० मु० पुनाचा : मैंने इस सम्बन्ध में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक रेलवे का सम्बन्ध है, हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। यूनिट रिकार्ड उपकरण के स्थान पर, हम कुछ और विशिष्टि यूनिट लगा रहे हैं जो बिजली द्वारा चलाये जायेंगे। मैंने 17 अक्तूबर को मद्रास के मुख्य मंत्री से स्वयं बात की है और इस चर्चा के बाद में 2 नवम्बर को एक और ब्योरेवार पत्र लिखा है। मुझे इस बात का विश्वास है कि उनको अब सब बातों की पूर्ण जानकारी है और वह पूर्णतया संतुष्ट हैं।

श्री हेम बरुआ : यह पता चला है कि हमें अमरीका से यें इलेक्टायिक कम्प्यूटर उधार में मिल रहे हैं और उन पर काफी किराया देना होगा। क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि किराया देने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यें कम्प्यूटर भारत में बनते हैं और भारतीय रुपयें के रूप में किराया दिया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

काली सूची में दर्ज समवायों की आस्तियों तथा दायित्वों के बारे में जाँच

*243. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में काली सूची में दर्ज समवायों को आस्तियों तथा दायित्वों की जाँच करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नीवेली लिग्नाइट बिजली घर से बिजली की सप्लाई

*246. **श्री पार्थसारथी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीवेली लिग्नाइट बिजली घर के पास अब बिजली काफी मात्रा में फालतू है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आँध्र प्रदेश में उसके पड़ोसी जिलों चित्तूर तथा कुडप्पा को यह फालतू बिजली देने के कोई प्रस्ताव हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) हम मद्रास राज्य विद्युत बोर्ड की पक्की माँग का पता लगा रहे हैं। ऐसा करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि निवेली के पास विद्युत शक्ति का अतिरेक है या नहीं।

सिडनी में एशिया और सुदूर-पूर्व के देशों के लिए आर्थिक आयोग का सम्मेलन

*249. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री मरंडी :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और सुदूर पूर्व के देशों के औद्योगिक विकास कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करने के लिये 4 से 11 सितम्बर, 1967 तक सिडनी में हुए एशिया और सुदूर पूर्व के देशों के लिये आर्थिक आयोग के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व था;

(ख) सम्मेलन में और किन देशों ने भाग लिया था; और

(ग) विशेष रूप से भारत के सम्बन्ध में सम्मेलन का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) एशिया और सुदूर पूर्व देशों के लिये आर्थिक आयोग की उद्योग और प्राकृतिक साधनों की समिति की धातु और इंजीनियरी संबंधी उप समिति के ग्यारहवें अधिवेशन में, जो सिडनी में 4 सितम्बर से 11 सितम्बर 1967 तक हुआ, भारत का भी प्रतिनिधित्व था।

(ख) जिन दूसरे देशों ने इसमें भाग लिया उनके नाम हैं:—

1. आस्ट्रेलिया
2. चीन (तैवान)
3. फ्रांस
4. इन्डोनेशिया
5. ईरान
6. जापान
7. फिलीपीन
8. सिंगापुर
9. थाईलैंड
10. सोवियत रूस
11. संयुक्त राज्य अमेरिका
12. हाँग काँग
13. न्यूजीलैंड

(ग) इन अधिवेशनों में धातु तथा इंजीनियरी उद्योगों को आयोजन और विकास से संबंधित वर्तमान समस्याओं तथा कुछ कम उन्नत देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर विचार विनिमय करने और सूचना का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया।

बैरल और ड्रम उद्योग

*250. **श्री समर गुह :** **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक कच्चे माल की कम सप्लाई और किसी उद्योग की वर्तमान लाइसेंस प्राप्त पूर्ण क्षमता प्रयोग करने की सरकार की घोषित नीति को देखते हुए बैरल और ड्रम उद्योग को गत कुछ वर्षों से प्रतिबन्ध वाले उद्योगों की सूची में रखा गया है;

(ख) यदि हाँ तो (1) हिन्द गैलवेनाहूजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता और (2) स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को अपनी वर्तमान क्षमता बढ़ाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने 'नई क्षमता' को सामान्यतः मानने और उपरोक्त दोनों कम्पनियों के उत्तरोत्तर विस्तार की अनुमति देने से पूर्व फर्मों की संख्या के आधार पर वर्तमान निर्माताओं के लिये कच्चा माल नियत किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) ढोल, पीपा (बैरल) और डब्बा उद्योग 1960 से 'अस्वीकृत वस्तु सूची' में रखा गया है, अर्थात् यह उद्योग सूची जिसमें उद्योग (विकास और विनियम) विधान, 1951 के अधीन लाइसेंस सामान्यतया अस्वीकृत हो सकते हैं। समय-समय पर इस प्रकार की अस्वीकृत वस्तुओं की सूचियाँ तैयार करते समय मौजूदा स्थापित क्षमता, कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति आदि पर विचार किया जाता है।

(ख) मैसर्स हिन्द गल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि०, कलकत्ता जिनकी रजिस्ट्री हैवी ड्यूटी बैरलों और छोटे ढोल बनाने के लिए पहले से ही हो चुकी है और जो आयल बैरल बनाने की अनुमति के लिए जोर दे रहे थे, जाँच करने पर यह ज्ञात हुआ कि मौजूदा मशीनों के लगाने से उनके लिए आयल बैरलों का उत्पादन करना संभव था। रक्षा मंत्रालय और तेल शोधशालाओं (आयल रिफाईनरीज) द्वारा वर्ष 1963-64 में इन बैरलों की बहुत अधिक माँग होने के कारण यह निश्चय किया गया था कि मैसर्स हिन्द गल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि० जो पहले से ही छोटे ढोल और हैवी ड्यूटी बैरल तैयार कर रही है, की उपलब्ध आयल बैरल उत्पादन क्षमता को पंजीबद्ध किया जाय, यद्यपि यह उद्योग अस्वीकृत सूची के अन्तर्गत है। मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम्स एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई को 11 सितम्बर, 1958 को प्रतिवर्ष 4200 टन क्षमता के बैरल, ढोल और पीपे आदि बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये गये। यह क्षमता लाइसेंस के आधार पर अस्थायी और पुनर्निर्धारण करने के आधार पर दी गई थी, प्रारम्भ में 3,700 टन के 40/45 गैलन आयल बैरल के लिए मंजूरी दी गई थी। यह क्षमता बाद को समस्त बैरल उत्पादक एककों की 1963–64 के आधार पर पुनर्निर्धारण करके बढ़ाकर 14,538 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कर दी गई थी। वास्तव में, इस क्षेत्र में समस्त बैरल उत्पादक कारखानों की क्षमता का समान रूप से पुनर्निर्धारण और परीक्षा की गई थी।

यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका का विषय है और यह विषय इसी हाई कोर्ट के विचाराधीन है।

(ग) समस्त आयल बैरल उत्पादकों को कच्चे माल का आवंटन इन कारखानों में से प्रत्येक कारखाने की एक ही पारी की निर्धारित क्षमता के आधार पर किया गया है, इसलिए उपर्युक्त विशेष मामलों में 'नई क्षमता' को मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

PURCHASE OF INDIAN ROLLING STOCK BY SOUTH KOREA

*252 **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that South Korea is purchasing Railway Rolling Stock of the value of 11 million dollars from India per annum ;

(b) whether it is also a fact that several other big countries also competed, and

(c) the advantages Indian rails have over those produced by other countries ?

The Minister of Commerce (**Shri Dinesh Singh**) : (a) to (c) The State Trading Corporation had submitted a tender in response to two global tender enquiries issued by South Koera for purchase of rolling stock worth about 11 million U.S. Dollars. Other countries like Japan, U.S.A., Sweden, Belgium and West Germany had also competed. S.T.C.'s offer which was the lowest, was accepted.

सरकारी उपक्रमों में अप्रयुक्त क्षमता

*253. **श्री कंवर लाल गुप्त** : **श्री महाराज सिंह भारती** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कितनी अप्रयुक्त क्षमता है तथा उसके कारण लगभग कितनी हानि है; और

(ख) गत तीन महीनों में सरकार ने पूरी क्षमता के उपयोग के बारे में क्या कार्यवाही की है तथा भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विभिन्न एककों में स्थापित की जाने वाली क्षमता भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में है और इस समय यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता कि कितनी क्षमता उपयुक्त रहा है। इसी कारण से अप्रयुक्त क्षमता के कारण कितनी हानि हुई है, यह बता सकना संभव नहीं है। फिर भी कुछ उपक्रमों में पहले से ही स्थापित क्षमता का इस्तेमाल किये जाने के बीच कुछ अन्तर है। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1716/67] ।

(ख) हाल के महीनों में उच्चतम स्तर पर सरकार द्वारा इस अन्तर का पता लगाने पर और अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों को ये निर्देश दे दिये गये है कि वे ऐसी योजनाएँ बनाएँ जिनमें क्षमता का और अधिक उपयोग किया जा सके। उन्हें ये उपाय करने के लिये कहा गया है:—

(1) उन वस्तुओं के उत्पादन में विविधता लाना जिनकी माँग अधिक है जिनमें उन फालतू पुर्जों का उत्पादन शामिल है जिनकी बार-बार माँग होती रहती है;

(2) सरकार के विकास संबंधी कार्यक्रम की दृष्टि से जहाँ कहीं व्यावहारिक हो सके उन वस्तुओं के लिये अधिक आर्डर प्राप्त करना जिनका औद्योगिक उत्पादों की माँग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो;

(3) निर्यात तथा देश के अन्दर बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से विक्रय संगठन को सुदृढ़ करना; और

(4) विद्युत परियोजनाओं, इस्पात, ढांचे तथा भारी इंजीनियरी उद्योगों के क्षेत्र में अदला-बदली के आधार पर संविदा करने के लिये सहयोग मंडल बनाना।

स्कूटरों के निर्माण सम्बन्धी योजनायें

*254. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री नाथूराम आहरवार :
श्री ग० च० दीक्षित :
श्री लाखन लाल गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों के निर्माण की 17 योजनाओं का परीक्षण करने वाली उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सरकार अपना अन्तिम निर्णय उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा लाइसेंस समिति द्वारा विचार किए जाने और उसकी सिफारिशों के प्राप्त हो जाने के बाद ही कर सकती है। ऐसा निर्णय सम्भवतः मार्च, 1968 के मध्य तक किया जा सकेगा।

दुर्गापुर धातु मिश्रित इस्पात का संयंत्र

*255. **श्री रमानी :**
श्री चक्रपाणि :
श्री एस्थोस :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर धातु मिश्रित इस्पात कारखाने को चालू करने में और अधिक विलम्ब होने की आशा है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसके कारण धातु मिश्रित इस्पात के आयात पर होने वाले व्यय में वृद्धि होगी; और

(ग) आयात के लिये कितनी अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) :

(क) पहले देरी की वजह से दुर्गापुर की मिश्र इस्पात प्रायोजना की विभिन्न इकाइयों के चालू करने के कार्य-क्रम में समय समय पर फेर बदल होते रहे हैं। लेकिन वर्तमान अवस्था में प्रायोजना को पूरा करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उससे और अधिक देर होने की संभावना नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात में कमी

*256. श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री शारदानन्द :
श्री विश्वम्भरम :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के पश्चात् भारत के निर्यात व्यापार में कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने करोड़ रुपये की कमी हुई है; और

(ग) इस गिरावट को रोकने के लिये तथा भारत का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) तथा (ख) : अवमूल्यन के पश्चात् पन्द्रह महीनों की कुल अवधि अर्थात् जून 66 से अगस्त 67 में भारत के निर्यात 1427.90 करोड़ रुपये के हुए जब कि मई, 1966 तक के पन्द्रह महीनों में 1951.00 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे। दोनों अवधियों की तुलना भी संगत नहीं होगी क्यों कि गत वर्ष कृषि-जन्य वस्तुओं की अत्यधिक कमी थी।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है।

विवरण

अवमूल्यन के पश्चात् की अवधि में निर्यात संवर्द्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत आयातित कच्चे माल की व्यवस्था। स्वदेशी कच्चे माल के आवंटन, निर्यात के लिए इंजीनियरी सामान के तैयार करने वालों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर लोहे एवं इस्पात का संभरण तथा निर्यात-अभिमुख एककों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के लिए विशेष आवंटन द्वारा निर्यात के लिए उत्पादन को सुकर बनाना।

(2) चुने हुए उत्पादों के निर्यात के लिए नकद सहायता तथा विदेशों में विपणन सम्बन्धी विशिष्ट कार्यकलापों के लिए विपणनविकास निधि से सहायता द्वारा विदेशों की प्रतियोगिता का सामना करने के लिये निर्यातकों को समर्थ बनाना।

(3) निर्यात शुल्क में कमी अथवा पुनर्समायोजन तथा उत्पादन शुल्क लगा कर अथवा उसमें समायोजन द्वारा देश में माल की खपत पर नियंत्रण करना।

हाल ही में वाणिज्य मंत्री तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से निर्यात संवर्द्धन सम्बन्धी मार्गोपायों पर बातचीत की। इन वार्ताओं के फल-स्वरूप सरकार ने कतिपय आशाजनक मदों को नकद सहायता बढ़ाने की घोषणा की है और उद्योग ने कुछ बड़े निर्यात आदेश करके अनुकूल प्रतिक्रिया प्रकट की है।

औद्योगिक परियोजनाएं

*257. **श्री चक्रपाणि:** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

श्री नायनार : **श्री गणेश घोष :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की सलाह पर सरकारी क्षेत्र में कुछ बड़ी मध्यम औद्योगिक परियोजनाओं के छोड़ दिये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):
(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए कच्चे माल का आयात

*258. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत् उपकरणों के लिए कच्चा माल विदेशों से आयात किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में किन-किन देशों से कितने कितने कच्चे माल का आयात किया गया;

(ग) क्या इनमें से कोई कच्चा माल हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और अलाय स्टील प्रोजेक्ट्स से उपलब्ध है; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में उनसे विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की कितनी मात्रा ली गई?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी हाँ, जहाँ तक आवश्यक हो।

(ख) गत तीन वर्षों में आयात मुख्यतया सोवियत रूस, चेकोस्लोवाकिया, स्वीडन, हालैंड, जापान तथा पश्चिमी जर्मनी से किया गया है। इन देशों से आयात की गई वस्तुओं के परिमाण के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा एलाय स्टील परियोजना से उपलब्ध कच्चा माल खरीदा गया था और केवल उन्हीं वस्तुओं का विदेशों से आयात किया गया जिनका सम्भरण ये परियोजनाएं नहीं कर सकती थीं।

निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को घाटा

259. श्रीमती सुशीला गोपालन: श्री पं० गोपालन:
श्री उमानाथ: श्री अब्राहम:
श्री भगवान दास : श्री विश्वनाथ मेनन:
श्री वि० नरसिम्ह राव:

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को गत पाँच वर्षों में घाटा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार ने इस निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) हाँ, महोदय।

(ख) निगम के शुरू होने से 1966-67 के अन्त तक 14.06 करोड़ रुपए की संचयी हानि का अस्थायी अनुमान है।

(ग) हाँ, महोदय। विभिन्न तकनीकी तथा दूसरी कठिनाइयों के कारण परियोजना अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं कर सकी।

(घ) हानि को समाप्त करने के निम्न उपाय किए गए हैं:-

1. प्रशुल्क के प्रत्याभूत उपक्रय और इसका संशोधन करके इसमें वृद्धि करने के लिये मद्रास राज्य तथा मद्रास राज्य विद्युत् बोर्ड से बातचीत की जा रही है।
2. लेकों की बिक्री बढ़ाई जा रही है।
3. जाँच समूह की सिफारिश के अनुसार उर्वरक प्लांट में संशोधनों तथा सुधारों पर विचार किया जा रहा है।
4. उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिये तथा और अधिक कुशलता द्वारा कीमत करने के लिये अध्ययन किया जा रहा है।

EXPORTS BY S. T. C.

260. **Shri Ramji Ram :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Prakash Vir Shastri :**
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the further progress made by the State Trading Corporation to increase the exports;

(b) whether it is a fact that devaluation has proved to be a hindrance in the way of this progress ; and

(c) whether any new schemes in this regard are under consideration ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) The S.T.C.'s exports in terms of its direct trade rose from Rs. 131.2 millions in 1965-66 to Rs. 309.9 millions in 1966-67. Although some uncertanties were created following devaluation, S.T.C. foreign trade has been steadily rising.

(c) **Yes, Sir.**

हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा लोहे की चादरों का आयात

*261. **श्री मृत्युजय प्रसाद:** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मोटर्स गाड़ियों के ढाँचे बनाने के लिए जापान तथा अन्य देशों से लोहे की चादरें आयात करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला स्थित कारखाने ने अपने किसी विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वित कहोने के पश्चात् हिन्दुस्तान मोटर्स के लिये अपेक्षित नमूने की इस्पात की चादरें बनाने का वचन दिया था; और

(ग) उस विस्तार कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है तथा वह कारखाना निकट भविष्य में कार निर्माताओं की चादरों की आवश्यकताओं को कहाँ तक पूरा कर सकेगा?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान स्टील्स लि०, राँची का राउरकेला विभाग मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स और अन्य गाड़ी निर्माताओं की चपटे इस्पात के उत्पादों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रत्येक प्रयास कर रहा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति तथा मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि० की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनकी योग्यता का पता इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय से लगाया जा रहा है।

औद्योगिक कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई

*262. **श्री रा० रा० सिंह देव:** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव:**
श्री वेदव्रत बरुआ: **श्री नं० कु० सांधी:**
श्री य० अ० प्रसाद:

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात करने वाले कारखानों की ओर से सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनको प्राथमिकता के आधार पर कच्चे माल की समय पर सप्लाई नहीं मिलती है: और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनपर क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय को कुछ इन्जीनियरी एककों से जो इस्पात के उत्पादों जैसे माल गाड़ी के डिब्बे ट्रांसमिशन टावर, चमकीली छड़ें, शाफ्ट, बाल्टियाँ

चूने गारे के तसले, हल्के दबाव के सिलेंडर आदि के निर्माण में लगे हुए हैं, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि इस्पात के प्रमुख उत्पादक निर्यात आवंटन के बदले माल का भुगतान शीघ्रता से नहीं कर रहे हैं। ये शिकायतें संयुक्त संयंत्र समिति / लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के स्थान में सुधार हेतु लादी गई हैं।

लकड़ी के स्लीपर

*263. **श्री चेंगलाराया नायडू**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने रेलवे बोर्ड से अभ्यावेदन किया है कि लकड़ी के स्लीपरों के मूल्य लाभदायक नहीं हैं तथा स्लीपर बड़े पैमाने पर अस्वीकार कर दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी बताया है कि रेलवे के इस रवैये तथा स्लीपरों को बड़े पैमाने पर अस्वीकार किए जाने से उनके राजस्व पर प्रभाव पड़ा है और इसके फलस्वरूप अच्छी इमारती लकड़ी काफी मात्रा में बेकार हो गई है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां, लेकिन अभ्यावेदन केवल कीमतों के सम्बन्ध में हैं, जो मद्रास, मैसूर और हिमाचल प्रदेश सरकारों से मिले हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वन विभाग के केन्द्रीय बोर्ड की उप समिति ने जो कीमतें निर्धारित की हैं उनमें संशोधन करके उन्हें बढ़ाया जाय।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता, क्योंकि ये कीमतें वन विभाग के केन्द्रीय बोर्ड की उप समिति द्वारा निर्धारित की गयी हैं जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी होते हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास कच्चे लोहे का स्टाक

*264. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1966 को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास तीन करोड़, ग्यारह लाख रुपए के मूल्य के कच्चे लोहे का, जिसका इस निगम ने 1964–65 में आयात किया था, स्टाक था;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह कच्चा लोहा भूमि के एक प्लाट में रखा गया था जिसका 4 लाख रुपए से अधिक किराया दिया गया था;

(ग) क्या इस कच्चे लोहे पर लगभग एक करोड़ रुपये का घाटा हुआ था;

(घ) यदि हां, तो इस स्टाक को पहले क्यों नहीं बेचा गया तथा क्या इस मामले की जांच करा कर इस भारी घाटे के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम रहा है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी नहीं। निगम के पास 1964–65 में किए गए आयात में से 31 दिसम्बर, 1966 को 18.5 लाख रुपए मूल्य का 5600 टन का स्टाक

मौजूद था। किन्तु उस तारीख को निगम के पास समस्त आयातों में से 52.139 टन का कुल स्टाक मौजूद था जिसका मूल्य अनुमानतः 230 लाख रुपए था।

(ख) निगम नें बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास के पत्तनों पर अक्तूबर, 1964 से 31 मार्च, 1967 तक 7.52 लाख रुपए का कुल किराया दिया।

(ग) और (घ) खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने जो कि लौह एवं इस्पात नियंत्रक के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, इन निर्यातों पर हुई कुल हानि का अनुमान 38.46 लाख रुपए लगाया। माल के निपटान में कठिनाई आई क्योंकि आयातित कच्चे लोहे का भाव देशी उत्पाद से अधिक था। चूंकि निगम को हुई हानि अपने सामान्य व्यावसायिक सौदे के दौरान हुई, अतः कोई विशेष छानबीन आवश्यक नहीं समझी गई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के मूल्यों सम्बन्धी संकट के कारण रेलों को हानि

*265. **डा० रानेन सेन:**
श्री हेमराज:
श्री कामेश्वर सिंह:
श्री रवि राय:
श्री श्रद्धाकर सूपकार:
श्री विभूति मिश्र:
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री:
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री राम सिंह अयरवाल:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गैर-सरकारी कोयला-उद्योगों ने रेलों को यदि रेलवे विभाग कोयले के मूल्य बढ़ाने को सहमत न हुआ तो कोयले की सप्लाई बन्द करने की धमकी दी थी;

(ख) क्या इस धमकी के कारण रेलवे को कुछ रेलों का चलना बन्द करना पड़ा:

(ग) यदि हाँ, तो इन रेलों का चलना बन्द करने के कारण रेलवे को कितनी वित्तीय हानि उठानी पड़ी;

(घ) क्या बाद में कोयले के मूल्यों का झगड़ा निबट गया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो समझौता किन शर्तों पर हुआ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) और (ख) जी हाँ।

(ग) वित्तीय हानि का बिल्कुल सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, लेकिन राजस्व में लगभग 30 लाख रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) समझौता इस आधार पर हुआ कि पहले के नियंत्रित/अधिकतम मूल्य की अपेक्षा 1.9.67 से बंगाल और बिहार के कोयले के मूल्य में 5 रुपये और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कोयले के मूल्य में 4 रुपए प्रति मीटरिक टन के हिसाब से तदर्थ वृद्धि कर दी जाये।

आम चुनावों के दौरान विशेष विकास निधि का दुरुपयोग

*266. **श्री धोरेश्वर कलिता:** **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस आरोप की जाँच की है कि आम चुनावों के दौरान सीमेंट आवंटन समन्वय संगठन ने राजनैतिक प्रयोजनों सम्बन्धी विशेष विकास निधि का दुरुपयोग किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी उपपत्तियाँ क्या हैं; और

(ग) उनपर क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) संगठन के लेखे की किताबों का निरीक्षण, कम्पनी विधि बोर्ड के दो अधिकारियों की टोली द्वारा किया गया था।

(ख) और (ग) मामला सक्रिय विचाराधीन है।

भारत-पश्चिम जर्मन उद्योग क्षेत्र में मन्दी

*267. **श्री श्रीधरन:** **श्री श्रीचन्द्र गोयल:**

श्री कामेश्वर सिंह:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत पश्चिम जर्मन उद्योगों पर मन्दी के प्रभावों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम जर्मनी से सहयोग के कोई नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

प्रशुल्क आयोग

*268. **श्री वासुदेवन नायर:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशुल्क-आयोग की कार्य प्रणाली संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उनके बारे में क्या निर्णय किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें समिति की सिफारिशों का संक्षेप दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०** 1717/67]

(ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात व्यापार पर प्रतिबन्ध

*269. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस प्रकार के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी काँग्रेस में व्यापार-संरक्षणवाद की भावना जोर पकड़ती जा रही है और इसके फलस्वरूप अमरीका में आयात व्यापार पर असंख्य प्रतिबन्ध लगने से भारत की अर्थ-व्यवस्था को बहुत हानि होने की संभावना है ;

(ख) सरकार ने अमरीकी सरकार को बाध्य करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि वह ऐसे विधान जिनका भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता हो, न बनाये; और

(ग) इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास के माध्यम से भारत सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई है कि यदि अमरीका ने प्रस्तावित वैधानिक उपायों को अधिनियमित किया तो उसका परिणाम भारत के साथ व्यापार पर अच्छा नहीं पड़ेगा;

(ग) अभ्यावेदन के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

Project Allowance for N.C.D.C. Workers

270. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the persons working under the National Coal Development Corporation used to be given twenty percent of the salaries as project allowance previously ;

(b) whether that allowance has now been reduced to only five per cent ;

(c) whether Government are considering any proposal to discontinue paying even this five per cent allowance to them ; and

(d) if so, the reasons therefor despite the gradual increase in prices and the famine conditions in Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi):

(a) All employees of the Corporation are not entitled to receive project allowance. The allowance is paid only to monthly paid employees working in new projects to compensate them for lack of accommodation and other amenities. The allowance is initially sanctioned at 20 % of the salaries but is gradually withdrawn, as per the scheme as and when accommodation and other facilities become available.

(b) and (c) In some projects the allowance has now been reduced to 5% of the salary on this basis. The project allowance will be withdrawn completely as and when all the prescribed amenities are provided to the employees posted in such projects.

(d) The project allowance is sanctioned to compensate the employees posted in new projects for lack of proper accommodation and other facilities in the new places. The allowance is not intended to neutralise the rise in cost of living index. For the purpose of neutralising such

a rise, the Corporation has sanctioned dearness allowance to its monthly rated employees at the rates applicacable to Central Government employees, as sanctioned by the Govrnment from time to time. The daily rated and piece rated employees get dearness allowance in accordance with the recommendations of Coal Wage Board. In consideration of the famine conditions that were prevalent in Bihar and Madhya Pradesh, the Corporation has sanctioned drought relief advance of Rs. 500/- per head or three month's pay, whichever was less, to the employees entiled thereto in terms of Government orders on the subject.

अतारांकित प्रश्न

Unstarred Questions

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का पुठनर्मन

1625. **श्री दामानी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात के कारखानों के प्रशासन के पुनर्गठन की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी हाँ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

ओखला औद्योगिक बस्ती के कारखानों की इमारतों का बीमा

1626. **श्री दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला औद्योगिक बस्ती के कारखानों की इमारतों के पट्टाधारियों ने अपने अपने इमारतों का बीमा करवा रखा है और क्या बीमापत्र अधिकारियों के पास जमा करवा दिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) 122 पार्टियों में से, 52 ने अपने कारखानों की सीमाओं का बीमा करा लिया है। इन 52 पार्टियों ने पालिसियाँ अधिकारियों के पास रख दी हैं।

(ग) इन पार्टियों ने मुख्य कारण अपनी वे वित्तीय कठिनाइयाँ बताया है जिनका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। फिर भी इन पार्टियों को अपने कारखानों का बीमा कराने के लिये समझाया जा रहा है।

ओखला औद्योगिक बस्ती में स्थित कारखानों से किराये की वसूली

1627. **श्रीदामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला औद्योगिक बस्ती में स्थित कारखानों से किराये की किश्तों की पूरी वसूली कर ली गई है

(ख) यदि नहीं, तो बकाया किश्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकस तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी नहीं।

(ख) 122 शेडों में से केवल दो कारखानों ने अपना अब तक का किराया दे दिया है, जबकि बाकी कारखानों पर एक महीने से साल भर तक का 13,80562.59 रु० किराया बकाया है।

(ग) जिन कारखानों के मालिकों पर तीन महीने से ज्यादा का किराया बकाया है उनसे कहा गया है कि वे किराये की राशि तत्काल अदा करें अन्यथा सार्वजनिक सीमा किराया वसूली और बेदखली अधिनियम के अधीन उनके विरुद्ध कायवाही की जायेगी।

LOOTING OF DANAPUR-RAJGIR TRAIN

1628. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the dacoits looted the Danapur-Rajgir train between Silao and Rajgarh Stations and three passengers were injured as a result of beating given to them by the dacoits in the last week of August, 1967 ;

(b) if so, the action taken by Government in the matter ; and

(c) the amount of property looted by the dacoits ?

The Minister of Railways (**Shri C. M. Poonacha**): (a) Yes, but the incident took place in the last week of September, 67 i.e. on 23.9.67. Only one passenger was injured.

(b) Government Railway Police, Bihar Sharif have registered a case No. 2 dated 24.9.67 u/s 395 IPC, which is still under investigation. No arrest or recovery has been made so far.

(c) Rs. 207.27 P. in cash and other personal belongings of the passengers are reported to have been lost.

MANUFACTURE OF PASSENGER CARS

1629. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **I ndustrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the proposal for the manufacture of passenger cars has been considered ; and

(b) if so, the details thereof and, if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs : (**Shri Fakhuruddin Ali Ahmed**) : (a) and (b) Government had received several proposals for the manufacture of passenger cars. All the parties, Indian as well as foreign, who had submitted proposals had been requested to furnish full details as per the proforma questionnaire supplied to them to enable Government to examine their economic feasibility. Detailed proposals have been received from 14 parties and these are now being examined.

YEOTMAL-ELLICHPUR N. G. LINE

1631. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any programme has been chalked out to improve passengers' facilities on Yeotmal-Ellichpur (via Murtazapur) Narrow Gauge Railway line in view of great difficulties being experienced by passengers ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (**Shri C. M. Poonacha**) : (a) No. I am not aware of any special difficulties experienced by passengers on this section of the Railway.

(b) Does not arise.

हावड़ा से दिल्ली के लिए सुपर-एक्सप्रेस रेलगाड़ी

1632. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा से दिल्ली के लिये सुपर-एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी हाँ।

(ख) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में तकनीकी ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसलिये इसे चलाने के बारे में अभी कोई तारीख नहीं बताई जा सकती।

मुकन्द आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, बम्बई के अंश

1633. **श्री मधुलिमये** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुकन्द आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, बम्बई में आस्थगित अंशों को साधारण अंशों में बदलने के अनुपात सम्बन्धी विवाद के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यूनिट ट्रस्ट और जीवन बीमा निगम जैसे राजकीय संस्थानों ने इस कम्पनी के कोई अंश खरीद रखे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों को इस विवाद के सम्बन्ध में सितम्बर, 1967 में बम्बई अंशधारियों की वार्षिक बैठक से पहले/में/के पश्चात् नीति निर्धारित करने के लिए अनुदेश दिया था और

(घ) यदि नहीं, तो साधारण अंशधारियों और स्वयं अपने हितों की रक्षा करने के लिए अनुदेश न देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हाँ श्रीमान्।

(ख) हाँ, श्रीमान्।

(ग) तथा (घ) जीवन बीमा निगम एक स्वायत्त निगम है, तथा अपने आर्थिक हित की सुरक्षा के लिये समय-समय पर वह निस्संदेह ऐसी कार्यवाही करेगा, जो आवश्यक हो। इस कार्य के लिये सरकार की ओर से किसी खास निदेशन की आवश्यकता नहीं है और न कोई प्रेषित हुई। साधारण सहभागीदारों के हित के लिए, यह वर्णित है कि आस्थगित शेयरों को साधारण शेयरों में बदलने की कोई योजना, लागू करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के अधीन उच्च न्यायालय की संस्वीकृति आवश्यक होगी, तथा उच्च न्यायालय को योजना की स्वीकृति देने से पहले, धारा 394 ए के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार को एक नोटिस प्रेषित करना आवश्यक है। धारा 394 ए के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त होने पर, मामलों की परीक्षा की जायेगी, तथा उच्च न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

विगों तथा विगलेटों तथा फालों का निर्माण

1634. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा मद्रास में विगों, विगलटों तथा फालों के निर्माण के लिये कारखानों को कब स्थापित किया गया था, उसमें कितना धन लगाया गया है, कितने कर्मचारी काम करते हैं, देखभाल का व्यय कितना है, किस-किस वस्तु का कितना-कितना वार्षिक उत्पादन होता है और इस कारखाने ने कितना मुनाफा कमाया है;

(ख) इस कारखाने में बनीकितनी वस्तुओं को देश में बेचा गया तथा कितनी वस्तुओं का निर्यात किया गया, ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इससे गत वर्ष कितनी आय रुपयों में तथा कितनी विदेशी मुद्रा के रूप में हुई;

(ग) हाँगकाँग की लायन राकट्रेडिंग कम्पनी के साथ किन शर्तों पर सहयोग सम्बन्धी करार किया गया है और उनको तकनीकी मामलों पर परामर्श देने के लिए कितनी रायलटी अथवा कमीशन दी गई और विदेशी मुद्रा के रूप में हाँगकाँग को अब तक कितनी धन-राशि भेजी गई है; और

(घ) लायन राक ट्रेडिंग कम्मनी के द्वारा उक्त कारखानों में कितने विदेशी तकनी की व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं; उनकी राष्ट्रीयता क्या है, उनको कितना वेतन तथा अन्य परिलब्धियाँ दी जाती हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह):

(क) विग-इण्डिया कारखाने में जून 1966 से काम होना आरम्भ हो गया था परन्तु औपचारिक रूप से 31 जनवरी, 1967 से उसका कार्य आरम्भ हुआ था। उसमें कुल पूंजी लगभग 25 लाख रुपए लगाई गई है। इस कारखाने में 946 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। देखभाल का खर्च लगभग 11.94 लाख रुपए है। वर्ष 1966 में 12000 विग्गों, विगलेटों और फालों का उत्पादन हुआ था। वर्ष 1966–67 में इस कारखाने को 3.51 लाख रुपए का लाभ हुआ है।

(ख) पिछले वर्ष 11,000 विगों, विगलेटों और फालों का निर्यात किया गया था और 6.02 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा कमाई गई थी। इसके अतिरिक्त 32.71 लाख रुपए के मूल्य के नकली बाल भी निर्यात किए गए थे। भारत में कोई विक्रय नहीं किया गया था।

(ग) यह सूचना देना राजकीय व्यापार निगम के व्यापारिक हित में नहीं है।

(घ) पाँच तकनीशनों को हाँगकाँग से बुलाया गया था जिनके पास हाँगकाँग के पारपत्र थे। इन तकनीशनों को दिए जाने वाला वेतन लगभग 15,000 रुपए बनता है। वे कुल 18 महीने के लिये यहाँ पर ठहरे। वेतन के अतिरिक्त उनको निःशुल्क सुसज्जित आवास, घरेलू कर्मचारी भत्ता तथा सवारी-भत्ता भी दिया जाता था।

कोयला खानों की रायल्टी की बकाया राशि

1635. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (एक) बलारपुर कोयला खान, चन्दा जिला महाराष्ट्र
(दो) शास्त्री कोयला खान, जिला महाराष्ट्र

(तीन) घुघुज कोयला खान जिला महाराष्ट्र

(चार) महाकाली कोयला खान जिला महाराष्ट्र

की आज तक की रायल्टी की बकाया राशि कितनी है;

(ख) ये बकाया राशियाँ किस अवधि की हैं; और

(ग) इन बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) से (ग) इस प्रश्न का मामला ऐसा है जिसका कि भारत सरकार का प्राथमिक रूप से कोई संबंध नहीं है।

त्रिवेन्द्रम में बुनकर सेवा केन्द्र

1636. **श्री विश्वम्भरम**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिवेन्द्रम में बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सरकार चालू वर्ष में त्रिवेन्द्रम में सेवा केन्द्र स्थापित कर देगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) त्रिवेन्द्रम में बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यह बात उक्त भाग (क) में कही गई बात के परिणाम पर निर्भर करती है।

नारियल-जटा बोर्ड का सचिव

1637. **श्री विश्वम्भरम:** **श्री अदिचन**:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नारियल-जटा बोर्ड के सचिव का पद किस तिथि से रिक्त पड़ा है;

(ख) सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र कब माँगे गये थे;

(ग) सचिव के चयन के लिये कितनी बार इन्टरव्यू लिया गया था;

(घ) क्या कोई ऐसी घटना हुई है कि सचिव के पद के लिये उम्मीदवारों को इन्टरव्यू पत्र भेजे गए हों, परन्तु बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया हो;

(ङ) यदि हाँ, तो उन्हें रद्द किए जाने के क्या कारण थे; और

(च) सचिव की नियुक्ति करने में देर किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) नारियल-जटा बोर्ड के सचिव का पद स्थानापन्न आधार पर, भर लिया गया है और रिक्त नहीं है;

(ख) अप्रैल, 1967 में।

(ग) तीन बार।

(घ) और (ङ) जी, हाँ, तीसरा इन्टरव्यू इसलिये स्थगित किया गया था ताकि केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।

(च) मुख्य रूप से प्रक्रिया सम्बन्धी कारणों से ऐसा हुआ था।

गुजरात में बिड़ला और टाटा के उद्योग

1638. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला और टाटा के गुजरात में कितने तथा किस प्रकार के उद्योग हैं;

(ख) बिड़ला और टाटा की गुजरात में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ग) बिड़ला और टाटा की फर्मों में नए कितने और किस प्रकार के उद्योगों के लाइसेंसों के लिये आवेदनपत्र दिए हैं तथा कितने लाइसेंस दिए गए हैं और कितने आवेदनपत्र विचाराधीन हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में नए उद्योग

1639. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : **श्री दा० रा० परमार** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गुजरात में नए उद्योग स्थापित करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत की है;

(ख) वे उद्योग कौन-कौन से हैं; और

(ग) उन्हें कहाँ-कहाँ स्थापित करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) चूंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप ननहीं दिया गया है इसलिए इस अवस्था में कोई भी निस्चित जानकारी नहीं दी जा सकती। फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे की रूप रेखा में गुजरात राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए अस्थायी रूप से निम्नलिखित धनराशि निश्चित कर दी गई है :—

राज्य क्षेत्र	14.70 लाख रुपए
केन्द्रीय क्षेत्र	62.60 लाख रुपए

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 1718/67]।

गुजरात में औद्योगिक बस्तियाँ

1640. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गुजरात में 1962 से अप्रैल, 1967 तक जिला वार कितनी औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गईं; और

(ख) उक्त अवधि में इस काम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात को कितनी राशि की सहायता दी गई?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) गुजरात में 1962 से अप्रैल, 1967 तक स्थापित की गई औद्योगिक बस्तियों की जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है :—

जिला का नाम	औद्योगिक बस्तियों संख्या
1. कैरा	1
2. बलसार	1
3. सुरेन्द्रनगर	1
4. अहमदाबाद	1
5. अमरेली	1
6. मेहसाना	1
7. कच्छ	1
8. पंचमहल	1
9. जामनगर	2

(ख) केन्द्र द्वारा गुजरात राज्य को 1962–67 (अप्रैल) की अवधि में दी गई सहायता निम्नलिखित है :—

वर्ष	सहायता की राशि (रु० लाखों में)
1962–63	2.85
1963–64	2.03
1946–65	3.93
1965–66	16.61
1966–67	9.00

वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 के आँकड़े अस्थायी हैं इनमें राज्य सरकारों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर हेर-फेर किया जा सकता है।

गुजरात में रेलवे लाइनें

1641. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी नई रेलवे लाइनें शामिल करने का प्रस्ताव किया है तथा उनका प्राथमिकता क्रम क्या है;

(ख) क्या गुजरात का विकास करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक रेलवे लाइन बनाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) गुजरात सरकार ने 22 नयी लाइनें बनाने और उनमें से कुछ लाइनों का मार्ग बदलने के काम को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के

लिए कहा था। प्राथमिकता क्रम में इन लाइनों के नामों की सूची अनुबन्ध में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1719/67]।

(ख) और (ग): गुजरात में इस समय तृतीय योजना की परियोजना के रूप में केवल एक नई लाइन का जिसका नाम झुण्ड-काँडला, 231 किलोमीटर बी० जी० है, निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस लाइन का निर्माण-कार्य अक्तूबर, 1969 में पूरा होगा। चौथी योजना में नई लाइनों के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

गुजरात में नई रेलवे लाइनें

1642. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में 1962 से लेकर अब तक गुजरात राज्य में कितनी नई रेलवे लाइनें स्थापित करने के बारे में सर्वेक्षण किया गया और उन्हें प्रायोजित किया गया;

(ख) क्या कुछ नई रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य अब भी चल रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) रेलवे बोर्ड द्वारा गुजरात में निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी और वर्ष 1962 से लेकर ये सर्वेक्षण किए गए:—

1. खोदियार को मिलाने वाली (बड़ी लाइन–10.4 किलोमीटर) नयी रेलवे लाइन के लिए इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण—इससे पता चला है कि यह लाइन अलाभप्रद है।

2. (i) राजकोट—जसदान (मीटर लाइन–61 किलोमीटर)।

   (ii) भावनगर–तारापुर (मीटर लाइन–141 किलोमीटर) का नया यातायात सर्वेक्षण इनका सर्वेक्षण कर लिया गया है और सर्वेक्षण के प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) धन की कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इनमें से किसी लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ होने की सम्भावना नहीं है। फिर भी गुजरात में झुण्ड से न्यू काँडला तक (बड़ी लाइन–231 किलोमीटर) एक नई लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इस लाइन का सर्वेक्षण 1959–60 में किया गया था और इसके निर्माण के लिए मई, 1964 में मंजूरी दी गई थी।

(ग) और (घ) झुण्ड-न्यू काँडला लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है और यह कार्य अक्तूबर, 1969 तक पूरा हो जाने की आशा है।

CALCITE DEPOSITS IN SAUGOR DISTRICT

1643. **Shri Ram Singh Agarwal** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a seven mile long range of calcite deposits, which contains almost cent percent calcite, exists in Saugor District and the biggest glass factory of India can be set up there ; and

(b) if so, whether Government have any proposal to set up a glass factory there and if so, by when it will be possible to do so ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs : **(Shri F. A. Ahmed)** : (a) Government of India have no information ;

(b) No.

आसाम के चाय बागान

1644. **श्री धीरेन्द्र नाथ देब** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पुराने पौधों (बुश) के स्थान पर नए पौधे लगाने के लिये चाय बागानों को वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो आसाम और नीलगिरि पहाड़ियों में विभिन्न चाय बागानों के लिए पृथक-पृथक 1966–67 में कितनी धन-राशि नियत की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पुराने पौधों (बुश) को बदलने के लिये सीधे रूप से कोई वित्तीय अनुदान नहीं दिया जाता। ऐसे बाग जो पुराने पौधों को बदलने का काम आरम्भ करते हैं, वे यदि चाहें तो चाय बोर्ड से बागान वित्त योजना के अन्तर्गत दीर्घावधि ऋण लेकर उसका लाभ उठा सकते हैं। इन बागान को केन्द्रीय आय-कर तथा राज्य कृषि-सम्बन्धी आय-कर के लिये कर योग्य आय की गिनती में पुनः आरोपण की लागत का 30 प्रतिशत विकास भत्ते के रूप में कटौती की छूट दी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात के बदले में मेवों का आयात

1645. **श्री भोला राउत** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 17 मार्च 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1938 तथा 19 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2748 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन दोषी निर्यातकों पर न्यायालय में पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है, उन मुकदमों का क्या परिणाम निकला है, किन-किन दोषी निर्यातकों पर अभी तक मुकदमा चल रहा है और विभिन्न दोषी निर्यातकों के विरुद्ध न्यायालयों में कब-कब मुकदमे दायर किए गए थे;

(ख) किन-किन दोषी निर्यातकों पर अभी मुकदमा चलाया जाना है और वे मुकदमें कब चलाये जायेंगे तथा अभी तक मुकदमें न चलाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन दोषी निर्यातकों पर मुकदमा नहीं चलाया जायेगा तथा उनपर मुकदमा न चलाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2748 के उत्तर में उल्लिखित किसी भी फर्म पर अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को निम्नलिखित तीन फर्मों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये कहा गया है :

(1) मैसर्स हिडोर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटा।

(2) मैसर्स नाजको वर्लड ट्रेडर्स, बम्बई; और

(3) मैसर्स गोर्धनदास खेमचन्द, बम्बई।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2748 के उत्तर में उल्लिखित शेष फर्मों के विरुद्ध इसलिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जा रहा क्योंकि उनके मामलों में बैंक गारण्टी बाण्डों को जब्त कर लेने और जहाँ आवश्यक समझा गया है, उन्हें निर्यात लाइसेंस आदि देने पर प्रतिबन्ध लगाने की विभागीय कार्यवाही पर्याप्त समझी गई है।

प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, पुडूसेरी

1646. **श्री एस्थोस :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में पालघाट जिले में पूडूसेरी के निकट स्थित सूक्ष्म औजार कारखाना, जिसे चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में शामिल किया गया है, पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहा है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : अगस्त, 1966 में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति के पश्चात् पालघाट जिले में सूक्ष्म यंत्रों के कारखाने की स्थापना में निरन्तर प्रगति हो रही है। तबसे वहाँ एक परियोजना इंजीनियर, सहायक इंजीनियर और डिवीजनल अकाउन्टेन्ट को एक केन्द्रित संगठन बना दिया गया है और पालघाट में निर्माण किए जाने वाले उत्पादों के क्षेत्र में इंजीनियरों को रूस में प्रशिक्षण दिए जाने तथा प्रौद्योगिनीय पूलेपों का शीघ्रता से प्राप्त करने की योजनाएं बना ली गई हैं।

हवी प्लेट्स एन्ड वैसल प्रोजेक्ट

1647. **श्री एस्थोस** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी कि हैवी प्लेट्स एन्ड वैसल्स प्रोजेक्ट को स्थापना के लिए तकनी की दृष्टि से कोचीन सर्वोत्तम स्थान है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार कोचीन स्थित एफ० ए० सी० टी० के प्रेसर वैसल प्रोजेक्ट का विस्तार करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) लोकसभा में 9 जून, 1967 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2119 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) मैसर्स फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स त्रावणकोर, लि० के कोचीन में एक प्रेशर वेसल परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों के यातायात प्रशिक्षणार्थी

1648. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों के यातायात प्रशिक्षणार्थियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में उन्हें संसद सदस्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) जी हाँ।

(ख) किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया जिसका आरोप ज्ञापन में लगाया गया था और माननीय सदस्य को व्योरेवार उत्तर भेज दिया गया है जिसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

खाद्य तेल का आयात

1649. **श्री पार्थसारथी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिवर्ष कितना खाद्य तेल आयात किया जाता है; और

(ख) सरकार का इस वर्ष कितना खाद्य तेल आयात करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) पिछले तीन वर्षों में आयात किए गए खाद्य तेल की मात्रा निम्नलिखित है:—

वर्ष	मात्रा (टन)
1964–65	10,442
1965–66	56,281
1966–67	47,514

(ख) यह अभी विचाराधीन है।

ट्रैक्टरों का निर्माण

1650. **श्री अमृत नाहटा** : **श्री श्रीचन्द गोयल** :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) अभी नहीं, श्रीमान्। प्रस्ताव पर अब भी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

LOSS TO RAILWAY ON ACCOUNT OF BENGAL BANDH

1651. **Shri R. S. Vidyarthi:** **Shri C. K. Bhattacharyya:**

Shri Shiv Kumar Shastri: **Shri Hem Barua:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the loss incurred by the Railways on account of Bengal Bandh organised on the 24th August 1967 :

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : The loss has been estimated at about thirty **lakhs.**

कोरबा में एल्युमीनियम संयंत्र

1652. **श्री न० कु० साँघी :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

श्री य० अ० प्रसाद : **श्री वेदव्रत बरुआ :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में कोरबा नामक स्थान पर 200,000 टन की क्षमता का एक एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) क्या यह संयंत्र विदेशी सहयोग से स्थापित किया जावेगा और उस फर्म का नाम क्या है और सम्बन्धित देश का नाम क्या है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) भारत सरकार की एक निकाय-भारत एल्यूमीनियम कम्पनी द्वारा कोरबा (मध्य प्रदेश) में एक 200,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला एल्यूमिना प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार ने प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया है। इस एल्यूमिना को एक एल्यूमिनियम धातु में बदलने के लिए एक लाख टन क्षमता का एल्यूमिनियम प्रद्रावक स्थापित करने का विचार है, जिसके साथ साथ कोरबा स्थान पर ही एल्यूमीनियम सेमिस के निर्माण की सुविधा भी होगी। प्रयोजन का यह अंग रूसी अधिकारियों के सहयोग से पूरा किया जाना है। इन्हें परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिये कहा जा रहा है।

(ख) एल्यूमिना प्लांट की अनुमानित लागत 33.5 करोड़ रुपए है जसमें 2.05 करोड़ रुपए नगर बसाने का खर्च भी शामिल है।

(ग) एल्यूमिना प्लांट की स्थापना विदेशी सहयोग से की जा रही है, उसके तकनी की परामर्शदाता मैसर्स चैमीकोम्पलैक्स हैं जो कि हंगरी में सरकार की अपनी एक कम्पनी है।

अयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संस्था

1653. **श्री यज्ञदत्त शर्मा**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संस्था में कितने नियंत्रक हैं;

(ख) उनके वेतन तथा भत्तों पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है;

(ग) क्या माथुर समिति ने आयात तथा निर्यात नियंत्रक का पद समाप्त करने की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हाँ,तो इस समिति की सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह:) (क) 67।

(ख) चालू वर्ष के बजट में की गई व्यवस्था के अनुसार 8.81 लाख रुपए।

(ग) जी, हाँ।

(घ) आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संस्था के समग्र पुनर्गठन के सम्बन्ध में माथुर समिति द्वारा की गई सिफारिशों में नियंत्रक के पद को समाप्त करने की भी एक सिफारिश है, जिसमें और बातों के साथ-साथ उप-मुख्य नियंत्रक और सहायक नियंत्रक के अतिरिक्त पद बनाने की बात भी सम्मिलित है। पुनर्गठन योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और जैसे ही उन्हें अंतिम रूप दे दिया जायेगा, नियंत्रक के पद को समाप्त करने से सम्बन्धित सिफारिश को क्रियान्वित किया जायेगा।

इंजीनियरिंग उद्योगों में मन्दी

1654. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्नलिखित इंजीनियरिंग उद्योगों ने लगभग गत दस महीनों से अपने उत्पादों के मूल्य कम कर दिए हैं:—

उद्योग	जितना मूल्य कम किया गया
इस्पात की ढलाई पर	20 से 45 प्रतिशत
ढांचा निर्माण	20 ,,
ट्रान्सफॉर्मर्स और स्विच गियर्स	20 से 25 ,,
पोइन्ट्स और क्रॉसिंग	30 से 50 ,,
वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स	15 से 30 ,,
औद्योगिक भट्टियाँ	10 से 15 ,,
विद्युत् पूंजीगत सामान	10 से 20 ,,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार मूल्यों में कमी किए जाने के बावजूद इंजीनियरिंग के उपयुक्त सामान की माँग नहीं बढ़ी है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस्पात के मूल्यों में तदनुसार कमी किए बिना पूंजीगत सामान तथा इंजीनियरिंग के सामान के मूल्यों में कमी करने के सुझाव दिए जाने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) भारी बिजली उद्योगों में लगभग 10 से 20 प्रतिशत तक कीमतें कम हो गई हैं। इन उपकरणों की माँग बहुत कुछ स्थिर रही है।

(ग) उत्पादकों को कीमतों में कमी के लिए कोई परामर्श नहीं दिया गया था। कीमतों में अभी आयात लाइसेंस के लिये उदार नीति अपनाये जाने, कुछ कच्चे माल जैसे ताँबा आदि के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी हो जाने और देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने के फलस्वरूप हुई है।

अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्धारित मूल्यों पर वितरण

1655. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1967 के "पैट्रियट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में 27 केन्द्रों में निर्धारित मूल्यों पर अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) वहाँ, कौन-कौन सी वस्तुएँ बेची जायेंगी;

(घ) क्या ये सभी वस्तुएँ देश में उपलब्ध हैं, और

(ङ) क्या ये वस्तुएँ केवल नगरों, शहरों तथा श्रमिक महत्व के क्षेत्रों के लिये ही बेची जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) जी, हाँ। देश में 27 केन्द्रों में निर्धारित मूल्यों पर अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण किए जाने के बारे में जिस योजना का समाचार-पत्रों में उल्लेख किया गया है, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा रही।

M/s. RAYMON ENGINEERING WORKS, CALCUTTA

1656. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Companies belonging to Raymon Engineering Works, Calcutta and the names of the articles manufactured by them ;

(b) the names of the foreign factories and companies with whose collaboration the owners of the above mentioned firm are doing business in the country and abroad ; and

(c) the amount of foreign exchange given to this firm during the last 4 years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

टाइल उद्योग

1657. **श्री लोबो प्रभु :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टाइलों की लागत मूल्य पर भी माँग न होने के कारण इस उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) सरकार को ऐसे किसी भी संकट की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

धनबाद स्थित हिन्दुस्तान जिंक फैक्टरी में हड़ताल

1658. **श्री नायनार :** **श्री एस्थोस :**

श्री अब्राहम : **श्री सत्य नारायण सिंह :**

श्री उमानाथ :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टुन्डू धनबाद स्थित हिन्दुस्तान जस्ता कारखाने के कर्मचारियों ने 15 अक्तूबर, 1967 को हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या थीं ; और

(ग) सरकार ने इस विवाद को निपाटाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) :

(क) हाँ, महोदय। टुन्डू स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के सीसा प्रद्रावक के कर्मचारी 15 से 18 अक्टूबर 1967 तक हड़ताल पर रहे।

(ख) कर्मचारियों की माँग थी कि उन्हें 1965–66 लेखा वर्ष के लिए उनके पहले प्रबन्धक मैसर्ज मैटल कारपोरेशन आफ इन्डिया के बीच हुए दीर्घ अवधि समझौता दिनाँक 29–11–60 की शर्तों के अनुसार बोनस दिया जाए ताकि पेमेंट आफ बोनस एक्ट 1965 के अनुसार उन्होंने 1966–67 वर्ष के लिए भी बोनस की माँग की।

(ग) 1965–66 वर्ष के देय बोनस का प्रश्न हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रबन्धकों तथा टुन्डू श्रमिक संघ ने मिलाकर एक ट्रिव्यूनल को मध्यस्थ फैसले के लिए निदेशित किया था। ट्रिव्यूनल के फैसलों के विरुद्ध हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होने तक कम्पनी के प्रबन्धकों ने 4 प्रतिशत मासिक वेतन का भाग अनुग्रहीत तथा एक माह की राशि अग्रिम वेतन के रूप में देना स्वीकार किया है, जिसका हिसाब बाद में 1965–66 के लिए दिए जाने वाले बोनस में लगा लिया जाएगा।

इसी प्रकार वेतन का 4 प्रतिशत बोनस अनुग्रहीत दे दिया गया है जिसे कि 1966-67 को दिए जाने वाले भत्ते में लगा लिया जाएगा।

केलों का निर्यात

1659. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्त के अन्तर्गत भूमि के हिसाब से केलों के निर्यात से काफी तथा चाय की तुलना में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है; और

(ख) यदि हाँ,तो इसकी काश्त को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारशों का क्रियान्वित किया जाना

1660. **श्री देवेन सेन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) ने गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) हिन्दुस्तान केबल्स लि० वेतन तथा भत्ते के मामले में सरकारी नियमों का पालन नहीं करती और इन मामलों में कम्पनी अपने नियमानुसार तथा इंजीनियरी उद्योगों के लिए केन्द्रीय मज़दूरी मण्डल की सिफारिशों के अनुसार कार्य करेगी। अतः गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर

1661. **श्री विश्वम्भरन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 सितम्बर, 1967 को पुलिस और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस झगड़े के क्या कारण थे; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जाँच की गई थी।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्यमंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जब हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के कर्मचारियों ने हिंसा अपनाई और पुलिस पर पत्थर आदि फेंके तो पुलिस ने लाठी चार्ज का सहारा लिया और आँसू गैस के 14 गोले छोड़े।

(ख) कर्मचारियों द्वारा यह हिंसात्मक प्रदर्शन उनकी 20 प्रतिशत लाभांश दिए जाने की माँग के समर्थन में किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

विदेशी विनियोजन

1662. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विदेशी विनियोजन और सहयोग के सम्बन्ध में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिये एक उच्च स्तरीय विनियोजन बोर्ड स्थापित करने के हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

विदेशी विनियोजन बोर्ड की स्थापना करने के प्रस्ताव के ब्योरों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

सस्ते कपड़े का मूल्य

1663. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व कपड़े के उत्पादन पर कानूनी नियंत्रण लागू किए जाने के बाद राजधानी में सस्ते कपड़े के दाम लगभग 60 प्रतिशत बढ़ गए हैं;

(ख) क्या इसका कारण सस्ते कपड़ों की इन किस्मों पर सरकार द्वारा लाभ का अंश निर्धारित न किया जाना है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जहाँ तक सरकार को पता है ऐसा नहीं हुआ है ?

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निर्यात बढ़ाने के लिए संगणक

1664. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी ब्यूरो आफ सेन्सस के डा० जे० एडवर्ड एली ने यह सिफारिश की है कि आँकड़ें एकत्र करने, कदाचारों का पता लगाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी व्यापार से सम्बन्धित केन्द्रीय विभागों में एकीकृत इलेक्ट्रोनिक संगणक व्यवस्था अपनायी जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसके प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या स्वचालित यंत्रों का विरोध करने वाली समिति के अध्यक्ष (कनवेनर) ने इन संगणकों को काम में लाये जाने के प्रति विरोध प्रकट किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) स्वचालित यंत्रों के विरोध में किसी समिति के अस्तित्व का सरकार को पता नहीं है, अतः इसके संयोजक (कनवेनर) द्वारा संगणकों को लगाने के विरोध का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कृष्णा और गंटूर जिलों में कपास का उत्पादन

1665. **श्री राममूर्ति :** **श्री उमानाथ :**

श्री नम्बियार

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1967 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गंटूर जिलों में पैदा की गई बढ़िया किस्म की 30,000 क्विंटल कपास बेची नहीं जा सकी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में हल ढूंढ़ने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) कपास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने से नियंत्रण को हटाने तथा निर्धारित अत्यधिक मूल्य को हटाये जाने से जमा हुए अत्यधिक भण्डार उत्पादकों के लिये आकर्षित मूल्यों पर बिक गये हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप यह आशा है कि भविष्य में भी भण्डार जमा नहीं होंगे।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अंश

1666. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री चक्रपाणि :**

श्री नम्बियार : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट दोनों को मिलाकर सरकार ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के 40 प्रतिशत अंश खरीद रखे हैं;

(ख) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन पर सरकार अपना नियंत्रण किस प्रकार कड़ा करना चाहती है;

(ग) क्या सरकार भद्री के राजा को ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या भद्री के राजा को कम्पनी के प्रबन्ध का अनुभव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) सरकार, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट के ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में 39.50 प्रतिशत इक्विटी सहभाग हैं।

(ख) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का प्रबन्ध निदेशक मंडल के निदेशन एवं नियंत्रणाधीन है, उसका संयोजन एवं उसमें समय-समय पर परिवर्तन, केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित होते हैं।

(ग) नहीं श्रीमान्।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास

1667. **श्री समर गुह :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले आठ महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त अवधि में नए उद्योगों के विकास, वर्तमान उद्योगों में विस्तार तथा पुराने उद्योगों में नए सिरे से विनियोजन करने के बारे में पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है; और

(ग) क्या सरकार इससे सम्बन्धित आवश्यक आँकड़े सभा-पटल पर रखेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

मोटरकार किस्म जाँच समिति का प्रतिवेदन

1668. **श्री दी ०चं० शर्मा : डा० प० मंडल :**

श्री सम्बन्धन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाद कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोटर कार किस्म जाँच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) समिति को निर्माताओं, विक्रेताओं, जनता और सरकारी विभागों इत्यादि से बहुत से आँकड़े इकट्ठे करने पड़े। उसको कार बनाने वाले और कुछ आवश्यक सहायक सामान बनाने वालों कारखानों को देखने भी जाना पड़ा था। समिति को कुछ विशेष अध्ययन भी करना पड़ा। इन्हीं कारणों से समिति ने माँग की और समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 नवम्बर 1967 तक के लिये समय की अवधि बढ़ा दी गई है।

रेलवे तथा इस्पात कारखानों को सप्लाई किए गए कोयले की कीमत

1669. **श्री दी० चं० शर्मा : श्री विश्वनाथ मेनन :**

श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग ने अपने आप रेलवे और सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को दिए जाने वाले कोयले का मूल्य बढ़ा दिया है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने और रेलवे अधिक मूल्य देने के लिए तैयार नहीं हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उचित मूल्य तय करने के लिये क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने और रेलों जैसी अत्यावश्यक सेवाओं के काम को अव्यस्थित होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (ग) कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार होने तथा सरकार का कोयले की कीमतों पर से नियन्त्रण हट जाने के कारण कोयला उद्योग ने विभिन्न श्रेणी के कोयले की कीमतों में 1-9-1967 से औसतन 7.08 रुपये प्रति टन की वृद्धि की घोषणा की। रेलवे इस्पात प्लांटों और कोयला उद्योग के बीच कीमत की वृद्धि के विषय में कोई समझौता नहीं हुआ।

लम्बी बातचीत के बाद सहमति हुई कि 1–9–67 से बंगाल/बिहार कोयला में 5 रुपये प्रति टन, मध्य प्रदेश कोयले में 4 रुपये प्रति टन तथा आन्ध्र प्रदेश कोयले में 5.23 रुपये प्रति टन के हिसाब से कोयले की कीमत में बढ़ती की जाए।

(घ) सरकारी क्षेत्र की कोयला उत्पादन करने वाली निकायें निःसन्देह कोयले के मूल्य में मनमानी बढ़ती को रोकेंगे। इसके अतिरिक्त रेलें तथा इस्पात प्लांट बड़े उपभोक्ता होने के कारण कोयले की कीमतों के स्तर को स्थिर रखने में काफी प्रभाव रखेंगी।

नए उद्योगों की लागत तथा मूल्य व्यवस्था

1670. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री कामेश्वर सिंह :**

श्री एस० एम० जोशी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क (टैरिफ) आयोग की कार्यप्रणाली सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये गये नये उद्योगों की लागत तथा मूल्य व्यवस्था के बारे में जाँच की जाये,;

(ख) क्या इस सिफारिश पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा इस सिफारिश पर सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

TEACHERS IN RAILWAY SCHOOLS

1671. **Shri Satya Narain Singh**. Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the rules prescribed for the promotion of teachers of educational institutions run by Railways ;

(b) whether highly qualified teachers in primary schools are eligible for promotion to Higher Secondary Schools ;

(c) whether qualified teachers in primary schools experience any difficulty in their promotion to Higher Secondary Schools due to the direct recruitment of teachers in the latter schools ; and

(d) if so, the steps taken by the Railways to remove their difficulties ?

The Minister of Railways (**Shri C. M. Poonacha**) : (a) Rules governing recruitment and promotion of teachers in railway schools are contained in various letters issued by the Railway Ministry from time to time.

(b) Yes, primary school teachers possessing the requisite qualifications prescribed for higher grade posts are eligible for promotion to those posts.

(c) No.

(d) Does not arise.

हैवी इंजीनियरिंग राँची के अध्यक्ष

1672. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री भगवान दास :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राँची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष ने इस वर्ष अक्तूबर के पहले सप्ताह में त्यागपत्र दे दिया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) श्री डी० आर० गुप्त, अध्यक्ष हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने 19 सितम्बर, 1967 को अपना त्याग पत्र दे दिया था।

(ख) उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें अपने कार्य पर अधिक समय और ध्यान देना होगा तथा पश्चिम बंगाल में श्रमिकों की समस्या / इंजीनियरी उद्योग में सामान्य मंदी आदि बातों को ध्यान में रखते हुए वह हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कार्य में यथोचित समय नहीं दे सकेंगे।

पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यकार्यालयों में संगणकों के प्रयोग के विरुद्ध प्रदर्शन

1673. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री उमानाथ :**

श्री नम्बियार : **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों ने संगणकों के प्रयोग के विरुद्ध पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य कार्यालयों तथा रेलवे के अन्य कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हाँ,

(ख) रेलवे के कार्यालयों में संगणक लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव को समाप्त करने की मांग की गई थी;

(ग) प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संगठित मजदूरों को संगणकों से होने वाले लाभ तथा कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिये की गई कार्यवाही के बारे में बताया गया है।

मिट्टी के बर्तनों की कला के विकास का केन्द्र

1674. **श्री तुलशीदास जाधव :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

श्री हरदयाल देवगुण : **श्री राजदेव सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड ने मिट्टी के बर्तनों की कला के विकास के अपने केन्द्र को बम्बई से बंगलौर में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार ने उक्त केन्द्र को मिट्टी के बर्तनों की हस्तकला के संवर्धन संबंधी बढ़ती हुई गतिविधियों के लिये गोरगाँव में अपना वर्क शैड देने सहित सभी सम्भव सुविधायें दी हैं;

(घ) क्या बोर्ड ने इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य सरकार के विचारों का पता किया है और यदि हाँ, तो उसके बारे में बोर्ड की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या बोर्ड ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि केन्द्र के बंगलौर में स्थानान्तरण से बम्बई के कुम्हारों के बड़े समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बम्बई में मिट्टी के बर्तनों के विकास के लिये कोई और संस्था नहीं है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) हस्तकला बोर्ड ने मिट्टी के बर्तनों के बनाने की कला के विकास केन्द्र को बम्बई से बंगलौर स्थानान्तरण करने के लिये हाल ही में सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड ने यह प्रस्ताव इस कारण दिया है कि बंगलौर के केन्द्रीय हस्तकला विकास केन्द्र में सिरामिक के लिये एक सुसज्जित वैधशाला है जो कि बम्बई में नहीं है। दूसरे बम्बई केन्द्र का पर्यवेक्षण बंगलोर वैधशाला के भारसाधक के अधीन काम करने वाले एक सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। अतः बम्बई केन्द्र को बंगलौर स्थानान्तरित करने से इसमें अधिक कुशलता से काम होगा और मितव्ययिता भी होगी।

(ग) से (ङ) इससे पूर्व कि सरकार इस मामले में कोई निर्णय करे, इन प्रश्नों के प्रति उल्लिखित बातों पर विचार किया जायेगा।

निर्यात सार्थसंघ

1675. **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1967 के 'स्टेटसमैन' में तीन निर्यात सार्थ-संघ स्थापित किये जायेंगे' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस व्यवस्था के द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्यात तथा आयात किया जायेगा; और

(ग) भारत को इससे क्या लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): अभी तक दो सार्थ-संघ एक ए०ए०सी०/ए०सी०एस०आर० तथा दूसरा बिजली की तारों के लिये स्थापित किये गये हैं। सब स्टेशन उपकरणों के लिये अभी तक तीसरा सार्थ-संघ स्थापित नहीं किया गया है परन्तु इराक तथा सुडान में परियोजना के लिये सब-स्टेशन उपकरण के लिये विशिष्ट सार्थसंघ स्थापित किये गये हैं।

(ख) ये सभी सार्थ-संघ निर्यात सार्थ-संघ हैं और ये केवल निर्यात ही करेंगे न कि आयात। भाग (क) में उल्लिखित सार्थ-संघ एल्यूमिनियम कंडक्टर तथा पावर केबलों का निर्यात करेंगे।

(ग) (i) सप्लाई और सेवायों का समन्वय (ii) विकास कर रहे कुछ देशों में डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग निर्माण तथा स्थापित करने की सुविधायें उपलब्ध नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप विदेशों में समूची परियोजना के उनको ठेके दिये जाते हैं। इससे पूर्व ऐसे पैकेज ठेके विदेशी फर्मों को दिये जाते थे। भारतीय निर्माताओं, डिजाइन, निर्माण तथा संस्थापन इंजीनियरों के सार्थ-संघ बन

जाने से अपनी इंजीनियरी की वस्तुओं के निर्यात को बड़े पैमाने पर बढ़ाने और (iii) भारतीय फर्मों की आपसी स्पर्धा रुक जायेगी । क्योंकि भाग (ख) में उल्लिखित वस्तुओं के मूल्य केवल एक फर्म ही देगी ।

INDIA-YUGOSLAVIA-U.A.R. MEETING

1676. **Shri Bibhuti Mishra:** **Dr. Ranen Sen:**

Shri Marandi:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to the news-item published in the 'Patriot' dated the 20th August, 1967 under the caption "India-Yugoslavia-U.A.R. Group to meet on August 21-3 Nation collaboration" ;

(b) if so, the topics discussed in the said meeting in regard to collaboration amongst the said countries ; and

(c) the extent to which India would benefit as a result of the said discussion ?

The Minister of Commerce (**Shri Dinesh Singh**) : (a) Yes, Sir.

(b) The topics considered at the meeting were :

(i) identifying industries where Tripartite collaboration could be pursued to the mutual advantage of the three countries, (ii) examining the broad pattern of industrial cooperation and laying down conditions that would help in achieving fruitful and beneficial results.

(c) While accelerating the pace of industrialisation the industrial cooperation between the three countries would help in the export of manufactured goods including machinery from India.

LOSS IN SALT PRODUCTION IN THANA DISTRICT

1677. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that salt worth nearly five lakh of rupees was destroyed due to recent rains in the salt producing areas of Thana District ;

(b) whether it is also a fact that this salt was meant for export ;

(c) whether this loss occurred due to non-availability of railway wagons ; and

(d) if so, whether any action has been taken against the persons responsible for this lapse ?

The Minister of Commerce (**Shri Dinesh Singh**) : (a) to (c). No, Sir.

(d) Does not arise.

HEAVY ELECTRICAL PLANT NEAR HARDWAR

1678. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri Shiv Kumar Shastri:**

Shri Ramji Ram: **Dr. Surya Prakash Puri :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made in the construction of the Heavy Electricals Plant near Hardwar ;

(b) the time by which the construction of this plant would be completed ; and

(c) whether some progress has also been made in the production in this plant ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b) : The scheduled dates of completion of different items of work and the cumulative progress as on 30th September, 1967 is as under :

I. Civil Works	*Due date of completion*	*Cumulative progress*
(a) site development	completed in June, 1964	100%
(b) factory building excluding machine foundations	March, 1968	68%
(c) External services :		
(1) Roads and Railways	December, 1968	72%
(2) Water installations	December, 1967	96%
(3) Power installations	December, 1968	15%
(4) Sewerage	March, 1971	95%
(5) Storm water drainage	December, 1967	90%
II. Plant and Equipment		
(a) Shipment of machinery from USSR	June, 1969 (all machines other than unique machines)	
	December, 1969	(Unique machines)
(b) Machinery installed	December, 1969	(All machines other than unique machines)
	June, 1970	(Unique machines)

(c) Up to end of Octobr, 1967, 60 flame proof motors ranging in capacities from 66 K. W. to 140 K. W. were manufactured.

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की जापान यात्रा

1679. **श्री हेमराज :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधि मण्डल ने हाल ही में जापान का दौरा किया था :

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) औद्योगिक विकास के लिये जापान से अधिक सहयोग और सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) और (ख) एक गैर सरकारी निकाय भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ द्वारा अपने अध्यक्ष श्री एल० एन० विड़ला की अध्यक्षता में भेजे गये एक प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्य रूप से भारत में भारत-जापान व्यापार सहकारिता समिति और जापान में जापान-भारत व्यापार सहकारिता समिति की संयुक्त बैठक में भाग लेने और दोनों देशों के बीच व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र में अधिक आर्थिक सहायता तथा सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये सितम्बर 1967 में जापान का दौरा किया था। संघ द्वारा प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की प्रतियों को भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों को भेजा गया है।

(ग) प्रतिवेदन की प्रतियों को पार्लियामेंट पुस्तकालय में रखा गया है।

सरकारी उपक्रमों का विस्तार

1680. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री महाराज सिंह भारती :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की क्षमता बढ़ाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

लाइसेंस देने की नीति के सम्बन्ध में डा० हजारी का प्रतिवेदन

1681. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस नीति के बारे में डा० हजारी का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) तथा (ख) औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस नीति पर अन्तिम रिपोर्ट डा० हजारी द्वारा पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

दिल्ली एक शुष्क पत्तन के रूप में

1682. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री क० हाल्दर :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को एक शुष्क पत्तन घोषित करना सरकार ने स्वीकार किया है;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली को एक शुष्क पत्तन घोषित किये जाने के लिये दिल्ली की जनता और दिल्ली प्रशासन की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो अपने ज्ञापन में उन्होंने इस मांग के समर्थन में क्या मुख्य कारण दिये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) से (ग) दिल्ली को शुष्क पत्तन बनाने संबंधी प्रस्ताव पर दिल्ली प्रशासन के परामर्श से विचार किया जा रहा है ? व्यापारियों से प्राप्त अभ्यावेदन / सुझाव मुख्य रूप से इस दृष्टि से दिये गये हैं कि वे माल भरने की बन्दरगाह के बजाये दिल्ली तथा इसके आस पास सीमा शुल्क की औपचारिकताओं को पूरा कर सकें।

अप्रयुक्त माल डिब्बे

1683. **श्री कंवर लाल गुप्त** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े बुकिंग केन्द्रों पर भी बहुत से व्यापरियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय पर माल डिब्बे नहीं मिलते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस शिकायत की कोई जाँच की है;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से माल डिब्बे बेकार पड़े हुए हैं और यदि हाँ, तो कितने; और

(घ) माल डिब्बों की फालतू क्षमता को प्रयोग करने के लिये व्यापारियों और उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) अक्तूबर 1967 के अन्त तक बड़ी लाइनों पर केवल 8028 माल डिब्बों के इन्डैन्टों का और मीटरगेज लाइनों पर 10168 माल डिब्बों के इन्डैन्टों का निपटान किया जाना था। जो रेलों के माल भरने की बड़ी मुश्किल से एक दिन की क्षमता है।

(ग) जी हाँ। जुलाई 1967 से अक्तूबर 1967 के दौरान यातायात के अभाव के कारण भारतीय रेलों के बेकार पड़े माल डिब्बों की दैनिक औसत निम्नलिखित है :

माल	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
जुलाई, 67	677	1636
अगस्त, 67	4158	3311
सितम्बर, 67	12439	5478
अक्तूबर, 67	11617	3654

(घ) जब कभी परिवहन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता तब वाणिज्य व्यापार तथा उद्योग संघ से इसका पूरा उपयोग करने के लिये बातचीत की जाती है। नये यातायात का विकास करने या ग्राहकों को अच्छी सवायें उपलब्ध करने की दृष्टि से रेल का उपयोग करने वालों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाने के लिये रेलों में विपणन तथा बिक्री संगठन स्थापित भी किये गये हैं।

EXPORT OF GRAMOPHONE RECORDS

1684. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India exported gramophone records worth nearly Rs. 40 lakh during 1967-68 to Hong Kong, Malayasia and U.S.A. ;

(b) whether it is also a fact that the demand of gramophone records in these countries far exceeds the production and due to less production, these cannot be exported in larger number ;

(c) whether Government propose to take some concrete steps in order to boost their production ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir ; exports of gramophone records during April to August, 1967 to Hong Kong, Malaysis and U. S. A. account for Rs. 1.79 lakhs, 5.69 lakhs and 0.54 lakhs respectively ;

(b) There is no report about insufficient production to meet overseas demand.

(c) and (d) : Do not arise.

MANUFACTURE OF PIG IRON AT KATNI

1685. **Shri Ram Avtar Sharma:** **Shri G. C. Dixit :**

Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3407 on the 23rd June, 1967 regarding the manufacture of 300,000 tonnes of pig iron from iron ore at Katni and state the present position of the proposal ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : Keeping in view the present and prospective availability of pig iron and the anticipated demand by 1970-71, there is no scope at present for licensing any fresh capacity.

बिनौले का जहाज पर निःशुल्क मूल्य

1686. **श्री रामावतार शर्मा:** **श्री नाथूराम अहिरवार:**

श्री गं० चं० दीक्षित: **श्री लाखन लाल गुप्त:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें विदेशी विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर अथवा विदेशी ग्राहकों की संतोषजनक रिपोर्ट के आधार पर बिनौले के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के लिये आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने के लिये आल इन्डिया सीड क्रशर्स एसोसिएशन को निदेश दिये जाने के लिये सरकार की सहायता माँगी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (मुहम्मद शफी कुरैशी):

(क) जी हाँ ।

(ख) सरकार द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है।

बस्तर में कागज तथा लुग्दी कारखाना

1687. **श्री रामावतार शर्मा:** **श्री गं० च० दीक्षित:**

श्री नाथूराम अहिरवार:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर में कागज और लुग्दी कारखाना स्थापित करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, जिस पर इस समय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

नाखेड़-अमरावती रेलवे लाइन

1688. **डा० अ० ग० सोनार:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे की नाखेड़–अमरावती रेलवे लाइन का प्रारम्भिक सर्वेक्षण काफी समय पहिले पूरा हो गया था;

(ख) क्या अब इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(घ) क्या इस लाइन को चौथी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है; यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाइयाँ हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) से (घ) इस रेलवे लाइन के लिये (बड़ी लाइन के रूप में) 1946 में यातायात सर्वेक्षण किया गया था और प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण 1946–47 में किया गया था। यह परियोजना लाभदायक नहीं थी इसलिये शेष भाग का इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया था। साधनों की कठिन स्थिति को देखते हुए इस लाइन के निर्माण कार्य को चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल किये गये जाने के बहुत कम अवसर हैं।

हवादार माल डिब्बे

1689. **डा० अ० ग० सोनार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फसल के दौरान संतरों का परिवहन करने के लिये मध्य रेलवे के कलमेश्वर, कोहली, नाखेड़, पाढ़हना, कटोला तथा मुलताई स्टेशनों पर हवादार माल डिब्बों की बहुत कमी होती है;

(ख) क्या मुलताई रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से मरशी तहसील के सभी संतरों का निर्यात किया जाता है, प्रतिदिन कम से कम 16 हवादार माल डिब्बों की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है; और

(ग) उक्त स्टेशनों पर पिछले वर्ष कितने हवादार माल डिब्बे दिये गये थे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) नहीं। मध्य रेलवे के कलमेश्वर, कोहली नाखेड़, पाढ़सनाँ, कटोल और मलताई स्टेशनों पर यात्रियों के लिये उपयुक्त ढके हुए माल डिब्बे सप्लाई करने की माँग की गई थी और माँग के अनुसार ढके हुए माल डिब्बे सप्लाई किये गये हैं।

(ख) मुलताई स्टेशन पर संतरे लाने के लिये आगामी मौसम के दौरान माँग के अनुसार उपलब्ध हवादार माल डिब्बों सहित ढके माल डिब्बे सप्लाई किये जायेंगे।

(ग) गत मौसमों (अम्बिका और भरीज में) कलमेश्वर, कोहली, नाखेड़, पाढ़े सवा, कठोल और मुलताई स्टेशनों पर संतरे भरने के लिये हवादार माल डिब्बों सहित कुल 3,033 माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे। संतरे भरने के लिये ढके हुए माल डिब्बों की माँग की गई थी न कि हवादार किस्म के ढके हुए माल डिब्बों के लिये। सप्लाई किये गये ढके हुए माल डिब्बों में एक बड़ी संख्या हवादार किस्म के ढेके हुए माल डिब्बों की थी। सप्लाई किये गये दोनों किस्म की ठीक संख्या का पता नहीं है।

गाड़ियों का न चलाया जाना

1690. **श्री रामानी :** **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

श्री म० ला० सोंधो : **श्री ज्योतर्मय बसु :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी खानों के मालिकों के रेलवे को कोयला न देने के निर्णय के कारण कुछ यात्री गाड़ियों तथा माल गाड़ियों को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी गाड़ियों को बन्द किया गया है; और

(घ) इन गाड़ियों को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) जी हाँ, 7.9.67 से 14.9.67 तक कुछ गाड़ियों को बन्द कर दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रतिदिन बन्द की गई गाड़ियों की संख्या अलग-अलग है परन्तु उसकी औसत 615 यात्री गाड़ियाँ हैं।

(घ) कोयला व्यापार की संयुक्त कार्यकारी समिति के साथ लम्बी बातचीत के पश्चात् समझौता हुआ है और गैर-सरकारी कोयला खानों द्वारा कोयला पुनः सप्लाई किये जाने के फलस्वरूप बन्द की गई अधिकांश गाड़ियाँ पुनः चालू कर दी गई थीं ।

मरहरा वाहनान्तर (ट्रांशिपमेंट) यार्ड के कर्मचारियों की हड़ताल

1691. **श्री रामानी:** **श्री भगवानदास:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मरहरा वाहनान्तर यार्ड के कर्मचारी 7 सितम्बर 1967 से हड़ताल पर हैं,

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या थीं;

(ग) कितने माल डिब्बे रुके पड़े हैं;

(घ) हड़ताल के कारण उत्तरी बिहार को खाद्यान्न भेजने पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) झगड़े के निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) जी हाँ, परन्तु उन्होंनें 11.9.67 को पुनः काम शुरू कर दिया था ।

(ख) कर्मचारियों की हैंडलिंग ठेकेदार को तुरन्त भुगतान करने की माँग थी;

(एक) औद्योगिक न्यायाधिकरण, बिहार द्वारा दिये गये अन्तरिम पंचाट के अनुसार उनकी मजूरी में 10 प्रतिशत वृद्धि; और

(दो) बोनस ।

(ग) 8.9.67 से 10.9.67 से बड़ी लाइन पर 754 और मीटर लाइन पर 651 माल डिब्बे रुक गये थे।

(घ) बड़ी लाइन पर खाद्यान्न के 254 माल डिब्बे रुक गये थे;

(ङ) कर्मचारियों और हैडलिंग ठेकेदारों के झगड़े को बिहार सरकार द्वारा न्याय निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण, बिहार, पटना को सौंपा गया और इस पर अभी निर्णय किया जाना है।

जयपुर के लिए बुक किए गए माल डिब्बों का लापता होना

1692. **श्री रमानी:** **श्री भगवान दास:**

श्री ओंकार लाल बेरवा:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर के लिये बुक किये गये चीनी के माल डिब्बे लापता हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कब से;

(ग) ऐसे कितने माल-डिब्बे हैं तथा उनमें कितनी चीनी थी;

(घ) माल डिब्बे कब और किस स्थान से बुक किये गये थे; और

(ङ) इन माल-डिब्बों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ) माननीय सदस्य के संकेत शायद उन कुछ माल डिब्बों की ओर हैं जिनमें गोला गोकरन नाथ (पूर्वोत्तर रेलवे में) से चीनी लादी गई थी और जयपुर के लिये रवाना किये गये थे। सितम्बर अक्तूबर में काफी लम्बी बारिश के कारण पश्चिम रेलवे में अचनेरा तथा भरतपुर के बीच लाइनें खराब हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप, इन माल-डिब्बों को छोटी लाइन एवं बड़ी लाइन एवं छोटी लाइन मार्ग से बरेली और भटिन्डा से होकर अथवा हिसार या दिल्ली सराय रोहिला से होकर भेजना पड़ा था और ऐसी स्थिति में उनमें से कुछ डिब्बों के पहुँचने में वस्तुतः अत्यधिक विलम्ब हो गया था लेकिन सभी डिब्बे गन्तव्य स्थान में पहुँच गये थे।

2. पचास डिब्बों के पहुँचने में अत्यधिक विलम्ब हुआ।

3. बुकिंग की तारीख तथा जयपुर में माल उतारने की तारीख बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **(पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1720/67]**

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार

1693. **श्री रामानी:** **श्री भगवान दास:**

श्री ज्योतिर्मय बसु: **श्री रा० बरुआ:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य को भेजे गये अर्ध-सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने यह पता लगाया था कि दोनों देशों के बीच हुए भारत-संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार करार के अन्तर्गत 25 प्रतिशत व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश है ;

(ख) यदि हाँ, तो जिन वस्तुओं का व्यापार बढ़ाना संभव है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य से और अधिक वस्तुओं का आयात करने में हिचकिचाहट के कारण भारत का संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार नहीं बढ़ रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार संयुक्त अरब गणराज्य से अधिक वस्तुओं के आयात की संभावनाओं का पता लगायेगी; और

(ङ०) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस प्रतिनिधि मंडल को, जिसने यह पता लगाया कि संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार बढ़ाने की काफी गुंजाइश है, भारतीय निर्यात

संगठन फेडरेशन द्वारा प्रायोजित किया गया था तथापि उसमें इस व्यापार करार में निधारित स्तर के अतिरिक्त किसी विशेष प्रतिशतता का कोई उल्लेख नहीं है—अर्थात् कितना प्रतिशत व्यापार बढ़ाया जा सकता है।

(ख) इन वस्तुओं में ट्रक, बसें, मोटर गाड़ियों के फालतू पुर्जे तथा सहायक पुर्जे, इंजीनियरिंग की वस्तुएँ, दवाइयाँ, तथा संयुक्त अरब गणराज्य में औद्योगिक कारखानों के लिये पुर्जे तथा फालतू पुर्जे शामिल हैं।

(ग) और (घ) यह सुझाव कि भारत द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य से और अधिक वस्तुओं का आयात करने में हिचकिचाहट के कारण भारत का संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार नहीं बढ़ रहा है, निराधार है। आयात की जा सकने वाली वस्तुओं पर विचार करते समय स्वभावतः भारतीय अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है।

(ङ०) प्रश्न ही नहीं उठता।

मण्डपम स्टेशन से धनुषकोडी तक रेलवे लाइन

1694. **श्री जगन्नाथराव जोशी:** **श्री शारदानन्द:**

श्री ना० स्व० शर्मा: **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डपम स्टेशन से धनुषकोडी तक रेलवे लाइन बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) और (ख) मण्डपम स्टेशन से आगे पामबन तक पहले ही रेलवे लाइन मौजूद है। पामबन-धनुषकोडी लाइन को जो, दिसम्बर, 1964 में तूफान के समय नष्ट हो गई थी, फिर से बिछाने का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कालमेसरी (केरल) कारखाने का विस्तार

1695. **श्री चक्रपाणि:** **श्रीमती सुशीला गोपालन:**

श्री विश्वनाथ मेनन: **श्री अ० कु० गोपालन:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के मसौदे की रूप रेखा में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कालमेसरी (केरल) स्थित कारखाने के विस्तार की व्यवस्था की गई हैं।

(ख) यदि हाँ, तो इस सयंत्र के विस्तार के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और विस्तार योजना का क्रियान्वयन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ।

(ख) मशीनों की माँग गिर जाने को ध्यान में रखते हुए विस्तार योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है इसलिए अभी कोई धन राशि स्वीकृत नहीं की गई है। कुछ और समय तक माँग की प्रवृत्ति को देखते हुए योजना की पुनः जाँच की जायेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में हड़ताल के कारण उद्योगों को हुई हानि

1696. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 अगस्त, 1967 को पश्चिम बंगाल में शासक दल के तत्वाधान में हुई हड़ताल के कारण उद्योगों की आय तथा उत्पादन में कोई हानि हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो वह कैसे तथा कितनी हुई थी?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ।

(ख) अभी पता नहीं लगाया है।

यूरिया की उत्पादन लागत

1697. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेली लिग्नाइट कारखाने में यूरिया की उत्पादन लागत घटाने की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चन्ना रेड्डी): (क) और (ख) नयवेली लिग्नाइट निगम की यूरिया की उत्पादन लागत को कम करने की सम्भावना पर जाँच की जा रही है। भारत सरकार ने अगस्त, 1967 में उर्वरक प्लाँट के चालन की जाँच के लिये एक विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की थी। नयवेली लिग्नाइट निगम उनकी रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड द्वारा फालतू पुर्जों तथा उपकरणों का निर्माण

1698. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पहले ही प्रयोग में लाये जाने वाले बिजली के उपकरणों के लिये भारत हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड में कल और पुर्जों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में ऐसे स्वदेशी कल-पुर्जों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) सभी राज्यों में विद्युत् बोर्डों को लिख दिया गया है कि वे अपनी फालतू पुर्जों के निर्माण की आवश्यकता का ब्यौरा भारत हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स को भेज दें।

निर्यात-प्रधान कताई मिलें

1699. **श्रीमती सुशीला गोपालन:** **श्री० अ० कु० गोपालन:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार उसके द्वारा चलाई जाने वाली निर्यात-प्रधान कताई मिलें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिये अब तक कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल में एक निर्यात-प्रधान कताई मिल स्थापित करने के बारे में दिसम्बर 1965 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में तीन केन्द्र प्रायोजित निर्यात-प्रधान कताई मिल स्थापित करने का विचार है लेकिन इस मामले में अन्तिम निर्णय लेना अभी बाकी है;

(ख) अभी तक कोई राशि नियत नहीं की गई है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में कि इन मिलों को कहाँ-कहाँ स्थापित किया जाये, अन्तिम निर्णय लेते समय इस प्रस्ताव पर उचित रूप से विचार किया जायेगा।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में लौह अयस्क के भण्डार

1700. **श्रीमती सुशीला गोपालन:** **श्री अ० कु० गोपालन:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालीकट जिला (केरल) में लौह-अयस्क के भण्डार के सम्बन्ध में जापानी भूतत्त्व वेत्ताओं की ओर से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया है और यदि हाँ, तो उसपर क्या निर्णय किए गए हैं; और

(घ) इन निर्णयों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) नहीं, महोदय।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

DERAILMENT OF SAURASHTRA MAIL

1701. **Shri Ramji Ram:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the inquiry ordered into the causes of derailment of certain compartments of Saurashtra Mail which left Bombay Central on the 15th August, 1967 has been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The enquiry committee came to the conclusion that the accident was due to failure of mechanical equipment.

(c) Suitable action is being taken against the staff at fault.

STONE-THROWING INCIDENTS ON TRAINS

1702. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the General Manager, Eastern Railway stated at the meeting of the Zonal Railway Users' Consultative Committee that during the last five months, 29 Railway employees were attacked and 16 were injured as a result of stone-throwing incidents;

(b) whether he has given any suggestion to Government to ensure smooth railway traffic;

(c) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Ponacha) (a) Yes.

(b) Yes. The General Manager while pointing out the operational difficulties under these conditions appealed to the committee for creating public opinion against unruly elements resorting to assault on Railwaymen.

(c) and (d). The General Managers, Eastern and South Eastern Railways met the Chief Minister, Deputy Chief Minister, other Ministers and Senior Officials of the West Bengal Government on 12th September 1967 and discussed various aspects of law and order problem affecting train services and attacks on railway staff and property. The West Bengal Government agreed to deal with anti-social and unruly elements who interfere with train operations and attack railway installations etc. deterrently. The General Managers agreed to give publicity to the difficulties in maintaining punctuality of train services and to seek public co-operation.

CAPACITY OF STEEEL PLANTS

1703. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** pleased to state :

(a) which of the plants of the Hindustan Steel Ltd. are working to full installed capacity;

(b) the annual profit earned by them during the last three years and what percentage of the total capital outlay it represents ; and

(c) if these plants have incurred any loss, what measures are being taken to make them profitable concerns ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) During the current financial year the steel plants under Hindustan Steel Ltd. have been generally working below the full installed capacity for a number of reasons including sluggishness in the Iron & Steel market, labour unrest, extensive repair work to the Coke Ovens at Durgapur, some delay in the commissioning of expansion units or their not having achieved the full rated capacity.

(b) A statement indicating the profit/loss made by the Rourkela, Bhilai and Durgapur Steel Plants during 1964-65, 1965-66, 1966-67 and the percentage of return on capital employed is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT-1721/67]**.

मोटर-कारों के लिए अपेक्षित विभिन्न किस्म की धातुओं तथा उत्पादों का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों द्वारा निर्माण

1704. **श्री मृत्युञ्जय प्रसाद** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में केवल लोहे की चादरें ही बनाई जाती हैं और यदि हाँ, तो गार्डरों, फ्लैटों, ऐंगल्स, पटरियों, छड़ों आदि का निर्माण करने की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या रूरकेला में वे सभी किस्म की चादरें बनाई जाती हैं जिनकी मोटर कार बनाने वाली कम्पनियों को जरूरत पड़ती है; और

(ग) विभिन्न किस्म के धातुओं की यथा, इस्पात, लोहा तथा मिश्रित धातु जिनकी स्प्रिंग, कैंची, छुरे, काँटे, उस्तरे, ब्लेड, सर्जरी चाक् आदि बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, विभिन्न किस्म के औजारों तथा फालतू पुर्जों और उन औजारों की जिनकी विमानों, मोटर-कारों तथा कारखानों को जरूरत पड़ती है, माँग हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों द्वारा कहाँ तक पूरी की जा रही है और लोहा, इस्पात तथा धातु के किन-किन किस्मों का विदेशों से आयात किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जब रूरकेला इस्पात कारखाने में 10 लाख धातु-पिंड टन की उत्पादन क्षमता पर आ जायेगी उसमें हैवी प्लेट, हौट रोल्ड स्ट्रिप्स/शीट्स नैरो प्लेट्स कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स/शीट्स, टिन प्लेट्स तथा पाइप का उत्पादन हो सकेगा। जब इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 18 लाख धातु पिंड टन हो जायेगी, तब उसमें नालीदार चादरें, बिजली वाली इस्पात की चादरें भी बनने लगेंगी, दुर्गापुर और भिलाई के इस्पात कारखानों में गर्डर्स, प्लैट्स, एंग्ल्स, रेल, छड़ें आदि भी बनाये जायेंगे। इन कारखानों में बनाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का ब्यौरा इन कारखानों की योजना बनाते समय विभिन्न श्रेणी के इस्पात की वस्तुओं की माँगों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया था और यह बात भी ध्यान में रखी गई थी कि उन्हें किस प्रकार बढ़िया किस्म की बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विस्तारपूर्वक उत्पादन का प्रश्न रूरकेला इस्पात कारखाने की प्रारम्भिक उत्पादन-क्षमता के समय इस्पात की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा तत्सम्बन्धी उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर निश्चित किया गया था। किसी कारखाने की मूलभूत योजना में परिवर्तन किए बिना उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में आमतौर पर फेर-बदल नहीं किया जा सकता जिनका निर्धारण उस कारखाने की योजना बनाते समय अथवा उसका विस्तार करते समय किया गया था।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

REMODELLING OF KALYAN RAILWAY STATION

1705. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the time likely to be taken in remodelling the Kalyan Railway Station on the Central Railway in respect of which an amount of Rs. 11 lakhs was allocated in the Railway Budget for the year 1965-66?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : It is presumed the reference is to the work of "provision of an additional platform, for suburban trains and other minor alterations" appearing in 65-66 budget at an estimated cost of Rs. 12.82 lakhs. Only Rs. 5 lakhs were allotted for this work during 65-66. The work is in progress and is expected to be completed by end of 1968.

ACCIDENT BETWEEN KIRKEE AND SIVAJINAGAR
(CENTRAL RAILWAY)

1706. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an accident took place between Sivajinagar and Kirkee stations (Bombay Division) of the Central Railway on the 23rd October, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that the accident took place because of the dissatisfaction caused among the factory workers and also because of negligence shown towards inordinately delayed complaints lodged by pass-holders ; and

(c) if so, the remedial steps taken by Railway Administration in this matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b) No accident took place but on 23.10.67 T.2 Poona-Talegaon Local had to be detained at Shivajinagar for about 30 minutes due to a signal defect. This apparently enraged some passengers on the train who did not allow the Local to depart for another about 100 minutes. The passengers subsequently also placed obstructions on the track and pelted stones at 310 Up Poona-Bombay Janata Express and at the station building, injuring 3 persons and causing some damage to the coaches and station building.

(c) A special watch is kept on the running of Poona-Talegaon Local and other suburban services and everything feasible is being done to ensure that these services run to time.

लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिये निगम

1707. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं के निर्यात की व्यवस्था करने के लिये सरकार का विचार एक पृथक निगम स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

IMPORT OF ANGORA WOOL

1708. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to stop the import of Angora wool into India ;

(b) if so, the amount of foreign exchange that would be annually saved thereby; and

(c) the names of the places at which wool production centres are proposed to be set up for the production of Angora wool and the details of the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Kureshi) :

(a) and (b) The matter is under consideration.

(c) There is only one unit namely the International Angora Breeding Farm, Kulu (Himachal Pradesh), producing Angora Wool at present.

Railway Parcel Office, Varanasi

1709. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Railawys** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some unauthorised person received delivery of boxes of medicines valued at about Rs. one and a half lakhs from Railway Parcel Office, Varanasi in August, 1967 ;

(b) if so, whether Government have investigated into the matter ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Loss to Durgapur Steel Plant

1710. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri K. Lakkappa** :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the Durgaur Steel Plant has suffered a loss of Rs. 54 crores due to the misappropriation by officers ;

(b) whether the factory has reached a stage of closure as a result of mismanagement ;

(c) whether Suku Sen Committee constituted to investigate into the misappropriation and other embezzlements in the factory has since submitted its report to Government ; and

(d) if so, the salient points of the report and the proposals of Government to run the factory at a profit and the time by which those proposals are likely to be implemented ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy):

(a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) No such Committee was appointed.

Bhilai Steel Plant

1711. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the items manufactured at Bhilai Steel Plant are exported to foreign countries and, if so, the names thereof with quantity exported in each case during the last year ; and

(b) the annual foreign exchange earned by way of export of Bhilai Steel and Steel products?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) Yes, Sir. During the year 1966-67, Bhilai Steel products of the value of Rs. 56.6 million were exported to foreign countries. A country-wise statement showing the exports of Bhilai Steel Plant products during 1966-67 is laid on the Table of the House. [**Placed in Library, See No. LT-1722/67**].

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में मन्दी

1712. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री न० कु० सांधी :**

श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में भारी मन्दी आ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत छः महीनों में कितनी राशि का घाटा हुआ है; और

(ग) इस दिशा में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी हाँ,

(ख) छः मास के अन्दर अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, 1967 तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के उत्पादन में 453 लाख रु० के कुल नुकसान का अनुमान है।

(ग) कम्पनी जटिल मशीनी औजारों गैस आटौमैट, कापीइंग, खरादों, बहुउद्देशीय खरादों आदि बनाने के कार्य को अपने हाथ में लेकर विविध उत्पादन कर रही है। उसकी योजनाएं प्रेस और धातु की चादरें तैयार करने की मशीनें बनाने की भी हैं वह छपाई की मशीनें भी बनाना चाहती है।

कम्पनी ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सुधरी हुई और औजारों वाली मशीनें भी दे रही है।

उसने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये देश भर में विशेष स्थानों में अनेक बिक्री सह सेवा केन्द्र खोले हैं। उसने फैन्कफर्ट (पश्चिमी जर्मनी) और न्यूयार्क (अमेरिका) में बिक्री सह सेवा केन्द्र खोले हैं। मशीनी औजारों के निर्माण के लिए जहाज तक निःशुल्क मूल्य पर नकद उपदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये उपकरणों का आयात

1713. **श्री रा० रा० सिंह देव:** **श्री वेदव्रत बरुआ:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अब भी ऐसे उपकरण तथा अन्य पुर्जे आयात कर रहे हैं जिनका देश में निर्माण किया जा सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य मंडल संघ ने ऐसे कई मामले बताये हैं कि उपकरण भारत में उपलब्ध थे और फिर भी उनकी आयात की अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपचार कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) सामान्यतः आयात का सहारा तब लिया जाता है जब कि देशी उत्पाद अपेक्षित विवरण के अनुकूल नहीं बन पाते या वे नियत अवधि में उपलब्ध नहीं होते। कभी-कभी पुर्जों के आयात की अनुमति विदेशी सहयोगी द्वारा पहले भेजे गए उपकरणों के दूसरे पुर्जों से अनुरूपता बनाए रखने के कारण भी दी जाती है।

(ख) जी, हाँ। फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स तथा इन्डस्ट्री ने तीन ऐसे उदाहरण बताए थे।

(ग) तथा (घ) एक मामले में तो परियोजना के प्रारम्भ में अनुचित विलम्ब को रोकने और विदेशी सहयोगी द्वारा भली प्रकार कार्य करने की गारन्टी देने के संकोच के समाधान के लिए अनुमति दी गई थी। दूसरे मामले में तकनीकी अधिकारियों द्वारा ध्यानपूर्वक जाँच कर लेने तथा सहयोगी

से परामर्श के पश्चात् आयात की अनुमति दी गई थी ताकि पहले से प्राप्त उपकरणों में अनुरूपता रखी जाय। तीसरे मामले में विस्तृत विवरण अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है।

(ङ) सरकार ने हाल में आयातित वस्तुओं की जाँच को और कड़ा कर दिया है ताकि देश की क्षमता का अधिकतम प्रयोग किया जा सके ।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिये नकद सहायता

1714. **श्री रा० रा० सिंह देव:** **श्री मरंडी:**

श्री य० अ० प्रसाद:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं मुख्यतया इंजीनियरी सामान तथा इस्पात के लिये दी जाने वाली नकद सहायता की दर में वृद्धि करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ?

भारतीय रेलवे को वित्तीय सहायता के बारे में पश्चिम जर्मनी के साथ बातचीत

1715. **श्री रा० रा० सिंह देव:** **श्री मयावन:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर सितम्बर, 1967 में भारत सरकार और पश्चिम जर्मनी की सरकार के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, हाँ।

(ख) कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राज्य व्यापार निगमके पास ऊन के स्टाक का इकट्ठा होना

1716. **श्री हेमराज:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार निगम के पास ऊन का स्टाक इकट्ठा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मात्रा और मूल्य कितना है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार तथा आस्ट्रेलिया की सरकार के बीच हुए एक करार के अनुसार, ऊनी वस्तुओं के निर्यातकों को अग्रिम ऋण देने के लिए एक कच्चा ऊन निकाय बनाने के हेतु कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलियन सरकार 40 लाख

पौंड लच्छेदार (ग्रीज) ऊन की सप्लाई करने के लिये राजी हुई है। नवम्बर 1966 से लेकर अगस्त, 1967 तक की अवधि में राज्य व्यापार निगम ने, जो इस निकाय का संचालन कर रहा है; 92.93 लाख रुपए मूल्य की 16.26 लाख पौंड ऊन का आयात किया। निर्यात करने वाली फर्मों को 14.95 लाख रुपए मूल्य की कच्ची ऊन दी जा चुकी है, राज्य व्यापार निगम ने और ऊन देने के प्रश्न पर उद्योग के साथ विचार विमर्श किया था और आशा है कि यह उद्योग जल्दी ही इस समूची मात्रा को ले लेगा।

हरयाना, दिल्ली और पंजाब के लिये माल-डिब्बे

1717. **श्री हेमराज :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरयाना, दिल्ली तथा पंजाब के औद्योगिक नगरों को जाने वाले रेलवे माल-डिब्बों में से अधिकांश इस समय यार्डों में रुके पड़े हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे समय-सारिणी

1718. **श्री हेमराज :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्दियों के लिए रेलवे के नए समय अक्तूबर, 1967 से लागू हो गए हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे की समय-सारिणी 17 अक्तूबर, 1967 तक उत्तर रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध नहीं थी?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) जी, नहीं। उत्तर रेलवे के अंग्रेजी तथा हिन्दी समय सारिणियों की बिक्री क्रमशः 23 तथा 27 सितम्बर, 1967 से आरम्भ हुई और 17 अक्तूबर, 1967 तक उसकी कापियाँ निश्चित संख्या में स्टेशनों को भेजी गई थीं।

खानों के लिए रायल्टी की दरें

1719. **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 अक्तूबर, 1967 को श्रीनगर मे हुई एक बैठक में अखिल भारतीय खनिज सलाहकार बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया था कि भविष्य में खानों की रायल्टी की दरें खान द्वार मूल्य की प्रतिशतता के बजाये खानभार के आधार पर निश्चित की जानी चाहिये।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) बोर्ड ने और क्या-क्या निर्णय लिये हैं और क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) खनिज सलाहकार मण्डल ने श्रीनगर में 26 और 27 सितम्बर, 1967 को हुई अपनी चौदहवीं बैठक में और बातों के अलावा सिफारिश की कि स्वामित्व लगाने संबंधी गत-मुख-मूल्य की प्रतिशतता के विचार को छोड़ देना चाहिये क्योंकि इसके कारण स्वामित्व के प्रत्यादान में बहुत लचकीलापन आ जाता है।

(ख) यह विचाराधीन है।

(ग) मण्डल की अन्य मुख्य सिफारिशों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1723/67] । सरकार द्वारा आम तौर पर उनको मान लिया गया है और आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

पटसन उद्योग को हानि

1720. **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं की कीमतों में भारी अन्तर होने के कारण पटसन उद्योग को प्रतिमास डेढ़ करोड़ रुपए की हानि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो यह भी सच है कि गत एक वर्ष में चार मिलें बन्द हो गई थीं तथा कुछ और मिलें बन्द होने वाली थीं;

(ग) यदि हाँ, तो इस संकट के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं की कीमतों में अन्तर के कारण इस उद्योग को हुई हानि के बारे में भारतीय जूट मिल्स संस्था से अभ्यावेदन मिल रहे हैं ।

(ख) और (ग) वर्ष 1967 के दौरान चार मिलें बन्द हुई हैं; इन मिलों के बन्द होने का एक कारण अलाभप्रद कार्यप्रणाली तथा वित्तीय कठिनाइयाँ थीं और दूसरा कारण श्रम सम्बन्धी झगड़े थे। इनमें से एक मिल इस बीच फिर चालू हो गई है। सरकार को इस बात का पता नहीं है कि और कोई मिलें बन्द होने वाली हैं ।

(घ) जूट उद्योग की समस्याओं के बारे में 10 अगस्त, 1967 को इस सभा में दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

जिंक संयंत्र, उदयपुर

1721. **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की यह कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर में जिंक संयंत्र पूरा करके 2 अक्तूबर, 1967 को चालू किया गया था;

(ख) क्या उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो संयंत्र की वार्षिक क्षमता क्या है; और

(घ) इस संयंत्र पर कुल कितनी लागत आयेगी?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) और (ख) उदयपुर के पास देबारी में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की जस्ता प्रद्रावक परियोजना का निर्माण तथा उसकी स्थापना, एक-दो छोटे एककों को छोड़कर, अक्टूबर–नवम्बर, 1967 के दौरान प्रायः पूर्ण हो गया था। प्लांट का शुरू होना तथा लगातार चलना कुछ निलम्बित हो गया जिसका कारण था, राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल से विद्युत् शक्ति का पर्याप्त मात्रा में प्राप्त न होना।

(ग) जस्ता-प्रद्रावक की वार्षिक क्षमता निम्न प्रकार है:—

(1) विद्युदांशिक जस्ता 18,000 टन

(2) गन्धक का तेज़ाब 28,000 टन

(3) उपरोक्त (2) से प्राप्त सुपरफास्फेट 75,000 टन

(4) कैडमियम 75 टन

(घ) जिंक प्रद्रावक पर खानों को छोड़कर पूंजी की अनुमानित लागत 9.52 करोड़ रुपए है।

छोटी कार

1722. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सभी प्रकार के कर मिला कर भारत में कार के कुल विक्रय मूल्य का औसतन 32 प्रतिशत होते हैं;

(ख) क्या उन्हें कोई ऐसी छोटी कार बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी उत्पादन लागत इतनी कम हो कि उपरोक्त करों को मिला कर भी उसे 6000 रुपए में बचा जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो किस प्रकार से सस्ती कार बनाने का सरकार का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) "सस्तापन" एक सापेक्ष शब्द है। एक "सस्ती" कार का अभिप्राय यह नहीं है कि वह कर मिलाकर अनिवार्य रूप से 6000 रु० में बेची जाये। सरकार एक ऐसी कार के उत्पादन की संभावना पर छानबीन कर रही है जो देश में आम प्रचलित कीमतों की कारों की अपेक्षा कम कीमत की होगी।

स्वर्ण सायनाइड का आयात

1723. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अगस्त, 1967 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में 'सोना बनाने की सरल विधि' के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) पिछले दो वर्षों में कुल कितने स्वर्ण सायनाइड का आयात किया गया;

(ग) स्वर्ण सायनाइड से सोना बनाने के कदाचार के समाचार को ध्यान में रखते हुए क्या स्वर्ण सायनाइड के आयात पर रोक लगाने का सरकार का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार स्वर्ण सायनाइड को, उससे सोना अलग करने के लिये, बड़े पैमाने पर मँगाने का है ताकि सोने के मूल्य कम किए जा सकें?

वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) स्वर्ण सायनाइड के आयात पर प्रतिबन्ध है।

Railway Station, Diphu (N. E. Rly.)

1724. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at Diphu Railway Station of the N. E. Railway, neither the waiting room facilities are available there nor any quota is reserved for sitting as well as sleeping berths in the trains at that Station ;

(b) whether it is also a fact that drinking water is supplied at the Diphu Station from a small pond in which the sewage of the lavatories built at its banks flows ; and

(c) if so, the action being taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No, Diphu Station is on N.F. Railway. One upper class waiting room and one general waiting hall have been provided at this station. A quota of the one berth in First Class and one seat in III Class in 4 Dn. Assam Mail and one berth in First Class and two sleeper berths in III Class by 20 Dn. Passenger has been allotted to Diphu Station from 1.10.1967.

(b) No. River water after filtration through jewel filter is supplied at Diphu Station.

(c) Does not arise.

नाहन ढलाई घर (फाउंड्री) द्वारा 'केन क्रशरों' की सप्लाई

1725. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नाहन ढलाई घर ने दिसम्बर, 1964 में सौराष्ट्र की एक गैर-सरकारी फर्म को 1320 प्रति बेलन की दर से, जो लागत मूल्य से भी कम है, 150 सुल्तान 'केन क्रशर' देने का वचन दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि नाहन ढलाई घर ने अपने लेखों में इस ठेके में 33,000 रुपए की हानि की पहले ही व्यवस्था करदी थी, जबकि वास्तविक सप्लाई 1965 में की गई थी;

(ग) क्या खरीदार ने पहली लाट में क्रशरों में कुछ दोष पाये थे और इन दोषों को दूर करने के लिए सभी क्रशरों की ढलाई घर के खर्च पर ढलाई घर में वापस लाया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस कुप्रबन्ध के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया था और जाँच की गई थी और यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला था?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (घ) जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

उद्योग निदेशक दिल्ली, द्वारा जारी किए गए अनिवार्यता प्रमाणपत्र

1726. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्योग निदेशक, दिल्ली, ने कितने अनिवार्यता प्रमाण-पत्र दिए हैं और उनका कुल मूल्य कितना है तथा वे मदें कौन सी हैं जिनके लिये 50000 रुपए से अधिक मूल्य के प्रमाणपत्र दिए गए हैं और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वालों के नाम क्या हैं;

(ख) 1965–66 में कितने अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किए गए थे तथा ऐसे कितने उद्योग हैं जिन्होंने 1962–63 में अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए थे और उनमें नए उद्योग कितने थे;

(ग) क्या सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस बारे में उद्योग निदेशक, दिल्ली के कार्यालय में बड़े पैमाने पर अनियमितायें हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या कोई जाँच की गई थी और इसका क्या परिणाम निकला था और क्या इन अनियमितिताओं को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) प्रश्न में यह नहीं बताया गा है कि किस अवधि के लिए सूचना चाहिये।

(ख) वर्ष 1965–66 में सामान्य वस्तुओं के लिये दिए गए अत्यावश्यक प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या 882 थी, इसमें 3 नए कारखाने भी शामिल हैं। वर्ष 1962–63 में दिए गए अत्यावश्यक प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में अनियमिततायें

1727. **श्री प्रेम चन्द वर्मा**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के प्रबन्ध में बहुत सी अनियमततायें हुई थीं; और

(ख) क्या इस बारे में कोई जाँच की गई थी और यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में निर्मित औजारों के गुण-प्रकार

1728. **श्री प्रेम चन्द वर्मा:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में बनने वाले औजारों का गुण-प्रकार बहुत गिर गया है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री में कमी हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वहाँ बनने वाले औजारों का गुण प्रकार गिर गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या प्रबन्ध व्यवस्था में कोई अदला-बदली की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी नहीं, बिक्री में कमी आर्थिक मंदी के कारण हुई है।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

ईवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा खरीदे गए पानी के मीटर

1729. **श्री प्रेम चन्द वर्मा:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ईवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने 1964 में 6 लाख रुपए के मूल्य के 6,000 पानी मीटर खरीदे थे जिनका उपयोग 31 दिसम्बर, 1966 तक नहीं किया गया;

(ख) क्या इन मीटरों का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया था, क्योंकि वे त्रुटिपूर्ण थे; और

(ग) इससे कितना नुकसान हुआ तथा इस नुकसान के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) बस्ती में मकानों के लिए ईवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने फरवरी, 1963 से जनवरी 1965 की अवधि में बस्ती के क्वार्टरों के लिए 6.02 लाख रुपए के 6,912 पानी के मीटर खरीदे।

(ख) तथा (ग): अप्रैल, 1963 से जून, 1965 की अवधि में 1.09 लाख रुपए के मूल्य के 2.129 मीटर लगाये गए थे। निम्न वेतन के कर्मचारियों के आन्दोलन तथा समझौते की कार्यवाही के फलस्वरूप 500 रु० मासिक या इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों से पानी के खर्चे की दर को पर्याप्त मात्रा में घटाने का निश्चय किया था और विशिष्ट वर्ग के मकानों बारे में कुछ सीमा तक पानी का खर्च न लेने का निश्चय किया गया था। दर में कमी हो जाने के कारण पानी के मीटरों को लगाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं था इसलिए यह निश्चय किया गया था कि पानी का खर्च ऊँची श्रेणी के मकानों में रहने वालों से समान दर पर लिया जाय और इसके अतिरिक्त श्रेणियों को इसे खर्च न लिया जाय। इसलिए पानी की खपत का हिसाब लगाना अनावश्यक हो गया। इन सब चीजों का अनुमान मीटरों का खरीद के समय नहीं लगाया जा सकता था। खरीदे गए मीटरों में से 4541 मीटर अभी भी बिल्कुल नई हालत में स्टोर में रखे हैं और उनको बेचने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसलिए कम्पनी के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

1730. **श्री क० प्र० सिंह देव:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में कुटीर उद्योगों को और विकास करने की कोई गुंजाइश है;

(ख) यदि हाँ, तो और कितना विकास करने की गुंजाइश है; और

(ग) उड़ीसा में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन ने के लिये सरकार ने कितनी सहायता दी है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) तक जानकारी एकत्रित की जावेगी और यथासमय सभापटल हर रखी जायेगी?

माल यातायात के सम्बन्ध में रेलवे का कार्य

1731. **डा० रानेन सेन**:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में माल यातायात के सम्बन्ध में रेलवे का कार्य आशा से बहुत कम रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में रेलवे के कार्य में प्रगति करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ। चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में राजस्व अर्जित करने वाले माल का लदान पूर्वानुमान से कम हुआ था।

(ख) मन्दी तथा सूखे की स्थिति के कारण सभी वस्तुओं का यातायात विशेषत: इस्पात कारखानों को तथा इस्पात कारखानों से कम हुआ था।

(ग) ये कारण रेलवे के वश के बाहर थे। नए यातायात का विकास करने तथा हमारे ग्राहकों के लिये और अच्छी सेवा की व्यवस्था करने की दृष्टि से रेल उपभोक्ताओं के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिये सभी रेलवेज में विपणन तथा बिक्री संगठन स्थापित किए गए हैं।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

1732. **डा० रानेन सेन**: **श्रीमती सावित्री निगम**:
श्री मरंडी: **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी**:

क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान मालिकों ने 1 सितम्बर, 1967 से कोयले की सभी किस्मों का मूल्य बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) और (ख) हाँ, महोदय। कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूरा करने से जो प्रभाव पड़ा है, उसे काफी निष्फल करने के विचार से आपस में बातचीत करके सहमति हुई है। 1 सितम्बर, 1967 से बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश के कोयले का मूल्य क्रमश: 5 रुपए 4 रुपए और 5.23 रुपए प्रति टन बढ़ा दिया जाए।

कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे

1733. **डा० रानेन सेन:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता क्षेत्र में एक वृत्ताकार रेलवे बनाने की व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा की गई जाँच के निष्कर्ष सरकार को भेज दिए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़ी रेलवे लाइन को जोगीघोपा से तिनसुकिया तक बढ़ाना

1734. **श्री धीरेश्वर कलिता:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाने के लिये बड़ी रेलवे लाइन को जोगीघोपा से तिनसुकिया तक बढ़ाने के लिए उन्हें 21 अक्तूबर, 1967 को गोहाटी में भारतीय साम्यवादी दल की आसाम राज्य परिषद् से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ।

(ख) कठिन अर्थोपाय स्थिति के कारण, इस प्रकार की परियोजना का इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

गुंटाकल-बंगलौर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1735. **श्री आगाड़ी:**

क्या **रेलवे** मंत्री 18 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1903 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुंटाकल-बंगलौर मीटर गज सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में यातायात सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसपर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा यह कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) अभी नहीं।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता।

काण्डला तथा कराइकल पत्तन

1736. **श्री अगाड़ी:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांडला और कराइकल (दक्षिण) को निर्बाध पत्तन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित पत्तनों के आसपास कोई क्षेत्र निश्चित किए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। काँडला या कराइकल को निर्बाध पतन घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उत्पन्न ही नहीं होते।

मैसूर में उद्योगों का बन्द होना

1737. **अगाड़ी** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने राज्य द्वारा प्रबन्धित उद्योगों में से कुछ उद्योग बन्द करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हाँ तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ ऐसे अत्यावश्यक उद्योगों को अपने प्राधिकार में लेने का विचार किया है जिनका प्रबन्ध मैसूर सरकार अच्छी तरह से नहीं कर सकती ; और

(ग) यदि हाँ, तो किन-किन उद्योगों को बन्द करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में मशीनी औजारों के भंडार

1738. **श्री अगाड़ी** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखानों में वहाँ निर्मित मशीनी औजारों के बड़े भंडार बिना बेचे पड़े हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो 1 अगस्त, 1967 को प्रत्येक कारखाने में इस प्रकार बिना बिके कितने मूल्य के भंडार पड़े हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बंगलौर से बम्बई तथा अन्य स्थानों पर बिना रिकार्ड तथा द्वारपत्रों के औजारों के कई पार्सल भेजे गए थे ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रकार कितने पार्सल थे जिनको गन्तव्यव स्थानों पर नहीं छुड़ाया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) : 31 अक्तूबर, 1967 में स्टाक निम्न प्रकार था :—

31-10-1967 **को निम्नलिखित का कुल स्टाक आगे दिये जाने तथा आस्थगित ऋण की शर्तों पर दिये जाने के लिये रोक लिया गया**

कारखाना	कुल स्टाक			
	मशीनों की संख्या	(मूल्य लाख रु० में)	संख्या	(मूल्य लाख रु० में)
बंगलौर	419	196	154	62
पिंजोर	121	88	38	17
कालामापेरी	45	16	34	14
हैदराबाद	10	35	10	35
	595	335	236	128

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बोकारो इस्पात कारखाने का निदेशक बोर्ड

1739. **श्री श्रीधरन :** **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के निदेशक बोर्ड में एक ब्रिटिश नागरिक की नियुक्ति की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता।

सिंगापुर की मण्डी से रूई का आयात

1740. **श्री श्रीधरन :** **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सिंगापुर की मण्डी से रुई खरीद रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1966–67 के दौरान कितनी रुई खरीदी गई और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ग) क्या यह भारतीय जहाजों में लाई जाती है; और

(घ) यदि नहीं तो, भाड़े के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा विदेशी जहाज कम्पनियों को दी गई?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उत्पन्न ही नहीं होते।

काली मिर्च का निर्यात

1741. **श्री अदिचन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में काली मिर्च के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) काली मिर्च का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) कमी इंडोनेशिया से प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।

(ग) मूल्य स्थिरीकरण के लिये इंडोनेशिया को एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

शिशु आहार का मूल्य

1742. **श्री अदिचन:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में शिशु आहार का मूल्य बढ़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शिशु आहार के मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी हाँ।

(ख) मूल्य में वृद्धि, तरल दूध, चीनी, विटामिनों, रसायनों तथा टीन के डिब्बों के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है।

(ग) शिशु खाद्य उत्पादक स्वेच्छा से मूल्य नियंत्रण रखने के लिए तथा मूल्य में और अधिक वृद्धि करने से पूर्व सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिये राजी हो गए हैं।

नारियल जटा बोर्ड

1743. **श्री अदिचन:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने जून, 1967 में एक कल्याण योजना प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) नारियल जटा उद्योग कामगरों के जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक है लाभ के लिये नारियल जटा बोर्ड ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) नारियल जटा बोर्ड ने नारियल जटा श्रमिकों के आम कल्याण के लिये अप्रैल, 1967 में क योजना प्रस्तुत की थी।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 1724/67]।

(ग) नारियल जटा बोर्ड ने अब तक नारियल जटा श्रमिकों के आम कल्याण सम्बन्धी कोई योजना शुरू नहीं की है। फिर भी, बोर्ड द्वारा शुरू की गई सभी विकास योजनाएँ नारियल जटा श्रमिकों के लाभ के लिये ही हैं।

अरब देशों को निर्यात

1744. **श्री वासुदेवन नायर:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरब देशों द्वारा अपने-अपने देश में पश्चिमी वस्तुओं का बहिष्कार किए जाने के पश्चात् उन देशों के साथ भारत का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किए गए हैं;

(ख) क्या इन प्रयत्नों के फलस्वरूप इन देशों के साथ हमारे निर्यात व्यापार में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अरब देशों ने पश्चिमी सामान का बहिष्कार नहीं किया है हालाँकि उनमें से कुछ देशों ने अन्य स्रोतों से सामान प्राप्त करने के लिए कमोबेश प्रयत्न किए हैं। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ ने व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करने के लिये दो व्यापार दल भेजे थे और व्यक्तिगत व्यापारियों ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया है।

(ख) संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, कुवैत और ईराक के मामले में निर्यात व्यापार में काफी वृद्धि होने की आशा है। स्वेज नहर से दूर की ओर स्थित अरब देशों को निर्यात पर स्वेज नहर के बन्द होने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) इन प्रयासों के परिणामों का सही-सही मूल्यांकन करने में कुछ समय और लगेगा।

इंजीनियरिंग उद्योग में मंदी

1745. **श्री वासुदेवन नायर : श्री जो० ना० हजारिका : श्री नन्दकुमार सोमानी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग उद्योग में मंदी को रोकने के लिये क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या इन उपायों से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितना ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) माँग में कमी के कारण अप्रयुक्त क्षमता में सुधार करने के लिये किए गए कुछ उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) जहाँ तक देश में उपलब्ध क्षमता से संभव हो सके, आयात पर रोक लगाना। इनमें उस आयात का पुनरीक्षण भी सम्मिलित है जिसकी स्वीकृति तो दी जा चुकी है किन्तु जिसके लिए यह वचन नहीं दिया गया है कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(2) सरकार कर विकास कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना जिसका प्रभाव उद्योगों की मांग पर पड़ता है और जहाँ तक व्यवहारिक हो जैसे रेलवे वैगन इत्यादि के लिये और अधिक आर्डर दिए जाना :

(3) अधिक उदार रूप में विखिलता लाने के लिये मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार किया जाना :

(4) गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों की बिक्री के अधिक सुदृढ़ तरीकों से निर्यात का बढ़ाया जाना। इस आशय की एक अपील हाल ही में बड़े औद्योगिक क्षेत्र में चुने हुए एककों के मुख्य प्रशासकों को भेज दी गई है।

(5) मन्दी की प्रवृत्ति को रोकने के लिये नई ऋण नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के अन्तर्गत कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों जैसे निर्यातोन्मुख, इंजीनियरी और धातु कर्म उद्योगों, कृषि सम्बन्धी मशीनों तथा उपकरणों, ट्रकों, गाड़ियों और लघु उद्योगों आदि के लिये सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध होने की आशा है। आशा

है कि घोषित नीति से उद्योग के बहुत बड़े भाग की मुख्य कठिनाइयां बहुत बड़ी सीमा तक कम हो जायेंगी।

(ख) और (ग) युक्तिसंगत समय बीतने पर ही इस बात का पता लगाना सम्भव हो सकेगा कि इसमें कहाँ तक सुधार हुआ है।

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार

1746. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री क० लक्कप्पा :**

श्री बलराज मधोक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के व्यापार को और अधिक बढ़ाने की संभावना का अध्ययन किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हाँ।

(ख) व्यापार प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट हो जायेगा:

मूल्य मिलियन रुपयों में

	1965	1966	1967 (जनवरी-जुलाई)
भारत में आयात	1500.81	1836.59	1376.38
भारत से निर्यात	1515.65	1927.20	1430.51

उद्योगों के लिये विदेशी सहयोग

1747. **श्री यशपाल सिंह**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों द्वारा उनकी विदेश यात्राओं के दौरान उद्योगों में विदेशी सहयोग प्राप्त करने हेतु कोई नियम आदि बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिड़ला फर्मों को जारी किए गए लाइसेंस

1748. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री स० कुंडू :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में पिछले सत्र की समाप्ति के पश्चात् ऐसी फर्मों को कोई लाइसेंस दिया गया है, जिनसे बिड़लाओं का काफी सम्बन्ध हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितने फर्मों को और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) बिडला फर्मों के लिये औद्योगिक लाइसेंसों के हेतु कितने आवेदन पत्र निर्णयाधीन हैं और कितने आवेदनपत्र मंत्रिमंडल उप समिति के पास भेजे गये हैं और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन

1749. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री ईश्वर रेड्डी**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वर्तमान ढांचे के पुनर्गठन के लिये उन्होंनें अपनी योजनाओं को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पुनरीक्षित योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) से (ग) जी नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के कुली

1750. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री अब्राहम :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर कुली अपनी कार्य की शर्तों से सन्तुष्ट नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों के लाइसेंस प्राप्त कुली कुछ समय से शिकायत करते रहे हैं वे कुछ सुविधाएँ चाहते हैं जिनके वे हकदार नहीं है । श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय ने भारतीय रेलों के लाइसेंस प्राप्त कुलियों की जीवनयापन तथा काम की दशाओं में जाँच करने तथा उनमें सुधार के लिये सुझाव देने के लिये हाल ही में एक अध्ययन दल बनाया है । इस दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

गाड़ियों में बिजली तथा पंखों के दोषपूर्ण उपकरण

1751. **श्री० स० चं० सामन्त :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि महत्वपूर्ण मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों सहित विभिन्न गाड़ियों में बिजली तथा पंखों का उपकरण बहुत बार खराब हो जाता है जिससे अन्धेरा हो जाता है अथवा बत्तियाँ टिमटिमाती रहती हैं;

(ख) क्या इन दोषों का कारण घटिया किस्म की बैटरियाँ तथा डायनमों हैं अथवा इसका कारण कर्मचारियों की अदक्षता है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) गाड़ियों में लगी हुई बत्तियों तथा पंखों में कभी तथा खराबी के कुछ मामले हुए हैं।

(ख) इनका मुख्य कारण समाज विरोधी तत्वों द्वारा डिब्बों से विभिन्न उपकरणों की बड़े पैमाने पर चोरी है। इस समय देश में अपर्याप्त निर्माण क्षमता के कारण बैटरियों की कमी के कारण यह स्थिति और भी अधिक खराब हो गई है।

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये अनेक प्रत्योपाय किये गये हैं जिनमें से कुछ नीचे दिये गये हैं:

(एक) टर्मिनल स्टेशन पर गाड़ी में प्रकाश करने सम्बन्धी उपकरण के रख-रखाव के स्तर में सुधार।

(दो) गाड़ियों के उन स्टेशनों से चलने से पहले निरीक्षण जहाँ कि वे शुरू होती हैं जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गाड़ियों में बत्तियाँ, पंखे तथा अन्य सुविधायें ठीक काम कर रही हैं अथवा नहीं।

(तीन) यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि मार्ग में कोच अटेंडेंट बत्तियों, पंखों तथा अन्य सुविधाओं को ठीक स्थिति में बनाए रखे और छोटी मोटी खराबी को ठीक करदे, जैसे बल्ब, ब्रश, फ्यूज आदि बदलना।

(चार) इस बारे में जारी की गई विभिन्न हिदायतों पर पूरी तरह से अमल किया जाता है या नहीं इसे देखने के लिये प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बार-बार निरीक्षण।

(पाँच) उपकरण के साथ अनधिकृत छेड़छाड़ को कम करने के लिये चोरी विरोधी उपायों की पूर्ति।

(छै) संधारण सुविधाओं पर पुनर्विचार, उनका पुनर्गठन तथा उन्हें आधुनिक रूप देना।

(सात) संतोषजनक स्तर के पुर्जों विशेषकर महत्वपूर्ण पुर्जों की पर्याप्त मात्रा में खरीद।

(आठ) डिब्बों में उपकरण की सुरक्षा के लिये रेलवे सुरक्षा दल के सहयोग से सुरक्षा उपाय करना।

(नौ) देश में गाड़ी में प्रकाश करने वाली बैटरियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त वर्तमान कमी को दूर करने के लिये बैटरियों के आयात के लिये भी प्रबन्ध किये गये हैं।

(दस) डिब्बों में इस समय प्रकाश की जो व्यवस्था है उसकी क्षमता तथा विश्वसनीयता में तकनीकी परिवर्तन द्वारा सुधार करने के बारे में भी पुनर्विचार हो रहा है।

इस समस्या को हर संम्भव उपाय करके हल किया जा रहा है ताकि बत्तियाँ तथा पंखे ठीक तरह से काम करते रहें।

दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

1752. **स० चं० सामन्त :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन के कितने भाग में विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलने लगी हैं;

(ख) इस मार्ग पर पूरी लाइन का विद्युतीकरण करने में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) विद्युतीकरण के कारण यात्रा करने वाली जनता को क्या-क्या अधिक सुविधाएँ एवं लाभ प्राप्त होंगे तथा रेलवे प्रशासन को इससे क्या लाभ होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) दिल्ली और हावड़ा के बीच बरास्ता ग्रांड कोर्ड 1441 किलोमीटर की कुल दूरी में से हावड़ा और कानपुर के बीच 1017 किलोमीटर में विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया हैं। बिजली की गाड़ियाँ हावड़ा और कानपुर के बीच भी चल रही हैं।

(ख) कानपुर और दिल्ली के बीच के शेष 424 किलोमीटर की दूरी में से कानपुर और टूण्डला के बीच 220 किलोमीटर का विद्युतीकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में करने का कार्यक्रम है और यह काम 1970-71 तक पूरा हो जाने की आशा है। टूण्डला से दिल्ली तक की दूरी का विद्युतीकरण करने के बारे में इस समय कोई अन्तिम प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विद्युतीकरण से यात्री धुएं से बच जायेंगे और गाड़ियाँ भी तेज चलेंगी और रेलवे प्रशासन को इससे यह लाभ होगा कि रेलों का संचालन कुशल तथा लाभप्रद हो जायेगा।

एक्सप्रेस/मेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना

1753. **श्री स० च० सामन्त :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों के आमतौर पर विलम्ब से चलेने के क्या कारण हैं जब कि स्वतन्त्रता से पूर्व के समय (टाइमिंग्स) की तुलना में उनको 300 मील जाने के लिये लगभग दो घन्टे अथवा उससे भी अधिक समय दिया जाता है; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे कि रेल गाड़ियाँ समयानुसार चलें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) हालाँकि स्वतंत्रता में पूर्व के समय की तुलना में कुछ मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों का यात्रा समय (रनिंग टाइम) कुछ बढ़ गया है, बहुत सी अन्य गाड़ियों का यात्रा समय कम ही गया है। कुछ मेल। एक्सप्रेस गाड़ियों के यात्रा समय में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं : अतिरिक्त स्टापों की व्यवस्था तथा जनता की माँग पर हाल्ट की अवधि में वृद्धि के कारण अधिक समय लगना, स्लिप कोचों की संख्या में वृद्धि करने से जंक्शन स्टेशनों पर उन्हें लगाने तथा हटाने में अधिक समय लगना और अतिरिक्त परिवहन क्षमता पैदा करने के लिये लाइन पर अधिक विकास कार्यों के कारण अतिरिक्त समय की व्यवस्था करना। एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों के देर से चलने के विभिन्न कारण हैं। बहुत भीड़ वाले एक लाइन वाले सैक्शनों पर एक गाड़ी के देर से चलने के कारण अन्य गाड़ियों के गुजरने में भी देरी होना, यात्रिकी तथा सिग्नलिंग उपकरण का अचानक खराब हो जाना, संचार उपकरण का खराब हो जाना तथा इंजनों में कभी-कभी खराबी हो जाना आदि-आदि। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस तथा मेलगाड़ियों के देर से चलने के कारण ये भी हैं: जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि, आन्दोलनकारियों द्वारा गाड़ी का ठप्प किया जाना, समाज-विरोधी तत्वों द्वारा ताँबे के तारों तथा रेलवे उपकरण की चोरी और बाढ़ तथा उसके कारण लाइन का टूट जाना।

(ख) मेल / एक्सप्रेस तथा अन्य गाड़ियों की दिन प्रति दिन की प्रगति पर सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इस बारे में हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है कि गाड़ियाँ समयानुसार चलें।

माल डिब्बा निर्माण उद्योग

1754. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र में माल डिब्बा निर्माण उद्योग की कितनी क्षमता है और चालू वर्ष में अब तक इसमें कितना उत्पादन हुआ है,

(ख) यदि इसमें क्षमता कम उत्पादन हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) (एक) सरकारी क्षेत्र में विशेषकर माल डिब्बों के निर्माण की क्षमता उत्पन्न नहीं की गई है। 1960 से रेलवे वर्कशाप में नये माल डिब्बे बनाए जा रहे हैं जब कि रेलवे की बढ़ती हुई माँग का पूरा करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में वैगन निर्माण उद्योग की क्षमता पर्याप्त नहीं थी। यह निर्माण प्रोत्साहन योजना लागू करके अधिक उत्पादन के द्वारा इन वर्कशापों में उत्पन्न की गई फालतू क्षमता का उपयोग करके किया जा रहा है। यह काम मरम्मत तथा संधारण वर्कशापों में किया जाता है और मरम्मत तथा संधारण कार्य के धीरे-धीरे बढ़ जाने पर इसे कम कर दिया जायेगा।

(दो) चालू वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में अर्थात् 31 अक्तूबर 1967 तक वास्तविक उत्पादन चार पहिये वाले 2200.5 वैगन है जबकि 1967–68 में लगभग ऐसे 4300 वैगन बनाने की लक्ष्य है।

(ख) क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

सरकार द्वारा सूती कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेना

1755. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में सरकार ने जो आठ सूती कपड़ा मिलें अपने हाथ में ली थी उनमें दो मिलें बन्द कर दी गई हैं तथा छः मिलें घाटे पर चल रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल 1966 में प्राथमिकता के आधार पर कपास देने तथा श्रम कानून के कुछ उपबन्धों को ढीला करने के बावजूद एक करोड़ बियासी लाख रुपये का घाटा हुआ था;

(ग) यदि कानून के उपबन्धों को ढीला नहीं किया जाता तो क्या घाटा और भी अधिक होता और यदि हाँ, तो मिलों के कार्य संचालन में ढील देने का क्या वित्तीय प्रभाव होता है; और

(घ) ऐसे अनुभव को देखते हुए क्या सरकार का विचार ऐसी सूती कपड़ा मिलों को वास्तविक मालिकों को सौंप देने का है और घाटे में चलने वाली मिलों को भविष्य में अपने हाथ में लेने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (घ) 1965-66 और 1966-67 के दौरान सरकार ने जिन आठ मिलों को अपने अधिकार में लिया है उनमें से दो बन्द कर दी गई हैं और छः घाटे पर चल रही हैं।

इन आठ मिलों में से 1966 में केवल सात प्राधिकृत नियंत्रकों के अधीन थी और उनमें से केवल चार चल रही थी। इन मिलों को घिसाई आदि दिये जाने पश्चात् 1966 में लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपये का घाटा हुआ। इस घाटे में बहुत सी ऐसी राशि भी शामिल थी जो प्राधिकृत नियंत्रकों ने मिलों को लिये जाने से पहले उनके दायित्व के लिये दी थी। श्रम कानूनों के उपबन्धों को इन मिलों के पक्ष में विशेष रूप से ढीला नहीं किया गया था। 1966 में अधिकतम मूल्य के हिसाब से इन मिल पर वस्त्र नियंत्रण द्वारा कपास के नियतन का वित्तीय प्रभाव केवल 50,000 रुपये था।

इन मिलों को उनके वास्तविक मालिकों को वापस दिये जाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। जहाँ तक भविष्य में घाटे पर चलने वाली मिलों को सरकार द्वारा लिये जाने का सम्बन्ध है सरकार का विचार किसी ऐसी मिल को अपने हाथ में लेने का नहीं है जब तक सूती कपड़ा कम्पनियाँ (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा पुनर्निर्माण अथवा परिसमापन) विधेयक 1967, जो पहले पुरस्थापित किया जा चुका है, पास नहीं हो जाता।

पश्चिमी बंगाल में उद्योगों का बन्द होना

1756. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:** **श्री बलराज मधोक:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक और सामाजिक अशांति के कारण मार्च, 1967 से लेकर अब तक कई औद्योगिक तथा वाणिज्यक एकक अंशत: अथवा पूर्णतया बन्द हो गये हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी हो गई है, कर्मचारियों को जबरी छुट्टी दे दी गई है और छंटनी कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका कितने औद्योगिक एककों पर प्रभाव पड़ा है, कितने श्रमिकों की छटनी की गई है और कितने श्रमिकों को जबरी छुट्टी दे दी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक एककों में भावी विस्तार रुक गया है और वहाँ पर विद्यमान असुरक्षा की दशाओं में उद्यमकर्ता और पूंजी लगाने के लिये तैयार नहीं है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (घ) सरकार के पास इस विषय पर कोई संक्षिप्त आंकड़े नहीं हैं और न ही प० बंगाल में औद्योगिक तथा सामाजिक अशांति का तथा उसका औद्योगिक सम्भाव्यताओं पर प्रभाव का कोई विधिवत् सर्वेक्षण किया गया है। हमें औद्योगिक अशांति तथा उत्पादन पर उसके विपरीत प्रभाव की निस्सन्देह जानकारी है। सरकार औद्योगिक शांति बढ़ाने के लिये राज्य सरकार से निरन्तर सम्पर्क स्थापित किए हुए है।

पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों पर हमला

1757. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

श्री ज़ु० को० मण्डल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में पश्चिम बंगाल में उत्तेजित भीड़ ने कितनी बार रेलगाड़ियों पर हमला किया ;

(ख) ये उपद्रव किन कारणों से हुए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि रेल सुरक्षा दल इन सभी घटनाओं में रेलवे सम्पत्ति की अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर सका ; और

(घ) इन उपद्रवों के कारण रेलवे को कितना नुकसान हुआ ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)

(क) उस अवधि के दौरान किन्हीं ऐसी घटनाओं के समाचार नहीं मिले हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बिड़ला औद्योगिक कारखानों द्वारा कदाचार

1758. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़ला के नियंत्रणाधीन औद्योगिक कारखानों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचारों और कंदाचारों के आरोपों के बारे में कोई जाँच की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) सरकार ने बिड़ला समूह की कम्पनियों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जाँच के लिए सक्रिय जाँच प्रारम्भ कर दी है। चूंकि जाँच का क्षेत्र विस्तृत है और कुछ विस्तृत उत्तर अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। इन उत्तरों का शीघ्रता से अध्ययन किया जा रहा है जिससे की जाने वाली कार्रवाई की रूपरेखा शीघ्र ही तैयार की जा सके।

औद्योगिक उत्पादन

1759. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के कुछ महीनों में औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन में हो रही कमी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) जुलाई, 1967 में औद्योगिक उत्पादन का सरकारी सूचकांक 199.3 (आधार 1956—100) था, जब कि जनवरी 1967 में यह 199.8 और 1966 में 192.6 था। यद्यपि इंजीनियरी उद्योग जो भारी पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करते हैं, पिछले कुछ महीनों में मन्दी से प्रभावित हुए। इसके मुख्य कारण आर्डरों का अभाव, विकास कार्यक्रमों की काट-छांट, संयन्त्र तथा परियोजनाओं को अन्तिम रूप न दिया जाना तथा श्रमिक अशान्ति थे।

(ग) उत्पादन की कमी को रोकने के लिए समय-समय पर नीचे लिखे पग उठाए गए हैं:—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अभिनियम के उपबन्धों से कई उद्योगों को लाइसेन्स संबंधी उपबन्धों से मुक्त किया गया है।

(2) स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये उत्पादन में विविधता लाने में सहायता करना;

(3) कच्चे माल के आयात में उदारता बरतना;

(4) एक उच्च अधिकार प्राप्त निदर्शन समिति का गठन किया गया है जो विभिन्न कठिनाइयों पर विचार करेंगी और उनके निवारण के लिये उपायों का सुझाव तथा कार्यवाही की रूप-रेखा तैयार करेगी।

(5) रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया ने ऋण को सक्रिय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाने की घोषणा 31 जुलाई, 1967 की प्रेस विज्ञप्ति में की है।

(6) उत्पादकों को सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं जैसे माल डिब्बों आदि के लिए अग्रिम आर्डर दे दिए गए हैं।

दुर्गापुर तथा रूरकेला इस्पात कारखानों का विस्तार

1760. **श्री पं० गोपालन:** **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों के विकास की एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और विस्तार की यह प्रस्तावित योजना कब लागू की जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में दुर्गापुर स्थित कारखाने के सम्बन्ध में 16 लाख टन पिंड इस्पात की क्षमता में 34 लाख टन पिंड इस्पात की क्षमता और रूरकेला इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में 18 लाख टन पिंड इस्पात की क्षमता से 25 लाख टन पिंड इस्पात क्षमता बढ़ाने का उपबन्ध है। तथापि, इस्पात की माँग में धीमी प्रगति और संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए इन कारखानों के विस्तार का काम इस समय स्थगित कर दिया गया है।

इस बीच राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने लोहा और इस्पात की माँग का अध्ययन आरम्भ कर दिया है तथा भारत की बढ़ती हुई निर्माण क्षमता को महत्व को ध्यान में रखते हुए एक समिति बनाई गई है जो इस्पात बनाने की क्षमता के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होने के लिये

सरकार को परामर्श देगी। उन प्रतिवेदनों के 1968 के आरम्भ में मिलने की आशा है। उसके पश्चात् दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों के विस्तार के बारे में निर्णय करने का प्रस्ताव है।

ईराक, लेबनान तथा लीबिया को व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

1761. **श्री प० गोपालन:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईराक, लेबनान तथा लीबिया को इस वर्ष जाने वाला भारत का व्यापार प्रतिनिधि मण्डल अब वहाँ नहीं जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इन देशों को व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल भेजने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, नहीं। भारतीय निर्यात संगठन संघ द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि-मण्डल के स्थान पर जिसने पहले ईराक, लेबनान तथा लीबिया का दौरा किया था अब एक दूसरा प्रतिनिधिमण्डल वहाँ पर जायेगा तथा उसके वहाँ पर जाने का समय अभी निश्चित नहीं किया गया है।

(ख) लेबनान और लीबिया का दौरा स्थगित करने का मुख्य कारण यह है कि दोनों देश स्वेज नहर से बहुत दूर हैं तथा स्वेज नहर के बन्द होने के कारण वहाँ जाना बहुत कठिन हो गया है।

(ग) और (घ) भारतीय निर्यात संगठन संघ जब उचित समय समझेगा तो लेबनान, लीबिया तथा एक अथवा दो देशों को प्रतिनिधिमण्डल भेजना प्रायोजित करेगा।

इस्पात का निर्यात

1762. **श्री पं० गोपालन:** **श्री नम्बियार:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1967 के 'इकानामिक टाइम्स' में छपी इस आशय का खबर की ओर दिलाया गया है कि सरकार की वर्तमान निर्यात नीति में कुछ विषमतायें होने के कारण इस्पात का निर्यात करने में बाधा पड़ती है;

(ख) यदि हाँ तो, विषमतायें क्या हैं; और

(ग) विषमताओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, हाँ।

(ख) समाचार में बताई गई विषमतायें इन प्रकार है:—

(एक) जब कि इस्पात उद्योग को मंदी का सामना करना पड़ रहा है और उसमें माल भी जमा हो रहा है परन्तु फिर भी न तो अधिकारी और न ही मुख्य उत्पादक निर्यात अवसरों का पूरा लाभ उठाने के उत्सुक हैं। इस्पात निर्यातकर्ता संस्था में बहुत कठिनाई से सदस्य बनाया जाता है।

(दो) चूंकि इस्पात का निर्यात करने से बहुत हानि होती है इस लिये निर्यातकर्ता उसका निर्यात तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें काफी राज सहायता न दी जाये। राजसहायता केवल इस्पात निर्यातकत। संस्था के सदस्यों को अथवा बम्बई और मद्रास के ऐसे व्यापारियों को दी जाती है जो इस्पात के निर्यात व्यापार में भाग लेते हैं। मुख्य उत्पादक तथापि, बम्बई अथवा मद्रास को निर्यात योग्य सामान सप्लाई करने के इच्छुक नहीं।

(चार) चूंकि व्यापारियों को अपने भाण्डागारों के स्टाक से सामान का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती है इसलिये वे तुरन्त सप्लाई करने वाले माल के क्रयादेशों को स्वीकार नहीं कर सकते है।

(ग) यह बात सही नहीं है कि इस्पात उद्योग अथवा अधिकारी निर्यात अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठाते हैं। तथ्य तो यह है कि इस्पात का निर्यात गत वर्ष किये गये निर्यात की तुलना में अधिक हुआ है। इस्पात निर्यातकर्त्ता संस्था के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। राजसहायता लोहे और इस्पात के मुख्य उत्पादकों, ला मेंस प्राप्त उत्पादकों और रि-रोलरों अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों को भी दी जाती है। यह सही है कि मुख्य उत्पादक इस्पात निर्यातकर्ता संस्था के सदस्यों को ही सामान सप्लाई करते हैं। यह देखने के लिये सुरक्षात्मक उपाय करना आवश्यक है कि बहुत से निर्यातकर्ता विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में घाटा रहे। भिलाई से केवल विजगा और कलकत्ता इस्पात भेजन के लिये रेलवे के भाड़े में छूट दी जाती है इसलिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इन बन्दरगाहों के माध्यम से ही इस्पात भेजना चाहती हैं। निर्यात किये जाने वाले इस्पात की किस्म बनाये रखना भी आवश्यक है इसलिये निर्यात किये जाने वाला सम्पूर्ण सामान प्राधिकृत किस्म का होना चाहिये।

उद्योग (विकास और वियिमन) अधिनियम, 1951

1763 **श्री न० कु० साल्वे :** क्या **ओद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा अत्य.-वश्यक पण्य अधिनियम, 1955 के कुछ उपबन्धों की द्विरावृत्ति तथा एक ही काम दोनों द्वारा किये जाने की जाँच करने तथा इन असंगतियों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है, जिसके कारण उद्योगपतियों को असुविधा और परेशानी होती है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) इस मामले को औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी प्राक्कलन समिति की नवीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) में भी उठाया गया है और जिसकी सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

तकनीकी विकास महनिदेशालय

1764 **श्री न० कु० साल्वे :** क्या **ओद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी विकास के महानिदेशक के उपयोग के लिये आंकड़े और जानकारी की जाँच और व्यवस्थित रूप से संकलन के बारे में कोई निर्णय किया है ताकि वह औद्योगिक

लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने में औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के तथा उद्योगों को पूंजीगत माल, संरक्षण वस्तुओं तथा कच्चे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के नियतन के लिये आवेदनपत्रों को निपटाने में वाणिज्य मंत्रालय के तकनीकी सलाहकार के रूप में अधिक प्रभावी रूप में काम कर सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) तकनीकी विकास का महानिदेशालय में सूचना संकलन करने की विधि को परामर्श देने वाली फर्म अर्थात् मेसर्स बूज एलन ऐण्ड हैमिल्टन इन्टरनेशनल इंनकारपोरेशन द्वारा आयात विद्यमान व्यवस्था की जाँच की गई थी। परामर्श देने वाली फर्म ने इस योजना पर अक्टूबर 1965 में कार्य आरम्भ किया था और अपना प्रतिवेदन मार्च, 1966 में दे दिया था। यह प्रतिवेदन मुख्यतया तकनीकी विकास का महानिदेशालय में सूचना संकलन की प्रक्रियाओं और विशेषतः आयात के लाइसेंस दिये जाने तथा विदेशी मुद्रा के आवंटन के बारे में है। इसमें वर्तमान प्रणाली का विश्लेषण और सुधार की सम्भावनाएँ जो कि विद्यमान समझी जाती हैं, का उल्लेख किया गया है। कुछ ऐसी परिस्थितियों को जो कि अब उपस्थित हो गई हैं, जाँच की जा रही है जैसे आयात की उदार नीति। कुछ उद्योगों का लाइसेंसयुक्त किया जाना और सामग्री आयोजन की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू किए जाने की दृष्टि से जाँच की जा रही है।

विदेशों के साथ व्यापार

1765. **श्री न० कु० साल्वे:**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आस्ट्रेलिया की इण्डिया लीग के प्रधान के हाल ही के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि आस्ट्रेलिया में भारत को अपना बिक्री योग्य माल बेचने के लिये अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाने की आवश्यकता है; और

(ख) क्या हमारे दूतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों की विशाल श्रृंखला के माध्यम से भारत को आगे बढ़ने वाले तथा प्रगतिशील देश के रूप में, जो मोटर गाड़ियों, विमानों जनित्रों तथा अन्य अनेक प्रकार की वस्तुओं के रूप में बढ़िया तथा उत्तम वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, दर्शाने के लिये क्या कोई प्रभावी प्रयत्न किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह):

(क) जी, हाँ। हमने ऐसे निर्देश भारत के समाचारपत्रों में देखे हैं।

(ख) भारत को आगे बढ़ने वाले तथा प्रगतिशील देश के रूप में जो बढ़िया तथा उत्तम वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, दर्शाने के लिये प्रभावी प्रयत्न किये गये हैं। एक विवरण, जिसमें इस सम्बन्ध में किये गये कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य दर्शाये गये हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1725/67]

पेरिस में महाराष्ट्र सरकार वाणिज्यिक केन्द्र

1766. **श्री न० कु० सालवे:**

क्या **वाणिज्य** मत्री यह बतानें की कृपा करेंगे क :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में लघु उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शनार्थ महाराष्ट्र सरकार ने अपनी इच्छा से पेरिस में एक वाणिज्यिक केन्द्र खोला है; और

(ख) यदि हाँ, तो विदेशो बाजार में राज्यों के प्रवेश के ऐसे सीधे प्रयत्नों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

धातुमण्डल और विशेष इस्पात परियोजनाओं के लिये परियोजना प्रतिवेदन

1767. **श्री न० कु० साल्वे:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धातुमिश्रित और विशेष इस्पात परियोजना के लिये पाँच वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये दिसम्बर 1959 में एक गैर सरकारी कम्पनी के साथ करार किया था;

(ख) क्या बहुत सी और धनराशि दिये जाने पर इस अवधि को और तीन वर्षों के लिये बढ़ाया गया था; और

(ग) क्या निश्चित धनराशि दिये जाने पर इस अवधि को बढ़ाना उचित था क्योंकि परियोजना प्रतिवेदन को पूरा करने में देरी के लिये वह कम्पनी उत्तरदायी थी और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) कम्पनी द्वारा परियोजना प्रतिवेदन के पूरा किये जाने में कोई देरी नहीं हुई। जहाँ तक परियोजना को पूरा करने में देरी होन की सम्बन्ध है, यह कई कारणों से हुई, जिन पर अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के लिये निर्णय करते समय विचार किया गया था।

केरल में लौह अयस्क के निक्षेप

1768. **श्री रमेश चन्द व्यास:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में लौह-अयस्क के बड़े भारी निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उपलब्ध लौह-अयस्क की अनुमानित मात्रा कितनी है तथा वह किस गुण-प्रकार और श्रेणी का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसे निर्यात करने का है और यदि हाँ तो किस बन्दरगाह से ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) और (ख) हाँ, महोदय। व्यधन आदि और अधिक संचय सिद्ध करने के कार्यों के परिणामों का पता लगने से पहले, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि केरल में को झीकोड क्षेत्र के समीप लगभग 333 मिलियन टन कच्चे लोहे के अनुमति निक्षेप हैं। ये अयस्क-मुख्यतः मैगनेटाईट प्रकार के हैं और इनमें 30 से लेकर 58 प्रतिशत लोहा है, जो कि आक्सीजनकृत सतह पर पाए जाते हैं। सम्भवतः अनआक्सीजन कृत मैगनेटाइट क्वार्टजाईट में नीचे लगभग 30 से लेकर 35 प्रतिशत लोहा होगा।

(ग) इस प्रश्न पर सचय तथा श्रेणी सिद्ध करने के लिये और आगे किये गये विस्तृत अनुसधान के बाद विचार किया जाएगा।

कांडला पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात

1769. **श्री रमेशचन्द्र व्यास:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काण्डला पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात क्यों बन्द कर दिया गया है और क्या निकट भविष्य में उसे पुनः चालू करने की कोई सम्भावना है; और

(ख) क्या काण्डला पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात पुनः आरम्भ करने की दृष्टि से सरकार ने राजस्थान में खानों का विकास करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : कांडला पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात दो बातों के कारण बन्द किया गया है। पहली बात तो यह है कि राजस्थान का अयस्क, छोटे पैमाने पर जिसका इस पत्तन से निर्यात होता था, विश्व के बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा बाजार में स्वीकार नहीं किया जाता था। दूसरी बात यह है कि इस पत्तन में ढलाई की जो सुविधायें उपलब्ध थीं वे लौह अयस्क के व्यापार के लिये अपर्याप्त थीं। इन परिस्थितियों में कांडला से पुनः लौह अयस्क का निर्यात करना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बॉक्साइट का निर्यात

1770. **श्री रमेशचन्द्र व्यास**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से माइन्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम अनिवार्य रूप से बॉक्साइड का निर्यात होने लगा है तब से इसका निर्यात कम हो गया है और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) निर्यात में हुई इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, नहीं। अगस्त 1967 से जब से माइन्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से बॉक्साइट का निर्यात किया जाने लगा है पहले 12 महीनों की अवधि के दौरान बॉक्साइट का कुल निर्यात निगम के माध्यम से किये जाने वाले निर्यात के पहले के 12 महीनों में किये गये 55,000 टन के निर्यात की तुलना में 82,000 टन हुआ है। रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् बॉक्साइट का निर्यात निगम के माध्यम से नहीं किया जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Manufacturing of Tractors in India

1771. **Shri R. S. Vidyarathi** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any firm in the country has submitted a proposal to Government for manufacturing 12,000 tractors against Rupees 5 crores only ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) the name of the aforesaid firm ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs: (Shri F.A.Ahmed): (a) to (c) Recently the Punjab State Industrial Development Corporation have submitted a scheme for setting up an Industrial undertaking at Ludhiana for the manufacture of agricultural tractors with a capacity of 12,000 Nos. per annum and a total investment of Rs. 9 crores. This scheme is under examination.

रेलवे में चार्जमैन और फोरमैन

1772. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के चार्जमैन और फोरमैन को मिलने वाली उपलब्धियों और अन्य सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे इसी वर्ग के कर्मचारियों को मिलने वाली उपलब्धियों में अन्तर है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके उत्तरदायित्वों, कार्य के स्वरूप और कार्यभार आदि में क्या विशिष्ट अन्तर है जिसके कारण रेलवे के पर्यवेक्षकों और उपयुक्त उपक्रमों के पर्यवेक्षकों में इतना अन्तर है; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान एन्टी बायटिक्स और उसके कर्मचारियों के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का ध्यान रखते हुए मजूरी ढांचे में उपर्युक्त अन्तर न्याय संगत है, जिसमें विभिन्न उपक्रमों में काम की एक सी क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के लिये, चाहे उनके नियोजक अथवा प्रबन्धक कोई भी हो, एक सा मजूरी ढाँचा रखने के लिये कहा गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी।

रूसी ट्रैक्टरों के लिये टायर तथा ट्यूबों की आयात

1773. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूसी ट्रैक्टरों के लिये टायर तथा ट्यूबों का आयात इस आधार पर बन्द कर दिया है कि इन टायरों तथा ट्यूबों का निर्माण देश में किया गया है और वे उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन टायरों तथा ट्यूबों का निर्माण कर रही, भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं, और पिछले दो वर्षों में इन्होंने किस-किस आकार के तथा कितनी मात्रा में ये टायर तथा ट्यूबें तैयार किये हैं और उन्हें कहाँ बेचा है और वर्तमान सम्भरण स्थिति क्या है;

(ग) क्या टायरों के न मिलने के कारण सैकड़ों रूसी ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है और खाद्य उत्पादन में बाधा पहुँच रही है, और

(घ) यदि हाँ, तो सम्बन्धित अधिकारियों की इस उपेक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ट्रैक्टरों के लिये टायरों और ट्यूबों सम्बन्धी आयात नीति, जो 1967-68 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक में दी गई है, वास्तविक उपभोक्ताओं तथा पुराने आयात कर्ताओं दोनों के लिये शून्य है। परन्तु सभी ट्रैक्टरों के लिये कुछ विशेष किस्मों के टायरों और ट्यूबों की अस्थायी कमी को ध्यान में रखते हुए रूस से उनका कुछ मात्रा तक आयात किये जाने की अनुमति दी गई है।

(ख) ट्रैक्टरों के टायरों और ट्यूबों के निर्माताओं के नाम निम्नलिखित हैं :—

(एक) मेसर्स डनलोप, कलकत्ता

(दो) मेसर्स फायरस्टोन, बम्बई

(तीन) मेसर्स गुड यीअर, बल्लभगढ़

(चार) मेसर्स मद्रास रबड़ फैक्टरी, मद्रास

ट्रैक्टरों के टायरों और ट्यूबों के उत्पादन की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	टायर	ट्यूब
1965	77,813	101,202
1966	90,223	80,876
1967	72,625	79,156

(जनवरी-सितम्बर)

विभिन्न आकारों और पृथक्-पृथक् उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ट्रैक्टरों और टायरों के कुछ आकारों के अलावा अन्य अधिकांश आकारों के सम्बन्ध में हम आत्म-निर्भर हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रतिवेदन सरकार को नहीं मिला है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रावनकोर टिटानियम प्रोडक्ट्स

1774. **श्री नायनार** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ट्रावनकोर टिटानियम प्रोडक्ट्स के विस्तार कार्यक्रम के लिये कोई ऋण देने का वचन दिया है; और यदि हाँ, तो कितना ऋण देने का वचन दिया है;

(ख) क्या सरकार ने वह धनराशि दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो केरल सरकार को कब तक ऋण दिये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ। 1967–68 के बजट में 30 लाख रुपये का ऋण मंजूर करने की व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य सरकार को जब भी आवश्यकता पड़ेगी ऋण की स्वीकृति दे दी जाएगी।

Lock-out in Kalemessari Unit of H.M.T.

1775. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lock-out was declared in Kalemessari (Kerala) unit of Hindustan Machine Tools from 13th September, 1967 ;

(b) if so, the estimated loss as a result thereof ; and

(c) the reasons for the lock-out ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) :

(a) Yes, Sir.

(b) Rs. 60 lakhs approximately.

(c) The workers of Hindustan Machine Tools Factory at Kalemesseri resorted to 'go-slow' tactics from 18th August, 1967, and went on indefinite strike from 9th September, 1967, on the issue of immediate payment of Profit sharing bonus, interim reliefs and special allowances. As there was likelihood of violence and damage to the property of the factory the management declared a lock-out on the 13th September, 1967

Fixation of Railway Fares for Suburban Journeys

1776. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the maximum increase in the fares for suburban journey in the big cities like Calcutta, Bombay and Madras has been fixed at Rupee one ;

(b) whether it is also a fact that this facility has not been extended to the suburban travellers in Delhi ;

(c) whether it is also a fact that thousands of passengers from neighbouring towns travel to and from Delhi daily ; and

(d) if so, the reasons for not extending such facilities to the Delhi passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) (b) and (d). In the case of suburban areas of Bombay, Calcutta and Madras, season ticket fares were put up, from 15.6.1967, by 10% for all distances, for third Class monthly season tickets, the increase was limited to a maximum of Re. 1. On the other hand, non-suburban season ticket fares, which are charged in other cities, including Delhi, were put up (by 10%) only for distances up to 14 kms. The resultant increase in monthly season ticket fares was in no case more than 50 paise. There was, therefore, no occasion for making the maximum of Re. 1 applicable in non-suburban areas.

(c) That is correct, but in the context of the question asked and in view of what is stated above, that has no particular significance.

पारादीप बन्दरगाह में पटसन मिल

1777. **श्री वैधर बेहेरा** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप बन्दरगाह में पटसन का एक मिल स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Non-supply of Spare Wheel with New Vespa Scooters

1778. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the spare wheel along with tyre and tube, which used to be supplied with Vespa Scooter, is not being supplied now and the price thereof is deducted from the price of the scooter ;

(b) whether it is also a fact that this is being done because higher price is obtained for it when sold in black market ;

(c) whether it is also a fact that other spares of the scooter are also sold in black market ; and

(d) if so, the steps taken by Government to check such black marketing ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) No. There has been a shortage of Scooter tyres for original equipment because, while the production of scooters has increased appreciably, the production of scooter tyres has not yet kept pace with the increase in scooter production. The manufacturers of Vespa scooters have, therefore, as a temporary measure, discontinued the supply of the spare tyre in order to avoid curtailment of their production which would not be desirable in view of the heavy pent-up demand for scooters.

(c) No specific instance of black-marketing in the sale of spares for scooters has been brought to Government's notice.

(d) Does not arise.

Vehicles sold in Black-market

1779. **Shri N. S. Sharma** : Will the Minister of **Indiustrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tyres and tubes of cycles, scooters, cars and trucks etc. are sold in the black-market on a large scale ;

(b) whether it is also a fact that the spare parts of scooters and motors etc. are sold in black-market on a large scale ;

(c) if so, the number of persons arrested in this connection during the last three years ; and

(d) the punishment awarded to them ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) No specific instances of large scale selling of tyres and tubes of cycles, scooters, cars and trucks etc. and spare parts of scooters and automobilies in the black market have come to the notice of the Government.

(c) and (d) Do not arise since there is no statutory control on these items.

संयंत्रों की पूरी क्षमता का प्रयोग

1780. **श्री उमानाथ :** **श्री मयावन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राँची स्थित हैवी इंजीनियरिंग काम्पलैक्स और कलकत्ता स्थित माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त संयंत्रों के पूर्ण प्रयोग के लिये सरकार कोई योजना बनाना चाहती है; और

(घ) यदि हाँ, तो योजना की मोटी बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी की तीन परियोजना में से फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट तथा भारी औजार संयंत्र को अभी पूरा किया जाना है और उत्पादन केवल आंशिक रूप में प्रारम्भ हुआ है। हाल में भारी मशीनी औजार संयंत्र में फालतू क्षमता नहीं है किन्तु 1970-71 में समस्या उत्पन्न होगी। चूंकि यहाँ मशीनों का उत्पादन आर्डरों के अनुरूप किया जाता है इसलिए नमूनों औद्योगिक प्रलेखों आदि की तैयारी में लगभग 18 महीने लग जाती हैं। और इसके पश्चात् उत्पादन पर 12 महीने और लगते हैं। उत्पादन का इतना लम्बा चक्र होने के कारण क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में आर्डर अग्रिम रूप से प्राप्त किए जाएं। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि संयंत्र को अग्रिम आर्डरों से लाद दिया जाय और यथा सभव उत्पादन में विवधता भी लाई जाए। निर्यात के लिए मंडियों की खोज की जा रही है।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड

कोयले के उत्पादन के लक्ष्यों में कमी की जाने तथा वर्तमान खानों में मशीनीकरण की अपेक्षाकृत धीमी गति होने के कारण कोयला खनन उपकरणों की माँग एकदम गिर गई और माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन जिसका निर्माण मुख्यतया इन वस्तुओं के निर्माण के लिए किया गया था, को आर्डरों के अभाव के कारण अनुपयुक्त क्षमता की समस्या का संयन्त्र सामना करना पड़ रहा है।

इस स्थिति का सामना करने के लिए कुछ पग उठाए गए हैं जिनमें उत्पादन कार्यक्रम में विविधता तथा पुनर्गठन पुर्जों का मानकीकरण और स्टाक आर्डरों के लिए मानक हिस्सों का निरन्तर सामूहिक उत्पादन इत्यादि शामिल है। इस संयंत्र को आर्डरों से लादने के लिए तमाम सरकारी क्षेत्र के समस्त उपक्रमों और स्वायत्त निगमों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी उन वस्तुओं की आवश्यकताएँ जो माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के उत्पादन कार्यक्रम तथा क्षमता में आती है, को स संगठन से प्राप्त करें।

मैसूर में अयस्क तथा खनिजों के लिये सर्वेक्षण

1781. **श्री क० लकप्पा:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में चिक्का नामक नहल्ली स्थान पर उपलब्ध अयस्क तथा खनिजों की मात्रा का सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या सरकार ने जापानी विशेषज्ञों के सहयोग से कच्चा लोहा उद्योग आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) क्या स्थिति की जाँच करने तथा उद्योग आरम्भ करने का भी सरकार का विचार है, क्योंकि इस क्षेत्र में बढ़िया अयस्क उपलब्ध है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) हाँ, महोदय।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) देश में पिग आयरन काम्पलैक्स को स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाने के लिये कुछ सक्यता जाँचें प्राप्त की गई थीं अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप प्राप्त हो जाने के बाद यह प्रश्न हाथ में लिया जाएगा।

राज्यों में केन्द्र राज्य प्रायोजित उद्योगों में रोजगार

1782. **श्री क० लकप्पा**:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उद्योगों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ।

(ख) सामान्यतः जहाँ नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती से की जाती है तो रिक्त पद का उचित रूप से विज्ञापन किया जाता है। निम्न श्रेणी के रिक्त पदों जैसे लिपिक, चतुर्थ श्रेणी के पद तथा तबदीली पदों का, जिनका वेतनक्रम 500 रुपये प्रतिमास से कम होता है, स्थानीय पत्रों में, नौकरी दिलाऊ दफ्तरों में / उपक्रमों के कर्मचारियों के संगठनों में निर्माण कार्य में लगे व्यक्तियों (जिन में नौकरी से छटनी किये गये सम्मिलिति हैं) आदि में विज्ञापन को ही पर्याप्त समझा जाता हैं। ऊँचे पदों जैसे अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, महा प्रबन्धक (जहाँ वे प्रबन्ध निदेशक का कार्य करते है) और प्रबन्ध सम्बन्धी ऐसे पदों का जिनका वेतन 2,250 रु० प्रतमिास से अधिक है, विज्ञापन देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों और बिक्री क्षेत्रीय भाषाओं तथा काफी बिक्री वाले दैनिक समाचारपत्रों में किया जाना आवश्यक है। इन सब मामलों में ऐसे उम्मीदवार जो कम्पनी की नौकरी में हैं और इन पदों के उपयुक्त हों उन्हें भी बाहरी व्यक्तियों के समान ही आवेदन देने की अनुमति दी जाती है। अन्य सब चीजों के समान रहते हुए, रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

India Belting and Cotton Mills, Serampur

1783. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7958 on the 4th August, 1967 and state :

(a) whether scrutiny of the report of the Investigating Officer in regard to the documents recovered from the Indian Belting and Cotton Mills, Serampur (West Bengal) has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b) The enquiry conducted by the S.P.E. has since been completed. The Registrar of Companies, Calcutta has been instructed to initiate necessary disciplinary proceedings, as per rules, against a non-gazetted member of the staff. The result of this enquiry is awaited. The report furnished by the S.P.E. also involves a gazetted officer and the report together with the relevant papers has therefore been submitted to the Central Vigilance Commission, for their advice. On the receipt of the Commission's advice the matter will be processed further.

Bomb Near Railway Line in Bihar

1784. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7943 on the 4th August, 1967 and state :

(a) the progress made in the investigations in regard to the bombs found near the Railway line, Nayagaon, Bihar ; and

(b) the reasons for delay in investigations, if any ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b) Police investigation is pending finalisation as the report of the Explosive Expert is still awaited.

Stopping of Trains by Public

1785. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the places where the Railway trains were made to stop during the last two years and the places where the trains were stopped by the public and the disruptive elements ;

(b) the number of persons against whom action was taken and the nature of action taken ; and

(c) the loss of life and property suffered as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) to (c) The information regarding the number of cases, places, persons concrened, the loss of life and property suffered as a result of stoppage of trains on Indian Railways throughout the country during the last two years for various reasons and causes is not readily available. The labour involved in collecting the information called for will be too voluminous.

Loaded Wagons Lying on Stations on N. Railway

1786. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 2,000 loaded wagons have been held up on different stations North of Delhi on the Northern Railway ;

(b) if so the commodities along with their quantity contained in these wagons ; and

(c) the reasons for keeping these wagons there for such a long time ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha). (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Reconstruction of Khem Karan Station

1787. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have started reconstruction of the Khem Karan railway station;

(b) if so, the total amount to be spent in this regard and when the work is likely to be completed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The cost of the work will be Rs. 1.41 lakhs approximately and work is expected to be completed by 31.1.1968.

(c) Does not arise.

रेलवे की अर्थ-व्यवस्था में मंदी

1788. **श्री जनार्दनन :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थ व्यवस्था में आयी हुई मंदी का मुकाबला करने में सहायता देने के लिये रेलवे ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है (**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1726/67)

नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात

1789. **श्री जनार्दनन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल जटा के रेशे और नारियल जटा की वस्तुओं के निर्यात में हाल में कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नारियल जटा और नारियल जटा की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) निर्यात में कमी होने के कारण हैं नये ढंग की बढ़िया सूक्ष्म वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा, उन्नति देशों में जीवन स्तर में सामान्य वृद्धि तथा उपभोक्ताओं की बढ़िया किस्मों के उत्पादों के लिये रुचि। निर्यात में कमी होने का कारण कम मुनाफा होने का हो सकता है।

(ग) एक विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

नारियल जटा की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये किये गये उपाय निम्नलिखित हैं:—

(एक) निर्यात बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाये किये गये हैं जैसे विदेशों में प्रचार, प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना, प्रचार साहित्य, दस्तावेजी फिल्मों आदि पर दिखाया जाना।

(दो) यह सुनिश्चित करने के लिये कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म अच्छी हो, नारियल जटा के पावदानों और नारियल जटा के रेशे का निर्यात करने से पहले उनका अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना आरम्भ कर दिया है।

(तीन) नारियल जटा की वस्तुओं को सुन्दर बनाने और परम्परागत उत्पादों को आधुनिक बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। नये उत्पादों जैसे रबड़ मिला कर बनी हुई नारियल जटा की वस्तुयें छल्लेदार वस्तुयें, दीवार पर लटकने वाली वस्तुयें, निर्यात करने के लिये अनिवार्य रूप से बनाई जाती हैं।

(चार) बढ़िया किस्म की वस्तुओं की माँग को पूरा करने के उद्देश्य से नारियल जटा की चटाइयों को हाल में मशीनों से बनाना आरम्भ किया गया है। एक कारखाना स्थापित किया जा चुका है तथा नारियल जटा बोर्ड पाँच हथकरघों वाला एक कारखाना स्थापित कर रहा है। हथकरघों से चटाइयाँ बनाने वाला एक और कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में शीघ्र ही स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

(पाँच) एक प्रतिनिधि मण्डल दिसम्बर 1967 में पश्चिम यूरोप जा रहा है ताकि वह प्रशुलक तथा नारियल जटा उत्पादों के निर्यात सम्बन्धी प्रस्तावकों के उदारीकरण के सम्बन्ध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ बातचीत कर सके।

(छः) नारियल जटा के रबड़ मिले उत्पादों का निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से कुछ अफ्रीकी देशों का दौरा करने के लिये एक दल तैयार किया जा रहा है।

रेलवे की आय

1790. **श्री जनार्दनन :** **श्री चलपाकान्त भट्टाचार्य :**

श्री मोहन स्वरूप :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के प्रथम पाँच महीनों में रेलवे की आय आशा से बहुत कम रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी नहीं। चालू वर्ष के पहले पाँच वर्षों में आय बजट अनुपात से केवल 1.15 प्रतिशत कम रही है।

(ख) आय में कुछ कमी होने के मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में मंदी तथा सड़क यातायात की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा हैं।

(ग) रेल व्यवस्था में सुधार करके उदाहरण के तौर पर माल डिब्बों को पर्याप्त संख्या और समय पर सप्लाई करके माल को शीघ्र लाने ले जाने और सुरक्षात्मक तरीके से माल ले जाने की व्यवस्था करके रेलवे का यातायात बढ़ाने के उपाय किये जा रहे हैं। जहाँ उचित हो दर समायोजन भी दिया जाता है। निस्सन्देह बहुत सी बात इस पर निर्भर करती है कि अर्थ व्यवस्था कैसा रुख लेती है। जहाँ तक कार्यवाही व्यय का सम्बन्ध है इस बात की कड़ी निगरानी की जाती है कि जहाँ तक सम्भव हो किसी भी रूप में व्यय में कमी की जाये।

प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी, पालघाट

1791. **श्री जनार्दनन:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केरल राज्य में पालघाट जिले में प्रीसीजन इस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी का निमाण रोक दिया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जी, नहीं।

दिल्ली से अमृतसर को जाने वाली गाड़ियों का देर से चलना

1792. **श्री अब्दुल गनी दार:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से अमृतसर को जाने वाली फ्लाइंग मेल तथा अन्य एक्सप्रेस गाड़ियाँ बहुधा देर से चलती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन गाड़ियों को नियमित रूप से और समय पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) फ्लाइंग मेल-फ्रन्टीयर मेल तथा दिल्ली-अमृतसर जनता एक्सप्रेस प्राय: ठीक समय पर चलती है। 57 अप जैसी लम्बे रास्ते पर चलने वाली पठानकोट एक्सप्रेस जैसी गाड़ियाँ कुछ कारणों से लेट चली हैं जिनमें खतरे की जंजीर खींचना, सिगनलों का नियंत्रण तथा विफलता, बाढ़ तथा दरारें भी सम्मलित हैं। कुछ क्षेत्रों में एक गाड़ी के लेट होने पर अन्य कई गाड़ियाँ लेट होती हैं। यात्री गाड़ियों पर हर स्तर से निगरानी रखी जाती हैं। उन्हें नियमित रूप से चलाने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

लघु उद्योग

1793. **श्री अब्दुलगनी दार:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1947 से 1960 तक और 1963-64 से 1966-67 तक लघु उद्योगों के लिये प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि दी गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तलाय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1727/67].

भेड़-बकरी के आयात के लिये लाइसेंस

1794. **श्री अब्दुलगनी दार :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जिन पार्टियों को भेड़ बकरी की चर्बी, सोडा बाइकारबोनेट तथा ताड़ के तेल के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने वास्तविक उपभोक्ता हैं;

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक पार्टी / व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु कितनी मात्रा में दी गई;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने यह आयात लाइसेंस प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिये हैं; और

(ङ) क्या उन लाइसेंसों के दिये जाने में की गई अनियमितताओं के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ङ) चूंकि आयात नियंत्रण संगठन के मुख्य कार्यालय तथा बन्दरगाह कार्यालयों से विभिन्न पार्टियों को गत तीन वर्षों में भेड़-बकरी की चर्बी, सोडा बा कारबोनेट तथा चीड़ के तेल के आयात लिये इतने अधिक लाइसेंस दिये गये हैं कि उन सबके बारे में जानकारी एकत्र करने में अत्यधिक श्रम और समय की आवश्यकता होगी जो सम्भव नहीं है।

फिर भी राज्य व्यापार निगम को दिये गये लाइसेंसों के सम्बन्ध ये जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1728/67].

संसद् सदस्यों को फिएट कारों का आवंटन

1795. **श्री अब्दुलगनी दार** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ससद् सदस्यों को फिएट कारें दो वर्ष की बजाय चार वर्ष पश्चात् आवंटित की जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संसद सदस्यों को आवंटन के लिये प्रतिवर्ष कितनी 'फिएट' कारें नियत की जाती हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) फिएट कार की अत्यधिक माँग को ध्यान में रखते हुए संसद सदस्यों को केन्द्रीय सरकार के कोट में पिछली फिएट कार की खरीद की तारीख से चार साल की अवधि पूरी हो जाने से पहले आवन्टन नहीं किया जाता है। सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के बारे में भी जिन्हें केन्द्रीय सरकार के कोटे से कार का आवन्टन किया जाता है यही प्रक्रिया लागू है।

(ग) संसद सदस्यों के लिए 50 कारें प्रति तिमाही का सामान्य कोटा निर्धारित है किन्तु किसी भी तिमाही में संसद सदस्यों की वास्तविक माँग के अनुसार इसमें छूट दे दी जाती है।

मैसर्स अमींचन्द प्यारे लाल एण्ड कम्पनी

1796. **श्री अब्दुल गनी दार** : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :

श्री शिवकुमार शास्त्री: **श्री सूर्य प्रकाश पुरी**:

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल एण्ड कम्पनी के इस्पात के सौदों के बारे में की जा रही जाँच-पड़ताल में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालयमें उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख) अनुमान लगाया जाता है कि माननीय सदस्यों ने (इस्पात सौदों के सम्बन्ध में नियुक्त) जाँच समिति का

जिक्र किया है, जो लेखा समिति के 1966 के 50वें तथा 56वें प्रतिवेदनों में निहित सिफारिशों के आधार पर नियुक्त की गई थी। लोक लेखा समिति के उक्त दोनों प्रतिवेदनों में उल्लिखित सभी स्पष्ट मामलों के सम्बन्ध में यह समिति जाँच करेंगी तथा समिति ने इस सम्बन्ध में अनेक गवाहों से साक्ष्य ले ली है। सम्भवतः जनवरी 1968 तक एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

गेहूं के उत्पादों के लिये भारतीय मानक विशिष्टियाँ

1797. **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय गेहूँ में कम प्रतिशत नमी होती है और विदेशी आयातित गेहूँ में अधिक प्रतिशत नमी होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय रोलर फ्लोर में 1957 में बनाई गई गेहूँ के उत्पादों के बारे में भारतीय मानक विशिष्टियों को अव्यहार्य और अवास्तविक बताया है; और

(ग) यदि हाँ तो फ्लोर मिलों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ। आयतित गेहूँ की कुछ किस्मों में देशी गेहूँ की अपेक्षा अधिक प्रतिशत नमी होती है।

(ख) से (ग) जी हाँ। रोलर फ्लोर मिल्स ने कुछ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता के संबंध में भारतीय मानकों का पुनरीक्षण के लिए निवेदन किया है। सरकार इस पर भारतीय मानक संस्था तथा खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के परामर्श से विचार कर रही है।

दक्षिण कोरिया को रेल के माल डिब्बों का निर्यात

1798. **श्री नम्बियार:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने रेल के माल डिब्बों के निर्यात के लिये दक्षिण कोरिया की सरकार के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्रयादेश कुल कितनी राशि का है; और कितने माल डिब्बों का निर्यात किया जायेगा;

(ग) क्या करार किये जाने के पश्चात् स्पात की कीमतें बढ़ गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या करार का पुनरीक्षण करने या निर्यात के लिये राज्य सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार का दक्षिण कोरिया सरकार से लिखा-पढ़ी करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) 1100 माल डिब्बों के लिये 110 लाख अमरीकी डालर।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल दुर्घटना में हताहत व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाना

1799. **श्री विश्वम्भरन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों अथवा उनके उत्तराधिकरियों को अधिक से अधिक कितनी राशि दी जाती है;

(ख) मुआवजा किस आधार पर निश्चित किया जाता है;

(ग) मुआवजे की अदायगी का विनियमन करने वाले कानून और नियम कब बनाये गये थे; और

(घ) क्या यह सच है कि यदि कोई दर्शक रेल दुर्घटना में हताहत हो जाये तो क्या उसके मामले में रेलवे अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा लागू नहीं होगी; और

(ङ) क्या सरकार का रुपये के मूल्य में कमी हो जाने के कारण तथा नियमों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये अधिनियम तथा नियमावली में संशोधन करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 की धारा 82 क के अधीन आने वाली दुर्घटनाओं के लिये 20,000 रुपये।

(ख) रेलवे दुर्घटनाओंएँ (प्रतिकर) नियम 1950 में निर्धारित अनुसूची के आधार पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की आय पर विचार करने के पश्चात् दावा आयुक्त (क्लेम्स कमिश्नर) मुआवजे की राशि निश्चित करता है।

(ग) 31 जनवरी 1950।

(घ) जी हाँ। इस प्रकार के मामलों से सम्बन्धित दावों को ला आफ टार्टस या बड़ी दुर्घटना अधिनियम 1855 के अधीन लिया जा सकता है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मुआवजे की अधिकतम राशि मार्च 1962 से 10.000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आय समूहों को दिये जाने वाले मुआवजे सम्बन्धी अनुसूची को उदार बनाया गया है।

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्कूटरों का निर्माण

1800. **श्री अब्राहम :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने स्कूटरों के निर्माण के हेतु एक कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस माँगा है;

(ख) क्या यह सच है कि केरल के पप्पाननकोड औद्योगिक बस्ती में मैसर्स रंजन मोटर कम्पनी ने एक पूर्णतया देशी स्कूटर तैयार किया है जिसकी जाँच कर ली गई है और जिसे पूर्णतया संतोषजनक पाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या लाइसेंस देने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हाँ।

(ख) यह फर्म लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ आयातित पुर्जों जैसे फलाईव्हील मैग नैटों और कार-बोटर से स्कूटरों का निर्माण कर रही है।

(ग) स्कूटर बनाने के लिये अतिरिक्त औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Derailment near Howrah

1801. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three bogies of a goods train derailed near Howrah on the 20th August, 1967 ;

(b) whether the enquiry into this accident, which had been ordered by Government, has been completed ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c) : Do not arise.

राजस्थान में गंधक के निक्षेप

1802. **श्री एस्थोस:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में गंधक के बड़े निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हाँ, तो गंधक की अनुमानित मात्रा क्या है;

(ग) उन्हें निकालने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या उन से गंधक निकालने के लिये सरकार कुछ विदेशी सार्थी के साथ सहयोग के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) राजस्थान के सिकार जिले के सलादिपुरा में पाईराइट-पिरोहटाहट (सल्फाइट-अयस्क) के निक्षेप पाये गए हैं।

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ने अभी तक जो अनुसंधान किए हैं उनके फलस्वरूप पाइराइट-पिरोहटाइट के 115 मिलियन टन के अनुमित संचय सतह से 250 मीटर की गहराई पर प्राप्त हुए हैं जिनमें 22.5% गन्धक है। तथापि सिद्ध संचय 15 मिलियन टन के स्तर के ही हैं।

(ग) इन निक्षेपों के विदोहन का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में विमान द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण

1803. **श्री ईश्वर रेड्डी:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में विमान द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) और (ख) हवाई खनिज सर्वेक्षण जो कि आपरेशन हार्ड रोक परियोजना का प्रथम चरण है, आन्ध्र प्रदेश में लगभग पूरा हो गया है। अभी तक 30,500 लाइन किलोमीटर की हवाई उड़ानें पूर्ण की जा चुकी हैं। अभी परिणामों का बताना सम्भव नहीं, क्योंकि अभी प्राप्त की गई सामग्री के निष्कर्ष निकाले जाने हैं। राजस्थान और बाद में बिहार के चुने हुए क्षेत्र जल्दी हाथ में लिए जाएंगे।

(ग) और (घ) इसी प्रकार के सर्वेक्षण दंडकाराण्य और सम्भलपुर बोलंगरि के क्षेत्रों में रूसी सहायता से तथा दूसरे अन्य क्षेत्रों में फ्रान्सीसी सहायता से किये जाने के प्रस्ताव हैं और सम्बन्धित अधिकारियों से बात चीत की जा रही है। एन० जी० आर० आई०, हैदराबाद द्वारा पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों का एरोमैगनेटिक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश में ताँबे और शीशे के निक्षेप

1804. **श्री ईश्वर रेड्डी** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अमरीकी फर्म ने आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में अग्निगुंडाला में पाये गये ताँबे और सीसे के बड़े विशाल निक्षेपों के विकास हेतु सहयोग की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो उस कम्पनी ने सहयोग की क्या शर्तें रखी हैं;

(ग) क्या सरकार ने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली है;

(घ) क्या इन निक्षेपों को निकालने के सम्बन्ध में कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) से (ग) सहयोग सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है तथा इसके विस्तारों पर बातचीत की जा रही है।

(घ) नहीं, महोदय।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था सम्बन्धी थैकर समिति का प्रतिवेदन

1805. **श्री स० मो० बनर्जी** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था सम्बन्धी एम० एस० थैकर समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी नहीं।

(ख) थैकर समिति 22 जुलाई, 1967 को गठित की गई थी और आशा है कि वह अपने गठन से छः महीने के अन्दर सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के लिये निगम

1806. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री राममूर्ति :**

श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री सम्बन्धन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के लिये निगम बनाने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) यह मामला अभी तक विचाराधीन है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों का कार्य-संचालन

1807. **श्री स० मो० बनर्जी** **श्री कंवरलाल गुप्त :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों के कार्य संचालन के बारे में कोई अग्रेतर जाँच की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो किन किन सुधारों का सुझाव दिया गया है; और

(ग) उन सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों के कार्यकलापों की पूछताछ करने के लिये वैज्ञानिकों का कोई दल नियुक्त नहीं किया गया है। तथापि श्री जी० आर०कामत की अध्यक्षता में एक समिति राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यकलापों की पुनरीक्षाकरण रही है। इस समिति में एक खनन इंजीनियर भी है। इस समिति की स्थापना के बारे में एक संकल्प 26–7–67 को सदन के पटल पर रखा गया था। आशा है कि जनवरी 1968 तक समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देगी।

राज्य व्यापार निगम के पदाधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा

1808. **श्री राम चरण :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1965 से 31 अगस्त 1967 तक राज्य व्यापार निगम के पदाधिकारियों द्वारा विदेशों में यात्रा करने पर कितना व्यय हुआ और उसमें विदेशी मुद्रा की कितनी राशि थी; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य व्यापार निगम क अध्यक्ष द्वारा की गई विदेश यात्राओं पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा मैसर्स इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ मशीन्ज को किया गया भुगतान

1809. **श्री राम चरण:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के मशीन टूल एकक के लिये मैसर्स इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ मशीन्ज से कुछ मशीनें खरीदी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय तथा विदेशी मुद्रा के रूप में मैसर्स इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ मशीन्ज को कितनी पृथक-पृथक् धनराशि दी गई है; और

(ग) गत बारह महीनों में न मशीनों की मरम्मत तथा सफाई इत्यादि पर कितना व्यय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह):

(क) जी, हाँ। कुछ मशीनें नई दिल्ली के इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन वर्ल्ड ट्रेड निगम से खरीदी गई हैं।

(ख) अब तक 6.76 लाख रुपयों का भुगतान किया जा चुका है। विदेशी मुद्रा में भुगतान का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(ग) इन मशीनों की मरम्मत और सफाई आदि पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया है। इनकी देखभाल सफाई आदि से सम्बन्धित शर्तों पर विचार किया जा रहा है।

मेढकों की टाँगों का निर्यात

1810. **श्री राम चरण:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ फर्में विभिन्न देशों को मेढकों की टागों का निर्यात कर रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पशु निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत मेंढकों की टाँगों को फ्रीज करने की विधि निर्दयतापूर्ण तथा अमनावीय कृत्य हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पशु कल्याण बोर्ड (खाद्य तथा कृषि मंत्रालय) ने टाँगों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध सरकार से किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो स सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हाँ:।

(ख) जिन्दा मेंढकों की टाँगों को काटना निर्दयतापूर्ण माना गया है। और अब तीन महीने से तो इस उद्योग ने एक नया तरीका अपना लिया है जिसकी सिफारिश मत्स्य-पालन प्रौद्योगिक की के केन्द्रीय संस्थान ने की थी। इस तरीके के अनुसार मारने से पहले मेढक को बेहोश कर लिया जाता है। यह तरीका अनेक फर्मों द्वारा अपनाया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ मशीन्ज लिमिटेड से आयात तथा निर्यात के महानियंत्रक द्वारा मशीनों की खरीद

1811. **श्री राम चरण:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ मशीन्ज लिमिटेड से आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के मशीन टूल एकक के लिये कुछ मशीनें खरीदी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मशीनों का सप्लाइ से पूर्व अथवा पश्चात् किसी सरकारी इंजीनियर द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है;

(ग) क्या मैसर्स इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ मशीन्ज लिमिटेड ने ऐसी कोई गारन्टी दी है कि ये मशीनें एक निश्चित समय तक ठीक ढंग से काम करेंगी;

(घ) क्या यह सच है कि इन मशीनों के कार्य तथा प्रवर्तन से पता लगता है कि ये मशीनें नई नहीं हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो मैसर्स इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ मशीन्ज लिमिटेड अथवा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह):

(क) जी, हाँ। नई दिल्ली के इन्टरनेशनल बिजेनस मशीन वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन से कुछ मशीनें खरीदी गई हैं।

(ख) और (ग) इस प्रकार के निरीक्षण के लिये कोई आवश्यकता न थी क्योंकि खरीद सीधे रूप से की गई थी जो गारन्टी से सम्बद्ध थी।

जो आश्वासन दिये गये हैं उसके अनुसार आई० बी० एम० चलती हुई मशीनों को 90 दिनों तक देख-रेख करेगा और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक मरम्मत करेंगी। मशीनों को ठीक बैठायेगी और बिगड़ जाने पर मशीनों आदि को बदलेगी। उक्त कारपोशन ने यह आश्वासन भी दिया है कि वह एक वर्ष तक मशीनों की खराबियों को ठीक करेगा तथा तकनीकी सहायता भी देगा।

(घ) जी नहीं, मशीने नई हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयना में एल्यूमीनियम कारखाना

1813. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 7 अप्रैल 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 751 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से महाराष्ट्र में कोयना में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले एल्यूमीनियम कारखाने सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) महाराष्ट्र राज्य के कोयना जिले के रतनागिरि स्थान पर एक एल्यूमीनियम परियोजना स्थापित करने के लिये पश्चिम जर्मनी के परामर्शदाताओं द्वारा बनाई गई परियोजना रिपोर्ट पर विचार किया गया है। विचार करने के फलस्वरूप परियोजना के कुछ पहलुओं का पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसका सम्बन्ध मुख्यतया देशी उपकरण तथा सेवाओं का अधिकाधिक प्रयोग यकीनी बनाने से है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से उल्लिखित पुनरीक्षण के बाद निर्णय होने पर परियोजना का मुख्य काम शुरू किया जाएगा। तथापि, आशा है कि कुछ प्रारम्भिक कार्य शीघ्र हाथ में लिये जाएंगे।

जोगीघोपा से गोहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार

1814. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम रेल लिंक बड़ी लाइन को जो इस समय जोगी घोंपा में समाप्त होती है, आगे बढ़ाकर गोहाटी तक ले जाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चलचित्रों का निर्यात

1816. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर 1967 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में विदेशों को कितने चलचित्रों का निर्यात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि में इन फिल्मों से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई और किन-किन चलचित्रों का निर्यात किया गया; और

(ग) सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किन-किन चलचित्रों से कमाई गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) 1962–63, 1963–64, 1964–65 और 1965–66 में क्रमश। 404, 70, 472 और 40 चलचित्र निर्यात किये गये हैं जिनसे 1.52 करोड़, 2.15 करोड़, 2.01 करोड़ और 1.37 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा कमाई गई है। वर्ष 1966–67 तथा अप्रैल-अक्तूबर 1967 में कितने चलचित्र निर्यात किये गये और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

1962–63 से 1965–66 तक तथा अप्रैल 1966 जनवरी 1967 तक निम्नलिखित चलचित्रों ने सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाई:

1. संगम	13,18,000/-
2. अराउण्ड दी वर्ल्ड	11,40,000/-
3. गाइड	3,13,000/-

4. मुगले आज़म	6,74,920/-
5. गीत गाया पत्थरों ने	5,32,500/-
6. मेरे महबूब	5,09,100/-
7. आरजू	5,04,080/-
8. ताज महल	4,72,472/-
9. आई मिलन की बेला	3,20,072/-
10. जंगली	2,66,856/-
11. लीडर	2,60,000/-
12. दोस्ती	2,02,075/-

अक्टूबर 1967 को समाप्त होने वाले गत पाँच वर्षों में कौन-कौन से चलचित्रों का निर्यात हुआ तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई तथा फरवरी-अक्टूबर 1967 के दौरान किन चल चित्रों ने अधिक विदेशी मुद्रा कमाई, इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रॉक फास्फेट का आयात

1817. **श्री नन्द कुमार सोमानी:**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष, 1967-68 में लगभग 13 लाख टन रॉक फॉस्फेट की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) क्या इस वर्ष के पहले चार महीनों अर्थात् जुलाई 1967 तक केवल 1.38 लाख टन का आयात किया गया था जब कि 4.40 लाख टन की आवश्यकता थी और शेष अपेक्षित मात्रा के लिये राज्य व्यापार निगम ने ऐसे करार नहीं किये हैं जहाँ से पूरी मात्रा में माल मिल सके;

(ग) अरब देशों से कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है और स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण कितनी मात्रा कम मिलने की संभावना है; और

(घ) क्या रॉक फॉस्फेट की सप्लाई के सम्बन्ध में इजरायली स्रोतों से और अधिक अच्छा प्रस्ताव आया था जिसे राजनैतिक कारणों से ठुकरा दिया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1967-68 के पहले चार महीनों में राज्य व्यापार निगम मे 1.38 लाख टन रॉक फॉस्फेट का आयात किया है। वर्ष के प्रारम्भ में लगभग 3.75 लाख टन का स्टाक बचा हुआ था। कुल मिलाकर जब तक के लिये पर्याप्त होगा तब तक नया रॉक फॉस्फेट यहाँ पहुँचेगा। राज्य व्यापार निगम ने जितनी मात्रा के लिये समझौते कर रखे हैं वह पूरे वर्ष के लिये पर्याप्त होगी।

(ग) अरब देशों से लगभग 7.1 लाख टन रॉक फॉस्फेट मंगाया जायेगा। यद्यपि स्वेज नहर बन्द होने से निश्चित कार्यक्रम में गड़बड़ी आ गई है फिर भी उसकी कमी होने का कोई डर नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

लाइट रेलवे

1818. **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रेलवे अधिनियम के अध्याय 6 क के अधीन लाइट रेलवे को दी गई छूट को समाप्त करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार लाइट रेलवे को दी गई छूट को वापिस लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुन्नाचा) : (क) जी, हाँ।

(ख) लाइट रेलवे के कर्मचारियों के संगठनों से जो अभ्यावेदन आये हैं वे काम के अधिक घंटों तथा अपर्याप्त विश्राम के बारे में हैं तथा लाइट रेलवे के प्रबन्ध की ओर से जो आभ्यावेदन आये हैं उनमें उन अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का जिक्र किया गया है जो स्थायी उपबन्धों को अमल में लाने के मार्ग में आती हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्ची ऊन का आयात

1819. **श्री मधु लिमये :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में आयात स्थिति की घोषणा होने के पश्चात् कपड़ा आयुक्त की मंत्रणा पर 'वूलन मिल्ज़ फैडरेशन' के नाम में कच्ची ऊन के आयात के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि चार प्रमुख ऊन निर्माताओं को ऊन सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया गया था;

(ग) क्या ये सलाहकार माल खरीदने के लिये विदेश गये थे;

(घ) क्या दिया गया मूल्य प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक था;

(ङ०) क्या वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा सीधे आयात करने की सामान्य प्रक्रिया छोड़ दी गई थी; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इससे विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) जी हाँ।

(घ) से (च) ऊन के मामले में वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा ऊन आयात करने की प्रक्रिया इस दृष्टिकोण को लेकर समाप्त कर दी गई थी ताकि प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक कच्चा माल शीघ्रता से मंगाया जा सके तथा इसका उन सभी एककों में समुचित वितरण किया जा सके जिन्हें पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक द्वारा पहले ही आदेश दिये जा चुके हैं। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने फेडरेशन द्वारा दिये गये मूल्यों की जाँच के आधार पर यह विचार व्यक्त

किया है कि फेडरेशन ने ऊन का मूल्य उससे अधिक नही दिया है जो विभिन्न मिलों ने उसी प्रकार की ऊन के लिये उसी अवधि में दिया था। इस प्रकार विदेशी मुद्रा की हानि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई की कुछ फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के मामले में की गई अनियमितताएं

1820. **श्री मधु लिमये:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डंकन स्ट्रैल एण्ड कम्पनी, गैमन इंडिया लि० बम्बई, बाम्बे आक्सीजन तथा अन्य फर्मों द्वारा की गई अनियमितताओं और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस बारे में जाँच लगभग 2½ वर्ष से लम्बित है;

(ग) क्या ठोस कार्यवाही की गई है तथा दोषी व्यक्तियों को क्या दंड दिया गया है; और

(घ) यदि कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है और सजा नहीं दिलाई गई है तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) हाँ श्रीमान्।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1729/67**]

कपास के मूल्य

1821. **श्री मधुलिमये**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास रुई के मूल्यों में हाल ही के सप्ताहों में कोई कमी हुई है;

(ख) क्या मूल्य अब भी समर्थन मूल्यों से अधिक हैं;

(ग) कपास के मूल्यों में किसी अचानक कमी के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। और

(घ) क्या किसानों को प्रोत्साहन देने के रूप में समर्थन मूल्यों में वृद्धि का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) जब कि कुछ सप्ताह पूर्व कच्ची रुई के मूल्यों में गिरावट देखी गई थी, वे फिर भी निम्नतम समर्थन मूल्यों से अधिक थे। अभी हाल ही में कपास के मूल्यों में फिर वृद्धि हुई है और कुछ मामलों में तो निम्नतम समर्थन मूल्यों से मूल्य 50 प्रतिशत तक अधिक हैं। कपास के मूल्यों में अचानक गिरावट आने का कोई कारण नहीं है।

(घ) जी नहीं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चावल का निर्यात

1822. **श्री मधु लिमये:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि राज्य व्यापार निगम ने अच्छी किस्म के बासमती चावल लगभग 60 टन का निर्यात 88,830 रुपये में किया है जो कि बहुत ही कम कीमत है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य व्यापार निगम ने इस चावल का निर्यात किस भारतीय अथवा विदेशी फर्म के माध्यम से किया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस चावल को प्राप्त मूल्य के लगभग दुगने मूल्य पर बेचा जा सकता था; और

(घ) इससे विदेशी मुद्रा की जो हानि हुई है उसके बारे में क्या कोई जाँच आदेश दिया गया हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (घ) सरकार ने बासमती चावल का निर्यात मूल्य 75 पौंड प्रति मीट्रिक टन निश्चित किया है। इससे कम पर राज्य व्यापार निगम ने कोई चावल निर्यात नहीं किया है। 77–17 शिलिंग की दर पर राज्य व्यापार निगम ने जनवरी 1966 में मैसर्स ज्ञान चन्द ऐंड कम्पनी सिंगापुर के साथ 400 मीट्रिक टन बासमती चावल निर्यात करने के लिये करार किया था 1 सितम्बर 1967 में निगम ने 60 मीट्रिक टन निर्यात किया जिसका मूल्य 98,091 रु० बनता है। जब राज्य व्यापार निगम ने करार पर हस्ताक्षर कर दिये थे तो एक प्रतिस्पर्धी देश ने 70 पौंड प्रति मीट्रिक टन की दर से बासमती चावल देने की पेशकश की थी। इसलिये विदेशी मुद्रा की कोई हानि नहीं हुई है।

कटक से पारादीप पत्तन तक रेलवे लाइन

1823. **श्री प्र० के० देव:**

क्या **रेलवे** मंत्री 26 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक को परादीप पत्तन से मिलाने वाली रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस लाइन का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे मंत्री श्री (चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) योजना आयोग की अनुमति प्राप्त करने के बाद इस लाइन का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के दलकोल्हा और तेलता स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना

1824. **श्री नायनार:** **श्री ओ० प्र० त्यागी:**
श्री हेम बरुआ:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के दलकोल्हा और तेलता स्टेशनों के बीच 15 अगस्त, 1967 को एक दुर्घटना हुई थी;

(ख) उस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए;

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे और क्या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ, ।

(ख) इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप 19 व्यक्ति तत्काल मरे 29 घायल हुए जिनमें से 22 गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों में से एक अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में मर गया और 7 अस्पताल में मर गये।

(ग) यह दुर्घटना कुछ व्यक्तियों द्वारा छत पर सफर करने से हुई जबकि ऐसा करना भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 118 (2) के विरुद्ध है।

(घ) छत पर सफर करना भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 118 (2) के अन्तर्गत अपराध है।

सभी स्टेशनों पर छत पर बैठे व्यक्तियों को रेलवे पुलिस द्वारा उतार दिया जाता है।

काकिनाडा पत्तन में कच्चे लोहे की चोरी

1825. **श्री बाबू राव पटेल** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या काकिनाडा पत्तन में निर्यात के लिये घाट में जमा किये हुए कच्चे लोहे की नियमित रूप से चोरी की जा रही है और यदि हाँ, तो पिछले एक वर्ष में कितना लोहा कम हुआ है;

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वर्ष 1967 में इस कारण कितनी हानि ई;

(ग) क्या यह सच है कि चुराया गया कच्चा लोहा विजयवाड़ा, हैदराबाद तथा वैलोर जैसे स्थानों में उपलब्ध है; और

(घ) कच्चे लोहे की ऐसी दिन दहाड़े लूट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को काकिनाडा पत्तन पर कच्चे लोहे को चीरी के कारण कुछ हानि का पता लगा है। चोरी हुए कच्चे लोहे को पुलिस द्वारा बरामद भी किया गया है। हानि का सही अनुमान स्टाक लेने के पश्चात् ही लगाया जा सकता है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी है और मामला विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

इन्टेग्रल कोच फैक्टरी को इस्पात की चादरों की सप्लाई

1826. **श्री बाबू राव पटेल:** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास की इन्टेग्रल कोच फैक्टरी में उपयोग के लिये 6,000 मीट्रिक टन भार की विशेष इस्पात की जिन चादरों का क्रयादेश दिया गया था और जो फ्रांस की एक फर्म ने सप्लाई की थीं, उनमें ताँबे का अंश बिलकुल भी नहीं था, जबकि उनमें 0.2 से लेकर 0.35 प्रतिशत तक ताँबे का अंश होना चाहिये था;

(ख) क्या यह भी सच है कि लन्दन स्थित इण्डिया सप्लाई मिशन ने इन इस्पात की चादरों का निरीक्षण किया था और उन्हें पास किया था और यदि हाँ, तो सम्बन्धित अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने घटिया किस्म के माल को किस कारण पास किया;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह जानने के बाद भी कि पिछले वर्ष सप्लाई की गई इन इस्पात की चादरों की 3,000 मीट्रिक टन भार की पहली खेप की चादरों में अपेक्षित प्रतिशतता में ताँबे का अंश नहीं है, इन्टेग्रल कोच फैक्टरी ने 3,000 मीट्रिक भार की और चादरों के लिये क्रयादेश दिया और यदि हाँ, तो सम्बन्धित अधिकारियों के नाम एवं पद क्या हैं तथा उनके द्वारा ऐसा काम किये जाने के क्या कारण थे ; और

(घ) निम्न स्तर के तथा घटिया किस्म की इन इस्पात की चादरों के लिये तथा उसके द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिये उत्तरदायी सभी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) इन्टे ग्रल कोच फैक्टरी द्वारा प्राप्त किये गये 6530 टन इस्पात में से लिये गये बहुत सारे नमूनों में से अधिकांश नमूनों में ताँबे की मात्रा 0.2 से लेकर 0.35 प्रतिशत से भी कम थी।

(ख) आई० एस० एम०/लन्दन के तकनीकी अधिकारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुसार इस्पात का परीक्षण किया था। उनके भौतिक गुण विशिष्ट विवरण के अनुसार थे।

(ग) क्रयादेश दिय गये 6530 टन में से, इन्टैग्रल कोच फैक्टरी ने कुछ नमूनों के आधार पर इस्पात की चादरों में ताँबे की कमी बताई थी। इस अवस्था पर रेलवे बोर्ड द्वारा इस फर्म को टेन्डरों के आधार पर 2,708 टन चादरों के लिये क्रयादेश दिया गया था। शिकायत की पुष्टि के पश्चात् क्रमादेश को रद्द कर दिया गया है।

(घ) मामला विचाराधीन है और जाँच का परिणाम पता लगने के पश्चात् उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

भौतिक गुण दोष तथा लचीलापन संतोषजनक था और इसीलिये यात्रियों को सुरक्षा को संकट में डालने का प्रश्न ही नहीं उठता। संक्षारण को रोकने के लिये इस्पात में ताँबा मिलाया जाता है ; यह डिब्बों पर रंग करने के अतिरिक्त है।

विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का कारखाना

1827. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **इस्पात,, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने के कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव को चतुर्थ परियोजना में शामिल करने के बाद उसे समाप्त कर देने का क्या कारण हैं;

(ख) पोलैंड के तकनीकी दल को, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसने अक्तूबर, 1964 में जस्ता पिघलाने का कारखाना स्थापित करने की सम्भाविता का अध्ययन करने के लिये भारत का दौरा किया था, उपपत्तियाँ क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने एक पोलिश फर्म सेंट्रोजैप के साथ परियोजना सम्बन्धी एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे और यदि हाँ तो सेंट्रोजैप के साथ समझौते की शर्तों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(घ) पोलिश फर्म द्वारा सितम्बर, 1966 तक ठीक-ठीक कितना काम किया गया है और सरकार द्वारा उसे कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ङ०) सरकार को कुल कितनी हानि हुई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) चौथी योजना काल के दौरान हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं में एक परियोजना विशखापट्टनम से पोलिश तकनीकी और आर्थिक सहायता से स्थापित किया जाने वाला जस्ता-प्रद्रावक था। फिर भी उच्च अग्रता प्राप्त परियोजनाओं के लिये संसाधनों के पुनः आवंटन के कारण चौथी

(च) सरकार विशखापट्टनम की जस्ता प्रद्रावक परियोजना को फिर से पुर्न जीवित करने की सम्भावना पर विचार कर रही है। अतः स अवस्था में किसी हानि का प्रश्न नहीं उठता।

काण्डला में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

1828. **श्री मनोहर लाल सोंधी :** **श्री चं० चु० देसाई :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काण्डला में निर्बाध व्यापार क्षेत्र को, 10 वर्षों के पश्चात् भी कोई सफलता नहीं मिली है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में देशाभ्यन्तर परिवहन सुविधाओं, पीने के पानी और बिजली की कमी है;

(ग) क्या 330 प्रार्थनापत्रों में से केवल 110 को निर्बाध क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी और मुश्किल से दो कारखानों ने उत्पादन आरम्भ किया है;

(घ) क्या परियोजना से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आशाएँ पूरी नहीं हो सकी हैं; और

(ङ०) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या भारतीय उपक्रमियों को विशेषकर हाँगकाँग, सिंगापुर और नैरोबी से भारतीय उपक्रमियों को आकर्षित करने के लिये और अधिक रियायतें देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं। काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में विकास कार्य लगभग 3 वर्ष पहले आरम्भ किय गये थे और काम का मोटा भाग अब तक पूरा कर लिया गया है। चार कारखानों ने पहले से ही उत्पादन आरम्भ कर दिया है जिनमें से एक कारखाने ने अब तक 11.65 लाख रु० के मूल्य का माल निर्यात किया है।

(ख) जी, नहीं। क्षेत्र में इन कारखानों को पर्याप्त अन्तर्देशीय परिवहन सुविधाएँ, पेय जल तथा बिजली उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने के लिये प्राप्त हुए 386 प्रार्थनापत्रों में से 135 एक चयन समिति द्वारा अनुमोदित कर लिये गये थे। 73 पक्षों ने अपना काम चालू करने के लिये प्लाटों पर कब्जा कर लिया है। 26 पक्षों द्वारा दी गई कारखानों के निर्माण की योजनाओं को मंजूर कर लिया गया है। इस समय चार कारखानों में उत्पादन चालू है, और अधिक में शीघ्र उत्पादन आरम्भ होने की आशा है। नये कारखानों की स्थापना में कुछ समय लगता है।

(ङ) हालही में कुछ रियायतों की घोषणा की गई है। सरकार निरन्तर रूप से इस बात की जाँच कर रही है कि निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उद्योगपतियों और व्यापारियों को आकर्षित करने के लिये और क्या सुविधाएँ दी जा सकती हैं।

ट्रांजिस्टर के सेलों का वितरण

1829. **श्री म० ला० सोंधी:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेल बनाने वाली कम्पनी द्वारा ट्रांजिस्टरों के लिये सैल वितरित किये जाने की वर्तमान नीति संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) क्या वर्तमान व्यवस्था से रेडियो व्यापारियो और विशेषकर जनसाधारण को उचित रूप से और पर्याप्त मात्रा में सैल सप्लाई नहीं किये जाते है ; और

(ग) ट्रांजिस्टर व्यापारियों और ट्रांजिस्टर प्रयोगकर्ताओं को सेलों की निश्चित सप्लाई हो इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) पहले सूखी बैटरी प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हुआ करती थीं, किन्तु इस उद्योग के प्राथमिकता उद्योगों की सूची में आने के बाद से स्थिति सुधर गई है। जब कभी गलत विवरण व्यवस्था के संबंध में शिकायतें आईं, तो उन्हें निर्माताओं की जानकारी में लाया गया और उन्होंने, इन्हें दूर करने के लिये कदम उठाये। बड़े और मझौले सहकारी भण्डारों (स्टोरों) ने जो निर्माताओं या अपने थोक विक्रेताओं से सीधे ही माल लेते हैं, उपभोक्ताओं तथा आम जनता की रुचि का ध्यान रखा। वितरण का विनियमन करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी करने के प्रश्न पर भी यदि कभी ऐसी स्थिति आई तो विचार किया जायेगा।

Parliament Assistants in the I. D. & C. A. Ministry

1830. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7274 on the 28th July, 1967 and state :

(a) whether the matter of rotation of appointment of Parliament Assistants has since been reviewed ; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed).

(a) Yes, Sir.

(b) Both the Parliament Assistants in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs who had completed more than 3 years in their posts, have since been replaced.

आसाम में तंगला से मंगलादायी और खरुपतिया तक रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना

1831. **श्री हेम बरुआ:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आसाम में रेलवे लाइन को तंगला से मंगलदायी और खरुपतिया तक बढ़ाने को है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): ((क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में बड़ी लाइन का विस्तार

1832. **श्री हेम बरुआ:**

क्या **रेलवे** रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी लाइन का विस्तार करने के लिये पश्चिम आसाम के कुछ क्षेत्रों में हाल में सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सर्वेक्षण के लिये किन-किन क्षेत्रों को चुना गया था; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Tractor Factory in Punjab

1833. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Punjab Government have submitted a proposal to the Central Government for the setting up of a factory to manufacture tractors with foreign collaboration ; and

(b) if so, the place where this factory would be set up and the conditions for the foreign collaboration ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed : (a) An application for the grant of an industrial licence for the establishment of an undertaking for the manufacture of tractors has been received from the Punjab State Industrial Development Corporation.

(b) The proposal is to set up the factory at Ludhiana.The Corporation have stated that the scheme would be implemented with foreign collaboration in the shape of a consultancy agreement but the details thereof have not so far been furnished.

M/S. Raymon Engineering Works Calcutta

1834. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether M./S Raymon Engineering Works,Calcutta were given any contract by his Ministry during the last five years ;

(b) whether it is also a fact that this firm has not supplied the material so far;

(c) if so, the value and particulars of the materials required to be supplied under the contract and the action taken against the firm ; and

(d) if no action has been taken against the firm, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Import of Rubber

1835. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints against the import licences for rubber being granted indiscriminately ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) and (b) Some representations were received stating that licences for import of rubber have been issued in excess of requirements. The allegation was not found to be tenable. No licences have so far been issued for imports for the 1967-68 period.

Manufacture of Small Car

1836. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri J. K. Mondal :**

Shri Valmiki Chaudhary : **Shri N. K. Somani :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have since taken a decision to manufacture the small car ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the date by which a decision is likely to be taken ; and

(d) the details of the Indian and foreign proposals received in this connection ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A . Ahmed):

(a) Not yet.

(b) Does not arise.

(c) Government are desirous of taking an early decision in the matter.

(d) It is not considered proper to divulge at this stage, details of the various proposals, before these have been examined and a decision taken.

पानीपत और गोहाना के बीच रेल संपर्क

1837. **श्री रणधीर सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाना के लोगों द्वारा निरन्तर रूप से की गई इस माँग की जानकारी है कि उत्तर रेलवे की रोहतक पानीपत शाखा पर पानीपत और गोहाना के बीच फिर से रेल सेवा आरम्भ की जाये ;

(ख) यदि हाँ. तो यह रेलवे लाइन फिर से कब चालू होने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में 26 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 644 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसमें बताई गई स्थिति अब भी नहीं है।

हरियाना में रेलवे लाइनें

1838. **श्री रणधीर सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले चार वर्षों में हरियाना में कितने मील लम्बी रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है तथा कौन-कौन सी लाइनें बिछायी जायेंगी ;

(ख) क्या हरियाणा सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) चतुर्थ योजना में नई लाइनों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) नये हरियाणा राज्य की सरकार ने रेलवे मंत्रालय को नई लाइनों के लिये अभी कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं भेंजी हैं।

हरियाना में ट्रैक्टर परियोजना

1839. **श्री रणधीर सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरियाना राज्य में किसी स्थान पर किसी विदेशी सहयोग अथवा किसी अन्य उद्योग के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रताव का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्यमंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोहतक में इस्पात का कारखाना

1840. **श्री रणधीर सिंह:** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हरियाना खनिजों की दृष्टि से सम्पन्न है, सरकार का विचार उस राज्य में रोहतक में एक इस्पात कारखाना खोलने का है;

(ख) यदि हाँ तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी):

(क) इस समय एसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रोहतक में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

रेलगाड़ियों की टक्कर तथा पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं

1841. **श्री रणधीर सिंह:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवीय तत्वों के कारण रेल की टक्कर या उसके पटरी से उतर जाने की दुर्घटनाओं को रोकने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) रेलवे प्रशासन का यह बराबर प्रयत्न रहता है कि मानवीय असफलताओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को कम से कम किया जाये। काम की हालतों में सुधार करने के लिये निरन्तर रूप से प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि कर्मचारियों से कम गलतियाँ हों। कर्मचारियों में चेतना पैदा करने के लिये एक चहुमुखी अभियान चालू

किया गया है। ऐसी रेल दुर्घटनाओं की संख्या जिनके लिये रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार ठहराये गये थे 1961-62 में 1,056 थी और वह 1966-67 में कम होकर 679 रह गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Trade with Iraq

1842. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an eight member Indian trade delegation under the leadership of Shri Patanwala visited Iraq in August with a view to fostering trade between India and Iraq ;

(b) whether the delegation has on return from Iraq, submitted a report to Government on the possibility of increasing trade between the two countries ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) whether the delegation also visited any other country in addition to Iraq and if not, the reasons for visiting Iraq alone ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Delegation has submitted a report to the Federation of Indian Export Organisations which had sponsored its visit.

(c) The report has been published by the FIEO and widely circulated to interested parties. According to the report, there is considerable scope for export of items such as batteries, diesel engines and pumps, pharmaceuticals and toilet requisites to Iraq. There is also a large potential in Iraq for setting up joint ventures in a variety of fields according to the survey carried out by the Delegation.

(d) The Delegation also visited Kuwait and Saudi Arabia.

सरकारी सीमेंट कारखाना सुवाखेडी

1843. **स्वतंत्र सिंह कोठारी:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नीमच के निकट सुवाखेड़ा में सरकारी सीमेंट कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस कारखाने का निर्माण कार्य पूरा होने तथा इसमें उत्पादन आरम्भ होने की क्या निश्चित की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया से नीमच (मध्य प्रदेश) में 2 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

नये उद्योग

1844. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशी तथा देशी उपक्रमियों ने सरकार को सूचित किया है कि परियोजनाओं की स्वीकृति दी जाने तथा विभिन्न सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा बड़ी संख्या में अपे-

क्षित लाइसेंस तथा मंजूरियाँ दी जाने में विलम्ब होने के कारण नये उद्योगों को स्थापित करने में बहुत समय और शक्ति नष्ट हो जाती है जिसे बचाया जा सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो लाइसेंस देने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, लालफीताशाही को कम करने और उद्योगों को स्थापित करने के लिये न्यूनतम समय में मंजूरी की जाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) समय समय पर यह बता दिया गया है कि औद्योगिक लाइसेंस विदेशी सहयोग की स्वीकृति इत्यादि जैसे नियन्त्रणों को लागू करने में देरी हो जाती है; सरकार नियन्त्रण की बराबर समीक्षा करती रहती है और जहाँ कहीं ऐसा लगा है कि किसी नियन्त्रण का बने रहना जनता के हित में आवश्यक नहीं है और नियन्त्रण समाप्त किया जा सकता है, तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। हाल ही में कुछ उद्योगों से जो लाइसेंस हटा दिये गए हैं वह इसी नीति के द्वारा किया गया है।

यूरोप और अमरीका में चाय संमिश्रण कारखाने

1845. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूरोप और अमरीका में चाय सम्मिश्रण कारखानों के स्थापित किये जाने को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं जिससे भारतीय चाय को भिन्न-भिन्न पैकटों और छोटी थैलियों में बेचा जा सके और उसके वर्तमान मूल्यों की अपेक्षा ऊँचे मूल्य प्राप्त हो सकें।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : यूरोप तथा अमरीका दोनों में पहले से ही चाय पैक करने वाले और संमश्रिण करने वाले बड़ी संख्या में हैं जो विभिन्न देशों से आयात की गई चाय को संमिश्रण करके परचून में बेचते हैं। अतः संमिश्रण और पैक करने वाले कारखानों को स्थापित करने के लिये और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यूरोप में भारत के चाय के संमिश्रण कर्ताओं और पैकरों को प्रोत्साहन देने के लिये कदम उठाये गये हैं। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर भारतीय चाय 20 प्रकार के भिन्न पैकेटों में उपलब्ध है। अमरीका में पूर्ण रूप से भारतीय चाय का कोई पैकेट बड़े पैमाने पर नहीं बेचा जा रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में अमरीका में बड़ी संख्या में सुपरबाजारों के द्वारा शुद्ध भारतीय चाय के पैकेटों की बिक्री के लिये एक योजना मंजूर की है।

बिजली से चलने वाले लघु उद्योग

1846. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत चलित छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में ऐसे उद्योगों की स्थापना करने के बारे में क्या प्रवृत्ति रही ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के लघु उद्योग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लघु उद्योगों की सहायता की गई है वे सामान्यतया विद्युत चालित उपकरण इस्तेमाल करते हैं। इस कार्यक्रम

के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाएँ निम्नलिखित हैं :

1. तकनीकी सहायता
2. चल तथा कार्यवाहक पूंजी के लिए
3. औद्योगिक बस्तियों में कारखानों के लिए निर्मित स्थान दिया जाना।
4. किराया खरीद आधार पर मशीनों का उपलब्ध किया जाना।
5. सहायक उद्योगों के रूप में विकास।
6. सरकारी माल खरीद कार्यक्रम में भाग लेना।
7. बिजली की सप्लाई में आर्थिक सहायता।
8. कच्चे माल, पुर्जों आदि का सम्भरण।

(ख) कुछ समय से लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन की दिशा में परम्परागत वस्तुओं के स्थान पर जटिल मशीनों उत्पादों में विशेष परिवर्तन हुआ है। लघु उद्योग एकक उत्पादन के आधुनिक तरीकों को न केवल अपने विद्यमान उत्पादन क्षेत्र में ही प्रयोग कर रहे हैं अपितु उत्पादन की नई-नई वस्तुओं के निर्माण की ओर भी ध्यान दे रहे हैं जैसे इलेक्ट्रानिकस, प्लास्टिक रसायन तथा वैज्ञानिक औजार इत्यादि।

इस्पात कारखानों को दिये गये कोयले का मूल्य

1847. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात कारखानों को दिये जाने वाले कोयले के मूल्य में कितनी वृद्धि करने की माँग कोयला उद्योग ने की है;

(ख) अन्ततोगत्वा मूल्यों में कितनी वृद्धि करना तय हुआ है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इस्पात कारखानों को कितना अतिरिक्त व्यय प्रति वर्ष करना पड़ेगा; और

(घ) क्या समुचित ढंग से नमूने का निरीक्षण करके कोयले का गुण प्रकार कायम रखा जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी): (क) कोक कोयले के विनियन्त्रण के पश्चात् कोयला उद्योग ने 11 रु० प्रति टन की मूल्य वृद्धि की माँग की थी (18 प्रतिशत राख वाले कोयले पर आधारित थी)।

(ख) 1 सितम्बर, 1967 से सभी श्रेणियों के कोक कोयले के मूल्य में 5 रु० प्रति टन की वृद्धि करना मंजूर कर लिया गया है।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और मैसर्स टाटा आयरन ऐंड स्टील कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के आधार पर अनुमान है कि कोक कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण प्रति वर्ष अनुमानत: 9 से 10 करोड़ रु० अतिरिक्त व्यय होगा। ऐसी ही जानकारी मैसर्स इन्डिया आयरन ऐंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अनुमान लगाया जाता है कि इस इस्पात कारखाने में कोक कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण लगभग 1 करोड़ रु० प्रति वर्ष अतिरिक्त व्यय होगा।

(घ) नमूने की एक सामूहिक स्वीकार्य पद्धति निकालने के लिये संयुक्त नमूने की समूची समस्या की जाँच करने के लिये ओक कोयले के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की गई है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तकनीकी दोष

1848. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने सम्बन्धी पांडे समिति के प्रतिवेदन में बाताये गये दोषों को दूर करने के लिये ब्रिटेन के विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) करखाने के प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी हाँ।

(ख) व्हील तथा एक्सल संयंत्र को संतोषजनक ढंग से चालू कराने के लिये विदेशी विशेषज्ञों की अपेक्षित सहायता का अनुमान लगाने के लिये दो ब्रिटेन के विशेषज्ञ पहले ही 26-8-67 को दुर्गापुर पहुँच चुके हैं तथा वे इस मामले की जाँच कर रहे हैं। उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है । इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के समुद्रपार विकास मंत्री, ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन की सलाह से तकनीकी सहयोग देने के लिये दुर्गापुर इस्पात कारखाने की अन्य आवश्यकताओं का अध्ययन करने हेतु एक दल भेजने को सहमत हो गये हैं।

(ग) कारखाने के प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:

(एक) जनरल मैनेजर, मुख्य अधीक्षक (कोक ओवन) तथा मैनेजर (ढलाईघर) को बदल दिया गया है।

(दो) एक नया जनरल अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया है।

(तीन) कोक ओवन विभाग का सारा कार्यभार एक नये मुक्य अधीक्षक को सौंप दिया गया है।

(चार) जनरल अधीक्षक की सहायतार्थ सहायक जनरल अधीक्षक के दो नये पद बना दिये गये हैं—एक का काम उत्पादन, योजना तथा नियंत्रण, देखरेख संगठन इत्यादि से सम्बन्धित मामलों की देख भाल करना है और दूसरे का काम संचालन सम्बन्धी मामलों और मुख्यतया बेलन मिलों के मामलों की देखभाल करना है।

(पाँच) भिलाई और रुरकेला से दक्ष कर्मचारियों—जनरल फोरमैन, सहायक अधीक्षक इत्यादि का तबादला करके कोक-ओवन, उप-उत्पाद संयंत्र, इस्पात पिघलाने की दुकान आदि का कार्य संचालन को अधिक सुचारु कर दिया गया है। उच्च स्तर पर दोनों प्रकार से अर्थात् तकनीकी दृष्टि से और प्रशासनिक तथा औद्योगिक दृष्टि से, इसे और शक्तिशाली बनाने का विचार किया जा रहा है।

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

1849. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों में विश्व में पटसन के समुचे व्यापार में भारत के हिस्से में काफी कमी हो गई है।

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) पटसन की वस्तुओं के निर्यात को गिरने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हाँ ।

(ख) कमी इन कारणों से हुई है:

(ए) अन्य निर्यातिक देशों और विशेषतया पाकिस्तान द्वारा प्रतियोगिता किये जाने के कारण;

(दो) अन्य देशों में पटसन मिल स्थापित किये जाने के कारण; और

(तीन) नकली वैकल्पिक वस्तुओं की प्रतियोगता तथा बल्क हैंडलिग इत्यादि के कारण।

(ग) एक विवरण संलग्न है (पुस्ताकलय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1730/67)

"एक्सपो-67" कनाडा में भारतीय मंडल

1850. **श्री काशी नाथ पाण्डे : श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) कनाडा में "एक्सपो--67" में भारतीय मंडप पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है;

(ख) उस प्रदर्शनी में अब तक कितने आदेश प्राप्त किये जा चुके हैं; और

(ग) उसके फलस्वरूप कितनी हानि अथवा लाभ हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) अक्तूबर, 1967 के अन्त तक प्रदर्शनी में भाग लेने पर भारत द्वारा 1,96,49,127.08 रुपये खर्च किये गये ।

(ख) हमारे प्रदर्शनों में भाग लिये जाने के परिणामस्वरूप 31 अक्तूबर, 1967 तक 5,49,450.00 कनाडा डालर जो कि 36,63,000.00 रुपये के बराबर होते है के आदेश प्राप्त किये गये अथवा इनके बारे में बातचीत जारी है। इस के अतिरिक्त बाऊनटीक पर 12,86,529.61 कनाडा डालर (85,76,864.07) रुपये और वहाँ स्थापित किये गये भारतीय रेस्तरां पर 4,85,589.88 कनाडा डालर (32,37,265.86 रुपये) की बिक्री की गई ।

(ग) "एक्सपो" कोई व्यापार मेला नहीं था, अपितु यह एक विश्व प्रदर्शनी थी, जिसका उद्देश्य था "मानव और उसका संसार" तथा इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा बिभिन्न क्षेत्रों जैसे बौद्धिकता, अर्थशास्त्र, विज्ञान, इंजीनियरी, संस्कृति तथा धर्म में की गई प्रगति को प्रतिबिंबित करने के लिये इस प्रदर्शनी में भाग लिया गया था। तथापि इस अवसर का लाभ कनाडा तथा अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिये भी उठाया गया। व्यापार के बारे में बहुत सी पूछताछ की गई और सम्बन्धित संगठन उन पर अग्रेतर कार्यवाही कर रहे हैं। "एक्सपो 67"

में भाग लेने से हमें अपनी निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओं का विश्वव्यापी प्रचार करने का अवसर भी मिला। भारत द्वारा "एक्सपो-67" में भाग लिये जाने के जो परिणाम निकले हैं, वे काफी उत्साहवर्द्धक हैं, परन्तु इस प्रकार की परियोजना--जो कि वणिज्यक न हो--के लाभ अथवा हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

टेलीविजन सेटों का आयात

1851. **श्री काशी नाथ पाण्डेय:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967 में अब तक विभिन्न देशों से कितने टेलीविजन सेटों का आयात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): जनवरी से जुलाई, 1967 तक आयात किये गये टेलीविजन सेटों की संख्या तथा मूल्य निम्नलिखित है:

I. टेलीविजन प्रसारण रिसीवर सेट, जोड़े जुड़ाय अथवा अन्यथा	संख्या एकक संख्या	'000' रुपयों में मूल्य
जर्मनी (एफ० आर० पी०)	5	29
यूगोस्लेविया	498	451
ब्रिटेन	1	2
जापान	3	3
नीदरलैंड	3	3
अमरीका	3	6
कुल ..	513	494

राज्य व्यापार निगम द्वारा नियुक्त वितरण एजेंट

1852. **श्री काशी नाथ पाण्डेय:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों से आयात के लिये 1960 से 1967 (अब तक) राज्य व्यापार निगम ने कितने बिक्री अथवा वितरण एजेन नियुक्त किये; और

(ख) एजेंटो के नाम क्या हैं तथा उन्हें किस वस्तु के लिये एजेंट नियुक्त किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये ब्रिटेन से सहायता

1853. **श्री काशी नाथ पाण्डे :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वह दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये अक्तूबर, 1967 में लन्दन गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो ब्रिटिश सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये क्या सहायता प्रदान की है ?

इस्पात खान, तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) मेरी अक्तूबर, 1967 की लन्दन यात्रा के दौरान जिन विषयों पर चर्चा की गई, तकनीकी सहायता का प्रश्न भी उन में से एक था।

(ख) ब्रिटेन के समुद्र पार विकास मंत्री, ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन की सलाह से इस कारखाने को पूरी क्षमता से चलाने के लिये तकनीकी सहयोग देने अन्य आवश्यकताओं का अध्ययन करने हेतु एक दल भेजने को सहमत हो गये हैं।

Phosphate Deposits in Udaipur

1854. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that phosphate deposits have been located in Udaipur in Rajasthan ;

(b) whether Government have conducted the survey thereof ; and

(c) if so, the estimated quantity of phosphate likely to be extracted ?

The Minister of Steel, and Mines Metals (Dr. Channa Reddy). : (a) Yes, Sir.

(b) Investigations by the Geological Survey of India are in progress .

(c) This can be worked out after the reserves and grade of phosphate deposits have been assessed.

Railway Accidents in 1966-67

1855. **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents during 1966-67 ;

(b) the number of casualties ; and

(c) the loss of property caused thereby ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) :During the year 1966-67, 1,097 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains took place on the Indian Government Railways.

(b) As a result of these accidents, 306 persons were killed and 1,279 injured.

(c) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 97,66,871-

Leather Tanning Material

1856. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the articles imported for leather tanning and the steps taken by Government to manufacture them in the country ;

(b) whether there is any proposal to set up a factory for preparing tanning material from the bark of trees and if so the type of trees and bark of which would be used as raw material for the said factory ; and

(c) whether Government have formulated any scheme for planting those trees ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) and (b) : The main items imported for use in leather tanning industry are vegetable tanning material such as Wattle Extract, Wattle Bark etc. and Synthetic Tanning materials.

A unit licensed for the manufacture of 3750 tonnes per annum of blended extracts from Wattle Bark, Babul Bark etc. available in Madras State has gone into production recently. Three other units for the manufacture of synthetic tanning matrials have also been approved for a total capacity of 5,700 tonnes per annum.

There is no other proposal for setting up a factory for preparing tanning material from bark of trees.

(c) Efforts have been made to set up wattle plantations in the country specially in Madras State with considerable success and two schemes covering a total area of 21,274 acres in that State have made considerable progress. Nursery and small scale field tests are being conducted in Asssam, Bombay, Orissa, Punjab, Uttar Pradesh and West Bengal for locating suitable areas for plantation of Wattle Trees.

पश्चिम बंगाल से उद्योगपतियों का पलायन

1857. **श्री जु० कि० मण्डल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1 जून से 31 अक्तूबर, 1967 तक की अवधि में पश्चिमी बंगाल के हावड़ा, कलकत्ता और वर्दवान जिले से अपने मुख्यालय दूसरे स्थानों को बदले ;

(ख) इस पर कुल कितना पूंजीगत व्यय हुआ ; और

(ग) उस राज्य में श्रम अशान्ति के कारण पश्चिमी बंगाल से पूंजी को बाहर जाने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (फखरुद्दीन अली अहमद)

(क) तथा (ख) सबसे ताजी प्राप्य सुचना के अनुसार, दो कम्पनियों अर्थात, वी० इच० बेरीवाल ब्रादर्स लिमिटेड तथा मीनाक्षी वायर इन्डस्ट्रीज (आसाम) लिमिटेड ने, अपने पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता से अन्य राज्यों को, 1 जून से 3 अक्तूबर, 1967 के मन्य स्थानान्तरित कर दिय हैं। दो अन्य कम्पनियों तथा रेक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स आफ इण्डिया लिमिटेड, अर्थात् रेलिस इण्डिया लिमिटेड ने भी अपने पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता से स्थानान्तरित करने की अनुमति देने के आज्ञा-पत्र के लिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र दे दिये हैं। इन कम्पनियों की कुल परिसम्मत्ति नीचे दिखाई जा रही है :—

कम्पनी का नाम	कुल परिसम्पति (रुपये)
1—रेलिस इण्डिया लिमिटेड	12,95,55002
2—रेक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स आफ इण्डिया लिमिटेड	34,41009
3—यी० एच० पैरीवाल ब्रादर्स लिमिटेड	7,58,470
4—मीनाक्षी वायर इन्डस्ट्रीज (आसाम) लिमिटेड	6,511

(ग) दो कम्पनियों द्वारा कलकत्ता से मुख्य कार्यालयों का हटा लेना, तथा दो अन्यों का, उसी उद्देश्य के लिये प्रार्थना पत्र देना, राज्य की राजधानी को हटाने के पर्याप्त संकेत नहीं माने जा सकते।

उत्तर रेलवे का वर्कशाप, अमृतसर

1859. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के लोकोमोटिव वर्कशाप, अमृतसर में कुछ वरिष्ठ अधिकारी अपनी अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कारण हैं कि अधिकारियों के एक विशेष स्थान पर ठहराने सम्बन्धी सामान्य नियमों के अनुसार उनको अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित नहीं किया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों में स्थानों का आरक्षण

1860. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन में गत दो से तीन वर्षों की अवधि के दौरान गाड़ियों में स्थानों के आरक्षण के बारे में की गई गम्भीर अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) यदि हाँ, तो कैसी अनियमिततायें की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ, कुछ अनियमिततायें पाई गई हैं।

(ख) जो अनियमिततायें पाई गई हैं, उनका स्वरूप संलग्न विवरण में दिखाया गया है, जो कि सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) केन्द्रीय सतकर्ता आयोग की सलाह पर उन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है, जो उन अनियमितताओं के जिम्मेदार पाये गये हैं।

विवरण

पाई गई अनियमितताओं का स्वरूप

(1) गाड़ियों में आरक्षित स्थानों के स्थगित किये जाने के परिणामस्वरूप खाली हुए स्थानों पर प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की अवहेलना करके अपने मन पसन्द व्यक्तियों के लिये स्थान आरक्षित कराने के लिये सिल्पें देना।

(2) उन डिब्बों में जिनमें आरक्षण अनिवार्य था, कुछ व्यक्तियों को बिना आरक्षण के ही यात्रा करने की अनुमति देना।

(3) यात्रा टिकट जारी करने के लिये ऐसे आदेश देना, जिनकी इन गाड़ियों की यात्रा के सम्बन्ध में स्पष्ट मनाही है।

(4) स्थानों के आरक्षण के लिये कुछ मनमाने कोटों का बनाया जाना तथा इसके अनुसरण में अपनी-अपनी पसंद के व्यक्तियों को स्थान देना।

(5) आरक्षण / प्रतीक्षा सूची के रिजस्टरों में दर्ज व्यक्तियों के नामों में अपनी पसंद के व्यक्तियों के नामों के लिये फेर बदल करना।

दक्षिण रेलवे में आय की कमी

1861. **श्री कृष्णमूर्ति:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे की आय में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ख) दक्षिण रेलवे में कार्यकुशलता और आय को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) दक्षिण रेलवे की आय में कोई कमी नहीं हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः मास की आय, पिछले वर्ष की इस अवधि की आय से कुछ अधिक है। यह आय और भी अधिक होती परन्तु गत सितम्बर में हुए कोयला संकट के कारण कुछ गाड़ियों के रद्द किये जाने तथा आम और अंगूर की फसल के कम होने के कारण न हो सकी।

(ख) अन्य रेलवों की भाँति दक्षिण रेलवे भी अधिक यातायात को आकर्षित करने तथा कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रही है।

कुछ उपाय ये किये गये हैं:

(एक) विशेष दरों का निर्धारण।

(दो) शीघ्रगामी सेवा का आरम्भ किया जाना।

(तीन) सुपर-एक्सप्रेस माल गाड़ियों का चलाना।

(चार) टिकट निरक्षण को अधिक प्रभावी बनाना।

(पाँच) संचलन डिब्बों तथा अन्य अस्तियों की अधिक अच्छी देखभाल तथा उनका अधिक उपयोग।

(छः) ऐसे खर्च न करना, जिनके बगैर काम चल सकता है।

(सात) कन्टेनर सेवा आरम्भ करने की योजना बनाना।

व्यापार मण्डल (बोर्ड आँफ ट्रेड)

1862. **श्री भोगेन्द्र झा:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार मण्डल को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या व्यापार मण्डल के कार्य को अपने हाथ में लेने के लिये कोई अन्य संगठन स्थापित किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) यह मामला विचाराधीन है।

हैवी इंजीनियरी निगम, रांची का कार्यकरण

1863. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राँची में हैवी इंजीनियरी उद्योग-समूह के कार्यकरण में सुधार करने के लिये उसके कार्यकरण की जाँच की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस उद्योग-समूह के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) यद्यपि सरकार राँची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारखानों के कार्यकलापों का कम्पनी से प्राप्त सावधिक रिपोर्टों और आँकड़ों, कम्पनी के निदेशक मण्डल के सरकारी प्रतिनिधियों के द्वारा तथा अधिकारियों से समय-समय पर होने वाली बातचीत के द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है किन्तु इस प्रकार की कोई भी जाँच नहीं कराई गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रीलंका से चाय का आयात

1864. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका से घटिया किस्म की चाय का आयात करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी चाय का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस आयात का प्रयोजन क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बोकारो इस्पात परियोजना का निर्माण

1865. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री प्र० न० सोलंकी :**

श्री हरदयाल देवगुण : **श्री मेघ चन्द्र :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात परियोजना का निर्माण कार्य निश्चित कार्यक्रम से बहुत पीछे रह गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) निर्माण कार्य को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी नहीं। वर्तमान संकेतों के अनुसार सारी परियोजना वर्ष 1971 की चौथी तिमाही के अन्त तक पूरी हो जायगी।

(ख) और (ग): रूसी संगठन द्वारा दिसम्बर, 1966 में निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार बोकारों इस्पात कारखाने का प्रथम चरण मार्च, 1971 के अन्त तक पूरा हो जाना था। यह बहुत अविलम्बनीय कार्यक्रम था तथा इस अनुमान से बनाया गया था कि नींव डालने तथा सिविल इंजीनियरी सम्बन्धी कार्य जनवरी 1967 में किसी समय आरम्भ किया जा सकेगा। उन ठेकेदारों का अन्तिम चयन करने में, जिन्होंने काम आरम्भ करना था हुई देरी के कारण यह काम अक्तूबर 1967 में वर्षा बन्द होने के बाद ही आरम्भ किया जा सका है। लगभग नौ महीने की इस देरी के परिणामस्वरूप अब—प्रथमचरण मार्च, 1971 की बजाय दिसम्बर, 1971 में पूरा होगा। चूंकि दिसम्बर, 1966 में बनाया गया कार्यक्रम बहुत अविलम्बनीय था, इस लिये यह आशा नहीं की जा सकती

कि प्रथम चरण में जो समय अधिक लगा है, उसकी पूर्ति निर्माण चरण में की जा सकेगी। यह सुनिश्चित करने के लिये कि योजना को निधोरित कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित किया जाये, योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण का कार्य साथ-साथ किया जा रहा है।

मशीनरी का आयात

1866. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री पाशाभाई पटेल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन में आई मन्दी को दूर करने के लिये भारत में बनाई जा रही अथवा बनाई जा सकने वाली मशीनरी, पुर्जों, माल आदि के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो विदेशों को दिये गये कितने तथा किन-किन वस्तुओं के क्रयादेश रद्द किये गये हैं अथवा किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) उस सामग्री, मशीनों तथा हिस्सों के आयात पर पूरा प्रतिबन्ध तब तक लगाना व्यावहारिक नहीं है जब तक कि वे वस्तुएं जिनका भारत में निर्माण किया जा रहा है या किया जा सकता है उनका निर्माण पर्याप्त परिमाण में और अपेक्षित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होने लगता है।

Incidents of Thefts and Dacoity in Running Trains

1867. **Shri Sashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 29th October, 1967 a gang of dacoits looted almost all the passengers travelling in a compartment of the Kanpur-Jhansi passenger train at the point of pistol near Jhansi and stabbed a military man when he offered resistance ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action being taken for the safety of the life and property of the passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Prevention and detection of crime on Railways and in Railway trains and premises being the responsibility of the State Police, the incident was reported to Government Railway Police, Jhansi, who have registered a case u/s 395/397 IPC. For the prevention of such incidents Assistant Inspector General, Railways, Senior Superintendents of Police, Kanpur and Jhansi have also been specially requested to arrange for the escorting of night Passenger trains on the affected Sections and take other suitable preventive measures as to bring offenders to book

New Steel Mines in Madhya Pradesh

1868. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Steel, Mines amd Metals** be pleased to state :

(a) the schemes being formulated by Government for the development of the newly found steel mines in Madhya Pradesh ;

(b) whether exploration work is still in progress there ; and

(c) whether the western Nimad districts of Madhya Pradesh are also included in this exploration work ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) The reference is probably for iron ore mines. The National Mineral Development Corporation is developing a mine based on deposit No. 14 in Bailadila area in Bastar District, Madhya Pradesh, for the production of 4 million tonnes of ore per annum for export. Production from this mine is scheduled to start by February-March, 1968. The National Mineral Development Corporation is also developing a mine based on depsoit No. 5 in that area for the production of 2 million tonnes sized ore per annum for export.

(b) The Geological Survey of India are carrying on investigations on deposits Nos. 10 and 11 in Bailadila area. The work was suspendedd due to monsoon and is to be resumed during the current field season.

(c) No Sir.

Railway Lines in the Western Nimar District

1869. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the details of the Railway lines surveyed so far in the Western Nimar District ;

(b) whether it is proposed to extend Railway lines to such places residents whereof are prepared to advance loan to Government for this purpose ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The following proposals for construction of new lines in the Western Nimar district of Madhya Pradesh were surveyed in the past :

(i) Bagmar-Barwani—a traffic survey was carried out for this 193.12 KM. long narrow gauge line. The cost was then estimated to be Rs. 72 lakhs and financial return 3.1%.

(ii) Bhusawal-Tarana Road—Engineering and traffic surveys for this 272 Km. long broad gauge line were carried out in 1946.

(iii) Khargaon-Sanwad—Surveys for this 64 Km. long metre gauge line were carried out in 1906.

(b) and (c) Construction of these lines was not taken up in the past due to their unremunerativeness and the stringent position of funds. In view of the present financial position, chances of constructions of these lines in the near future are slim. The question of constructing new lines by taking loans from the public does not arise as these loans will also have to be repaid ultimately by the Railways.

भारत के मार्ग से नेपाल द्वारा आयात

1870. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** **श्री प्र० ना० सोलंकी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने इस वर्ष सितम्बर में रक्सौल में हुई भारत-नेपाल सीमान्त व्यापार समिति की बैठक में नेपाल द्वारा अन्य देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के भारतीय राज्यक्षेत्र से स्वतंत्र तथा निर्बाध रूप से लाने-ले-जाने के लिये किसी प्रस्ताव पर चर्चा उठाई गई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो संक्षिप्त और सही रूप में उनकी माँग क्या थी और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेपाली नौभार का परिवहन

1871. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या कलकत्ता होकर नेपाली नौभार के परिवहन के लिये वर्तमान रेल एवं सड़क मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में नदी नौपरिवाहन का उपयोग करने की सम्भान्वाओं का पता लगाने के लिये हाल ही में नेपाली अधिकारियों का एक दल नई दिल्ली आया था जिससे अन्य देशों के साथ नेपाल के समुद्र-व्यापार को बढ़ाया जा सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो दल की मुख्य माँगें क्या थीं और उनके द्वारा माँगी गई विभिन्न रियायतें मंजूर करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) जी हाँ। जुलाई, 1967 में नेपाल सरकार के अधिकारियों का एक दल भारत आया था और उस दल के सदस्यों ने भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत की थी। यह समझौता हुआ था कि आगे अध्ययन किया जाये और सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं के लिये भारत-नेपाल बोर्ड के माध्यम से जानकारी और आंकड़ों की अदलाबदली की जाये।

नादियाद के निकट गुजरात एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

1872. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12 सितम्बर, 1967 को बड़ौदा और अहमदाबाद सैक्शन पर नादियाद के निकट गुजरात एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो दुर्घटना के क्या कारण थे और इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए अथवा मरे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ। गोधाज रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पटरी से उतर गई थी।

(ख) सामान्य गति पर गाड़ियों को गुजरने के लिये पलाइंट असम्बली, सिगनिलइग तथा इंटरलोकिंग में खराबी आने के कारण गाड़ी पटरी से उतर गई।

इस दुर्घटना में कोई व्यक्ति नहीं मरा। 23 व्यक्तियों का मामूली चोटें आई थीं।

भारत के निर्यात के बारे में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का दल

1873. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** **श्री जीतेन्द्र बहादुर :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के दल ने, जिसने 1967 के आरम्भ में भारत का दौरा किया था, भारत के निर्यात को बढ़ाने के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा क्या निर्णय किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1731/67]**।

आसंसोल यात्री गाड़ी

1874. **श्री रवि राय**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष 1 अक्तूबर, 1967 के बाद कितनी नई गाड़ियाँ चलाई गईं तथा । अक्तूबर के बाद से सामान्य यात्रियों को कौन सी अधिक सुविधाएँ दी गई हैं:—

(ख) क्या आसंसोल यात्री गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी बनाई [illegible] है?

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा के बालसोर जिले के लोगों की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) कुल मिलाकर 32 नई गाड़ियाँ चलाई गई थीं (बिजली से चलने वाली 22 उपनगरीय गाड़ियाँ भी इसमें शामिल हैं) और वर्तमान 16 गाड़ियों की दूरी बढ़ाई गई थी। यात्रियों की सुविधाओं सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1732/67]**।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी हाँ।

(घ) उड़ीसा सरकार के परामर्श से 12-10-67 से 397 डाउन एक्सप्रेस को नीलगिरी रोड और बस्ता में और 398 अप को हाल्दीपादा और बस्ता में ठहराने के प्रबन्ध किए गए हैं।

चाय, काफी और रबड़ का उत्पादन

1875. **श्री पार्थसारथी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चाय, काफी और रबड़ जैसे तीन मुख्य बगीचों में 1966–67 में हुए उच्चतम उत्पादन से संतुष्ट है, और

(ख) यदि नहीं, तो पहले निश्चित किए गए लक्ष्य से कितना कम उत्पादन हुआ है? और उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वित्तीय और/अथवा तकनीकी सहयोग

1876. **श्री प्रार्थसारथी** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी कितने उद्यमियों नें वित्तीय और/अथवा तकनीकी सहयोग प्राप्त किया है; और

(ख) इस सहयोग के परिणामस्वरूप कितना मुनाफा कमाया गया तथा कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जनवरी, 1960 से सितम्बर, 1967 की अवधि में सरकार द्वारा गैर सरकारी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में विदेशी तकनीकी / वित्तीय सहयोग के 2409 मामलों के लिए सहमति दे दी गई है।

(ख) इसका अभी पता नहीं लगाया गया है।

रेलवे विभाग में हिन्दी पर्यवेक्षक

1878. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में कितने हिन्दी पर्यवेक्षक हैं और उनका वेतनक्रम क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ रेलों में ये शिकायतें हैं कि हिन्दी पर्यवेक्षकों को जो काम सौंपे गए हैं वे उनको अच्छी तरह नहीं करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कारण से हिन्दी पर्यवेक्षकों के पदों को जहाँ वे खाली पड़े हैं? भरा नहीं गया है, ताकि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बजाय उन पदों को बाद में समाप्त कर दिया जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) हिन्दी पर्यवेक्षकों को 450–575 रु० (ए० स०) का वेतनक्रम दिया गया है। विभिन्न खण्डीय रेलों के लिये मंजूर किए गए हिन्दी पर्यवेक्षकों के पदों की संख्या इस प्रकार है:

रेलवे	मंजूर किये गये पदों की संख्या
मध्य	3
पूर्वी	2
उत्तर	2
पूर्वोत्तर	2
सीमान्त पूर्वोत्तर	1
दक्षिण	2
दक्षिण मध्य	1
दक्षिण पूर्व	2
पश्चिम	3

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे स्कूलों के अध्यापक

1879. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे के विभिन्न स्कूलों में ऐसे अध्यापकों की संख्या क्या है जो तीन वर्ष से अधिक की लगातार सेवा के बावजूद स्थायी नहीं बनाये गये हैं; और

(ख) उन्हें अभी तक स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) 41.

(ख) उनमें से 38 अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं और रेलवे अन्य को स्थायी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

दिल्ली में उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1880. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नियुक्त उत्तर रेलवे के साढ़े तीन हजार कर्मचारियों को 8–10 **वर्षों** तथा इससे अधिक समय से क्वार्टर नहीं दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को जिन्हें 2 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भी क्वार्टर नहीं दिए गए हैं उनकी संख्या क्या है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी हाँ।

(ख) (एक) क्वार्टरों की भारी कमी। दिल्ली क्षेत्र में क्वार्टरों की संख्या केवल 7,038 है जबकि यहाँ पर "आवश्यक" तथा "गैर-आवश्यक" श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों की संख्या 33,735 है; और

(दो) उपलब्ध क्वार्टरों में से 75 प्रतिशत आवश्यक श्रेणी के कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

(ग) रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के लिये सभी अधिकारियों को 'आवश्यक' समझा जाता है और सामान्यतः उनके दिल्ली में नियुक्त किए जाने/बदली किए जाने के 2 वर्ष के भीतर ही उन्हें क्वार्टर दे दिया जाता है।

बलोत्रा रेलवे स्टेशन

1881. **श्री अमृत नाहाटा**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बलोत्रा (बाड़मेर जिला) में रेलवे स्टेशन के नए भवन के निर्माण के लिये स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) वह भवन कब तक बन जायेगा?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं। प्रतीक्षा हाल के विस्तार और स्वच्छ स्नानगृह और शौचालयों की व्यवस्था के लिये मंजूरी दी गई है।

(ख) आशा है कि उक्त कार्य 1968 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

गुजरात में ब्राड गेज और नैरो गेज लाइनें

1882. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी मार्गों की कुल लम्बाई कितनी है तथा उसमें से गुजरात राज्य में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज लाइनों की लम्बाई कितनी कितनी है;

(ख) क्या उस राज्य में सभी नैरो गेज लाइनें बन्द करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि नैरो गेज लाइनों के बन्द किए जाने से परिवहन व्यवस्था बिल्कुल ही समाप्त हो जायेगी तथा गुजरात के लोगों को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ेगा?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) रेल मार्गों की लम्बाई के बारे में जानकारी राज्यवार नहीं अपितु रेलवेवार इकट्ठी की जाती है। रेल खण्डों के मार्गों की लम्बाई का पूरा ब्यौरा वर्ष 1965–66 के रेलवे बोर्ड के पूर्वक प्रतिवेदन के विवरण संख्या 8 में दिया गया है जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(ख) लाइनों के कार्य में सुधार करने के लिये भारतीय रेलों की अलाभप्रद लाइनों का अध्ययन चालू है जिसमें गुजरात राज्य की नैरो गेज लाइनों भी शामिल हैं और उस अध्ययन के आधार पर ही किसी विशिष्ट लाइन के भविष्य के बारे में प्रस्ताव बनाये जायेंगे।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनें

1883. **श्री मणी भाई जे० पटेल:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलों लाइनें बिछाने सम्बन्धी कुछ परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान घल्ली राजहरा और दान्तेवड़ा के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन के निर्माण की सिफारिश की है। किए गए अध्ययन से पता चलता है कि वित्तीय दृष्टि से इस लाइन को चलाना लाभप्रद न होगा और इसलिए इसके चतुर्थ योजना में निर्माण आरम्भ किए जाने की संभावना नहीं है।

थाईलैंड से घटिया किस्म के मेंस्टा का आयात

1886. **श्री मणी भाई जे० पटेल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने थाईलैंड के निर्यातकों द्वारा भारत को भेजे गए घटिया किस्म के मेस्टा के निर्यात की रिपोर्टों के बारे में जाँच कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उस मामले में इस समय कोई जाँच नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़ा उद्योग के लिये समिति

1887. **श्री मणी भाई जे० पटेल :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपड़ा उद्योग की पुरानी समस्याओं को हल करने के लिये संरचनात्मक उपाय सुझाने हेतु एक विशेष समिति नियुक्त की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति द्वारा इस काम में क्या प्रगति की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

बन्द माल डिब्बों की कमी

1888. **श्री श्रद्धाकर सुपाकर:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में बन्द माल डिब्बों की कमी है और इसी कारण वर्षा ऋतु आरम्भ होने के बाद रेलवे विभाग खाद्यान्न लाने ले जाने के लिये माल डिब्बों की सम्पूर्ण माँग को पूरा नहीं कर सका, और

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं। यातायात की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बन्द माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है।

वर्ष 1966 और चालू वर्ष के प्रथम 10 महीनों में खाद्यान्न बड़ी भारी मात्रा में आयात किया गया था। उसे मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को ले जाया गया था। 1965 में 63 लाख टन उर्वरक और अनाज रेल द्वारा ले जाया गया था जबकि 1966 में 92 लाख टन ले जाया गया था। 1967 के प्रथम 10 महीनों में 69 लाख टन माल रेल द्वारा भेजा गया। यदि अनाज कलकत्ता, विशाखापत्तनम और बम्बई पत्तनों पर उतारा जाता तो कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि वें प्राकृतिक पत्तन हैं, परन्तु अधिकांश अनाज मद्रास और काण्डला पर उतारा गया था। मद्रास और काण्डला पत्तनों से बड़ी मात्रा में अनाज रेल द्वारा ले जाये जाने की जानकारी इस प्रकार है;

(संख्याएं हजार टनों में)

पत्तन	बिहार और उत्तर प्रदेश को रेल द्वारा ले जाये गये अनाज की कुल मात्रा					
	(1966) जनवरी से अक्तूबर	(1967) जनवरी से अक्तूबर	स्तम्भ 2 के साथ स्तम्भ 3 की प्रतिशतता	(1966) जून से सितम्बर	(1967) जून से सितम्बर	स्तम्भ 5 के साथ स्तम्भ 6 की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मद्रास	54·7	701.5	1284	18·9	269.3	142.5
काण्डला	381.3	441.5	116	161.3	203.3	126
	436.0	1143.0	262	180.2	472.6	262

आयातित अनाज, उर्वरकों और देश में उत्पादित चावल की कमी वाले और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लम्बे रास्ते से ले जाना पड़ा था जो कि सामान्य तरीका नहीं था। वहन के चक्र को बनाये रखने और मद्रास और काण्डला पत्तनों को निरन्तर रूप से माल डिब्बे देने के लिये खाली माल

डिब्बों को उलटी दिशा में चलाना पड़ा था। ऐसा सारे वर्ष और वर्षा ऋतु में करना पड़ा था। इन असाधारण परिस्थितियों के कारण बन्द डिब्बों के अतिरिक्त खुले डिब्बे भी प्रयोग में लाये गए थे। पीड़ित क्षेत्र को कम से कम समय में अधिक से अधिक मात्रा ले जानी पड़ी थी और इसलिये खुले डिब्बों का प्रयोग अपरिहार्य था।

रेलवे दुर्घटनाएं

1889. **श्री बलराज मधोक** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 15 अगस्त, 1967 और 15 नवम्बर, 1967 के बीच भारतीय रेलवे में कितनी दुर्घटनाएँ हुईं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी दुर्घटना में तोड़ फोड़ का सन्देह किया गया है और क्या जाँच के परिणामस्वरूप यह सन्देह ठीक सिद्ध हुआ है, और

(ग) यदि हाँ, तो इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) उक्त अवधि के दौरान 307 रेल दुर्घटनाएं हुई थीं। उनमें से 16 टक्करें थीं; 262 पटरी से उतर जाने की दुर्घटनाएँ, 24 रेलगाड़ियों के रेलवे फाटकों पर सड़क यातायात से टकरा जाने की और 5 रेलगाड़ियों में आग लग जाने की घटनाएँ थीं।

(ख) चार मामलों में तोड़फोड़ का काम किया गया है चारों मामलों में अभी पुलिस जाँच कर रही है।

(ग) दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु किए गए उपायों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०1733/67**]।

Industries in U. P. in Public Sector

1890. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount given to U. P. during each of the four Plan periods for setting up Public Sector industries ; and

(b) the State-wise percentage of the total amount sanctioned during the aforesaid period?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) The following investments have been made in Uttar Pradesh during each of the Plan periods for setting up Public Sector Industries :—

I Plan	—	Rs.	Nil.
II Plan	—	Rs.	3.24 crores.
III Plan	—	Rs.	80.73 "
IV Plan	—		As the 4th Plan is still under finalisation, no firm figure be given.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See. No. LT-1743/67.]**

Tractor Factory in Varanasi

1891. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state ?

(a) the progress made in the setting up of a factory for manufacturing cheap tractors in the public sector at Varanasi ;

(b) whether there has been some delay in the matter and if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which that factory would start functioning ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed : (a) to (c) The first part of the Detailed Project Report containing a study of the economic feasibility of the project was received in May, 1967. This was examined in consultation with the technical advisers of Government and other departments concerned. The issues thrown up in the course of the examination were discussed with a team of Czech. experts who came to India for the purpose in September 1967. One of the important points brought out during the discussions was that the total investment proposed for the project was very high and ways and means should be explored for reducing the investment to the maximum extent possible. The Czech experts have agreed to do so and furnish a supplementary report by the end of December 1967.

In the meantime, even before Govt. had received the feasibility Report from the Czech Agency, a suggestion was made that Govt. should examine the possibility of setting up a unit in the public sector for the manufacture of agricultural tractors by utilising the existing engineering facilities in the country, particularly at the Heavy Engineering Corporation, Ranchi and the Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur. An inter-departmental Committee had been set up in September, 1966 to go into this question. The Report of this Committee has also been received recently and their recommendations will be taken into account in taking a decision on the Report of the Czech Agency.

A final decision on the project is expected to be taken early in 1968.

Railway Bridge over the River Ghaghra

1892. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ?

(a) whether his attention has been drawn to the grave danger threatening the Railway bridge (Elgin Bridge) constructed over the river Ghaghra and situated on the North Eastern Railway in Barabanki District due to a breach caused by that river ;

(b) whether on-the-spot investiagtion were carried out regarding this danger during August and September, 1967 ;

(c) if so, the result thereof ;

(d) whether it is a fact that the present dam cannot provide protection to the Elgin Bridge ; and

(e) if so, whether any scheme has been drawn up to protect the bridge and if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (e) No breach has been caused by the river Ghaghra though some erosion took place near Bahramghat Station. The matter was investigated in detail in August-September, 1967. It was felt that there was no danger of the river outflanking the Elgin Bridge between Chowkaghat and Gograghat Stations in the near future, as adequate protective measures to prevent the river from attacking the approaches already exist. Details of further strengthening works are being worked out and these will be carried out as necessary shortly.

Air-Conditioned Bogies

1893. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the capacity of air-conditioned bogies to carry passengers in the passenger trains running on all the lines in the country ;

(b) whether their full capacity was utilized in 1965-66 ;

(c) the amount of fare collected from passengers travelling in air-conditioned bogies in 1965-66 ;

(d) whether that amount was collected as a result of the utilization of their full capacity or a part thereof ; and

(e) the amount that would have been collected by the utilization of their full capacity, in case the amount of fare collected represents partial utilization ?

The Minister of Railways (**Shri C. M. Poonacha**) : (a) On an average, the following accommodation is provided on passenger trains daily in Air-conditioned First Class and Air-conditioned Third Class Chair Cars :—

B. G. — 686 Air-conditioned First Class berths.

M. G. — 65 do

B. G. — 579 Air-conditioned Third Class Chair Car seats.

M. G. — No Third Class Air-conditioned Chair Car is provided on the Metre Gauge.

(b) No.

(c) An amount of Rs. 254.55 lakhs was collected from Air-conditioned First Class and Third Class Air conditioned Chair Car passengers.

(d) As stated in part (b), the capacity was not fully utilised.

(e) Assuming full utilization of the coaches, it is estimated that the earnings would have gone up by about 80 lakhs.

Running of a Passenger Train Between Delhi and Lucknow

1894. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to run any passenger train during the day between Delhi and Lucknow to lessen the rush of passengers travelling between these two places ;

(b) if so, the date from which these trains would be introduced ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (**Shri C. M. Poonacha**) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) It is not operationally feasible at present to introduce an additional train between Delhi and Lucknow owing to paucity of coaching stock and non-availability of requisite line capacity on certain sections en route and of terminal facilities at Delhi/New Delhi.

बम्बई के एक फिल्म अभिनेता को स्टेन्लेस स्टील के आयात के लिए लाइसेंस का दिया जाना

1195. **श्री जार्ज फरनान्डेज :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के किसी फिल्म अभिनेता को 11 टन स्टेनलेस स्टील आयात करने के लिये लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) लाइसेंस कब दिया गया था और इसके कारण क्या हैं;

(ग) फिल्म अभिनेता द्वारा आयात किए इस्पात का मूल्य क्या है; और

(घ) वह इस्पात किस तरीके से निपटाया गया है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी): (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है।

रोलिंग शीट बनाने की धातु

1897. **श्री जार्ज फानेन्डीज** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रोलिंग शीट बनाने की धातु की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और हमारे स्पात कारखानों में इसका कितना उत्पादन होता है;

(ख) प्रति वर्ष चादर बनाने की कितनी धातु का आयात किया जाता है;

(ग) देश में उपलब्ध चादर बनाने की धातु का मूल्य क्या है तथा आयातित धातु का मूल्य क्या है;

(घ) क्या सरकार 12 टन रोल के बजाय, जैसा कि अब किया जा रहा है, 5 टन रोल में चादर बनाने की धातु तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार किया है, ताकि चादरों को आवश्यकतानुसार आकार में काटा जा सके और उपभोक्ताओं को शीघ्र दिया जा सके; और

(ङ) देश में ऐसे कितने कारखाने हैं जिनमें क्रमश: 12 टन रोल तथा 5 टन रोल में चादर बनाने की क्षमता है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) :

(क) चादरों की वार्षिक आवश्यकता अनुमानत: 13.9 लाख टन की है जबकि 1966–67 में कुल उत्पादन 6.5 लाख टन का था ।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में आयात की गई चादर धातु की मात्रा, उसका मूल्य प्रति टन कीमत इस प्रकार हैं:—

वर्ष	मात्रा टनों में	मूल्य हजार रु० में	प्रति टन औसत दर
1964-65	334,482	275,962	825
1965-66	263,442	243,915	926
1966-67	129,625	175,543	1354

स्वदेशी चादरों का प्रति टन मूल्य इस प्रकार है:—

चादर की श्रेणी	प्रति टन एफ० ओ० आर० मूल्य
कोल्ड रोल्ड शीट	1,250
कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स	1,200
हॉट रोल्ड शीट	1,000
हॉट रोल्ड स्ट्रिप्स	925
स्कैल्प	945

(घ) और (ङ) 6 टन से 14.5 टन तक के भार में रोल के रूप में चादरें केवल रूरकेला में ही बनाई जाती हैं। रूरकेला द्वारा बनाये गए क्वालिों को इस समय केवल तीन कारखाने ही काट सकते हैं।

स्टैंडर्ड हैरल्ड कारों के लिये दरवाजों के हैंडलों का आयात

1898. **श्री सम्बन्धन**: क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्टैंडर्ड हैरल्ड कारों के दरवाजों के हैंडलों का देश में निर्माण नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इनके आयात के लिये 1965–66 और 1966–67 में कितनी विदेशी मुद्रा दी गई?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख रीन अली अहमद):

(क) जी नहीं। स्टैन्डर्ड हेराल्ड के दरवाजों के हैन्डल अब देश में ही बन रहे हैं।

(ख) 1965–66 में 1,019 पौण्ड की विदेशी मुद्रा से 1584 हैन्डल आयात किए गए थे। 1966–67 में किसी विशेष आयात की अनुमति नहीं दी गई थी किन्तु हो सकता है कि उत्पादकों ने ऐसे सहायक पुर्जों के जो कि आयात की जाने वाली वस्तुओं कीसूची मे सम्मिलित नहीं है, के आयात के लिए किए गए इकट्ठे आवन्टन में से कुछ हैन्डल आयात किए हों। इस बारे में उत्पादकों से वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

निर्यात सवर्धन परिषदें

1899. **श्री सम्बन्धन**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी निर्यात संवर्धन परिषद मे ऐसे सगठनों की व्यर्थता के बारे में कोई रिपोर्ट अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि सरकार इन परिषदों की सिफारिशों की परवाह नहीं करती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नीवेली में बिजली का उत्पादन

1900. **श्री सम्बन्धन**: क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीवेली में बिजली की उत्पादन लागत अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्य कम करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) से (ग): मद्रास राज्य के दूसरे ऊष्म विद्युत् केन्द्रों के मुकाबले में यह अधिक नहीं है।

फिलिपीन के साथ व्यापार

1901. **श्री क० प्र० सिंह देव**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में फिलीपीन जाकर लौटे भारतीय उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल ने उस देश के साथ पूंजीगत माल के व्यापार की संभावना के बारे में सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) लगता है कि माननीय सदस्य उस गैर सरकारी प्रतिनिधि मंडल का उल्लेख कर रहे हैं जो सितम्बर, 1967 में फिलीपीन गया था जिसे भारतीय उद्योग तथा व्यापार मंडल संघ ने भेजा था। सरकार द्वारा प्राप्त इस प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) इस प्रतिवेदन में दिए गत सुझाव सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। वे इन पर विचार करेंगे और जिनपर कार्यवाही करने की आवश्यकता है उनपर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौते

1902. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग सम्बन्धी अधिकतर समझौतों में सम्मिलित किए गए किसी खण्ड के कारण कुछ भारतीय वस्तुओं के निर्यात करने की संभावनाएँ समाप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1966–67 में भारतीय उद्योग को विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई थी; और

(ग) समझौतों से ऐसे खण्ड को निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) आरम्भ के वर्षों में किए गए विदेशी सहयोग के समझौतों में निर्यातों पर कुछ प्रतिबन्ध हैं किन्तु इन प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप यदि कोई हानि हुई हो तो उसका निर्धारण करना संभव नहीं है। सरकार की वर्तमान नीति यह है कि या तो इन निर्यात प्रतिबन्धों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये या यदि यह व्यवहार्य न हो, तो अधिक से अधिक देशों को निर्यात करने के अधिकार प्राप्त किए जायें।

इस्पात के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए समिति

1903. **श्री क० प्र० सिंह देव**: क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी दो योजनाओं में देश में इस्पात की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) भविष्य में इस्पात की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये सरकार ने कोई समिति नियुक्त नहीं की है किन्तु सरकार ने 1980–81 तक अर्थात् छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक लोहा और इस्पात सम्बन्धी माँग का श्रेणीवार और किस्मवार आवश्यकता का अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् स्थापित की है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने इस बारे में अध्ययन में अपनी सहायता के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त की है।

(ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने मई, 1967 में एक अन्तरिम नोट प्रस्तुत किया था जिसमें उसने 1970–71 में लोहा, इस्पात तथा मिश्रित इस्पात की माँग सम्बन्धी अपने प्राक्कलन दिये थे। अन्तिम प्रतिवेदन 1968 के आरम्भ में प्राप्त हो जायेगा।

मध्य रेलवे में चलती गाड़ी से गिरने की घटना

1904. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अगस्त, 1967 को मध्य रेलवे के करपगाँव और करैली के बीच चार महिलाओं की गाड़ी से फेंके जाने अथवा गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस रात समस्त गाड़ी में बिजली नहीं थी ;

(ग) क्या गाड़ी के गार्ड और पुलिस द्वारा लाशों को नहीं खोजा गया था और उनमें से एक महिला का, जो कि जीवित बच गई थी, करपगाँव तक चलकर जाना पड़ा था तथा उसने इस घटना की सूचना दी थी ; और

(घ) क्या इस दुर्घटना की कोई जाँच कराई गई है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चलती गाड़ी से कूद जाने के कारण चार महिलाओं की मृत्यु हो गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गार्ड को इस दुर्घटना के बारे में पता नहीं था। उस गाड़ी में सरकारी रेलवे पुलिस का कोई कर्मचारी तैनात नहीं था।

(घ) जी हाँ। सरकारी रेलवे पुलिस, गड़ावाड़ा के स्टेशन अफसर ने इस मामले की जाँच की थी। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह दुर्घटना का मामला था और इसमें कोई अपराध नहीं किया गया था।

तम्बाकू का निर्यात

1905. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों में तम्बाकू, अखरोट, प्याज, केले, आम, हड़ तथा अन्य फलों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) क्या ये फल उत्पादन क्षेत्रों से बन्दरगाहों को मुख्यतया सड़क से ले जाये गये थे ;

(ग) यदि हाँ, तो सड़क से कितना माल ले जाया गया था ; और

(घ) जब भारतीय रेलें सस्ती परिवहन सुविधाएँ देती हैं तब सड़क वाहनों का इस्तेमाल किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है- **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी** 1735/67)।

(ख) से (घ) निर्यात किए जाने वाले तम्बाकू का 95 प्रतिशत सड़क से बन्दरगाहों तक ले जाया जाता है। ऐसा मुख्यतः निम्न कारणों से किया जाता है :—

(एक) बन्दरगाहों पर जहाजों में माल का लदान करने के लिये निर्यातकों को बहुत कम समय दिया जाता है जिससे उन्हें माल बहुत तेजी से लादना पड़ता है चूंकि इतने कम समय में रेलवे वैगन नहीं मिलते हैं इसलिये निर्यातकों को माल सड़क से ले जाना पड़ता है।

(दो) निर्यात किया जाने वाला तम्बाकू भरे जाने वाले स्थान पर लारियों में लादा जाता है और बन्दरगाह पर ही उतारा जाता है। रेलवे वैगनों द्वारा तम्बाकू की ढुलाई की स्थिति में पहले पेटियों में भरे जाने के स्थान से तम्बाकू को लारियों में भरकर रेलवे यार्ड तक ले जाना पड़ता है और वहाँ पर उसे उतार कर फिर वैगनों में लादना पड़ता है। यही उतारने और लादने का कार्य रेलवे के अन्तिम स्टेशनों पर भी करना पड़ता है और तब तक अन्त में तम्बाकू जहाज में लादा जाता है। निर्यात किये जाने वाले तम्बाकू को लादने और उतारने में अधिक लागत आने के अतिरिक्त तम्बाकू की गाँठों-पेटियों के बार-बार लादने और उतारने से मूल स्थान पर की गई पैकिंग बिगड़ सकती है जिससे पेटियों तथा गाँठों में बन्द तम्बाकू की किस्म पर प्रभाव पड़ सकता है।

केलों और आमों की ढुलाई मुख्यतः रेलों द्वारा की जाती है। अखरोट, प्याज और हड़ के बारे में जानकारी एकत्रित करना कठिन है क्योंकि इन वस्तुओं का निर्यात व्यापार पूर्णतः अनेक गैर सरकारी व्यापारियों के हाथ में है जो इस बारे में विस्तृत आँकड़े नहीं रखते हैं।

मध्य रेलवे की आय और ललितपुर, होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर स्टेशनों पर दी गई सुविधाएँ

1906. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य रेलवे के ललितपुर, होशंगाबाद और नरसिंहपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से पिछले पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी आय हुई;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्टेशन पर क्या क्या यात्री सुविधाएँ दी गई हैं;

(ग) क्या ये सुविधाएँ यात्रियों से प्राप्त आय के अनुपात में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) ललितपुर होशंगाबाद और नरसिंहपुर स्टेशनों पर पिछले पांच वर्षों में हुई आय इस प्रकार है :—

वर्ष	ललितपुर	होशंगाबाद	नरसिंहपुर
	रुपये	रुपये	रुपये
1962-63	4,53,165	3,87,714	4,33,163
1963-64	4,44,769	4,68,099	4,64,640
1964-65	4,71,636	5,46,564	4,72,864
1965-66	5,09,668	5,23,906	5,09,806
1966-67	5,45,295	6,07,522	5,07,039

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1736/67]।

(ग) किसी स्टेशन पर यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। सामान्यतः यह देखा जाता है एक समय में किसी स्टेशन पर कितने यात्री रहते हैं। ये सुविधाएँ केवल किसी स्टेशन से होने वाली आय पर ही नहीं दी जाती हैं। अपेक्षित होने पर स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लघु उद्योगों का विस्तार

1907. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ए० सी० एस० आर०। ए० ए० सी० कन्डक्टर बनाने वाले कुछ लघु उद्योगों को क्षमता बढ़ाने तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीयन की मंजूरी दी है;

(ख) क्या यह सच है कि पंजीयन की यह मंजूरी उस समय दी गई थी जब कि ये उपकरण प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची में सम्मिलित थी; और

(ग) यदि हाँ, तो पंजीयन की मंजूरी किस आधार पर दी गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) केबल तथा तार उद्योग को प्रतिबंधित सूची में शामिल किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित चार फर्मों को तकनीकी विकास का महानिदेशालय में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई थी :—

(1) मेसर्स जे० जे० एच० इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता।

(2) मेसर्स बिन्दावाला इन्डस्ट्रियल, कार्पोरेशन, कलकत्ता।

(3) मेसर्स एसोसियेएटेड वायर्स एण्ड कण्डक्टर्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जालंधर ।

(4) बिहार, केबल्स कम्पनी, पटना।

पहली तीन फर्मों के मामले में पंजीकरण की स्वीकृति इसलिए दी गई थी कि ये फर्में सामान्य विकास के द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र से ऊपर उठी हैं। बिहार केबल कम्पनी पटना का पंजीकरण इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि फर्म 1959 में ही जबकि यह बिहार औद्योगिक निदेशक के पास पंजीकृत हुई तो औद्योगिक ला सेंस पाने की हकदार थी।

दंडकारण्य में कागज तथा गूदा परियोजना

1908. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दण्डकारण्य क्षेत्र में कागज तथा गूदा परियोजना स्थापित किए जाने की व्यवहार्यता के बारे में हाल में कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अध्ययन पूरा हो गया है;

(ग) अध्ययन दल के द्वारा कितनी क्षमता के संयंत्र के निर्माण की सिफारिश की गई है तथा उसे किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा तथा संयंत्र में किन वस्तुओं के निर्माण की सिफारिश की गई है; और

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली महमद):

(क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता 50,000 मी० टन लुग्दी, छपाई तथा लिखने के कागज की है। अध्ययन दल ने जगदलपुर के निकट स्थापित करने की सिफारिश की है।

(घ) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है और इसपर शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है।

चश्मे (आप्टीकल) सम्बन्धी उपकरण परियोजना, लखनऊ

1909. **श्री सरजू पाण्डेय**:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963 में लखनऊ में एक प्रकाशीय उपकरण परियोजना आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना के लिए तकनीकी कर्मचारियों और व्यवसाय शिक्षुओं की भर्ती की गई थी; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार इस परियोजना को छोड़ने वाली है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जिसका सम्बन्ध इस परियोजना से है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिरला संगठनों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी

1910. **श्री सरजू पाण्डेय**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के बहुत से सेवानिवृत्त पदाधिकारी बिड़ला संगठनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार में कार्य कर रहे बहुत से पदाधिकारियों के निकट सम्बन्धी भी बिड़ला संगठनों में विभिन्न हैसियतों पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो वे कौन हैं और सरकारी कार्यालयों में कार्य कर रहे अधिकारियों से उनका क्या सम्बन्ध है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) किसी भी अवकाश प्राप्त प्रथम श्रेणी के अधिकारी को औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय से अवकाश प्राप्त करने के दो वर्ष के अन्दर किसी भी बिरला संस्थान में जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के न तो किसी भी प्रथम श्रेणी के अधिकारी ने अब तक कोई सूचना दी है और न आवश्यक अनुमति माँगी है, जैसा कि उनको अपने निकट सम्बन्धियों द्वारा किसी भी बिड़ला संस्थान में नौकरी प्राप्त करने के संबंध में नियमानुसार प्राप्त करनी होती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिहिनपुरवा स्टेशन के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

1911. **श्री सरजू पाण्डेय**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 2 सितम्बर, 1967 को पूर्वोत्तर रेलवे की 174 डाउन यात्री गाड़ी मिहिनपुरवा स्टेशन के निकट (कटारनयन घाट सैक्शन पर) पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा कितने व्यक्ति घायल हुए थे; और

(ग) इस गाड़ी के पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ।

(ख) इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 व्यक्तियों को मामूली चोट आई थी और एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुआ था; और

(ग) किसी व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा रेल की पटरी पर कुछ गड़बड़ किए जाने के कारण यह दुर्घटना हुई थी?

राज्यों द्वारा सूती कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेना

1912. **श्री सरजू पाण्डेय**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे कुप्रबन्ध वाली कपड़ा मिलों को तुरन्त अपने हाथ में ले लें; और

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन मिलों को अपने हाथ में लेने के बारे में सोच रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल जटा के रेशे के निर्यात पर उपकर

1913. **श्री श्रीधरन**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नारियल जटा के रेशे और नारियल जटा के अन्य उत्पादों के निर्यात से प्राप्त उपकर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने नारियल जटा उद्योग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए उस उपकर में से कुछ धन खर्च किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो 1965–66 और 1966–67 में कितनी धनराशि खर्च की गई थी?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात से प्राप्त उपकर का उपयोग नारियल जटा बोर्ड द्वारा नारियल जटा उद्योग के विकास की योजनाओं के लिए किया जाता है। आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं का विवरण नारियल जटा बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जाता है जो प्रतिवर्ष सभा पटल पर रखे जाते हैं।

(ख) इस बोर्ड द्वारा श्रमिक कल्याण की कोई योजना आरम्भ नहीं की गई है;

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

कच्चे रबड़ का मूल्य

1914. **श्री श्रीधरन: श्री गार्डिलिगन गौड़**:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टैरिफ आयुक्त ने कच्चे रबड़ के लिये जिस विक्रय मूल्य की सिफारिश की है वह रबड़ की खेती करने वालों के लिये लाभप्रद नहीं है और रबड़ की खेती के विकास के लियें हानिकारक है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: (क) श्रीमन्, सरकार की राय में ऐसा नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्जियर्स में सम्मेलन

1915. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: **श्री शिव चन्द्र झा**:

श्री रवि राय:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में 77 विकासशील देशों का एक सम्मेलन अल्जियर्स में हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें क्या क्या मुख्य निर्णय किए गए; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) इस सम्मेलन में किए गए निर्णय इस सम्मेलन के अन्त में स्वीकृत अल्जियर्स के घोषणापत्र में दिये गये हैं। इस घोषणापत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है **(पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल०टी० 1737/67)**।

(ग) इस सम्मेलन में किए गये निर्णयों में भारत सरकार का पूर्ण योगदान रहा है। आशा है कि नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में अल्जियर्स सम्मेलन में किए गए निर्णयों के आधार पर उन्नत तथा विकासशील देशों, दोनों के लिए सहायता तथा व्यापार के क्षेत्र में कोई समझौता कर सकना संभव होगा।

रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन

1916. **श्री गाडिलिंगन गौड़:** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1967 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 18 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले रूरकेला इस्पात संयंत्र इस समय बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संयंत्र में उत्पादन आरम्भ करने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है; और

(ग) रूरकेला इस्पात संयंत्र में सामान्य से कम उत्पादन होने के फलस्वरूप हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को अब तक हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० च० सेठी): (क) जी, हाँ।

(ख) 1966–67 के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा घोषित मजदूरों की मजूरी का 4 प्रतिशत कानूनी न्यूनतम बोनस के विरोध में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मजदूरों ने सितम्बर-अक्तूबर में बिना हड़ताल किए आन्दोलन किया था। चूंकि संयंत्र के कीमती उपकरणों को गम्भीर क्षति पहुँचने का खतरा था, इसलिये अक्तूबर, 1967 में कुछ समय के लिये रूरकेला में कोयला भट्टी तथा धमन भट्टी को खाली रखना पड़ा था। अब इस विवाद का सौहार्दपूर्ण हल हो जाने के परिणामस्वरूप 19 अक्तूबर 1967 से इस संयंत्र को फिर चालू कर दिया गया है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे समय सारिणी

1917. **श्री कृष्णमूर्ति:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए रेलवे विभाग के पास दो समय सारिणियाँ होती हैं; और

(ख) क्या देर से चल रही रेलगाड़ियों के समय का तालमेल बिठाने के लिये कुछ समय की गुंजाइश रखी जाती है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ। सार्वजनिक समय सारिणी में यात्री गाड़ियों के छूटने और पहुँचने का समय तथा यात्रा करने वाले लोगों के लिए सामान्य जानकारी होती है। विभागीय कार्य समय सारिणी में रेलवे कर्मचारियों के मार्ग दर्शन के लिए विस्तृत तकनीकी जानकारी तथा मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों को चलाने के बारे में हिदायतें होती हैं।

(ख) जंजीर खींचने, किसी के रेल से दब जाने, सिगनल खराब हो जाने के कारण अप्रत्याशित रूप से गाड़ियाँ रुक जाने के लिए कुछ गाड़ियों के गन्तव्य स्थानों पर पहुँचने में सामान्यत: कुछ गुंजाइश रखी जाती है।

अग्निगुंडला में ताम्बा परियोजना

1918. **श्री कृष्णमूर्ति :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में अग्निगंडला में ताम्बा परियोजना के लिये अमरीकन कम्पनी (एशलैंडस) के सहयोग का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी शर्तें क्या हैं और फर्म की वित्तीय स्थिति कैसी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) सरकार ने मैसर्स एशलैंड आइल रिफाइनिंग कम्पनी लि० अथवा किसी दूसरी विदेशी कम्पनी के विदेशी सहयोग पर सहायता से आन्ध्र प्रदेश के अग्निगुंडला के ताँबा सीसा निक्षेपों के विकास तथा विदोहन के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा विदेशी सहयोगी के बीच में इस समय सहयोग की शर्तों के विस्तारों पर बातचीत हो रही है। विदेशी सहयोग की शर्तों को अन्तिम रूप देने से पूर्व उनसे प्रागेतिहास तथा वित्तीय दशा के बारे में पक्का पता लगाया जाएगा।

आसाम में सीमेंट कारखाना

1919. **श्री जो० ना० हजारिका :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने आसाम में बोकाजन में सीमेंट का एक कारखाना आरम्भ करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके निर्माण-कार्य के कब से आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने बोकाजन (आसाम) में सीमेंट का एक कारखाना शुरू करने के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। फिर भी खुदाई का काम विस्तृत रूप से शुरू किया जा रहा है जिससे इस बात का निश्चय किया जा सके कि इस क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड का कितना चूने का पत्थर उपलब्ध हो सकता है। अन्तिम निर्णय की जा रही जाँच-पड़ताल के परिणामों पर ही निर्भर होगा।

अमरीका से रेल की पटरियों का आयात

1920. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने वर्ष 1966 में 5 करोड़ रुपए के मूल्य की रेल की पटरियों की सप्लाई के लिए अमरीकी फर्मों को क्रयादेश दिए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्लारपुर कोयला खान

1921. **श्री कृ० मा० कौशिक:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लारपुर कोलियरी (कोयला खान) कम्पनी को अपनी कोयला खानों को प्रयोग के लिये मशीनें खरीदने के लिये ऋण दिया गया था;

(ख) क्या मशीनों की आयात किया गया था और उसपर विदेशी मुद्रा व्यय हुई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन मशीनों के पहुँचने की तथा उस कोयला खान में उनके प्रयोग किये जाने की, जिसके लिये उसे लाया गया था, सत्यता की जाँच की गई थी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी):

(क) बलारपुर कोयलरी कम्पनी ने कोयला खानों में प्रयोग के लिये खनन मशीनें खरीदने के लिये निजी ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त किया।

(ख) हाँ, महोदय।

(ग) कोयला खान में सत्यापन का कार्य प्रगति कर रहा है।

इस्पात कारखानों में घेराव

1922. **श्री प्र० न० सोलंकी:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में विभिन्न इस्पात कारखानों के मजदूरों ने कितनी बार 'घेराव' किया है; और

(ख) सम्बन्धित मजदूरों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) गत छः महीनों के विभिन्न इस्पात कारखानों के मजदूरों द्वारा 'घेराव' के लगभग 147 मामले थे।

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने एक मामले में उचित अनुशासनिक कार्यवाही की है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा धातु मिश्रित इस्पात परियोजना में तथा भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी में जो अन्य मामले हुए उनके सम्बन्ध में प्रबन्धकों ने मजदूरों के विरुद्ध कार्यवाही करना उचित नहीं समझा क्योंकि उन क्षेत्रों में सामान्य औद्योगिक अशान्ति है।

Shunting at Kalyan Station Yards

1923. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of wagons involved in accidents during the period from 1st January, 1966 to 30th October, 1967 at the time of shunting in the yard for goods trains at Kalyan Station on the Central Railway (Bombay Division) ;

(b) the anticipated loss of railway property as a result thereof ;

(c) whether it is a fact that careless shunting is resulting in heavy loss every year ;

(d) if so, whether any responsibility has been fixed ; and

(e) the amount of compensation required to be paid to the owner of goods ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) During the period 1.1.66 to 30-10-67, 320 wagons were involved in accidencts during shunting operations in Kalyan Goods yard.

(b) Rs. 1,91,661/-.

(c) and (d) Some of the accidents are due to careless shunting and wherever staff are held responsible, they are dealt with suitably.

(e) It cannot be said what amount of compensation was paid as a result of damage to booked consignments during shunting at a particular station.

Diva-Dahanu Railway Line

1924. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the survey work in regard to the Diva-Virar Link Railway between the Central and the Western Railways has been completed ;

(b) the number of organisations from whom requests have been received to the effect that Diva-Dahanu link railway may be taken up instead of Diva-Virar ;

(c) whether the Chief Minister and the Food Minister of Maharashtra have also made a similar request ;

(d) if so, whether a survey of Diva-Dahanu link railway is proposed to be undertaken ;and

(e) if so, when ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The survey work is still in progress.

(b) Representations have been received from a number of individuals and various organisations for construction of Diva-Dahanu link in preference to Mira Road-Diva or Virar-Diva links.

(c) Yes.

(d) and (e) : The Diva-Dahanu link will be much longer and hence will be much more costlier to construct than the Diva-Mira Road/Viraro rail link. The proposal under consideration is for a short additional rail link between the Central & Western Railways for facilitating inter-change traffic and the Diva-Dahanu rail link is considered not suitable for this purpose and hence no surveys are proposed to be undertaken for it.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन

1925. **श्री दी० च० शर्मा :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पुनर्गठन के प्रश्न पर अभेतर विचार करने के लिये नियुक्त समिति के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) वह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्र० च० सेठी):

(क) और (ख) समिति अभी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्य कलापों की पुछ-ताछ कर रही है और आशा है कि यह जनवरी 1968 तक सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देगी।

पुर्तगाल के साथ व्यापार

1926. **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के पुर्तगाल के साथ अब भी व्यापार सम्बन्ध हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा पुर्तगाल से आयात की जाने वाली और उसे निर्यात की जाने वाली विशिष्ट वस्तुयें क्या हैं और भारत कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पुर्तगाल से व्यापार सम्बन्ध कब समाप्त किए गए थे तथा कितनी अवधि के लिये समाप्त किए गए थे और किन कारणों से किये गए थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अपने 20वें अधिवेशन में यह संकल्प पास किए जाने के पश्चात् कि सभी सदस्य देश पुर्तगाल के साथ व्यापार समाप्त कर दें, पुर्तगाल के साथ व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। प्रतिबन्ध तब से जारी है।

रूपनारायणपुर केबल्स फैक्टरी

1927. **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार मंत्रालय रूपनारायण कैबल्स फैक्टरी को अपने नियंत्रण में ले रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिड़ला बन्धुओं के बैंक

1928. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक-विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिड़ला बन्धुओं के कितने बैंक हैं ;

(ख) बैंकों अथवा कम्पनियों के कितने अन्तर्वर्ती निदेशक पदों पर बिड़ला बन्धु आसीन हैं ; और

(ग) बिड़ला बन्धुओं ने कितने उद्योग स्थापित किए हैं ; और उनके नियंत्रणाधीन उद्योगों में कुल वस्तु-उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) एकाधिकार जाँच आयोग की रिपोर्ट में, 36 बिड़ला कम्पनियाँ, 132 उत्पादनों में, से 5 शिखर उत्पादकों की कोटि में थीं। कम्पनियों के नाम, तथा इन उत्पादनों का सम्पूर्ण उत्पादन में भाग, जैसा 1964 में प्राप्त हुआ, संलग्न विवरण पत्र में उल्लिखित हैं। (**पुस्तकाय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1738/67**)। बिड़ला समूह से संबंधित अन्य कम्पनियों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है।

जापान को कोयले का निर्यात

1929. **श्री दामानी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को कोयला निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत किस अवस्था में है; और

(ग) क्या बातचीत में कोई अड़चन आ गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) मा इन्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ने कोयला निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये हाल में एक प्रतिनिधि मण्डल जापान भेजा था। प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट के अनुसार अ-कोकवार कोयले का उस देश को निर्यात करने की कोई सम्भावना नहीं है। जापानियों ने तथापि कोकवार कोयले का आयात करने में कुछ रुचि दिखाई है बशर्ते कि उन्हें बढ़िया किस्म का कोयला दिया जाये, बन्दरगाह सुविधायें बढ़ाई जायें तथा भारत यह स्वीकार कर ले कि वह लम्बी अवधि तक लगभग 15 लाख टन कोयला प्रतिवर्ष निर्यात करता रहेगा। इस बात पर विचार किया जा रहा है।

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना

1930. **श्री दामानी**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1966 में घोषित उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने की पद्धति के प्रभावों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव है;

(ख) प्रथम पुनरीक्षण कब तक किया जायेगा; और

(ग) यदि पुनरीक्षण पहले ही किया जा चुका है तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) 1967 के प्रारम्भ में मई, 1966 में घोषित कुछ उद्योगों से लाइसेंस हटाये जाने के प्रभावों का पुनरीक्षण करने का प्रयास किया गया था। तथापि यह समझा गया था कि इसके परिणामों के आँके जाने का समय नहीं है क्योंकि विशेष कर इस बीच कई दूसरे कारण भी उपस्थित हो गए थे। अब नया पुनरीक्षण किया जा रहा है।

रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा टिनप्लेटों की सप्लाई

1931. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाना भारत में उद्योगों को टिनप्लेटें सप्लाई कर रहा है;

(ख) क्या वह देश में टिनप्लेटों की समस्त माँग पूरी करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रति वर्ष कितनी टिनप्लेटों का आयात किया जा रहा है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गत तीन वर्षों में आयात की गई टिनप्लेटों की मात्रा इस प्रकार है:—

	मेट्रिक टनों में
1964-65	52,416
1965-66	34,034
1966-67	40,035

सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानें

1932. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र में सभी इस्पात कारखानों में 1967–68 में अब तक लोहे और इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) इस अवधि में कितनी मात्रा निर्यात की गई और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और ख) जानकारी बताने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 1739/67]।

इस्पात कारखानों के कार्य का समय-समय पर पुनर्विलोकन

1933. **श्री गणेश:** **श्री मुहम्मद इस्माइल:**

श्री राम मूर्ति: **श्री गणेश घोष:**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समय-समय पर इस्पात कारखानों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों और प्रबन्ध विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय दल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उसके कृत्य क्या होंगे?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन इस्पात कारखानों के कार्यसंचालन का पुनर्विलोकन करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों और प्रबन्ध विशेषज्ञों का एक उच्च-स्तरीय दल बनाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। कारखानों में विभिन्न एककों के कार्य तथा उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये दल बनाने के हेतु इस समय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड कार्य कर रहा है तथा एक ऐसा दल पहले ही बन चुका है जो उप-उत्पाद एककों की जाँच करेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इस्पात कारखानों की क्षमता

1934. **श्री अमृत नाहाटा :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये उपयोग की जा सकने वाली वर्तमान औद्योगिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनपर क्या निर्णय किया गया है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बैक्यूम ब्रेक

1935. **श्री शशि भूषण वाजपेयी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा तैयार की गई नई किस्म की वैक्यूम ब्रेकों का तेज गति से चलने वाली गाड़ियों में हाल में प्रयोग किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले?

रेलवे मंत्री (श्री ओ० वे० मु० पुनाचा): (क) जी, हाँ। रिसर्च डिजाइन्स एण्ड स्टेन्डर्ड्स आर्गेनाइजेशन ने यात्री गाड़ियों के वैक्यूम ब्रेक व्यवस्था पर उसमें कुछ सुधार करके तेज गति से चलने वाली गाड़ियों पर नियंत्रण के लिये आवश्यक शक्ति वाले ब्रेक बनाने के उद्देश्य से कुछ प्रयोग किए हैं। प्रयोग अभी भी किए जा रहे हैं और नवम्बर, 1967 के अन्त इसका पहला चरण पूरा हो जायेगा।

(ख) वैक्यूम ब्रेक में जो सुधार किए गए हैं उनके अनुरूप ब्रेक संतोषजनक कार्य कर रहे हैं।

सहकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का कारखाना

1936. **श्री अमृत नाहाटा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय--कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने के लिये सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारी वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के मूल्यों तथा वितरण पर नियंत्रण

1937. **श्री गणेश:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारी वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों के मूल्य तथा वितरण पर से नियंत्रण हटाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ।

(ख) व्यावसायिक गाड़ियों की बिक्री तथा वितरण पर अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण तथा सांविधिक नियंत्रण दोनों ही 19 सितम्बर, 1967 से उठा लिये गय हैं।

इन गाड़ियों का जहाँ तक प्रतिरक्षा दलों को सम्भरण करने का सम्बन्ध है, अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण अब भी लागू है।

पिंजोर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना

1938. **श्री गणेश :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिंजौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तथा उसको काफी घाटा हो गया है,

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(खे) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमेंट की मूल्य-वृद्धि

1939. **श्री शशि भूषण वाजपेयी:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट की कीमत बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) ढुलाई भाड़े में वृद्धि हो जाने और उत्पादन बढ़ जाने के कारण सीमेंट का एफ० ओ० आर० मूल्य बढ़ाने का उद्योग का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है।

इस्पात बिलैटों के निर्यात के लिये राज सहायता

1940. **श्री अमृत नाहाटा:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात बिलैटों के निर्यात के लिये राज सहायता देने के प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बुनकर सहकारी समिति

1941. **श्री सरजू पाण्डेय:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के समस्त हथकरघा बुनकरों को संगठित करने के उद्देश्य से सरकार का विचार बुनकर सहकारी समितियाँ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार कितना-कितना धन नियत किया गया है;

(ग) उत्तरप्रदेश राज्य में कितनी समितियाँ केन्द्रीय सहायता से कार्य कर रही हैं; और

(घ) यदि वहाँ पर कोई नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1740/67**]।

रबड़ का आयात

1942. **श्री वासुदेवन नायर:** **श्री बलराज मधोक:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1967–68 में रबड़ का आयात करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि इस वर्ष रबड़ का आयात करने की आवश्यकता नहीं है; और

(ग) 1967–68 के सम्बन्ध में रबड़ के उत्पादन तथा उसकी खपत के वे आँकड़े क्या हैं, जो रबड़ बोर्ड ने भेजे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) रबड़ बोर्ड के अनुमानों के अनुसार भारत में 1967–68 के दौरान (प्राकृतिक और कृत्रिम) रबड़ का उत्पादन 89,000 टन और खपत 105,000 टन होगी।

उपभोक्ता वस्तु निगम

1943. **श्री गणेश :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उपभोक्ता वस्तु निगम स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) मामला विचाराधीन है।

R. S. S. and Government Employees

1944. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether there is a ban on employees of the Central Government Undertakings to take part in the Rashtriya Swayam Sewak Sangh (R.S.S) activities ;

(b) whether Government are aware that the members of R.S.S. are even today indulging in such unlawful activities freely in N.C.D.C. Colony at Syal, District Hazaribagh, (Bihar ;) and

(c) if so, the action Government propose to take in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) Home Ministry's O. M. dated 30th November, 1966 has clarified the position about the participation of Government employees in activities of R.S.S. Regarding applicability of the above orders to employees of Central Government Undertakings, this depends on the rules governing the service conditions prescribed by the Central Government Undertakings.

(b) Information is being collected.

(c) Does not arise.

Supply of Water at Patratu

1945. **Shri Ramavatar Shastri** :Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that clean and filtered drinking water is not supplied to the Railway employees at Patratu (Hazaribagh in Bihar) ;

(b) whether it is also a fact that the diesel which flows from the Diesel Shed there mixes with the water of Damodar river and that water is supplied to the Railway employees for drinking purposes ;

(c) whether it is also a fact that the employees became victims of jundice and other diseases by drinking this diesel-mixed water ; and

(d) if so, whether Government propose to make arrangement to supply clean and filtered drinking water to the Railway employees at Patratu and, if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) No.

(c) No.

(d) Does not arise,

सैनिकों द्वारा बिना टिकट यात्रा

1946. **श्री वि० ना० शास्त्री**:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें पता है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आसाम सेक्शन में पहले दर्जे के डिब्बे में बहुत से सैनिक बिना आवश्यक टिकट अथवा पास के यात्रा करते हैं;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि सैनिकों द्वारा इस प्रकार अनधिकृत यात्रा किए जाने के परिणामस्वरूप वास्तविक यात्रियों को दिक्कत व परेशानी होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इसे बन्द करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ग) ऐसे उदाहरण नहीं मिले हैं जिनसे पता चलता हो कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आसाम क्षेत्र में सैनिक कर्मचारी पहले दर्जे के डिब्बों में बिना टिकट या अनुचित टिकटों के आधार पर यात्रा करते हैं। हाँ, ऐसे कुछ मामले सामने आये हैं जिनमें सैनिकों ने सुरक्षित डिब्बों को जबरदस्ती अपने प्रयोग में लाये हैं। इस प्रकार के मामलों में रेलवे यात्रा अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की सहायता से उनसे वे डिब्बे खाली करा लिये गये थे।

आसाम में रेल दुर्घटनाएं

1947. **श्री वि० ना० शास्त्री**:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर तथा अक्तूबर, 1967 में पूर्वोत्तर रेलवे के आसाम सैक्शन में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत सी दुर्घटनाएँ समुचित देखभाल न होने के कारण हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) सितम्बर और अक्तूबर, 1967 में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के उन सैक्शनों में रेलवे पटरी से उतर जाने की 19 घटनाएँ हुई थीं जो आसाम राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। गाड़ियों के परस्पर टकरा जाने, रेलवे फाटक पर सड़क पर चलने वाली मोटर गाड़ियों के साथ रेलगाड़ी की टक्कर होने और गाड़ियों में आग लग जाने की तरह की कोई रेल-दुर्घटना नहीं हुई।

(ख) इन 19 घटनाओं में ऐसी कोई भी घटना नहीं जो समुचित देख-भाल न होने के कारण हुई हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेशमी धागे का निर्यात

1948. **श्री वि० ना० शर्मा**:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेशम के धागे और रेशमी कपड़े के निर्यात के लिये क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; और

(ख) क्या रेशम की सभी किस्मों के निर्यात के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शुहम्मक शफी कुरेशी): (क) और (ख) वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत शुद्ध रेशमी कपड़े, सिले सिलाये कपड़े और तैयार वस्तुओं के रजिस्टर्ड निर्यातकों को ही अपने निर्यातों के बदले कुछ कच्चा माल आयात करने का अधिकार है। एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें रेशम से बनी उन वस्तुओं की किस्मों का उल्लेख है जिनके निर्यात की अनुमति है, इस प्रकार के निर्यातों के बदले कितने प्रतिशत आयात किया जा सकता है और उन वस्तुओं का भी उल्लेख है जिनके आयात करने की अनुमति है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1741/67**]।

उड़ीसा सरकार द्वारा सिफारिश किये गये औद्योगिक लाइसेंस

1949. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही**:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री निम्नलिखित सूचियाँ सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल से नवम्बर 1967 तक उड़ीसा सरकार द्वारा सिफारिश किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की सूचियाँ, और

(ख) जिन फर्मों और व्यक्तियों की सिफारिश की गई है उनके नामों की सूचियाँ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): अप्रैल 1967 से नवम्बर 1967 तक की कालावधि में उड़ीसा राज्य में नये उद्योग स्थापित करने के लिये और नयी वस्तुओं के निर्माण के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए चार आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। उड़ीसा सरकार ने सभी आवेदन-पत्रों की सिफारिश की है।

(ख) जिन फर्मों और व्यक्तियों को लाइसेंस देने के लिये उड़ीसा सरकार ने सिफारिश की है, वे निम्नलिखित हैं:

1. श्री के० के० जंजोडिया, कलकत्ता
2. मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला,
3. उतकल मशीनरी लिमिटेड. कंशाबल
4. उड़ीसा सरकार का सचिव, माइनिंग तथा जियालोजी विभाग, भुवनेश्वर।

उड़ीसा में खनन पट्टे

1950. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही**:

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के क्योंझर जिले में हाल ही में श्रीमती सरोजनी प्रधान को कितने खनन पट्टे तथा रियायतें दी गई हैं; और

(ख) किस प्राधिकारी की सिफारिश पर ऐसा किया गया है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) और (ख) श्रीमती सरोजनी प्रधान को हाल ही में कोई खनन पट्टा/रियायत नहीं दी गई है। तथापि 1964 में उड़ीसा सरकार ने उसे दो खनन पट्टे स्वीकार किए थे, जिसके लिये राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी थी।

मनीपुर से पशुओं का निर्यात

1951. **श्री मेघचन्द्र :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र से कितने पशुओं, मुख्यत: स्थानीय साँड़ों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने पशुओं के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है;

(ग) क्या सरकार निर्यात हेतु परमिट जारी करने के लिये कुछ शुल्क लेती है; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी राशि एकत्रित की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) कोई नहीं ।

(ख) निर्यात-नियंत्रण आदेशों को अनुसूची के भाग (क) के अन्तर्गत पशु की मद है और इसलिये सामान्य रूप से उनके निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रतनगढ़ और अहमदाबाद के बीच सीधा सवारी डिब्बा

1952. **डा० कर्णी सिंह:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतनगढ़ और अहमदाबाद के बीच एक सीधा सवारी डिब्बा लगाने के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी. हाँ।

(ख) इस प्रार्थना पर विचार करने से पता चला है कि नियमित रूप से गाड़ी का डिब्बा उपलब्ध न होने के अतिरिक्त उक्त स्थानों के बीच यातायात इतना कम है कि सवारी डिब्बे की व्यवस्था न्यायोचित सिद्ध नहीं होती।

Mob Attack at Howrah Station

1953. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several persons were injured in firing and lathi-charge resortee to in an encounter that followed an attack by a mob at Howrah Station and extensive damag;u was caused to Government property as reported in Hindustan dated the 12th September, 196ऽ

(b) if so, the causes of the disturbance ;

(c) the loss of life and property suffered as a result thereof ; and

(d) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) The correct position is that on 11.9.1967 at about 9.40 hours, due to failure of a point at Howrah Yard, dowd trains were detained near the Car Shed. The delay infuriated the passengers who got down from the train, proceeded towards the Route Relay Cabin, and attacked it with brickbats and stones. Glass panes of the cabin were broken due to stone throwing and six jawans of the Railway Protection Special Force guard were injured. The infuriated mob thereafter made a determined attempt to force their entry inside the cabin with the intention to damage and destroy the valuable equipments and attack the cabin staff. The Railway Protection

Special Force armed guard apprehending the imminent danger to the life of railway staff and property opened fire in the exercise of their right of private defence of the body and of railway property which they are required to protect under the R.P.F. Act, 1957.

The District Magistrate who arrived at the scene was also hit by a stone causing a bleeding injury. The Police had to resort to lathi-charge a violent crowd which had attacked Howrah Station and also assaulted two M.L.A.s who had gone there to pacify them.

(c) There was no loss of life due to firing, but damage to railway property has been estimated at Rs. 18,000 approximately.

(d) The General Managers, Eastern and South-Eastern Railways met the Chief Minister, Deputy Chief Minister, other Ministers and senior officials of the West Bengal Government on 12th September 1967, and discussed various aspects of law and order problem affecting train services and attacks on railway staff and property. The West Bengal Government agreed to deal with anti-social and unruly elements who interfere with train operations and attack railway installations etc. deterrently. The General Managers agreed to give publicity to the difficulties in maintaining punctuality of train services and to seek public cooperation.

सरकारी क्षेत्र का ट्रैक्टर परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन

1954. **श्री चं० चु० देसाई:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की ट्रैक्टर परियोजना हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये चेकोस्लोवाकिया की एक फर्म को 16 लाख रुपए दिए हैं और यदि हाँ, तो क्या वह प्रतिवेदन सेन्ट्रल मेकैनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्ट्यूट दुर्गापुर से तैयार नहीं करवाया जा सका था;

(ख) क्या चैकोस्लोवाकिया की फर्म को ट्रैक्टरों के निर्माण का अनुभव है और यदि हाँ, तो क्या 20 अश्व-शक्ति के ट्रैक्टर का चेकोस्लोवाकिया में सफलतापूर्वक परीक्षण एवं प्रयोग किया गया था; और

(ग) चैकोस्लोवाकिया की फर्म ने अब तक कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया है और उनमें से कितने ट्रैक्टरों का उपयोग भारत में किया जा रहा है और कितने समय से उनका उपयोग किया जा रहा है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) भारत सरकार तथा चैकोस्लोवाकिया के मैसर्स मोटोकोव के बीच खेती के ट्रैक्टरों और औजारों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना की स्थापना करने के हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये 28 अगस्त, 1965 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार की शर्तों के अनुसार भारत सरकार को चैक एजेंसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये 33 लाख रुपये (अव मूल्यन के पहले) का भुगतान करना पड़ेगा। रिपोर्ट का भाग 1 जिसमें तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन दिया हुआ है, पहले प्रस्तुत की जानी थी। इस सम्भाविता रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने और उकी जाँच कर लेने के पश्चात् भारत सरकार को इच्छा पर निर्भर करेगा। यदि परियोजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो ऐसी दशा में वह चैक एजेन्सी को केवल 16.50 लाख रुपए (अवमूल्यन से पूर्व) का ही

भुगतान करेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का पहला भाग अब मिल गया है किन्तु चैक एजेन्सी को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। जिस समय चैकोस्लोवाकिया विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये यह करार किया गया था सी० एम० ई० आर० आई० अपनी ओर से ट्रैक्टर के निर्धारित नमूने के विभिन्न पुर्जों के डिजाइन और विवरणों के बारे में पूरे आँकड़े नहोने के कारण इस प्रकार की विस्तृत परियोजना तैयार करने की स्थिति नहीं थी।

(ख) चैकोस्लोवेकिया की फर्म विभिन्न शक्ति वाले ट्रेक्टरों का निर्माण करने में बड़ा अनुभव रखती है। उसके पास परिक्षण की आधुनिक सुविधायें भी हैं। यद्यपि सरकार को चेकोस्लेवाकिया में बने 20 अश्व शक्ति के ट्रेक्टरों की जाँच और परीक्षण के बारे में तत्काल सूचना नहीं है तो भी उनके ट्रेक्टरों के नमूने कुशलतापूर्वक काम करने में सारे संसार में प्रसिद्ध है। जीटर 2011 ट्रेलर जिसका चुनाव भारत में बनाने का किया गया था, उसकी जाँच बुदनी स्थित सरकारी ट्रेक्टर प्रशिक्षण केन्द्र में विशुद्ध रूप में की गई थी और भारत में उसका काम बड़ा संतोषजनक पाया गया था।

(ग) मैसर्स मोटेकोव के अनुसार उन्होंने 1945 से 1963 की अवधि में कुल 278,000 जीटर ट्रेक्टर (2011,3011 तथा 4011) बनाये थे। बाद के वर्षों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस समय केवल 3 या 4 जीटर 2011 ट्रेक्टर भारत में इस्तेमाल में लाते हैं ये मई 1965 से यहाँ हैं।

चेकोस्लोवाकिया की एक फर्म के सहयोग से ट्रेक्टरों का निर्माण

1955. **श्री च० चु० देसाई :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया की फर्म, जिसके सहयोग से सरकार ट्रेक्टर बनायेगी, ने आरम्भ में 12,000 ट्रैक्टरों के बनाने के लिये 35 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने को कहा था और बाद में उसने इस राशि को घटा कर 18 करोड़ रुपये कर दिया और अब उसने इसे छः करोड़ रुपये कर दिया है।

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र के पाँचों उद्योगों में प्रति वर्ष 30,000 ट्रैक्टरों के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त होने पर कुल कितनी पूंजी लगाये जाने का अनुमान है;

(ग) क्या छोटे ट्रैक्टर बनाने के लिये भारत सरकार को बहुत सी ऐसी योजनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें दो से तीन करोड़ रुपये से अधिक पूंजी नहीं लगाई जायेगी और यदि हाँ, तो उन पर विचार न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र में बने चैकोस्लोवाकिया के 20 हार्स पावर के ट्रैक्टर का अनुमानित विक्रय मूल्य क्या होगा.

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) 1965 में मै० मोटोकोव द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट में 12,000 ट्रैक्टरों, 28.000 औजारों तथा 20 प्रतिशत फालतू पुर्जों की क्षमता वाली परियोजना पर कुल अनुमानित विनियोजन खर्चा 17.7 करोड़ रु० अवमूल्यन पूर्व दिखलाया गया था। इसमें एक ढलाई प्रेस शाप, तथा फोर्ज शाप की व्यवस्था थी।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो कि चेकोस्लोवाकिया से मई, 1967 में प्राप्त हुई थी, के खण्ड 1 में परियोजना में विनियोजन को पुनरीक्षित कर 23.48 करोड़ रु० अवमूल्यन पूर्व कर दिया गया था। इसमें ढलाई पर होने वाला विनियोजन भी सम्मिलित है।

भारत सरकार के अधिकारियों के विस्तृत विचार विनिमय के पश्चात् मे० मोटोकोव ने एक पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें से फोर्ज शाप, कोल्ड प्रेस शाप और गियर शाप को निकाल कर जिसके फलस्वरूप इमारतों, बिजली के उपकरण, हीट ट्रीटमेंट और दूसरे खर्चों में बचत होने के कारण कुल विनियोजन को घटा कर 15.26 करोड़ रु० दिखाया गया है। मे० मोटोकोव ने यह भी कहा है कि यदि देश में ही सहायक उद्योगों द्वारा बनाये जाने वाले पुर्जों तथा वर्तमान एक्कों की फालतू क्षमता का हिसाब लगाया जाये तो वह लागत को और कम कर सकते हैं। वह इस समय लागत का पुनरीक्षित अनुमान तैयार करने में लगे हुए हैं और वे इसमें भारत सरकार को इस वर्ष के अन्त तक प्रस्तुत कर देंगे।

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर बनाने वाले 5 कारखानों को केवल संयंत्र और उपकरणों पर लगी हुई कुल वर्तमान पूंजी 3.76 करोड़ रु० है। इस राशि में ट्रैक्टर निर्माताओं की जमीन और मकान पर लगने वाली पूंजी और दो इंजन निर्माता जो ट्रैक्टर बनाने वालों को इंजन देते हैं, की पूंजी सम्मिलित नहीं है। उपकरण पर लगी हुई उक्त पूंजीभी इन ट्रैक्टरों के सम्पूर्ण निर्माण के लिये उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के हिसाब से अपूर्ण है। वास्तव में पाँचों ट्रैक्टर निर्माता और दोनों इंजन निर्माता मोटे तौर पर यह संकेत दे चुके हैं कि उनको मशीन और उपकरण के आयात पर प्रति वर्ष 30,000 ट्रैक्टर की क्षमता प्राप्त करने के लिये लगभग 6.89 करोड़ रु० की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में भी अधिक से अधिक के पास अपनी फांउन्ड्री या फोर्ज अथवा प्रेस-शाप नहीं है। यदि फोर्ज शापों, फाउन्ड्रियों, प्रेस-शापों और इंजनों तथा जमीन मकान और अन्य सेवाओं पर लगी पूंजी का हिसाब लगाया जाए तो पाँचों गैर-सरकारी कारखानों को 30,000 ट्रैक्टर बनाने के लिये लगभग 25 करोड़ रु० की पूंजी की आवश्यकता होगी।

(ग) अपेक्षाकृत थोड़ी लागत के छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण की कुछ योजनायें सरकार को पहले प्राप्त हुई थीं। यह योजनायें निम्नलिखित एक या इससे अधिक कारणों से स्वीकार नहीं की गई तीः-

1. कुछ योजनायें प्रस्तावित विनियोजन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं थीं।

2. कुछ योजनाओं में 8 अश्व शक्ति से 22 अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। जिसे कृषि विभाग नें भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं समझा था।

3. उस समय तक कम अश्व शक्ति की श्रेणी के ट्रैक्टरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये 20 अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया जा चुका है।

(घ) मे० मोटोकोव से प्राप्त विस्तृत योजना प्रतिवेदन के खण्ड 1 के अनुसार जीटर--2011 ट्रैक्टर का फैक्टरी के चलते समय का मूल्य लगभग 14,250 रु० होगा। जिसमें उत्पादकों का लाभ 15 प्रतिशत तथा व्यापारियों का 15 प्रतिशत लाभ सम्मिलित है।

क्रालर ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये लाइसेंस

1956. **श्री चं० चु० देसाई:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्रालर ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी किये हैं और यदि हाँ, तो जिनको लाइसेंस जारी किये गये हैं, उनके नाम क्या हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और वह किस के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण करेंगे;

(ख) क्या भारत में अपेक्षित क्रालर ट्रैक्टरों का आयात केवल उन्हीं निर्माताओं से करने का विचार है जिनके लिये भारत में उत्पादन के लिये लाइसेंस दिये गये हैं या उनका आयात किसी अन्य साधन से भी किया जा सकता है; और

(ग) क्या ट्रैक्टरों के आयात पर कुछ देशों के राजनीतिक दबावों का प्रभाव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) क्रालर ट्रैक्टर बनाने के लिये निम्नलिखित फर्मों को लाइसेंस/स्वीकृति दी गई है :—

फर्म का नाम	विदेशी सहयोगियों का नाम	क्षमता प्रति वर्ष
1. मे० हिन्दुस्थान मोटर्स लि० उत्तरपाड़ा (प० बंगाल)	मे० जनरल मोटर्स कारपोरेशन (यूथिल्ड डिवी) आफ यू० एस०	240 संख्या
2. मे० भारत अर्थमूवर्स लि० बंगलौर (नियमित औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया गया है)	मे० कोमात्सू० मैन्यू० कं० लि० टौकियो, जापान	500 संख्या
3. मे० पाशाभाई पटेल ऐंड कं० बम्बई	मे० रुडनैप आफ यूगोस्लाविया	400 संख्या

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित दो फर्मों को आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं—

फर्म का नाम	सहयोगी का नाम	क्षमता प्रति वर्ष
1. मे० ब्रिटेनिया इंजी० क० लि०, कलकत्ता	मे० मार्शल्स आफ यू० के०	150 संख्या
2. मे० बर्ड एण्ड कं० लि०, कलकत्ता	मे० हनीमैग आफ प० जर्मनी	150 संख्या

(ख) प्रायोजक अधिकारियों की सिफारिश पर 50 डी० ब० एच० पी० से ऊपर के उपलब्ध साधनों से क्रालर ट्रैक्टरों का आयात करने के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं के आवेदन पत्रों पर पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। जिन किस्मों के क्रालर ट्रैक्टर देश में नहीं बनते उनके आयात के लिये अनुमति दी जाती है। फिर भी जिस प्रकार के ट्रैक्टर देश में बनते हैं उनसे मिलते जुलते क्रालर ट्रैक्टरों का आयात करने की सामान्यता अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे मामलों में सरकार यह अधिक अच्छा समझती है कि स्वीकृत निर्माताओं से ट्रैक्टरों का आयात अलग-अलग सारे पुर्जों सहित किया जाना चाहिये। ऐसा इसलिये किया जाता है जिससे इसका सुनिश्चय किया जा सके कि इस प्रकार के आयातों पर कम से कम विदेशी मुद्रा खर्च हो और (2) फालतू पुर्जों की आवश्यकता और मरम्मत संबंधी सुविधाओं के मामले में बिक्री के बाद की समस्यान उत्पन्न हो।

(ग) जी, नहीं।

Heavy Electricals Ltd., Bhopal

Shri Ram Singh Ayarwal : Will the Minister **of Industrial Development** and **Company Affairs** be pleased to state :

(a) the causes of an annual loss of Rs. six crores in the Heavy Electricals Ltd., Bhopal;

(b) whether any scheme has beeh formed by Government to make good the loss and, if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) For a project of this kind and magnitude, such a loss is usual during the construction period and for some time after commencement of production. In fact, the loss is envisaged in the Detailed Project Report.

(b) Efforts are being made to improve the working by.

(i) improving the manufacturing techniques and increasing output ;

(ii) having a stricter control over each item of expenditure.

(iii) making effective use of plant and equipment and selecting ranges of manufacture which will give optimum return, and

(iv) improving labour productivity by introduction of incentive scheme.

(c) Does not arise.

'आपरेशन हार्ड राके' अभियान

1958. **प्र० के० देव :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों द्वारा खनिज सर्वेक्षण करने के लिये देश के कुछ क्षेत्रों में 'आपरेशन हार्ड राके' अभियान चलाया गया हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और देश के किन भागों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या इस अभियान के अन्य क्षेत्रों में भी चलाये जाने की सम्भावना है और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या इस अभियान के लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ था और यदि हाँ, तो किन देशों ने भाग लिया, तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) हाँ, महोदय ।

(ख) हवाई खनिज सर्वेक्षण जो कि इस कार्य का प्रथम चरण है, आँध्र प्रदेश के पूर्वी कुडापा खंड में चालू किया गया है। अभी तक 30,500 लाइन किलोमीटर की उड़ानें पूर्ण की जा चुकी हैं। अभी परिणाम बताना इतनी जल्दी संभव नहीं, क्यों कि प्राप्त की गई सामग्री के अभी निष्कर्ष निकाले जाने हैं।

(ग) राजस्थान के अरावली खंड और बिहार के कुछ भाग भी इस परियोजना में शामिल कर लिये जाएँगे ।

(घ) हाँ, महोदय । परियोजना की 3.5 मिलियन डालर की विदेशी मुद्रा की लागत इसी रकम की अमरीकी औद्योगिक विकास एजन्सी के ऋण से पूरी की जा रही है । भारतीय सरकार की समस्त देख रेख के नीचे ये कार्य अमरीका की पारसंस कारपोरेशन जो कि हवाई सर्वेक्षण के काम के लिए एरो सर्विस कारपोरेशन से सम्बन्धित है, के द्वारा ठेके के आधार पर किये जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों के रेलवे कर्मचारी

1959. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये स्तर उदार बनाने के बारे में रेलवे बोर्ड के 30 दिसम्बर 1965 के परिपत्र संख्या एल / नम्बर ई (एस० सी० टी०)/64 सी एम 15/4 को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो 1965 से 1967 तक की अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों ने पदोन्नति के लिये आयोजित विभागीय परीक्षा दी थी;

(ग) पदोन्नति के लिये बोर्ड के परिपत्र के अन्तर्गत अपेक्षित अर्हता अंक कितने कर्मचारियों ने प्राप्त किये; और

(घ) कितने कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) से (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभापटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र में ऐल्युमिनियम कारखाने की स्थापना

1960. **श्री राने :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की अवधि में महाराष्ट्र में ऐल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना करने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने उनसें विचार-विमर्श किया था। यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) कारखाना कहाँ स्थापित किया जायेगा और उसकी आर्थिक क्षमता क्या होगी; और

(ग) उसमें अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी और लागत का कितना प्रतिशत केन्द्रीय सरकार और कितना महाराष्ट्र सरकार वहन करेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) हाँ, महोदय। भारत सरकार ने कोयना ऐल्यूमिनियम परियोजना को कार्यान्वित करने का आमतौर से निर्णय ले लिया है। यह परियोजना चौथी पंच वर्षीय योजना की प्रारूप रूप-रेखा में शामिल है। सरकार इस समय परियोजना के कुछ पहलुओं पर फिर से विचार कर रही है जिनका सम्बन्ध मुख्यतया देशी उपकरण तथा सेवाओं का अधिकाधिक प्रयोग करने से है।

(ख) प्रस्ताव है कि प्लांट को रत्नागिरि (महाराष्ट्र) में स्थापित किया जाए। इस परियोजना की 50,000 टन प्रति वर्ष एल्यूमिनियम धातु उत्पादन करने की क्षमता होगी साथ में स्फोदिज खनन और एल्यूमिना निर्माण की सहायक सुविधाएँ भी होंगी।

(ग) नगर बसाने की लागत को छोड़कर परियोजना पर लगभग 68.88 करोड़ रुपये की लागत आने का अस्थाई अनुमान है। केन्द्रीय सरकार की एक निकाय, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी परियोजना को कार्यान्वित करेगी। परियोजना की लागत का कोई भी भाग राज्य सरकार पूरा नही करेगी। तथापि महाराष्ट्र सरकार परियोजना से बाहर पानी तथा बिजली देने का प्रबन्ध, बन्दरगाह प्लांट स्थान तक पहुँचने वाली सड़कें बनाने तथा इन्हें चौड़ा करने का व्यय करेगी।

सोमपुर स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) में रेलवे के क्वार्टर

1962. **श्री अगाड़ी:**

क्या **रेलवे** मंत्री 4 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8088 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में गदग और होस्पेट के बीच सोमपुर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के क्वाटरों के बारे में कोई अग्रेतर जाँच की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) इस मामले की अभी जाँच की जा रही है। दक्षिण रेलवे द्वारा दी गई प्राथमिक जाँच से पता चला है कि जिस प्रकार का निर्माण किया गया है या जिस प्रकार का डिजाइन बनाया गया है उन दोनों में कोई दोष नहीं है हालांकि आधार शिला की गहराई के सम्बन्ध में किये गये निर्णय में गलती हो सकती है।

औद्योगिक बस्तियों की क्षमता

1963. **श्री प्र० न० सोलंकी:**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 नवम्बर 1967 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि औद्योगिक बस्तियों की बेकार क्षमता के कारण केन्द्रीय सरकार को बहुत निराशा हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या औद्योगिक बस्तियों को सक्रिय करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। चूंकि औद्योगिक बस्तियों का निर्माण और उनकी देखरेख राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है इसलिए राज्यों के उद्योग निदेश कों से कहा गया है कि वे औद्योगिक बस्तियों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएँ।

(ग) भिन्न-भिन्न राज्यों में औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो कमियाँ आ गई हैं उनका मूल्यांकन/अध्ययन किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारें रहने वालो को कुछ प्रोत्साहन भी दे रही हैं। और अन्य राज्य सरकारें भी विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। इस प्रकार के अतिरिक्त प्रोत्साहनों में लघु उद्योगों को प्राप्त अन्य सुविधा और रियायत के अतिरिक्त किराया और चुंगी आदि से छूट की रियातें शामिल हैं जैसे कि रियायती दर पर उधार, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से किराया खरीद या मशीनों की उपलब्धि, लघु उद्योग सेवा स्थानों से तकनीकी सहायता इत्यादि।

Sale of Cars by S. T. C.

1964. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of imported cars sold by the State Trading Corporation during the last five years ;

(b) the number of cars out of them sold by auction and the total amount obtained therefrom ; and

(c) the number of cars out of them given to Government Departments, Ministries and Institutions and the estimated auction value thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) The number of cars solb dy S. T. C. from Ist June, 1962 to 31st October, 1967 is 2389.

(b) The number of cars sold in auctions so far is 1422 and the amount obtained on the sale comes to Rs. 4,24,43,704.08.

(c) 967 cars have been sold by S. T. C. to priority users approved by Government such as tourist taxi operators, Government Departments—Central as well as States and Public Sector Undertakings. No estimate of the value of these cars if they had been put to auction can be made.

Pedestrian Overbridge on Dehu Road Station

1965. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleaed to state :

(a) whether it is proposed to build a pedestrian overbridge on Dehu Road Station on the Central Railway ;

(b) if so, when ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) One foot overbridge connecting Up and Down platforms is already existing at Dehu Road Station. It is considered quite adequate for the volume of traffic dealt with at present.

Import of Cotton

1966. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been an inordinate delay in issuing licencses to the textile industry for importng cotton consequent to which the textile mills are experiencing difficulty in procuring cotton ;

(b) if not, the resons therefor ; and

(c) the steps taken by Government ; to meet the long staple cotton requirements of the textile mills ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) There has been no inordinate dealy in making allocations of foreign cotton. In fact, bulk of the quantities proposed to be imported during the current cotton season, have already been allocated and long staple cotton pre-dominates in the allocation.

उद्योगों के लिये तरीके

1967. **श्री रा० बरुआ :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुग्दी तथा सीमेंट से बनी नालीदार चादरों और बाइंडर के बिना लकड़ी के बुरादे से तैयार पार्टिकल बोर्ड बनाने के तरीकों का; जो प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा निकाले गये है, उपयोग करने के बारे में किसी उद्योग के साथ बात चीत की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि ये तरीके व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध होते हैं तो क्या सरकार का विचार आसाम में इन मूल तरीकों के आधार पर उद्योग स्थापित करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ।

(ख) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने लुग्दी सीमेंट की नालीदार चादरों के निर्माण की प्रक्रिया का लाइसेंस बम्बई की एक फर्म को दे दिये है। इस मान ले पर एक दूसरी पार्टी से भी बातचीत चल रही है। कारपोरेशन ने बेकार लकड़ी से पार्टिकल बोर्ड बनाने की प्रक्रिया का बिना बन्धन के लाइसेंस आसाम की एक फर्म को दे दिया है।

(ग) सरकार का इन प्रक्रियाओं पर आधारित उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

आसाम में उद्योगों के लिये आयात लाइसेंस

1968. **श्री रा० बरुआ:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1960 से लेकर 1966 तक की अवधि में आसाम में उद्योग स्थापित करने के लिये किसी व्यक्ति अथवा निकाय को आयात लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उनमेंसे कितने व्यक्ति / निकायों ने इन लाइसेंसों का प्रयोग किया है और उस राज्य में उद्योग स्थापित किये;

(ग) क्या ऐसे मामलों का भी पता लगा है जिनमें ये लाइसेंस या तो बेच दिये गये अथवा उनका दुरुपयोग किया गया ; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी पार्टियों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (घ) तक उद्योगों की स्थापना के लिये, औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। इस अवधि में जारी किये गये लाइसेंसों का ब्यौरा औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस तथा निर्यात लाइसेंस पत्रिकाओं के साप्ताहिक बुलेटिन में दिया गया है, जिनकी कापियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इन लाइसेंसों के प्रयोग के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ऊन का निर्यात

1969. **श्री रा० बरुआ:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में कच्ची ऊन के निर्यात में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्यात में उत्तरोत्तर कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार का विचार राज सहायता देने और/अथवा उत्पादन शुल्क कम करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हाँ।

(ख) कच्चा ऊन के निर्यात में कमी का मुख्य कारण निर्यात बाजार में कम निकासी है, जो संश्लिष्टों के प्रतिस्पर्धा में आने तथा अन्य देश की तुलनात्मक किस्म की ऊन की यूनिट-कीमत में कमी के कारण हुई है।

(ग) राज सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्पादन शुल्क कम करने से निर्यात को बढ़ावा कैसे मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं है।

रेलवे माल डिब्बों के निर्यात के लिये क्रयादेश

1970. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में रेल डिब्बों के निर्यात के लिये कितने क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और वे कितने मूल्य के हैं;

(ख) माल-डिब्बों के विभिन्न निर्माताओं में इन क्रयादेशों के आवंटन की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या दक्षिण कोरिया से सबसे बड़ा क्रयादेश प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या यह सच है कि इस क्रयादेश की पूरी विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होगी, यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) राज्य व्यापार निगम को चालू वर्ष के दौरान रेलवे माल-डिब्बों की सप्लाई के लिये लगभग 9 करोड़ रुपये मूल्य के चार क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। गैर-सरकारी माल-डिब्बे निर्माताओं को सीधे प्राप्त निर्यात क्रयादेशों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(ख) राज्य व्यापार निगम का काम मुख्यतया उन माल-डिब्बे निर्माताओं को, जो सार्वभौमिक टेन्डरों के मामले में प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें देने में रुचि रखते हैं, निर्यात सम्बन्धी पूछ-ताछ के बारे में सहायता देने का है विभिन्न माल-डिब्बे निर्माताओं में क्रयादेश विशिष्ट रूप से बाँटे नहीं गये हैं। निर्यात के लिये कीमतें देने में रुचि रखने वाले निर्माताओं को राज्य व्यापार निगम तकनीकी तथा वाणिज्यक सलाह के रूप में सहायता देता है और इस निगम द्वारा भेजे जाने वाले टैन्डरों में उनके मूल्य कथनों को समाविष्ट किया जाता है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) दक्षिण कोरिया से प्राप्त क्रयादेश के लिये धन की व्यवस्था दक्षिण कोरिया को मिलने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण (आई० डी० ए०) ऋण से की जा रही है और अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण ऋण की शर्तों के अनुसार क्रयादेश के कुल मूल्य के केवल 50 प्रतिशत तक राशि का भगतान विदेशी मुद्रा में होगा और शेष राशि का भुगतान माल-सप्लाई करने वाले देश की मुद्रा में किया जायेगा।

"किसान" बोगीज़

1971. **श्री दे० अभात :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के किसानों ने गंगा घाटी के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में यात्रा के लिये रियायती दरों पर 'किसान' सवारी-डिब्बे दिये जाने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सुन्दरगढ़ के किसानों से गंगा घाटी के औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों की यात्रा के लिये सवारी डिब्बों के आरक्षण के सम्बन्ध में आवेदन पत्र मिला है।

2. सुन्दरगढ़ के कुछ व्यक्तियों में कुछ स्थानों यथा इलाहाबाद, मथुरा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, हरद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, विन्ध्याचल तथा गया जैसे स्थानों की, जो मुख्यतः धार्मिक स्थान हैं यात्रा के लिये सवारी डिब्बों के सम्बन्ध में निवेदन किया है। रियायत कोई नहीं माँगी गई है। ऐसी यात्राओं के लिये कोई रियायत दी भी नहीं जाती है।

रेलवे बोर्ड ने उनकी माँग के अनुसार दो सवारी डिब्बों की व्यवस्था कर दी थी।

बरसुआ स्थित लोहे की खानों में लौह-अयस्क की लागत

1972. **श्री दे० अभात** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की बरसुआ लोहा खानों में लौह अयस्क के उत्पादन की प्रति टन लागत कितनी है ; और

(ख) रुरकेला स्पात कारखाने द्वारा अन्य फर्मों से खरीदे जाने वाले लौह अयस्क का प्रति-टन क्रय-मूल्य कितना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) वर्ष 1966-67 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की बरसुआ लोहा खानों से लौह अयस्क निकालने की खालिस लागत 18.68 रुपया प्रति टन थी।

(ख) रुरकेला इस्पात कारखाने द्वारा खान तथा खनिज व्यापार निगम के माध्यम से खरीदे जाने वाले लौह अयस्क की लागत 16.00 रुपये प्रति टन है तथा प्रतिटन लौह अयस्क पर 30 पैसे कमीशन देना पड़ता है ?

रुरकेला इस्पात कारखाने में 'मन्द गति' से कार्य

1973. **श्री दे० भात** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुरकेला में हिन्द मजदूर सभा तथा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ काँग्रेस के कहने पर, रुरकेला इस्पात कारखाने के विभिन्न विभागों में वर्ष 1966–67 के दौरान बीच-बीच में कई बार काम मन्द गति से हुआ था ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोषी संघों तथा मजदूरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्ष 1966-67 के दौरान भिन्न-भिन्न विभागों में, बीच-बीच में मन्द गति से काम हुआ है।

(ख) प्रबन्धकों द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक कार्य हेतु अनुशासन संहिता के उल्लंघन किये जाने के मामलों के बारे में बताया गया था।

Train Service from Raipur to Bhopal

1974. **Shri Lakhan Lal Gupta** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any proposal is under consideration for starting a train service from Raipur to Bhopal ; and

(b) if not, whether it is proposed to start an Express Train Service from Vizianagram to New Delhi, via Raipur, Bilaspur, Katni, Jabalpur and Bhopal ?

The Minister of Railways (**Shri C. M. Poonacha**), (a) No.

(b) No.

भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, मैसूर

1975. **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स कुप्रबन्ध के कारण घाटे में चल रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस कम्पनी की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिये जाँच की जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

खोई हुई सम्पत्ति के दावे और रेलवे की सम्पत्ति की चोरी

1976. **श्री अचल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष खोई हुई सम्पत्ति के दावों की राशि क्या है और रेलवे की सम्पत्ति जैसे पंखे, बल्ब आदि की कितने की चोरी हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि खोई हुई सम्पत्ति के दावों और चोरियों में वृद्धि हो रही है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन चोरियों तथा सम्पत्ति की हानि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

	(क) चोरी और खोई हुई सम्पत्ति के कारण मुआवजे के रूप में दी गई राशि	बिजली के सामान के चोरी के कारण हुई हानि
1964–65	1,50,58191	10,04,293
1965–66	1,91,07,256	11,76,077
1966–67	2,44,53,899	11,57,858

(ख) दावों के भुगतान में वृद्धि का मुख्य कारण यातायात और मूलांक में वृद्धि तथा भारतीय रेलवे द्वारा लोकवाहकों के दायित्व को 1.1.1962 से स्वीकार किया जाना है।

जहाँ तक रेलवे सम्पत्ति (बिजली के सामान) की चोरी का प्रश्न है 1965-66 की तुलना में 1966-67 में दिये गये उक्त आकड़ों में सुधार हुआ है।

(ख) बुक किये गये सामान और रेलवे सम्पत्ति की चोरी रोकने के लिये निम्नलिखित निवारक कार्यवाही की गई हैं:—

बुक किये गये माल की चोरी :

1. भरे हुए माल डिब्बों में कील लगा कर सुरक्षित कर दिया जाता है। जिन माल डिब्बों में कीमत सामान भेजा जाता है उनमें इसके पेटेन्ट ताले लगाये जाते हैं तथा रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र सैनिक प्रभावित क्षेत्रों में इसकी रात को देखभाल करते हैं।
2. महत्वपूर्ण माल गाड़ियों की रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा रक्षा की जाती है।
3. अपराध का पता लगाने और भागे हुए अभियुक्तों को पकड़ने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सादे कपड़ों में नियुक्त किया गया है।
4. प्रभावित स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कर्मचारी गश्त करते हैं।
5. यार्ड और माल गोदामों में उचित घेरा और बिजली के प्रबन्ध की व्यवस्था की गई है।
6. चोरी के अपराध में पकड़े गये कर्मचारियों को सख्त सजा दी जाती है
7. चोरी की सम्पत्ति और अभियुक्तों का पता लगाने के लिये विशेष गुप्तचर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।
8. यार्डों, शेडों, प्लेटफार्मों और सामयिक महत्व के स्थानों पर चौबीस घन्टे रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचरियों की नियुक्ति की जाती है।
9. अभियुक्तों को रंग हाथों पकड़ने के उद्देश्य से जोनल हेडक्वार्टर्स और रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरों कर्मचारियों द्वारा अचानक छापा मारा जाता है।
10. माल भेजने वाले स्थानों, पार्सल कार्यालयों, और माल शेडों पर पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

रेलवे सम्पत्ति की चोरी :

प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने, अपराधियों का पता लगाने और चोरी गये रेलवे सामान और उपक्रमों का पता लगाने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जाता है। चोरी को रोकने के लिये डिब्बे में ताला लगाना, बिजली के उपक्रमों को केस में बन्द करके भेजने तथा क्लीट लगाने तथा डिब्बों के फ्रेम के भीतर बिजली के तार लगाने और चोरी जाने वाले उपक्रमों को डिब्बों के अन्दर लगाने, ताकि असमाजवादी तत्वों के लिये इनका निकालना कठिन हो, के लिये वर्तमान व्यवस्था है।

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

1977. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री 21 जुलाई, 1967 के प्रश्न संख्या 6404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय के आदेश के विरुद्ध अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड में इन्वेस्टीगेटर तथा स्टेटिस्टीकल असिस्टेन्टों के पदों पर विभागीय कोटे में अपर डिवीजन क्लर्कों को पदोन्नत किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पदोन्नत अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में फैरो क्रोम परियोजना

1978. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में वल्लर नाम के स्थान पर एक फैरो-क्रोम परियोजना और उद्योग-समूह स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त परियोजना पर कितना धन खर्च होगा; और

(ग) उससे क्या लाभ होने की सम्भावना है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी):

(क) से (ग): फैरो क्रोम परियोजना, उड़ीसा राज्य सरकार की एक सरकारी क्षेत्र की निकाय प्रौद्योगिक विकास निगम उड़ीसा लि० कं० जयपुर रोड पर दस हजार टन निम्न कारबन फैरोक्रोम प्रतिवर्ष निर्माण करने के लिये एक प्लांट स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है। योजना पर समस्त लागत 658.47 लाख रुपये के लगभग होगी। निम्न कार्बन फैरोक्रोम जो कि अकलुष स्पात तथा कुछ दूसरी मिश्रित स्पात की किस्में बनाने के लिये आवश्यक कच्चा पदार्थ है हाल में विदेश से मँगवाना पड़ता है। जिस सीमा तक यह भारत में पैदा होगा हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अनुमान है कि जब प्लांट पूर्ण उत्पादन करेगा तो विदेशी मुद्रा की बचत 4 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के स्तर की होगी। परियोजना के लिये तकनीकी सहायता स्वेडन से प्राप्त की गई है। आशा है कि 1968 के अन्त तक प्लांट तैयार हो जायेगा। तालचर का औद्योगिक काम्पलैक्ष औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा लिमिटेड ने तालचर में एक औद्योगिक काम्प्लैक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिससे प्रतिवर्ष 1,68,000 टन पिग, आइरन, 1,38,650 टन यूरिया तथा शुद्ध दूसरे उप-पदार्थ उत्पादित होंगे। इस काम्प्लेक्ष की समस्त लागत 46 लाख रुपए के लगभग होगी। इस तालचर काम्प्लैक्ष के लग जाने से दूसरे भी इसी प्रकार के प्लांट लगने का रास्ता खुल जायगा। इससे नान कोकिंग कोयले के उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, धातु कार्मिक कोयले का संरक्षण होगा जिसके संचय सीमित मात्रा में और इससे पिग-आयरन तथा रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में और सुविधाएँ प्राप्त होंगी। यह प्रस्ताव पर सम्बन्धित विभागों तथा संस्थाओं से परामर्श करके और विचार किया जा रहा है ताकि योजना पर इतना बड़ा व्यय करने से पहले संदेह के लिये कोई स्थान न रहे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कलकत्ता और केरल में चीन समर्थक नारे लगाये जाने के समाचार

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon.

"Reported Pro-Chinese Slogans in Calcutta and in Kerala recently"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नक्सलबाड़ी कृषक संग्राम सहायक कमेटी ने "नवम्बर 1967 की दोपहर को मोनूमेंट मैदान में एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें माओत्से तुंग, लेनिन, स्टालिन, होची मिन और जंगल संथाल के चित्र लगाये गये थे और उसमें चीन समर्थक नारे "माओत्से तुंग का आह्वान" आदि लगाये गये थे। कलकत्ता के विभिन्न भागों में से जलूस में आने वाले प्रदर्शनकारियों ने मार्ग में चीन समर्थक नारे लगाये थे तथा सभा में वक्ताओं ने क्रान्ति के चीनी तरीके का समर्थन किया था।

केरल सरकार के अनुसार चीन समर्थक नारे लगाये जाने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, तथापि माओ की कथित शिक्षा वाले कुछ इश्तहार 20 नवम्बर को त्रिवेन्द्रम में देखे गये थे। वह अग्रेतर जाँच कर रही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : What action has been taken by Government on the reported offer of West Bengal Chief Minister to bear the travel expenses of pro-Chinese elements for their farewell journey to China ? Why Government is hesitating to take severe action against them? What is the handicap. May I also know number of M. L. As. and M. Ps. who receive money form China to indulge in these activities ? Are they afraid of them ?

Shri Vidya Charan Sh[illegible] : There is no question of being afraid or being pressurised. We have been advised by [illegible] Minister that no action can be taken against these persons under the existing laws.

कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Shri Hukam Chand Kachwai: (Not Recorded).

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar). Can the government not take into detention these persons under the Preventive Detention Act ? Have the Central Government warned the States that in case such people are not apprehended, the State Government would be dismissed? Will the Government enquire whether majority of these people are left communists and whether the Govt. propose to ban the Left Communist Party?

Shri Vidya Charan Shukla : I may assure the Hon. members that we are keeping a strict watch on these persons. If it is considered necessary action would certainly be taken against such people under the Preventive Detention Act and such other Acts. As regards Kerala, a final report is yet awaited. On receipt of the same action to be taken would be considered.

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Left Communist Party be banned ?

Shri Vidya Charan Shukla : There is no such proposal at the moment.

श्री मं० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या सरकार साम्यवादियों के इन भारत विरोधी प्रचार के बारे में एक श्वेत-पत्र (ह्वाइट पेपर) प्रकाशित करने के उद्देश्य से सका बौद्धिक अध्ययन करने के लिये तैयार है ? इसके राजनैतिक और सैद्धान्तिक पहलू की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। क्या हम गृह-कार्य मंत्रालय से यह आशा कर सकते हैं कि वह भारतीय श्रमिकों को बतायेगा कि शंघाई में माओवादियों के सैनिक प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है ? हम सरकार से एक विशिष्ट कार्यवाही चाहते हैं ? हम सरकार से यह सुनते सुनते तंग आ गए हैं कि कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल: श्री सोंधी ने एक अच्छा सुझाव दिया है और हम अवश्य उस पर विचार करेंगे।

श्री नाथपाई: एक स्वतंत्र देश में विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिये, चाहे वे माओ के विचार हों। परन्तु इन इश्तिहारों के जरिये लोगों को देशद्रोह करने के लिये भड़काया जा रहा है। मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते हैं कि हम रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार को अनुच्छेद 355 और साथ ही अनुच्छेद 358 के अन्तर्गत इस प्रकार की देशद्रोह की गति-विधियों का दमन करने के लिये शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्या सरकार इनका प्रयोग करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल: मैं बता चुका हूँ कि जहाँ तक कलकत्ता में हुई घटनाओं का सम्बन्ध है, हमने इस विषय में तुरन्त विधि मंत्रालय से राय माँगी कि क्या हम वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। उसने सलाह दी है कि वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही संभव नहीं है। केरल के बारे में केरल सरकार की रिपोर्ट प्राप्त हो ईगई है। और इस पर विचार कर रहे हैं। यदि कोई कार्यवाही करना संभव होगा, तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री बलराज मधोक: क्या सरकार देशद्रोह के विरुद्ध कोई कानून बनाने के सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय: कोई उत्तर नहीं दिया जाये।

श्री नाथ पाई: माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत स्पष्ट शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे इन शक्तियों को प्रयोग करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय: वे उत्तर दे चुके हैं कि विधि मंत्रालय, जिससे राय ली गई थी, ने राय व्यक्त की है। हम उनसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे कहें कि वे आपकी स्थिति को स्वीकार करते हैं। संभवतः वरिष्ठ मंत्री इसपर विचार करेंगे और उस समय माननीय सदस्य के विचार भी उनके समक्ष रख दिये जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर सरकार की समीक्षा आरम्भ

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति. लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1703/67**]।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षाएँ।

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1704/67**]।

हिन्दुस्तान कापर प्राइवेट लिमिटेड का ज्ञापन और संस्था के अन्तर्नियम

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): मैं हिन्दुस्तान कापर प्राइवेट लिमिटेड के ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1705/67**]।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

1. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3760 की एक प्रति जो दिनाँक 16 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अत्यावश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजन के लिए उत्पादन तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 में एक संशोधन किया गया।

2. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 5-क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3761 की एक प्रति जो दिनाँक 16 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1706/67**]:

कोयला बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी): मैं निम्नलिखित पत्र को सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) कोयला बोर्ड, कलकत्ता के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1707/67**]।

(2) अल्प-सूचना संख्या 17 पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में 23 जून, 1967 को दिए गए एक आश्वासन के अनुसरण में जनवरी-मार्च, 1967 की अवधि के लिए नेशनल कोल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, राँची के वित्तीय प्रतिवेदन की एक प्रति [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1708/67]।

(3) सरकारी संकल्प संख्या सी–2–8 (7) / 67 की एक प्रति जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ा दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०** 1709/67]।

वर्ष 1966-67 **के लिये इलायची बोर्ड आदि का वार्षिक प्रतिवेदन आदि**

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) वर्ष 1966–67 के लिए इलायची बोर्ड के कार्यचालन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1710/67]।

(2) चाय बोर्ड के 1966-67 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1711/67]।

(3) वर्ष 1966–67 के लिए रबड़ बोर्ड के क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी०**1712/67)।

(4) काफी बोर्ड के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।[**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1713/67]।

(5) चाय अधिनियम 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चाय (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1394 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०**1714/67]।

(6) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4050 की एक प्रति जो दिनांक 2 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1715/67]।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह): 27 नवम्बर, 1967 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:

विचार तथा पारित किया जाना:

(1) न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1967

सूती कपड़ा कम्पनियाँ (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा परिसमापन अथवा पुनः स्थापन) विधेयक, 1967

करारोपण विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 1967
अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1967

(2) खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर देश में खाद्य की स्थिति पर चर्चा।

(3) श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किए जाने पर गुरुवार, 30 नवम्बर, 1967 को 4 बजे म० प० पर हाल ही में काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा भारी संख्या में घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।

(4) शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन पर अग्रेतर चर्चा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री ने हजारी प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में नहीं बताया है। डा० लोहिया के उपचार और स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में हमने एक प्रस्ताव की सूचना दी है। हमने मंत्रीकरण के बारे में भी एक प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये आप आधे घण्टे की सूचना दीजिये।

मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDNECE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रधान मंत्री से 1.45 और 2 बजे के बीच बोलने के लिये अनुरोध करूँगा। उसके बाद श्री मधु लिमये उत्तर देंगे। इसलिये 2 या 3 वक्ताओं को ही अवसर दिया जा सकता है।

श्री तेन्नेटि विश्वनायन (विशाखापतन) : हमारे दल को अवसर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस निर्दलीय दल के बारे में मैं एक घोषणा करूँगा।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : यह चर्चा मुख्यतः बंगाल की घटनाओं के बारे में रही है लेकिन बंगाल से निर्वाचित संसद सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला। उनको अवसर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है। दलों के नेता इस ओर ध्यान दें किसी भी दल ने किसी बंगाली को बोलने का अवसर नहीं दिया।

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : बंगाल की स्थिति के बारे में आकाशवाणी तथा समाचारपत्रों से प्राप्त होने वाले समाचार चिन्ताजनक हैं। इसलिए कलकत्ता में कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में गृह कार्य मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : कल आपने अब तक इस सभा में अपनाई गई दलों के नेताओं को ही अवसर देने की प्रथा के प्रतिकूल श्री हुमायूं कबीर को बंगाल की स्थिति पर उनकी स्वतंत्र हैसियत में बोलने की अनुमति दी थी। वे उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने वहाँ पर सरकार को समाप्त करने में हिस्सा लिया है। प्रातः मुझे ट्रंक काल आई कि कलकत्ता जल रहा है। आपको हमें अनुमति देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उनके दल ने स्वयं उन्हें अवसर नहीं दिया और वे मुझे दोष देना चाहते हैं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : चूंकि आपने बंगाल से निर्वाचित श्री कबीर और श्री ए० के० सेन को बोलने का अवसर दिया है, आपको बंगाल के अन्य सदस्यों के मामले में भी विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस दल का बहुत समय शेष है। श्री सेन कांग्रेस दल के सदस्य हैं। काँग्रेस दल को अवसर देने के स्थान पर मैं विरोधी पक्ष को समय दे रहा हूँ। कांग्रेस ने श्री सेन को अवसर दिया। आप अवसर नहीं देते हैं और उसके लिए दोष मुझे देते हैं। श्री डाँगे के कहने पर कि काँग्रेस का समय ही कबीर को दे दिया जाये श्री कबीर को अवसर दिया गया। मैं यहाँ पर शोर नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ अनुशासन चाहता हूँ।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली-दक्षिण) : मेरा सुझाव है कि पश्चिम बंगाल के बारे में दूसरे, प्रस्ताव को स्वीकृति देने के स्थान पर विचाराधीन प्रस्ताव का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : यदि हम साधारण सदस्यों का कोई अधिकार है तो हमें एक पक्ष अथवा दूसरे पक्ष की ओर से चिल्लाकर वंचित किया जा रहा है। अध्यक्ष तो एक निर्णायक है और यदि वे एक निर्णायक नहीं चाहते हैं, तो उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। मैं हमेशा से सभी अध्यक्षों के आदेशों का पालन करता रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप विरोधी पक्ष के साथ काफी उदार रहे हैं, जैसा कि एक अध्यक्ष को करना चाहिये। क्या हम यहाँ दूसरे सदस्यों के विचार सुनने के लिये आते हैं अथवा केवल शोर सुनने के लिये। हम साधारण सदस्यों को आपका संरक्षण चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमें छोड़कर आप सबको बोलने की अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। इसके बावजूद कि सरकार को असुविधा होती है, मैं जिस किसी भी विषय को महत्वपूर्ण समझता हूँ, यथासंभव समय देने का प्रयास करता हूँ। कोई सरकारी कार्य नहीं हो रहा। सरकार भी मुझे गलत समझ सकती है।

मैंने डा० रामसुभग सिंह को परामर्श दिया है कि वह एक घंटा समय और बढ़ा दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने पहले ही दिन कहा था कि पश्चिमी बंगाल से जो सदस्य आये हैं उन्हें भी मौका दिया जाये। अन्यथा वहाँ के मतदाता हमारे बारे में क्या सोचेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वक्ताओं के नाम देना दलों का कार्य है। यह अधिकार मेरे पास नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, can we also get a chance ?

अध्यक्ष महोदय : जो निर्दलीय सदस्य हैं उन्हें भी अवश्य अवसर मिलेगा। यहाँ 50–60 सदस्य निर्दलीय हैं और उन्हें समय मिलेगा।

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : महोदय मेरा उद्देश्य यह है कि मैं स्वतंत्र दल का पक्ष स्पष्ट कर दूँ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सामान्य रूप में यदि मंत्रिमंडल के विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव आये तो सारे विरोधी दलों को उसका समर्थन करना चाहिये। परन्तु इस प्रस्ताव ने हमारे रास्ते में रुकावट डाल दी है।

यदि श्री मधु लिमये इस प्रस्ताव को एक सप्ताह बाद लाते तो हम भी उनका समर्थन करते क्योंकि हमारा भी इस मंत्रिमंडल में कोई विश्सास नहीं है। परन्तु यह प्रस्ताव लाया गया है पश्चिमी बंगाल की स्थिति को ध्यान में रख कर और इस कारण हमारा सहयोग इसमें नहीं होगा।

हमारा पक्ष यह है कि राज्यपाल को वहाँ मंत्रिमंडल बर्खास्त करने का पूरा अधिकार था और उसने उचित रूप से ही उसे भंग किया है।

उसके साथ साथ सरकार दोहरी चाल चल रही है। मध्य प्रदेश के बारे में कल उपप्रधान मंत्री जी ने कहा कि वहाँ विरोधी पक्ष दूसरी बात कह रहे थे। मेरा कहना यह है कि वहाँ भी यदि विधान मंडल को भंग नहीं किया तो वरोधी पक्ष के कारण नहीं अपितु काँग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें यह परामर्श दिया था कि विधान मण्डल भंग न किया जाये।

आज पंजाब में भी ऐसी ही स्थिति है। वहाँ के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने विधान मंडल भंग करने का परामर्श दिया था परन्तु उसकी बात स्वीकार नहीं की गई। अब वह कह रहे हैं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा भूतपूर्व हारे हुए मुख्य मंत्री में अन्तर है। मेरे विचार में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। मेरा कहना तो यह है कि काँग्रेस का अब कोई स्तर ही नहीं रह गया है। वह प्रत्येक प्रश्न पर भिन्न तरीके से विचार करते हैं।

राजस्थान में विधान सभा के अधिकांश सदस्य राष्ट्रपति के पास भी आये और वहाँ हारे हुए मुख्य मंत्री को न केवल ठहरने दिया गया बल्कि जिस दिन विधान सभा की बैठक बुलाई गई, उसी दिन राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वहाँ के मुख्य मंत्री का हाथ अवैध रूप से लिये गए सोने में है जिसे चोरी सदरी सोना कांड कहा जाता है। गृह कार्य मंत्री का कहना है कि उन्होंने श्री सुखाडिया के विरुद्ध जाँच की परन्तु वह निर्दोष पाये गए। श्री नाथपाई ने कहा था कि एक संसदीय समिति इस मामले की जाँच करे। यदि सरकार का मन साफ है तो उन्हें यह बात मान लेनी चाहिये।

एक सदस्य : महोदय भोजन का समय हो गया है और सभा की बैठक स्थगित होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आज मध्याह्न भोजन के लिये बैठक स्थगित नहीं होगी।

श्री चं० च्० देसाई : बंगाल के बारे में मेरी सूचना यह है कि वहाँ राज्यपाल काफी समय पूर्व ही मंत्रिमंडल को भंग करना चाहते थे परन्तु गृह कार्य मंत्री ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। यदि उन्हें उस समय न टोका जाता तो स्थिति इतनी खराब न होती जितनी अब हो गई है।

यहीं से तार खींची जाती है। आजकल बैंकों को सामाजिक नियंत्रण में लाने की बात हो रही है। यह सामाजिक नियंत्रण राष्ट्रीयकरण का ही दूसरा नाम है। अन्तर केवल इतना है कि सामाजिक नियंत्रण में मुआवजा नहीं देना पड़ेगा जो राष्ट्रीयकरण में देना पड़ता। बैंकों को सामाजिक नियंत्रण में लाने से इस संस्था को नष्ट कर दिया जायेगा जिसे सर फिरोज सेठना तथा लाला हरिकृष्ण लाल ने स्थापित किया था। बैंकों का रुपया फिर कांग्रेस वालों की जेब में चला जायेगा। यदि इस धन को आप कृषि में लगाते तो भी कुछ समझ में आता परन्तु इसे आप सहकारी संस्थाओं को देकर नष्ट कर देंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न ऊँचे पदों पर भ्रष्टाचार से है। मैंने अभी चोरी सदरी सोने कांड का उल्लेख किया था। मैं आशा करता हूँ कि वर्तमान सरकार तथा गृह कार्य मंत्री इस मामले की जाँच के लिये एक संसदीय समिति के गठन की बात को स्वीकार कर लेंगे। हम विरोधी पक्ष वाले यह मानते

हैं कि उस सोने का गबन श्री मोहन लाल सुखाडिया ने किया है और उस धन को विरोधी पक्ष के सदस्यों को भ्रष्ट करने पर व्यय किया जाता है।

मुझे सूचना मिली है कि चीनी के विनियन्त्रण में भी बहुत रुपया दिया गया है। कोई कहता है कि 30% दिया गया और कोई उसे 40% कहता है। यह सारा धन अन्तोगत्वा कांग्रेस वालों की जेब में गया है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री (श्रीजगजीवन राम) : श्री देसाई ने जो आरोप लगाये हैं उनके लिये एक प्रक्रिया है कि आरोपों के सदन में उठाने से पूर्व सबूत के दस्तावेजों के साथ पहले अध्यक्ष जी के पास भेजा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रकार के आरोप यदि बिना सबूत के साथ लगाये गए तो इससे सदन का मान भंग होता है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): उन्होंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाये। उन्होंने एक साधारण ढंग से यह बात कही है। ऐसा कहना उनका अधिकार है। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया।

श्री नाथपाई (राजापुर): वह नियम तब लागू होना चाहिये जब आरोप में किसी व्यक्ति का नाम लिया जाये। श्री देसाई ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। इसलिये हमें अब इस मामले को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में अब इस मामले को समाप्त समझा जाये।

श्री चं० चु० देसाई: जहाँ तक कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरे विचार में जम्मू काश्मीर में कानून तथा व्यवस्था इस समय समाप्त हो गई है परन्तु वहाँ कोई कार्यवाही इसलिये नहीं की जाती क्योंकि वहाँ कांग्रेस का राज्य है।

पाकिस्तान के बारे में मेरा विचार यह है कि भारत तथा पाकिस्तान को आपस में मैत्रीपूर्ण तरीके से रहना चाहिये ताकि यह दोनों मिलकर चीन का मुकाबला कर सकें। हम सुरक्षा पर 1200 करोड़ रु० तथा पाकिस्तान 400 करोड़ रु० प्रतिवर्ष व्यय कर रहे हैं। यदि यह दोनों देश आपस में मित्रतापूर्ण तरीके से रहें तो चीन की समस्या नहीं रहेगी।

प्रधान मंत्री ने मंगला बाँध के बनने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति को जो बधाई का संदेश भेजा, उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी यह भावना रहेगी।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मंत्रिमंडल में कोई विश्वास नहीं है परन्तु वर्तमान प्रस्ताव क्योंकि पश्चिमी बंगाल को ध्यान में रख कर पेश किया है, इसलिये मैं इससे सहमत नहीं हूँ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : My Party supported the motion not because the Governor has dismissed the Bengal Government but for some other reasons also. In fact it would have been better had the Bengal Government been dismissed earlier. It had become necessary to dismiss the government because it was not only doing immense harm to the democracy but was also playing in the hands of anti-national elements. Even Shri Ajay Mukerjee admitted this thing that some of their colleagues have some connection with China. His ministry was also responsible for Bengali and non-Bengali riots. They were also instigating the

acts of violence and subversion. The Central Government instead of telling the people exact reasons for dismissing the West Bengal Government are talking about the rights of the Governor.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

What happened in the Punjab is that some members of the United Front resigned on the instigation and support of the Congress. If the Congress has any morality they should clearly say that they will not support the defectors. But they will not say like that because they hanker after powers. All praise for Shri Gurnam Singh who resigned as soon as he lost majority in the Assembly. But on the other hand Shri Ajay Mukerjee instead of resigning played in the hands of the Communists. The strategy of the Communist to acquire power first of all through democratic means and then start an armed revolution. For that purpose they are amassing arms. In this connection I would request the Hon. Home Minister to refute the charge being made by the Communists in Bengal that the Congressmen are collecting arms.

It is a matter for shame for all of us that that pro-Pakistani and pro-Chinese slogans are being raised in Kashmir and West Bengal respectively. The Government is expressing its helplessness to take any action agaisnt them. If the existing laws of the land are not sufficient to deal with these elements the Government should enact a law of treason as has been demanded by me so many times. But the difficulty is this that their own house is full of pro-Chinese, pro-American and pro-Russian elements.

So far as Punjab is concerned I would say that the ministry headed by Shri Gurnam Singh washed the sins committed by Congress in this twenty years time. Although the Congress is preaching political morality to others but they themselves are not practising it. They are indulging in all sorts of immoral political practices thus undermining the democracy. If they have any political morality they should not support the defectors in Punjab. The Congress also disturbing the Hindu Sikh unity. The Congress should hold fresh elections in Punjab in the interest of the people and democracy.

The Congress spokesmen are taking shelter for their actions under the Constitution. But in this connection I would say that the democracy cannot be run by the Constitution alone For that we have to set up healthy conventions and precedents. There is no constitution in Britain. The democracy is being run on the convention. This is the point where Congress has miserably failed. During the last twenty years rule Congress has subverted democratic procedures and have helped communalism and fissiparious tendencies. The present day feelings of communalism in the public are the result of the bad policies followed by Congress during their twenty years rule. Even the Pakistan radio is propagating for the new homeland for the muslims within India. The Congress rule has done a great harm to the spirit of nationalism amongst the people.

Historically, economically and politically Jammu and Kashmir is an integral part of India. The Maharaja of Kashmir like the other Maharajas signed the instrument of succession. That was full and final . I would also appeal to the Government to treat Jammu and Kashmir at par with other States. The policy of appeasement such as supplying of ration to the people subsidised rates is not going to pay. The recent communal riots are the result of the at activities of the pro-Pakistani elements who have intruded therein. I made a constructive speech there and this has been admitted by the Premier of Jammu and Kashmir Shri Sadiq. I would request that an equiry into the recent commual trouble there should be held by a Judge of the Supreme Court.

Shri T. Ram (Araria) : After tasting the fruits of twenty years Congress rule people wanted to give a chance to the opposition parties to show their worth. They were in hope that the opposition parties will fulfil their attractive parties and perhaps will bring 'Ram

Rajya' in India. People were also hoping that the corruption would be rooted out and other mal-practices hitherto followed by Congress would also be stopped. With this hope the people gave a chance to the opposition. But the hopes of the people are shattered within six months of the rule of the opposition parties. The parties who talk so loudly of democracy here in Parliament are responsible for instigating gheraos, stopping trains and also for other acts of violence. The Communists and Jansangh who are charging each other in Parliament for recent riots in Bihar are collaborating in many state Governments.

It is generally said that Congress do not want to leave the power. But in many States the opposition parties are desparately trying to regain the power where they have actually lost it. These parties have already been exposed due to their ugly deeds.

Nothing is common in the opposition parties still they are getting together for greed of power. The Governments formed by the United Front of the opposition parties have two different standards. For instance the Bihar Government is talking of holding an enquiry into a police firing which took place five years back but it refused to hold an enquiry into the recent police firing on the students.

In Bengal people are threatening of bloodshed instead of using the democratic methods. If the majority is with them they can turn the tables without burning the trains, buses, and doing other acts of violence. I would appeal to the mover of the motion to withdraw it.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The non-Congress Governents came into power in eight States after the recent general elections. It is misfortune that there is no single party which can replace Congress except in one or two States.

There was no other alternative except to dismiss the Governments in West Bengal and Haryana in view of the prevailing conditions in those States. There might have been some deficiencies so far as Constitution is concerned but on practical grounds this is a correct step taken by the Government.

It is our misfortune that there is no single party in the country which is as strong as the Congress is. I will hold Congress responsible for this also because they have been attracting members of the other parties.

So far as our foreign policy is concerned it is an utter failure. Even to our neighbouring countries it is not very successful. The post of the High Commissioner, London remained vacant for a long time. The Prime Minister also could act appoint a Foreign Minister for long.

Our internal policy has also been a failure. The Government have also failed to solve the problem of Assam. In this connection I would like to say that the recent statement of Shri Bhutto Ex-foreign Minister of Pakistan should also be kept in mind. He has pleaded for the reconsideration of the Assam question.

It is highly improper to suggest to settle the pending disputes with Pakistan on give and take basis. Any person who has regard for our country's honour would not agree to surrender an inch of an territory. As the policies of the Government have failed in all the spheres, it has no right to remain in power.

श्री वी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : विरोधी दलों ने कई राज्यों में मिली-जुली सरकारें बनाई थी और इस प्रकार शक्ति ग्रहण की। परन्तु वे सरकारें अधिक समय तक चल नहीं सकीं क्योंकि तेल और पानी कभी मिल नहीं सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है कि हम विदेशी ऋणों से दबे हुए हैं। आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसका कारण हमारी आर्थिक नीतियों का असफल होना है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्व के सभी देशों ने अन्य देशों से ऋण लेकर ही उन्नति की है। जर्मनी, जापान और रूस को ही लीजिए। इन देशों ने भी

अन्य देशों से ऋण लेकर अपने को उन्नत बनाया है। ऋण लेकर हमने भी वही कार्य किया है जो विश्व के अन्य देशों नें उन्नत बनने में किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया हमारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय का कार्य ठीक नहीं चल रहा है। उनका यह कहना निराधार है। श्रीमती गाँधी ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय कार्य भार संभाल कर बहुत सराहनीय कार्य किया है। माननीय सदस्यों ने गृह कार्य मंत्रालय का उल्लेख भी किया है। इस सम्बन्ध में केवल यही कहूँगा कि जब कभी भी गृह-मंत्रालय किसी अपराधी को दण्ड देना चाहता है तो यही लोग जो यहाँ पर मंत्रालय की आलोचना कर रहे हैं, जो अपने आपको कानून और व्यवस्था का एकमात्र संरक्षक समझते हैं, मंत्रालय के इस कार्य में अनेक बाधाएँ उपस्थित करते हैं। इस तरह मंत्रालय को अपना कार्य करने में कठिनाई होती है।

हम सब कुछ न कुछ त्रुटियाँ अवश्य करते हैं। ऐसा सुना जाता है कि दिल्ली महानगर परिषद के जनसंघ के सदस्यों को वितरण के लिए बीस-बीस बोरे चीनी दी गई थी जिसके वितरण में कुछ अनियमितता रही है।

श्री बलराज मधोक: मैं माननीय सदस्य के इस आरोप का खण्डन करता हूँ और यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि महानगर परिषद् अपने सीमित साधनों से बहुत अच्छा कार्य कर रही है।

श्री हरदयाल देवगुण: माननीय सदस्य को सदैव गोलमाल की ही बात सूझती है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बलराज मधोक उत्तर दे चुके हैं। जनसंघ के सदस्यों ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाये हैं। यदि कांग्रेस के सदस्यों द्वारा भी कुछ कहा जा रहा है तो इसमें आपत्ति की क्या बात है।

श्री दी० चं० शर्मा: विरोधी दलों के सदस्य तरह तरह की बातें करते हैं। जनसंघ को ही लीजिए। चंडीगढ़ के विषय में जनसंघ के विभिन्न सदस्यों के विभिन्न विचार हैं। कुछ सदस्य चाहते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब में चला जाये, कुछ लोग उसे हरियाना में चाहते हैं और अन्य कुछ उसे संघ राज्य क्षेत्र के रूप में ही बना रहने देना चाहते हैं।

श्री बलराज मधोक: चंडीगढ़ के बारे में जनसंघ का विचार है कि यह क्षेत्रीय मामला है। अतः पंजाब तथा हरियाना जनसंघ ने अपने अपने स्थान पर उचित दृष्टिकोण अपनाया है।

अध्यक्ष महोदय: चंडीगढ़ की समस्या इस समय यहाँ पर हल नहीं हो सकती है।

श्री दी० चं० शर्मा: मैं संयक्त दल की सरकारों वाले राज्यों के कुछ बड़े अधिकारियों से मिला हूँ। उनका कहना है कि संयुक्त दल की सरकारों के अधीन कार्य करना बड़ा कठिन कार्य है। प्रत्येक दल अपने अपने सिद्धान्तों और दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करना चाहता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने बंगाल के बारे में असंवैधानिक तथा अप्रजातंत्रीय ढंग से कार्यवाही की है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान 10 अक्तूबर, 1967 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार पत्र में प्रकाशित श्री अजय मुकर्जी के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने अपने त्यागपत्र देने के कारण बताये हैं। उनके अनुसार बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, आर्थिक स्थिति भी निरन्तर से खराब हो रही थी। उनके कुछ समर्थक देश के प्रति निष्ठावान नहीं थे तथा कुछ प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते थे। सरकार ने श्री अजय मुकर्जी के इस वक्तव्य के अनुसार ही कार्यवाही की है। सरकार ने यह कार्यवाही बहुत सोच विचार कर उचित समय पर की है। अतः मैं फिर दृढ़ता पूर्वक कह

सकता हूँ कि सरकार ने जो कोई भी कार्य किया है वह देश की परम्परा के अनुसार तथा देश के हित के लिए किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री द्वारा वाद विवाद का उत्तर दिये जाने से पहले पश्चिम बंगाल के कुछ माननीय सदस्य सभा को कुछ जानकारी देना चाहते हैं। श्री गणेश घोष।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : मैं इस सम्बन्ध में एक पूर्व परम्परा का उल्लेख करना चाहता हूँ। श्री जयरामदास दौलतराम जब बिहार के राज्यपाल थे उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कृष्ण सिन्हा तथा राज्यपाल के बीच मतभेद हो गया था। मैंने उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नेहरू से बात की थी। श्री नेहरू ने मुझे बताया था कि वह राज्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वह केवल राष्ट्रपति को राज्यपाल को पदमुक्त करने की सलाह दे सकें हैं। उस समय राज्यपाल को अपना पद छोड़ना पड़ा था। किन्तु इस समय बंगाल में संयुक्त दल की सरकार थी जिसे बिड़ला, टाटा आदि पूंजीपति नहीं चाहते थे। आज स्थिति यह है कि विधान सभा का सत्र बुलाने के बारे में मतभेद हो जाने पर केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के आदेश देती है। इसके क्या कारण हैं? समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार सायंकाल 8.20 बजे बर्खास्त की गई थी। उस दिन सायंकाल को ही राज्यपाल द्वारा सारे नगर में पुलिस की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। सेना को भी सचेत कर दिया गया था अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्यपाल ने वहां सरकार से पूछे बिना ही ये सारी व्यवस्था कर दी थी?

श्री समर गुह (कन्टाई): इस सरकार ने आई० सी० एस० नौकरशाही को, कठोर कार्यवाही करके प्रजातंत्रीय ढंग से स्थापित सरकार को समाप्त करने की अनुमति देकर बड़ी भूल की है। इससे उत्पन्न प्रतिक्रया प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। इस सरकार ने कानून और व्यवस्था न रहने के आरोप में पश्चिम बंगाल सरकार को बरखास्त किया है। इस सरकार ने 20 वर्ष के काले कारनामों के बाद केवल आठ महीने पहिले स्थापित सरकार पर यह आरोप लगाया है।

पश्चिम बंगाल में अत्याचार किया जा रहा है। आज प्रातःकाल मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार 19 व्यक्ति गोली से मारे गए, 60 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए और 1,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गये हैं। सेना कलकत्ता तथा उसके चारों ओर के क्षेत्रों में गश्त लगा रही है और शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। क्या वहाँ पर हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिए संयुक्त दल की सरकार उत्तरदायी है अथवा राज्यपाल?

22 तारीख को सारे पश्चिम बंगाल में हड़ताल की घोषणा की गई थी। चार बजे तक वहाँ पर बिल्कुल शान्ति रही। किन्तु शाम को जब कुछ लोग सत्याग्रह करने लगे तो पुलिस ने मारपीट आरम्भ कर दी जिससे उसकी प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई। अतः मैं राज्यपाल तथा कांग्रेस सरकार को वहाँ पर हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी ठहराता हूँ। मैं समझता हूँ कि सरकार राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को समाप्त करने का प्रयत्न कर रही है। सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करके देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय दे रही है। सरकार इस प्रकार की कार्यवाहियों से पश्चिम बंगाल में वियतनाम जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है। इस प्रकार सरकार ने अपनी इस भूल से न केवल पश्चिम बंगाल के राष्ट्रवादी लोगों के भाग्य को ही अंधकारमय नहीं बनाया है अपितु वहाँ उसने राष्ट्रविरोधी तत्वों को भी उभारा है।

श्री हो० ना० मुकरजी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या प्रधान मंत्री को इस बात की जानकारी है कि 21 तारीख को शाम के चार बजे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर ने मुख्य मंत्री श्री अजय मुकर्जी से पूछा था कि क्या वह 14 दिसम्बर से पहले विधान सभा का सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं जिसके उत्तर में उन्होंने राज्यपाल को बताया था कि वह 23 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक बुलायेंगे और उसके बाद बता सकेंगे कि उनके लिये 18 दिसम्बर से पहले विधान सभा का सत्र बुला सकना संभव है अथवा नहीं। क्या इन सब बातों को देखते हुए वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया गया था ?

प्रधान मंत्री तथा अणशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): मैंने सदस्यों के विचार ध्यान-पूर्वक सुने। उनके विचार सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि उन्होंने कोई नई बात न कहकर पुरानी ही बातें दोहराई हैं। मैं समझती थी कि सब सदस्य एक होकर इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन ही करेंगे किन्तु मुझे यह ज्ञात हुआ कि कुछ सदस्य इसका स्पष्ट रूप से विरोध कर रहे हैं। श्री रंगा तथा श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण समर्थन किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की विदेश नीति और आर्थिक नीति की आलोचना की है किन्तु उन्होंने इस बारे में वही पुराने तर्क दिये हैं।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूँ कि जब आलोचना में वही बातें दोहराई गई हैं तो यह स्पष्ट है कि उसका उत्तर भी वही पुराना ही होगा। अविश्वास प्रस्ताव में वैकल्पिक नीतियों के प्रस्ताव रखे गए हैं। किन्तु हम उन्हें नहीं मान सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत है और उनके स्वरूप अलग-अलग हैं। वास्तव में विरोधी दल में एक बात समान है और वह कांग्रेस की आलोचना करना।

श्री रंगा ने मुझपर आरोप लगाया है कि मैं रूस की पचासवीं वर्षगाँठ पर रूस सरकार के निमंत्रण पर रूस जा रही हूँ। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि यह निमंत्रण एक मित्र देश द्वारा दिया गया है। माननीय सदस्यों को इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहियें। मैं रूस उसी भावना से गई जिस भावना से हमारे राष्ट्रपति कनाडा की शताब्दी समारोहों के अवसर पर वहाँ गए थे। आज हमें सभ्य तरीकों से अन्य देशों के साथ मैत्री रखनी है।

गत आम चुनावों के परिणामस्वरूप राज्यों में अनेक नई सरकारें बनी हैं। मैंने इस नई सरकारों का स्वागत किया और इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की। मेरा इस बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं है। मैंने इन सरकारों को यथासंभव प्रोत्साहन भी दिया। मैंने कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि इन सरकारों को समाप्त किया जाये। मैं प्रधान मंत्री के रूप में तथा अपने सहयोगियों की ओर से यह कह सकती हूँ कि गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को कारगर ढंग से कार्य करने के लिए तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए उन्हें यथासंभव सहायता दी गई है। यह ठीक है कि उनकी सभी माँगें पूरी नहीं की जा सकीं। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम उनकी माँगें पूरी करना ही नहीं चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि जहाँ कहीं भी माँगें पूरी नहीं की जा सकी उसका कारण है हमारी सीमाएँ और वित्तीय संसाधन सम्बन्धी कठिनाइयाँ। हमने सभी सरकारों के साथ एक समान बर्ताव किया है। कांग्रेसी राज्य सरकारों की तो यह शिकायत है कि उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता क्योंकि वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। यह दुःख की बात है कि प्रत्येक गलती अथवा असफलता के लिए गैर कांग्रेसी सरकारें केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराती हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि हमने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्य सरकारों के नेता राज्यों में तथा केन्द्र में कांग्रेस

सरकार को गिराने के लिए बैठकों का आयोजन करते रहते हैं। यह अजीब बात है कि थोड़े से कार्यक्रमों को आधार बनाकर अपने स्वार्थों के लिए मिली जुली सरकारें बनाई गई हैं। हम चाहते हैं कि जनता अपना निर्णय स्वयं करे किन्तु मिली जुली सरकारों में आन्तरिक मतभेद हो जाने के कारण किसी गम्भीर स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर केन्द्रीय सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये।

मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि राजनैतिक दल बदल की नीति प्रजातंत्र के लिए घातक है। इस प्रकार बिना सोचे समझे दल बदलना अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के साथ विश्वासघात करना है। सभी को इसकी निन्दा करनी चाहिये हम सबको मिलकर प्रजातंत्र को मजबूत बनाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के बारे में सरकार पर कुछ आरोप लगाये गए हैं। मुझसे पूर्व वक्ता श्री एच० एन० मुकर्जी, श्री समर गुह तथा श्री गणेश घोष ने कुछ जानकारी देनी चाही थी तथा कुछ जानकारी माँगी है। श्री समर गुह ने कहा था कि वे राष्ट्र विरोधी तत्वों को दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर हिंसा का समर्थन कौन कर रहा है। बंगाल में घटनाएँ काफी लम्बे समय से हो रही है। उनके बारे में काफी समय से समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। श्री समर गुह को इस बारे में और अधिक जानकारी होगी। श्री दी० चं० शर्मा ने श्री अजय मुकर्जी का वक्तव्य पढ़ने का प्रयत्न किया था। मैं चाहती थी कि उनको इसकी अनुमति दी जानी चाहिये थी क्योंकि वह स्थिति पर प्रकाश डाल रहे थे। मैं भी उनका वक्तव्य पढ़कर सुनना चाहती थी किन्तु समय कम होने के कारण मैं थोड़ा भाग पढ़ूंगी। श्री अजय मुकर्जी ने इस वक्तव्य में कहा था कि वामपंथियों का असफल षडयंत्र के आरोप निराधार है। यह वक्तव्य उन्होंने अपने प्रस्तावित त्यागपत्र के समय नहीं दिया था। यह वक्तव्य उन्होंने 16 अक्तूबर को दिया था और उसके बाद उन्होंने सरकार में रहने का निर्णय किया था। उसमें उन्होंने कहा था:.....''राजनैतिक दल का एक भाग सशस्त्र क्रान्ति करने के लिए चीन को सहायता के लिए आमंत्रित कर रहा है....''

कुछ माननीय सदस्य: शर्म, शर्म।

श्रीमती इंदिरा गाँधी: ''पश्चिम बंगाल में ऐसी प्रवृत्ति को आरम्भ में कुचल दिया जाना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य से इस मामले में संयुक्त दल के अपने सहयोगियों से विरोध ही प्राप्त हुआ।''

मैं यह अवश्य कहूँगी कि जो भी घटनाएँ घट रही हैं उनसे मुझे बहुत दुख हो रहा है। बंगाल के लोगों का मैं बहुत आदर करती हूँ। भारत के जागरण इतिहास में उन्होंने बेजोड़ और मुख्य कार्य किया है। वहाँ के उच्च नेताओं ने देश में राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला और धर्म के बहुत से क्षेत्रों में सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने देश को राष्ट्रीय गान दिया। पहले की भाँति वे इन कठिनाइयों का मुकाबला करने में समर्थ होंगे और एक बार फिर शान्तिपूर्ण परिस्थिति में प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।

संविधान का प्रयोजन ऐसी सरकार की व्यवस्था करना है जो देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखे। हिंसा द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम हिंसात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करें।

जब कुछ माननीय सदस्यों ने जोश में आकर हमारी सेना और पाकिस्तान में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में गैर जिम्मेदाराना विचार व्यक्त किये तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये विचार उन लोगों के हैं जिन्हें भारत, उसकी जनता और हमारी लोकतंत्रात्मक प्रणाली में विश्वास नहीं है। मुझे भारतीयों की परिपक्वता और बुद्धिमानी में पूर्ण विश्वास है। मुझे अपनी सेना की बहादुरी और उच्च देशभक्ति में पूरा विश्वास है। इस बात का मुझे दुख है कि हमारी सेना राजनीतिक चर्चा का विषय बनी।

भारत का आदर और उसके विचारों का सम्मान का निर्णय उन लोगों को नहीं करना है जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से अनभिज्ञ है बल्कि इसका निर्णय विश्व परिषद् द्वारा हमारे विचारों तथा हमारे वक्तव्यों को विदेशी में दिये गये महत्व द्वारा किया जाना है।

श्री मधु लिमये द्वारा वियतनाम के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य का मैं तीव्र विरोध करती हूँ। मेरे विचार से वह वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना तथा झूठा था। वियतनाम संघर्ष के सम्बन्ध में मैंने अपने विचार सदैव स्पष्ट किये हैं।

भारत सरकार की यह नीति रही है कि वह राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता से स्वयं रहे और दूसरों को इसी प्रकार रहने दे। इसीलिये भारत सदा उपनिवेशवाद, जाति-विवाद और किसी प्रकार के प्रबल शासन का विरोधी रहा है।

हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे और इसी प्रकार हम किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते।

राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हमारे लिये आर्थिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व अमीर और गरीब देशों में बटा हुआ है और एक दूसरे में बहुत अधिक अन्तर है। अतः हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को बनाना है ताकि विकसित देश उत्पादन की वद्धि के उद्देश्य से साधनों को भी बढ़ा सकें। हमे दान की आवश्यकता नहीं, परन्तु अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है।

योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है और यह देश के सामने आने वाली समस्याओं को नया रूप दे रहा है। और देश की अर्थ व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से स्थिर और पहले जैसी बनाये रखने के लिये सुझाव दे रहा है। यह सुझाव दिया गया है कि चौथी योजना का कार्य 1968–69 की वार्षिक योजना के पूरे होने पर जनवरी, 1968 से आरम्भ किया जाये।

यह आशा की जाती है कि कृषि और पुनर्वास के तरीकों में सुधार किये जाने से हमारी अर्थव्यवस्था शीघ्र ही सुनिश्चित हो जायेगी। इतिहास साक्षी है कि किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था में हमेशा वृद्धि नहीं होती रही है, चाहे वह देश कितने ही सुगठित या विकसित देश क्यों न हों। प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्थ में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हमारे देश के सामने जो सूखे और मन्दी की समस्याएँ हैं उनकी हमें ठोस आलोचना करनी चाहिये। यदि हम ऐसी मुसीबतें जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, के सामने हिम्मत हार बैठेंगे तो हम अपने संघर्ष में सफल नहीं होंगे। इस वर्ष मार्च में जब सरकार ने कार्य भार संभाला तो देश को अकाल का सामना करना पड़ रहा था। देश के बहुत से राज्यों में अनाज की की बहुत कमी थी और सरकार को 5,000 लाख व्यक्तियों के लिये अनाज का व्यवस्था करने का कठिन कार्य करना था। इतिहास में कभी भी किसी देश को इस प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। हमने राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में पूरी सहायता की।

देश में फसल अच्छी न होने के कारण यहाँ की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत भारी असर पड़ा है। हमने अपने साधनों से अधिकतम अनाज का आयात किया है। लोगों की क्रय शक्ति घट गई है,

मूल्य बढ़ गए हैं, बेकारी बढ़ गई है और हम मंदी के बीच फंस गए हैं। हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यह सच है कि इस वर्ष प्रकृति ने हमारा साथ दिया है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमने भी अपनी उपज बढ़ाने के लिये भारी परिश्रम किया है। नये तरीके के बीज उर्वरक और अच्छी सिंचाई के साधनों से प्रयोग किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो और चाहे आर्थिक क्षेत्र, सरकार ने अपना दायित्व दृढ़ता और साहस से निभाया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा दिये गये तर्क को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। विपक्षी दलों का मजबूत न होने का आरोप सरकार पर लगाया गया है।

एक सदस्य ने गाड़ियों के आने जाने में देरी होने का उल्लेख किया। इस सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उनका उत्तर भी दिया जा चुका है।

मैं दोनों ओर के सदस्यों से निवेदन करूँगी कि वे अपने हित को छोड़ देश के भविष्य के विषय में सोंचे। हमें स्वतंत्रता प्राप्त किये 21 वर्ष हो गये हैं। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् आधे राष्ट्र का जन्म हुआ है। उन्हें आप स्वतंत्रता की कैसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि वह ये सोचें कि स्वतंत्रता कुछ नहीं है केवल शान्ति का लालच है क्या आप यह चाहते हैं कि वे अपने पूर्वजों पर गर्व करें और अपने भविष्य में कुछ आशा रखें।

आलोचना का मैं स्वागत करती हूँ, परन्तु वह ऐसी न हो कि जिससे हमारे आत्मविश्वास को क्षति हो। आगामी 5 या 10 वर्षों में हमें बहुत कार्य करने हैं और विकास तथा लोकतंत्र में लगाई गई पूंजी के फल को प्राप्त कर सकेंगे। मैं यह निश्चय के साथ कह सकती हूँ कि आगामी तीन वर्षों में हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। कहीं इतिहास यह न बताये कि सभा के इस दल ने अपना समय झगड़ने में व्यतीत किया और वह देश में विश्वास और आशा का बीज बोने में असमर्थ रहा।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[**Mr. Deputy Speaker** in the Chair]

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have heard the Prime Minister, but she has not replied to any of the questions raised and the criticism made during the debate. Several constitutional and political matters were raised during the debate, but she has not replied any of them. Only yesterday, Shri Morarji Desai said :—

"The Governor was entitled to dismiss the Chief Minister the moment it was proved to him that the majority was, not with him".

If this is the policy of the Government may I know the reasons for acting contrary to this policy by the Government twelve years before in Kerala by this Government. No Confidence Motion was not passed against Ajoya Mukerjee's Government in West Bengal. It was Governor's personal opinion that Ajoya Mukerjee's party was not in majority. But in the case of Kerala at that time there was minority Government for six months. Again Morarji said :—

"After losing the majority, no Chief Minister has a right to ask for a mid-term poll." But within few months i.e. from July to November this government has changed the view. In July we were discussing about Madhya Pradesh.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[**Mr. Speaker** in the Chair]

At that time Shri Chavan told that according to our Constitution Governor has a right to use discretion only in case of three articles. He has, explained them as follows :

"I would refer to the latest scholarly edition of the Constitution published by Mr. Servai, the Advocate General of Maharashta and he said that only under three Articles Governor of a State functions as an agent of the President. They are Articles 239(2), 200 and 236. Except in these three articles, the Governor functions as the Constitutional head".

It means that under Articles 143, 163 and 164, he has also to function as constitutional head. He further says :—

"But once having received the advice from the Chief Minister, let us not take into consideration whether the Chief Minister is Ajoy Babu or Mishraji ; let us not go into the names because then the matter becomes subjective. Let us be objective".

He told the Governor to behave like a Badshah or Sultan and disregard the advice of the Chief Minister regarding calling of the setting of the Vidhan Sabha. The Government wants nothing but power. They want to stick to it.

The Prime Minister has just said that people themselves have to decide in this matter. I want to know whether they are prepared to give rights and opportunites to the people in this regard ? If you are prepared to do so then preparation for election in West Bengal should be made.

During the last elections, the people were not with them. In 1962 Elections the Congress Party secured more than 47% of votes in West Bengal whereas in the last election, the oppositions parties even without forming a Joint front, were able to secure 41 % votes. I am of the view that if elections may be done immediately in West Bengal, the Congress will not secure more than 30% votes. In Bihar also they have secured eight per cent less votes as compared to the last election. In Uttar Pradesh they have secured merely thirty-two per cent votes.

Today, our Government is behaving as a dictator in our country.

As I have already said that no questions raised during the No Confidence Motion have been replied, Shri Morarji Desai told in his reply that they have achieved the target of food production during the second Five Year Plan.

In case of good crops, it is said that it is the result of Government's efforts whereas in the case of failure of crops, it is said that rains have failed .

It has been said that Government's foreign policy has been a great success. But my question regarding its success and principles has not been replied. Whether Government have any policy to give recognition to the States and to establish diplomatic relations with regard to them ? May I know the reasons for not giving recognition to the East German Government and not establishing diplomatic relations with it so far. It has not been done due to fear of West German Government. Prime Minister has not replied with regard to Isreal and Formosa.

This Government have no foreign policy or principles. Our Government should have diplomatic relations with them whether a country may have capitalism, dictatorship, democracy or communism. Our Government is under the pressure of the foreigners and it has not got its own foreign policy.

It has been said that Congress administration has become corrupted. The Prime Minister has said that it was false. I want to know whether the facts regarding the allegations made against the Chief Minister of Rajasthan, Shri Sukhadia would be decided by the Prime Minister.

Whether an impartial Court or a Parliamentary Committee should not be established so that people may go with proofs and it may be decided whether he was guilty or not ? The Government is not prepared to do so.

During last year in November I wrote a letter to the Prime Minister regarding Bird and Co. of Calcutta. Different types of allegations were made against that Company and about 20 Crores of rupees were sent out of India by this company within our knowledge. This Company was fined Rs. 1.65 lakhs for evasion of income taxes and violation of Custom laws. Later on it was reduced to 40 lakhs. I wrote to the Solicitor General regarding this matter and has described this as not proper.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई): माननीय सदस्य ने स्थिति का उचित वर्णन नहीं किया है। मैं माननीय सदस्य को पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि मामले को उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया गया है। यह कहने में कोई सचाई नहीं है कि मैंने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है।

Shri Madhu Limaye : Government is prepared to use the Defence of India Rules to arrest innocent people and not against those who are actually thieves. Defence of India Rules have been used several times to arrest persons like George Fernandes and myself and not against the corrupt persons.

This Government have good relations with dishonest firms like Amin Chand Pyare Lal. In a statement in a Bombay Court when it was asked from Shri S. K. Patil whether he had written some letters to this businessman for the elections, he replied that five letters were written in this regard.

The Congress Government wants to remain in power by removing the non-Congress Governments.

In Bihar and Orissa also no actions have been taken against the corrupt ministers.

The Prime Minister has told that the matters are not decided by violence. May I know whether they will be decided by dictatorship or by establishing military administration.

The concern expressed by the Prime Minister regarding changing of parties was nothing but a drama only. In 1948 when we were separated from the Congress Acharya Narendar Dev resigned from the Congress and presented an example by resigning from the State Assembly. This connection was first adopted by us.

I want to know whether some solid principles or policies have not been prescribed during the last twenty years by the Congress regarding changing the parties. Shri Prakash Vir Shastri meant to say that due to anti democratic and corrupt actions, efforts have been made to disorganise the opposition and it is due to that the opposition parties are not progressing.

When the question regarding the rights of the Governor was raised, Shri Ajoya Mukerjee asked to go to Supreme Court, but they refused to go to Supreme Court because there was already a decision in that regard.

I want to say that in a country where military is used against own people, it would not be able to defend its people from foreign attack. These people can misuse the military for sometime more. I want to say that if they use force its reply will be force and if they want to decide it by election we are ready to fight elections.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है "कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 88; विपक्ष 215

AYES 88 ; NOES 215

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was Negatived

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

चौदहवाँ प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) Sir, I move that this House agrees with Fourteenth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd November, 1967.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[**Mr. Deputy Speaker** in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 14वें प्रतिवेदन से, जो 22 नवम्बर, 1967 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

विधायकों द्वारा दल परिवर्तन के बारे में संकल्प--जारी

RESOLUTION RE : CROSSING OF FLOOR BY LEGISLATORS—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब श्री वेंकटासुब्बया द्वारा 11 अगस्त, 1967 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा शुरू करेगी।

"इस सभा की राय है कि विधायकों द्वारा एक दल को छोड़ कर दूसरे में निष्ठा व्यक्त करने और विधान सभाओं में बारम्बार दल परिवर्तन करने सम्बन्धी समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये सरकार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संवैधानिक विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति तुरन्त नियुक्त करे और यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह इस बढ़ती हुई प्रवत्ति को जो भयानक रूप से व्यक्त होती जा रही है, रोकने के लिये एक विशेष व्यवस्था करे और उपयुक्त विधान द्वारा प्रभावी उपाय करे ताकि देश में संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ एवं उपयोगी ढंग से चल सके।"

श्री वेंकटासुब्बया अपना भाषण जारी रखें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Last time I raised a point of order but on account of expiry of time, I could not complete my points. Neither the Speaker has given any decision

in that matter. The resolution as it is worded at present will come into conflict with our Constitution which recognises no political parties but only talks of territorial constituncies. The members in the Legislatures do not represent political parties but represent their respective constituences. It will, therefore, not be constitutional to impose any restrictions on floor crossing through legislation. Therefore, the question arises whether the resolution as at present worded can be discussed by the House or it needs suitable modification.

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने संविधान का हवाला देकर जो अपत्ति की है वह मेरी राय में वैध है। प्रस्तावक महोदय को सभा की सहमति से इस प्रस्ताव में उपयुक्त संशोधन कर देना चाहिये।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): आपने कहा है कि माननीय सदस्य की आपत्ति वैध है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव के रास्ते में संविधान की कौन सी धारा आती है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) मैं श्री मधु लिमये की आपत्ति का समर्थन करता हूँ। सचेतकों के सम्मेलन में भी इस चीज को उठाया गया था। वहाँ पर दो सुझाव दिये गये थे। एक यह था कि दल परिवर्तन की इस प्रवत्ति को रोकने के लिये कोई विधान बनाया जाये। सम्मेलन के सभापति डा० रामसुभग सिंह ने इसे नहीं माना था। दूसरा सुझाव यह था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर दिया जाये जिसके द्वारा इस प्रकार दल परिवर्तन करने वाले विधायक की सीट को खाली घोषित कर दिया जाये। यह कहा गया कि इस प्रकार दल परिवर्तन को "कैजुअल्टी" नहीं समझा जा सकता और इसे त्याग दिया गया। वहाँ पर यही तय हुआ कि यह एक राजनीतिक प्रश्न है और इसे राजनीतिक स्तर पर ही हल किया जाना चाहिये। इसलिये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रस्तावक महोदय इस प्रस्ताव के बाद के हिस्से को हटाने के लिये राजी है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस बारे में कोई निर्णय देने से पहले विधि मंत्री तथा अन्य माननीय सदस्यों के विचार भी जानना चाहता हूँ।

श्री गोविन्द मेनन: मैं श्री मधु लिमये की आपत्ति को पूरी तरह नहीं समझ सका हूँ। आपने कहा है कि आप भी श्री मधु लिमये द्वारा उठाई गई आपत्ति की वैधता से सहमत हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि संविधान का कौनसा उपबन्ध इस प्रस्ताव में की गई सिफारिश के रास्ते में अड़चन पैदा करता है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : यदि "राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा संवैधानिक विशेषज्ञों" के स्थान पर "संसद् सदस्यों" रख दिया जाये तो यह आपत्ति दूर हो जायेगी।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है जो संविधान के विरुद्ध जाती हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम का संशोधन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रस्ताव में उल्लिखित समिति ऐसा करने की सिफारिश करती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। अन्यथा इस प्रस्ताव में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : संसद् को संसद् के सदस्यों अथवा विधान मण्डलों के सदस्यों की अर्हताओं और अनर्हताओं को निर्धारित करने की पूरी शक्ति है। इसी प्रकार दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों के बारे में भी वह इस आशय का उपबन्ध कर सकती है कि यदि कोई व्यक्ति एक मान्यताप्राप्त दल के टिकट पर चुना जाकर दूसरे दल में जा मिलता है तो वह सदस्य नहीं रहेगा। संसद् को ऐसा करने की शक्ति प्राप्त है।

श्री नायनार (पालघाट) : यह प्रस्ताव मेरी राय में संविधान की भावना के विरुद्ध है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अत: संविधान के अन्तर्गत दल परिवर्तन की प्रवृत्ति को रोकने के लिये विशेष उपबन्ध नहीं किया जा सकता।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

अधिकारियों के सम्मेलन में भी यह विषय उठाया गया था और मैंने इस पर विचार भी किया था। हमारा संविधान मूलभूत अधिकारों आदि की गारंटी देता है। इसलिये मैंने महसूस किया कि विधि मंत्री के परामर्श से इस प्रस्ताव को मूर्त्त रूप दिया जाना चाहिये। यदि वे चाहें तो संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य इस समस्या पर ध्यान केन्द्रित कराना तथा उसका हल निकालना है।

श्री रणधीर सिंह श्री मधु लिमये की मूलभूत आपत्ति क्या है ?

Shri Madhu Limaye : Our Constitution recognises no political parties but only refers to territorial constituencies. The persons elected to Parliament and Assemblies represent their constitutency and not any political party as such. If an amendment to the constitution had been brought forward, then this Resolution was justified. But you are going to legislate by this resolution. My contention therefore is that legally we cannot ban crossing of floor by legistators.

श्री क० नारायण राव : यह राजनीतिक नैतिकता का मामला है। जब मतदाता किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वे उसके दल तथा कार्यक्रम को भी दृष्टि में रखकर उसे वोट देते हैं। इस बार बार के दल परिवर्तन से हमारी नैतिकता को बहुत धक्का पहुँचता है। जिस क्षेत्र से कोई व्यक्ति चुन कर आता है वहाँ के मतदाता भी यह चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि ठीक तरह से व्यवहार करे और कोई भद्दा कदम न उठाए। संसद् इस तरह का प्रतिबन्ध लगा सकती है।

जहाँ तक किसी व्यक्ति के किसी अन्य दल में शामिल होने के अधिकार का सम्बन्ध है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव केवल यही पड़ता है कि उसे अपने पहले दल के प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। दल परिवर्तन करने पर उसे नये दल के प्रतिनिधि के रूप में पुन: चुनाव लड़ना चाहिये।

श्री मधु लिमये ने अनुच्छेद 81 का उल्लेख किया है। मेरी राय में अनुच्छेद 81 का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा): संविधान राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देता। दल परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिये अन्य कोई हल निकाला जाना चाहिये जिससे संविधान में संशोधन करके ऐसे सदस्य को वापिस बुलाया जा सके।

श्री गु० सिं० डिल्लो (तरनतारन): श्री मधु लिमये तथा श्री चटर्जी ने जो राय व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूँ। हम इस प्रथा को किसी आम विधान द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। यह केवल संविधान में संशोधन करके ही समाप्त की जा सकती है।

श्री बेतब्रत बरुआ (कलियाबोर) : इस समस्या को संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करके हल किया जा सकता है। परन्तु वह समिति ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसका इस प्रस्ताव में उल्लेख है। दल परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिये। यह प्रस्ताव नियमानुकूल है और इस पर विचार किया जा सकता है। संविधान के अन्तर्गत विधायक को प्रतिनिधि ही माना गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा है कि यह प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है। यह एक राजनीतिक रोग है जिसे सभी राजनीतिक दलों के नेता मिलकर हल कर सकते हैं। हमें इस रोग का निवारण करना है ताकि प्रशासन में स्थायित्व आ सके और राजनीतिक जीवन स्थिर बन सके। इस प्रस्ताव की शब्दावली में थोड़ा बहुत अन्तर किया जा सकता है।

विधिमंत्री (श्री गोविन्द मेनन): मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस प्रस्ताव को नियमानुकूल बताया है जिसपर इस सभा में चर्चा की जा सकती है। हालांकि संविधान में "राजनीतिक दलों" का उल्लेख नहीं है फिर भी किसी प्रस्ताव में इसका उल्लेख करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यदि अनुच्छेद 19 द्वारा कोई कठिनाई उत्पन्न होगी, तो संविधान के विशेषज्ञों द्वारा उसपर विचार किया जायेगा। प्रस्ताव में विधान बनाने का भी उल्लेख है लेकिन मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव में कोई ऐसी बात है जो संविधान के विरुद्ध जाती हो।

श्री मधुलिमये ने अनुच्छेद 81 का उल्लेख किया है जो संसद् में क्षेत्रीय प्रतिनिधान के बारे में हैं। हालांकि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को किसी व्यक्ति को संसद् का सदस्य चुनने का अधिकार है फिर भी अनुच्छेद 101 और 102 में यह व्यवस्था है कि कुछ कारणों से इस तरह निर्वाचित व्यक्ति को अनर्ह ठहराया जा सकता है या उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि समिति यहाँ तक भी सिफारिश कर देती है कि दल परिवर्तन करने वाले सदस्य को संसद् का सदस्य बने रहने से अनर्ह कर दिया जाये तो भी वह कोई असंवैधानिक कदम नहीं होगा। यदि समिति को इस समस्या के हल के लिये उपाय सुझाने के लिये कहा जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह कोई विधान लाने की ही सिफारिश करे। वह यह भी कह सकती है कि कानून इस समस्या का सही हल नहीं है।

पिछले कुछ महीनों से देश में जिस बारम्बारता से दल परिवर्तन हुए है उसकी सर्वज्ञ निन्दा हुई है। इस प्रस्ताव को नियमबाह्य करार देकर स्वीकार न करना जनता की इच्छा का विरोध करना होगा। सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहती है। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे उसका विरोध न करें। उनके लिये ऐसा करना सराहनीय नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा है कि इसे स्वीकार न किया जाये। उन्होंने तो यह सुझाव दिया है कि संविधान की समूची योजना को ध्यान में रखकर इसमें उपयुक्त संशोधन कर दिया जाये। "विधान" की बजाय "आचार संहिता" आदि शब्दों का उल्लेख करके इसमें स तरह परिवर्तन कर दिया जाये जिससे यह सभी दलों के सदस्यों की इच्छा व्यक्त कर सके। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार इसे स्वीकार करना चाहती है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाये तो बेहतर होगा।

श्री गोविन्द मेनन: मैं आपकी परेशानी को समझ गया हूँ कि इस सभा में जो प्रस्ताव पारित किया जाये वह पूर्णतया उपयुक्त हो। परन्तु हमने समिति को कोई विशेष निर्देश नहीं दिया है। समिति जैसा उचित समझेगी सिफारिश करेगी।

यहाँ पर कल किसी माननीय सदस्य ने श्री रंगा पर दल परिवर्तन का आरोप लगाया था। ऐसा करके उन्होंने उचित बात नहीं की। यदि किसी व्यक्ति के विचार किसी दल से मेल न खायें तो वह ऐसा करने के लिये स्वतंत्र है और उसके ऐसे दल को छोड़ कर दूसरे दल में शामिल हो जाने में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। श्री अशोक मेहता के बारे में भी इस प्रकार की बात कहना शोभा नहीं देता। प्रत्येक दूसरे दिन किसी सरकार को गिराने के उद्देश्य से दल परिवर्तन करना

निन्दनीय है और उसको ही हमें रोकना है। इसलिये यह अच्छा ही होगा कि एक समिति नियुक्त की जाये जिससे यह सब चीजें स्पष्ट हो जायें। इन दल-परिवर्तनों के बारे में तरह-तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं।

कल श्री चटर्जी ने कहा कि डा० पी० सी० घोष संयुक्त विधायक दल के टिकट पर चुन कर नहीं आये थे। वह एक निर्दलीय के रूप में चुन कर आये थे परन्तु बाद में कुछ व्यक्तियों ने मिलकर वह दल बना दिया। मेरे विचार में वह समिति इसके लिये भी ठीक सिद्ध होगी। इसलिये इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: : श्री अशोक मेहता भी दो वर्ष तक इस बात का प्रयत्न करते रहे परन्तु इसके लिये अपने दल को सहमत नहीं कर सके । श्री रंगा के बारे में भी मेरा ऐसा ही विचार है। यदि राजनीतिक स्थिति तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ जाये तो एक व्यक्ति अपने राजनीतिक दल को बदल सकता है। अब श्री वेंकटासुब्बया अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पें० वेंकटा सुबय्या (नन्दयाल) मैं "यदि आवश्यक हो" शब्द जोड़ने के लिये तैयार हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन बार-बार दल बदलने के प्रश्न से संसदीय लोकतन्त्र को भारी खतरा होने के प्रश्न पर विचार करके सारे राजनीतिक दलों से यह सिफारिश करता है कि इस प्रकार की कार्यवाही बन्द होनी चाहिये।

श्री नायनार (पालघाट): मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह प्रस्ताव हमारे संविधान के विरुद्ध है ?

उपाध्याय महोदय: : मेरे विचार में यह वैसे ही संविधान के विरुद्ध नहीं है परन्तु इसमें संशोधन हो सकता है। श्री वेंकटासुब्बया अपना भाषण आरंभ करें।

[**श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए**
Shri S. M. Joshi in the Chair]

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दपाल): विधायकों द्वारा दल बदलने का खतरा इतना बढ़ गया है कि यह अब केवल विधायकों के ही ध्यान में नहीं रहा अपितु सारी जनता इससे परेशान है। इस लानत को शीघ्र समाप्त करना चाहिये ताकि इस देश में संसदीय लोकतन्त्र को बचाया जा सके।

दल बदलना राजनीतिक नैतिकता के विरुद्ध है तथा मंत्री पद प्राप्त करने के लिये भी किया जाता है। जब तक हम संसदीय जीवन में अच्छा नैतिक स्तर स्थापित नहीं कर पायेंगे, संसदीय लोकतंत्र के सफल होने की संभावना नहीं है। यहाँ वही स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो कुछ वर्ष पूर्व फ्रांस में थी परन्तु क्योंकि यह देशबहुत बड़ा है इस कारण उसके दुष्परिणाम यहाँ बहुत ही भयंकर होंगे।

आजकल अधिकतर उम्मीदवार दलों के कारण चुने जाते हैं। व्यक्तित्व का महत्व तो अब बहुत कम हो गया है। दल बदलने का अर्थ यह होता है कि उम्मीदवार अपने निर्वाचकों द्वारा व्यक्त किये विश्वास को समाप्त कर देता है। सब इस बात से सहमत होंगे कि इसका कोई इलाज तलाश करना चाहिये।

एक इलाज तो यह है कि एक ऐसी परम्परा स्थापित करें कि जो सदस्य अपना दल बदले अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दे तथा फिर से चुनाव लड़े। इस नियम का फिर सब कठोरता से पालन करे।

एक और इलाज यह है कि निर्वाचकों को यह अधिकार दिया जाये कि वह चुने हुए सदस्य की सदस्यता समाप्त करवा सकें। परन्तु इसमें कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिये ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके बारे में कानून बनाना चाहिये। वह व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। इस संदर्भ में चर्चिल तथा पामरस्टन और ग्लेडस्टोन द्वारा भी दल बदलने का उल्लेख किया जाता है।

इसलिये हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस समस्या का कोई हल तलाश किया जाये ताकि यहाँ संसदीय लोकतन्त्र मजबूती से स्थापित हो सके। मैं इस पर किसी दल के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या समझ कर बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। "इस सभा की राय है कि विधायकों द्वारा एक दल को छोड़ कर दूसरे में निष्ठा व्यक्त करने और विधान सभाओं में बारम्बार दल परिवर्तन करने संबंधी समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये सरकार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संवैधानिक विशेषज्ञों का एक उच्च-स्तरीय समिति तुरन्त नियुक्त करे। यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को जो भयानक रूप से व्याप्त होती जा रही है, रोकने के लिये एक विशेष व्यवस्था करे और उपयुक्त विधान द्वारा प्रभावी उपाय करे ताकि देश में संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ एवं उपयोगी ढंग से चल सके।"

इस पर कुछ संशोधन भी है।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, in our country the legislators have changed their party affiliation for the change of portfolios. If one did not have a propiftable ministry, he would go over to the other party so that the ministry may collapse and he may find a better portfolio in the new ministry.

Our Country was considered to be an ideal in regard to morals standards and we should start to read Manusmriti and Gita. But now we have gone down to such an extent that now we can be brought for money.

I an sorry that my own state Haryana has become most notorius in this respect. Our state had produced very brave soldiers who won Victoria Cross but now most of the defections have taken there. My friend suggested making such a provision in the Representation of the people Act. I want to tell them that much a provision exists in other countries.

In U. K. there was a time when a government had a majority of only two but defection did not take place there. Here we have majorities of even 40 M. L. As., yet nobody knows when the government may fall because of defection.

I agree with Shri Madhu Limaye that we are ridiculed by the world because of it.

I support that this resolution may be passed so that government may frame legislation about it.

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun). I am grateful to Shri Venkata subbaiah for bringing this resolution and I want to congratulate him for this.

I have fought election against Ministers but I did not find any Collector in the district giving me a step motherly treatment. Similarly I opposed Shri V.C. Shukla when I learnt that he caused lathi-Charge on the meeting of his adversaries.

I lay more emphasis on character.

We belong to country the Scripture of which say that one should not vote to a drunkard and to one who listens to dirty songs.

I left Congress because the Congress did not stand to the words of Gandhiji when he said: "I would not accept the partition of India even if the whole of country were to go into flames." Similarly I am supporter of Badshah Khan who is behind prison bars since 1942.

I feel that one should resign one's membership in the legistature if one changes one's political party. I again fully support this resolution.

Shri Shrichand Goel (Chandigarh) : I know that Congressmen are now supporting this resolution not because they feel that change of party affiliation by members was bad but because now they are the sufferers as a result of that. I know late Shri Kairon had opened a department, the responsibility of which was to corrupt members and make them join Congress party.

The President of Jan Sangh party Shri Madhok, wrote a letter to Smt. Indira Gandhi asking her to call a conference of all opposition parties to find a remedy to the curse of change in party affiliations. But no satisfactory reply was given to that by the Prime Ministers.

Shri Har Dwari Lal a member of the opposition in Haryana resigned for the membership of the legislature when he changed his party but can Congress also cite such an example?

I want the Congressmen to be honest in their profession on this resolution.

I do not understand the reason for Congress supporting the Gill Ministry in Punjab and the Ministry of Dr. P. C. Ghosh in West Bengal.

I support this resolution but I would appeal my friends to honestly implement it also as mere lectures will not solve it.

Shri Narindra Singh Mahida (Anand) : Mr. Chairman, On reading the report of the Governor of Haryana I felt that the members of all parties there are running after offices. This is a matter of great regret to me.

We have forgotten the ideal of selfless service. We are after power. All parties should condemn these defections which have assumed alarming proportions.

Members of Parliament should be included in the high level committee porposed in the Resolution to consider the problem of floor crossing. Suitable remedy should be formed out to check crossing of floor by members belonging to different political parties as well as independent members.

Legislators have lost respect in the public eye due to frequent defections. This respect has to be restored.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : It will not be wise and proper to make any legislation affecting individual legislators. There may be cases when a Member might have to change his political affiliation in the light of certain new developments after the elections. Some sort of a code of conduct should be evolved which political parties will have to follow. At the time of giving tickets to various candidates at the time of elections, political parties should see that tickets are given only to candidates who have staunch faith in their political ideology.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[**Mr. Deputy Speaker** in the Chair]

Tickets should not be given on considerations of caste, creed or financial standing. Political parties can also decide not to admit defectors back into their fold. It is therefore not neccssary to take recourse to some kind of legislation to stop crossing of floor by members. But various parties may sit together and evolve some code of conduct which can be given effect to at the party level.

It is not proper for political parties who opposed one another in the elections to form coalitions.

Shri Shashi Bhushan Bajpai (Khargone) : It is of utmost importance to put a stop to defections by legislators. Legislators should not betray the confidence reposed in them by the electorate. Defections have become so widespread and frequent that they pose a serious and grave threat to the functioning of democracy in this country. If this evil is allowed to continue unchecked, it will not be possible to have stable Governments in the States.

Suitable ways should be found out to meet the challenge posed by these defections of late. If a legislator changes his political loyalty he should resign his seat and seek a fresh mandate from the people.

The Resolution should receive the support and approval from all sections of the House. The mover deserves all praise for bringing this resolution before the House at an opportune time.

श्री राजाराम (सलेम): देश में दल छोड़ की यह बीमारी फैलाने के लिये कांग्रेस पार्टी उत्तर-दायी है। 1952 से कांग्रेस पार्टी द्वारा यह बीमारी उत्पन्न की गई।

यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने देश की यह हालत कर दी है। वे नैतिकता का प्रचार करते हैं परन्तु साथ-साथ सभी अनैतिक रास्ते अपनाते रहते हैं। वे संवैधानिक उपबन्धों की बात करते है और फिर भी वे असंवैधानिक कार्य करते रहते हैं। यदि वे कोई विधान ला कर उसे पास कराने में कामयाब हो जाते हैं तो उस पर अमल कौन करेगा ?

यह सुझाव दिया गया है कि एक आचार संहिता तैयार की जाये। यदि ऐसी आचार संहिता बन भी जाती है तो लोगों को उस पर अमल करने के लिये आगे आना चाहिये। यदि लोग उस पर अमल करने के लिये तैयार नहीं हैं तो सारे देश के लिये एक आचार संहिता बनाने का फायदा ही क्या है ?

कांग्रेस पार्टी को अपनी कथनी को अमली जामा पहनाना चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करती तो फिर दल छोड़ की प्रवृत्ति को रोकने के लिये विधान बनाने का कोई फायदा नहीं है।

मैं अपने दल की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर): आधे घण्टे की चर्चा के बारे में जो 5–30 बजे ली जानी थी, स्थिति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें 2½ घण्टे तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करनी है। आज हमने मध्याह्न भोजन के लिये भी सभा स्थगित नहीं की। आधे घण्टे की चर्चा अगली बार ली जायेगी। बहुत से माननीय सदस्यों ने मुझे ऐसा करने का सुझाव दिया था। परन्तु यदि सभा देर तक बैठ कर उसे भी समाप्त करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हमें पहले इस प्रस्ताव को निपटा देना चाहिये।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबार): सामान्य प्रक्रिया यह है कि आधे घण्टे की चर्चा निर्धारित समय पर ली जाती है।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या इसे अब लिया जायेगा या सोमवार को ?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सोमवार के लिये वादा नहीं कर सकता। उसके लिये उन्हें अध्यक्ष को लिखना होगा। अध्यक्ष महोदय ही कोई अन्य तिथि निर्धारित कर सकते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी: दूसरे प्रस्ताव के बारे में स्थिति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसे अभी पेश किया जा सकता है।

आधे घण्टे की चर्चा को 6–20 बजे लिया जायेगा। तब तक हम इस प्रस्ताव को निपटा दें।

श्री चेंगलराया नायडू : यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इस पर अगले दिन चर्चा की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: हम इसे आज ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे।

श्री सेझियान (कुम्बेकणम) : 2½ घण्टे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये निर्धारित है और इस समय कोई अन्य कार्य नहीं लिया जा सकता।

Shri Madhu Limaye : The discussion on this Resolution should be postponed for next Friday as we cannot dispose it today. We should now take up half an-hour discussion instead.

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सभा की राय जाननी है। क्या वे औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

Shri Madhu Limaye : I move that this discussion be postponed and half an hour discussion be taken up.

श्री सेझियान: मेरा निवेदन यह है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये निर्धारित समय में केवल गैर-सरकारी कार्य ही लिया जाये और गैर-सरकारी कार्य को निपटाने के बाद ही कोई अन्य मद लिया जाये । जो सदस्य आधे घंट की चर्चा में रुचि रखते हैं वे उस समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारे नियमों के अनुसार हम इस प्रस्ताव को अगले दिन नहीं ले सकते। इसे अगले सत्र में ही लिया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस प्रस्ताव पर कुछ चर्चा हो चुकी हो उसे दो सप्ताह के बाद लिया जा सकता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नियमों के अनुसार आज 2½ घण्टे गैर-सरकारी कार्य में के लिये दिये जाने चाहिये। यह 2½ घण्टे अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिये हम अन्य कार्य कैसे ले सकते हैं ?

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : कार्य सूची के अनुसार हम आधे घण्टे की चर्चा को 5–30 बजे ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: बात यह है कि गैर सरकारी कार्य 3 बजे की बजाय बाद में लिया गया।

श्री चेंगलराया नायडू : इसमें मेरा क्या दोष हैं। से 5–30 बजे लिया जाना चाहिये।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर): मैं इस प्रस्ताव के बारे में केवल एक वाक्य ही बोलना चाहता हूँ ताकि बाद में जब इस पर चर्चा हो तो मुझे अपना भाषण जारी रखने का अवसर मिल सके।

श्री पे० वेंकटसुब्बया का यह प्रस्ताव एक बच्चा मात्र है जिसे सभी माननीय सदस्य आशीर्वाद दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का वाक्य पूरा हो गया है।

मैं सभा की राय जानना चाहता हूँ।

Shri Madhu Limaye : Half an honr discussion may be taken up.

उपाध्यक्ष महोदय : तब इस प्रस्ताव पर गैर-सरकार कार्य के लिये निर्धारित अगले दिन के लिये चर्चा स्थगित की जाती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपने क्या राय ली है। केवल एक सदस्य ही इसके पक्ष में है। सभा की राय तो यह है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री शुक्ल इस बात पर दृढ़ हैं कि इसे आज ही पारित कर दिया जाये। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये हम चाहते हैं कि इस पर अच्छी तरह चर्चा हो। पाँच मिनट से कुछ नहीं बनेगा। इसलिये इस समय आधे घण्टे की चर्चा को ले लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे सामने प्रश्न समय बढ़ाने का नहीं है हालांकि मैं समय बढ़ाने के लिये तैयार हूँ। प्रश्न इस समय यह है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा रखी जाये या आधे घण्टे की चर्चा को पहले लिया जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : गैर-सरकारी कार्य के लिये निर्धारित किये गये समय के समाप्त होने से पहले पीठासीन अधिकारी को कोई अन्य कार्य की अनुमति देने का अधिकार नहीं है।

श्री चेंगलराया नायडू : आधे घण्टे की चर्चा के बाद गैर-सरकारी सदस्य के इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल 25 मिनट शेष हैं। हम 6–20 बजे आध घण्टे की चर्चा ले सकते हैं। तब तक माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें

श्री दी० चं० शर्मा : प्रश्न यह है कि क्या हम राजनीतिक अवसरवादी को पनपने देना चाहते हैं या राजनीतिक स्थिरता तथा राजनीतिक आदर्शवाद को। मेरी राय में कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि लोकतंत्र में हम स्थिरता तथा सुरक्षा चाहते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों को नहीं चाहते जो आये दूसरे-तीसरे दिन रंग बदलते रहते हैं। हम परिपक्व व्यक्तियों को चाहते हैं जो अपने दल के सिद्धान्तों पर दृढ़ रहें और आये दिन दल परिवर्तन करने के पूर्णतया विरुद्ध हों।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस सम्बन्ध में आचार संहिता से कोई लाभ नहीं होगा। हमने देखा कि कई आचार-संहिता के बावजूद अमल किसी पर भी नहीं होता इसलिये मैं नहीं समझता कि इन संहिताओं का कोई अर्थ है। इसी सभा में देखिये क्या होता है—क्या-क्या परम्पराएं निभाई जाती हैं? यहाँ क्या प्रक्रियायें बनाई जा सकती हैं? इस समस्या का हल केवल एक बात से हो सकता है—वह यह कि संविधान में प्रत्याह्वान के सिद्धान्त की व्यवस्था की जाये ताकि अपना राजनैतिक रंग बदलने वाले व्यक्ति को वापस बुलाया जा सके और उससे फिर से चुनाव लड़ने के लिये कहा जा सके। रूस के संविधान में इस सिद्धान्त की व्यवस्था है।

इसलिये, एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये, जो यह कहे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रत्याह्वान सिद्धान्त को स्थान दिया जाये।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, I am not opposed to the resolution before the House in principle. But I feel that a resolution or legislation of this nature will not solve the problem and also will not be of much practical use in the present state of affairs. The trend of floor crossing is the symptom of degeneration which has set in our political life and this very trend which has crept in cannot be checked through such methods.

At a meeting of various political parties held in Maharashtra in 1960, I had suggested that a convention should be established that no party should admit a defector to its fold. But our Home Minister, Shri Y. B. Chavan, who was then the State Chief Minister had expressed his inability to act on the suggestion immediately on the ground that political loyalties were inferment at the time. He, however, had promised to adhere to the convention after 1962 when political loyalties were stablished. But it is unfortunate that the congress

continues to encourage defections by not only admitting defectors to its fold but even appointing them as Ministers.

I personally feel that mere legislation will not help in this regard unless we establish a convention to shum defectors and adhere to it

Shri Vishwanath Roy (Deoria) The main factor responsible for the Present State of political instability in the country is the combination of various political parties which are having different ideologies and are opposed to one another in principle but have joined together by forming coalition Governments in various states with a view to achieving their political ends. It creates a vicious political atmosphere which retards the progress of the country and the country suffers.

श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए

Shri S. M. Joshi in the Chair.

These coalition governments cannot succeed and run administration as the ideologies of various constitutent units are quite different from one another. The result is that they are fighting among themselves and hence the large scale defections. A legislator never defect to any fold it he is politically conscious of his responsibilitis. These defections create conditions in which democracy cannot function properly. We have to establish healthy connentions to strengthen democracy anything that comes or creps into undermine it must be condemned and checked in its infancy. This desease which is spreading gradually has got to be checked to that democracy does not suffocate ; the country does not suffer. This is exactly what is intended to be done through the resolution and the mover deserves congratulations. We have not the principle of recall embodied in our constitution hence no check on the trend of floor crossing.

The Spirit of the resolution serves the interest of the political life of the nation. as a whole. It will bring political stability in the country. It should be passed and the Government should frame rules in this regard and if necessary, an amendment should be made in the constitution. I would like to add that a committee should be appointed to go into this question and frame rules etc. for the purpose. It would be better if all the political parties cooperated in this regard and formulate a code of conduct so that this frequent crossing of floor by the legislators could be stopped.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Chairman, Sir, I appreciate the spirit of the Resolution moved by my friend Shri P. Venkatasubbaiah. It is a matter of satisfaction that the Congress party has now, although after a pretty long time, realised seriousness of the desease of defection ; they have realised that crossing of floor by legislators is certainly bad.

The Congress Party has grown very unpopular and people have grown sick of this party and hence condemned by each and everyone. People welcomed the defections from the Congress party but insulted those who left other parties to join the Congress party. Still I am of the view that floor crossing is bad.

Mr Chairman : Now the House will take up half an-hour discussion. The Hon. Member may continue his speech next time when the House resumes discussion.

*नागालैंड में युद्ध-विराम

**CEASE FIRE IN NAGALAND

Mr. Chairman : Now we can take up the half-an hour discussion. Mr. Chengaloraya Naidu.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : वर्ष 1953 से नागा-उत्पात शुरू हुआ है, सरकार ने नागा समस्या को हल करने की गंभीर रूप से चेष्टा कभी नहीं की। वर्ष 1964 में सरकार ने भूमिगत नागा विद्रोहियों के साथ एक करार किया और उनके साथ युद्ध-विराम समझौता हो गया। इस युद्ध विराम समझौते की अवधि अब समय-समय पर बढ़ाई जा रही है। आज हम क्या देखते हैं कि कोहिमा में दो सरकारें हैं—एक निर्वाचित सरकार और दूसरी भूमिगत सरकार, यद्यपि वहाँ राजभक्त नागाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन उन्हें कष्ट उठाने पड़ रहे हैं और उन पर विद्रोही नागाओं द्वारा हमले किये जा रहे हैं और उन्हें तंग किया जा रहा है। नागालैंड के लोग जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को कर दे रहे हैं लेकिन उन्हें भूमिगत नागा विद्रोहियों को भी कर देने पड़ते हैं। समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार इन तमाम बातों को सहन कैसे कर रही है।

नागालैंड में कानून की जो हत्या होती है तथा वहाँ व्याप्त एक किस्म की अराजकता को दूर करने तथा वहाँ विधि और व्यवस्था कायम करने के लिये सरकार ने आज तक कभी गंभीरता से काम नहीं लिया। युद्धविराम सन्धि के अन्तर्गत, नागाविद्रोहियों को एक ओर तो अपने पाँव जमाने के लिये काफी समय मिल रहा है और दूसरी ओर वे अपने लोगों को गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में तथा अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग में प्रक्षिण प्राप्त करने के लिये चीन भेज रहे हैं। वे अपने लोगों को प्रशिक्षण के लिये पाकिस्तान भी भेज रहे हैं, नागालैंड के मुख्य मंत्री ने परसों कहा है कि :

Unless the attempt by a section of the misguided underground Nagas to seek aid from unfriendly foreign countries is stopped right now, Nagaland would face a grave danger. This would turn the State into a battle field."

क्या हमारी सरकार इतनी शक्तिहीन हो गई है कि वह विद्राहियों पर नियंत्रण नहीं रख सकती और उन्हें सीमा पार जाने से रोक नहीं सकती ? क्या हमारी सीमा बल को मजबूत नहीं बनाया जा सकता ? यदि सीमा सुरक्षा बल में अपेक्षित सक्रियता की कमी है, तो सरकार को चाहिए कि वह उसके कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करे। सरकार को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये नागा विद्रोही, जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं तथा हथियारों से लैस हैं, केवल मौके की ताक में हैं और जब उनका मौका आयेगा तो वे विद्रोह करेंगे और हमारे साथ उलझेंगे। यदि सरकार इस मामले से वास्तव में चिन्तित है तो उसके लिये यह जरूरी है कि वह नागा विद्रोहियों के साथ दृढ़ता से व्यवहार करे और युद्ध-विराम की अवधि को समय-समय पर बढ़ाने के लिये कदापि राजी न हो।

मालूम ऐसा हुआ है कि वहाँ केवल एक ही विद्रोही नागा सरकार नहीं है अपितु तीन हैं जिनके मुख्यालय नागा लैंड में हैं और इनमें से किसी का किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि हमारी उदारता के फलस्वरूप ऐसी चीजें हो रही हैं, और हम बैठे देख रहे हैं, तो भगवान ही जानता है कि भविष्य में हमें इसका क्या उपहार मिलेगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, we fail to understand why the Government was not firmly dealing with the Naga Problem. The Government ought to know that China and Pakistan were hinting at the recognition of the rebel Naga Government. Did it realise the

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half an hour discussion.

danger involved? There is no reason why the Government is so soft in the matter. Something must be done to solve this problem once for all.

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज मंत्री (श्री ब० रा० भगत): यह कहना गलत है कि सरकार नागा समस्या हल करने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। यह एक बहुत नाजुक सवाल है जिसमें बहुत-से लोगों की भावनाएँ अन्तर्निहित हैं और इस मसले को हल करने में हमें उनके साथ नपेतुले ढंग में तथा बहुत सतर्कता से व्यवहार करना होता है।

इस प्रश्न पर सभा में कई बार बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया जा चुका है और सर्व-सम्मति यही रही है कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिये जो बातचीत कर रही है, जिन शान्तिपूर्ण उपायों को काम में ला रही है तथा जिस तरह से उनकी शंका का निवारण कर रही है, वह नीति सबसे अच्छी। हमारी धारणा है कि सैनिक कार्यवाहियों से समस्याएँ हल नहीं होतीं।

हमने यह बात पूर्णतः स्पष्ट कर दी है कि जहाँ तक बात चीत के प्रश्न का सम्बन्ध है, उसे भारतीय संघ के अन्दर रहना होगा, नागालैंड भारत का एक अंग है, नागा लोग अन्य भारतीयों की तरह देश के नागरिक हैं और उन्हें नागरिकों के सभी अधिकार प्राप्त हैं ; नागालैंड में व्याप्त शान्ति ने वहाँ अनुकूल वातावरण पैदा किया है क्योंकि बहुत से लोग, लम्बी बरबादी तथा कठिनाइयों के बाद, शान्ति का महत्व महसूस करने लगे है। वर्तमान सरकार को अपने प्रयासों में सफलता मिल रही है और समझौते की बातें चल रही हैं। हमारा विश्वास है कि उग्रवादी तत्व जिन्हें बाहरी ताकतें भड़का सकती हैं अथवा जिनकी अपनी निजी आकांक्षाएँ हैं, बहुत कम है—सीमित हैं और अन्ततोगत्वा हम उन्हें मनाने में सफल होंगे।

यह संभव है कि राजभक्त नागाओं को, जिनका नागालैंड में बहुमत है, तंग किया जा रहा हो, लेकिन पिछले महीनों में अथवा गत तीन वर्षों में नागालैंड में कोई हिंसात्मक घटनाएँ नहीं घटीं। मनीपुर में ऐसी कुछ घटनाएँ हाल में हुई हैं लेकिन लोग स्थिति का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं।

जहाँ तक लोगों को सीमा पार करने से रोकने के प्रश्न का सम्बन्ध है, वह इतनी सरल बात नहीं है। नागालैंड बहुत विशाल राज्य है और उसकी सीमाएँ बहुत लम्बी हैं। यह प्रदेश घने जंगलों से भरा है और वहाँ भयानक ऊबड़ खाबड़ भूमि है। तथापि हमने बहुत से लोगों को सीमा पार करने तथा नागालैंड राज्य में घुसने से रोका है। यह सच है कि कुछ लोग हाल में चीन गये और उनमें से कुछ व्यक्ति वापस आ गये हैं। किन्तु स्पष्ट रुप से यह कहा जा सकता है कि हम अपने देश के आन्तरिक मामलों में किसी भी विदेशी को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे और यदि कोई देश ऐसी कोशिश करता है, तो हम उसके साथ उसी तरह व्यवहार करेंगे जिस प्रकार बाहर से हस्तक्षेप करने वाले के साथ किया जाता है।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 27 नवम्बर, 1967/6 अग्रहायन, 1889 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 27, 1967 Agrahanaya 6, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.